ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका : म.प्र. के विशेष संदर्भ में

डॉ. एस. आर. मेहरा
सहा. प्राध्यापक भूगोल शास. स्ना. महाविद्यालय शहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र)

सारांश – भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश देश का 'हृदय स्थल' प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश के चारों दिशाओं में अनेक पर्यटन स्थल हैं। यहॉ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक या भौगोलिक आदि पर्यटन स्थल हैं जिसमें प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश देश का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है, जहॉ 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्यता एवं वन्य प्राणियों को देखने के लिए आते हैं जिससे मध्यप्रदेश शासन के राजस्व में वृद्धि तो हो ही रही है साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। वर्तमान मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मीटिंग पचमढ़ी में निर्णय लिया गया है कि सरकार पर्यटन बोर्ड का गठन करेगी, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुधार एवं रोजगार की संभावनाओं का विकास किया जा सके। इन राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, शेर, मोर, हिरण, खरगोश, बंदर, नीलगाय आदि अनेक पशु–पक्षी पाये जाते हैं। कान्हा–किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सन् 1974 ई. में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था परन्तु बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहॉ के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले पशु चीतल है। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यानों एवं पर्यटन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाना प्रासांगिक है।

भारत का हृदय मध्यप्रदेश पर्यटकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जहॉ देशी–विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। मध्यप्रदेश का इतिहास, वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और आलीशान ऐतिहासिक विरासतें मध्यप्रदेश को पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाती है, इसलिए कहा जाता है कि मध्यप्रदेश खूबसूरत पर्यटन स्थलो का खजाना है। ''मध्यप्रदेश भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है जहॉ 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिनमें प्रतिदिन पर्यटक बड़ी सख्या में देखने के लिए आते हैं।''[1] कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश का सबसे बड़े पर्यटक स्थल माने जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को मध्यप्रदेश की पर्यटन राजधानी कहा जा सकता है, जहॉ बाघ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, चिंकारा तथा नीलगाय एवं अनेक प्रजातियों के पक्षी पाये जाते है जा पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों की उपयोगिता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि इन उद्यानों में सीधे भ्रमण नहीं किया जा सकता, प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ता है तथा सुबह 6.00 बजे पहुंचना पड़ता है। इस प्रकार मध्यप्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का संक्षिप्त अध्ययन करने का प्रयास इस शोध पत्र के माध्यम से किया गया है।

शोध विधि तंत्र :– प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ–साथ पाये जाने वाले प्राणियों, पक्षियों एवं वनस्पतियों की प्रजातियों तथा पर्यटकों की जानकारियों को अध्ययन के लिए शामिल किया गया है। कुछ तथ्यात्पक आंकड़े बेबसाइट के माध्यम से सर्च कर प्राप्त किया गया है। उपयोगी छायाचित्र भी बेबसाइट स डाउनलोड कर प्राप्त किया गया है।

मध्यप्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान :– मध्यप्रदेश में छोटे–बड़े कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है परन्तु अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख 7 राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन किया जा रहा है :–

1. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान :–कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मण्डला जिले के अंतर्गत आता है। ''यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लगभग 940 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे सन् 1933 ई. में अभ्यारण्य तथा 1955 ई. में नेशनल पार्क बनाया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1974 ई. में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था।''[2]इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा,

चीतल, चिंगारा, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाये जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रीवेंशन योजना चल रहीं है।

(कान्हा राष्ट्रीय उद्यान : बाघ)

2. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान :–यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल जिलों में है, इसका स्थापना सन् 1968 ई. में की गई थी तथा इसे 1993 ई. में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाये जाते हैं । यह क्षेत्र 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। ''811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी–छोटी अनेक पहाड़ियाँ है। पार्क में साल और बंबू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक विमानतल जबलपुर है जो कि 164 किमी. की दूरी पर स्थित है।''[3]रेलमार्ग से भी जबलपुर, कटनी और सतना बांधवगढ़ से जुड़ा है। खजुराहो स बांधवगढ़ के बीच 237 किमी. की दूरी है । दोनों स्थानों के बीच केन नदी के कुछ हिस्सों को कोकोडाइल रिजर्ब घोषित किया गया है। ''शेर, बाघ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, आदि 22 पशु प्रजातियाँ एवं 250 पक्षिओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं । इस उद्यान में 108000 पर्यटकों का आगमन दर्ज है।''[4]

(बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान : चीता)

(बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान : सफेद शेर)

3. राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघवा :– यह उद्यान डिण्डौरी जिले की शहपुरा तहसील के अंतर्गत आता है जो कि शहपुरा से 14 किमी. दक्षिण दिशा में है । ''क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किमी. है,परन्तु पुरातात्विक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है । इसकी स्थापना 1968 ई. में की गई गयी थी । इस उद्यान में पादपों एवं जीव–जन्तुओं के जीवाश्म पाये जाते हैं । यहॉ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों के जीवाश्म अमूल्य धरोहर के रूप में मौजूद हैं।''[5] कान्हा से बांधवगढ़ जाने वाले पर्यटक यहॉ जरूर रूकते हैं।

(राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुवा,शहपुरा डिण्डौरी) (जीवाश्म) ताड़ के वृक्षों के जीवाश्म बेहद खास है, क्योंकि मध्य भारत में इस तरह के पेड़ नहीं पाये जाते हैं। 1970 में यहां जीवाश्मों की खोज की गई थी। ''खोज करने वालों में मण्डला जिले के सांख्यिकी अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र प्रसाद, एस. आर.इंगले और डॉ. एम.बी.बांदे मुख्य हैं ।''[6]यहॉ के जीवाश्म बेहद खास है जो धरती के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं । इनसे भारत के वनस्पतियों के इतिहास की भी जानकारी मिलती हैं, पार्क के बारे में कहा जाता है कि यहॉ करोड़ों साल पहले अरब सागर हुआ करता था । प्राकृतिक परिवर्तन एवं भू–गर्भिक हलचलों की वजह से पेड़ से पत्ती तक जीवाश्म में परिवर्तित हो गए । घुघवा नेशनल जीवाश्म पार्क में डायनासौर के अंड़े, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, यूकेलिप्टिक ट्रो, केले के जीवाश्म देखने को मिलते हैं । सही समय पर बाहर ना आने और प्राकृतिक परिवर्तन के चलते ये पत्थर में परिवर्तित हो गए हैं।

4. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान :–''पन्ना राष्ट्रीय उद्यान म.प्र. के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किमी. है, जिसकी स्थापना 1981 ई. में हुई थी एवं इसे 1994 ई. में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश का 5वॉ एवं भारत का 22वॉ बाघ परियोजना में चयनित राष्ट्रीय उद्यान है।''[7] ''इस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अच्छे प्रबंधन एवं व्यवस्थित रख–रखाव के लिए ''अवार्ड आफ एक्सीलेंस'' से वर्ष 2007 में नवाजा गया । इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2009 में 22563 पर्यटकों का आगमन हुआ ।''[8] इस उद्यान में बाघों क अलावा सरीसृपों का भी घर है। यह पार्क बहुत दिलचस्प जगह स्थित है। पार्क के अंत में उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जंगली वेल्ट शुरू हो जाती है । यहॉ आसानी से चीतल, स्लोथ भालू, सांभर और चिंकारा को देखा जा सकता है । इस पार्क में कई प्रकार की चिड़ियॉ पाई जाती है । जैसे–किंग बल्चर, हनी कजार्ड, बार हेडेड और ब्लासम–हेडेड पाराकिट आदि।

5. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान :– यह होशंगाबाद जिले में लगभग 525 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि सन् 1983 ई. में स्थापित किया गया था।

सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है । यह खासतौर से बाघ संरक्षण के रूप में विख्यात होने के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के जीव–जन्तुओं और पेड़–पौधों का घर है । इस नेशनल पार्क में आने के बाद पर्यटक चितकबरे हिरण, साही, बाघ, तेंदुआ और दलदल वाले मगरमच्छ आदि को आसानी से देखा जा सकता है । अनोखे आकर्षणों में काले हिरण और विशालकाय भारतीय गिलहरी शामिल है । नेशनल पार्क में कई प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं, जिन्हें देखना अद्‌भुत अहसास होता है । इस नेशनल पार्क में पेड़–पौधों का अनोखा संग्रह है जिसमें पौधों की 1300 से अधिक प्रजातियॉं और कई औषधीय पौधे पाये जाते हैं।

6. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान :– वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है जो कि अरेरा को पहाड़ियों के मध्य है। ''इसकी स्थापना 1979 ई. में की गई थी जिसका क्षेत्रफल 452 वर्ग किमी. है । यह थ्री इन वन राष्ट्रीय उद्यान है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ–साथ चिड़ियाघर तथा जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी है ।''[9]यहॉं ज्यादतर वो जानवर है जो लावारिस, कमजोर, रोगी, घायल अथवा बूढ़े थे या फिर जंगलों में भटककर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आ गए थे तथा बाद में उन्हें पकड़कर यहॉं लाया गया। 5 किमी. लम्बे इस राष्ट्रीय उद्यान के एक तरफ पूरा पहाड़ है और हरा–भरा मैदानी क्षेत्र है जो जंगलों तथा हरियाली से आच्छादित है तो वही दूसरी ओर भोपाल का मशहूर और खूबसूरत बड़ा तालाब है। यह उद्यान भोपाल में ही स्थित है इसलिए यहॉं पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहॉं वर्ष 2011 में 250000 पर्यटकों का आगमन हुआ था।

7. पेंच राष्ट्रीय उद्यान :– यह उद्यान सिवनी–छिंदवाड़ा जिलों में तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फेला हुआ है। ''इसकी स्थापना 1975 ई. में हुई थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किमी. है।''[10] इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैण्ड क्षेत्र तथा वाटर रॉफ्टिंग सुविधा उपलब्ध है। देश का टाईगर रिजर्व होने का गौरव इस उद्यान को 1993 ई में मिला। यहॉं 210 पक्षियों की प्रजातियों के साथ–साथ अनक जीव–जन्तुओं से भरा हुआ है। अनेक दुर्लभ जीवों और सुविधाओं वाला पेंच नेशनल पार्क तेजी से प्र्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। इस उद्यान में लगभग 64 बाघ वर्तमान में मौजूद है।

समीक्षा :– आज पर्यटन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । पर्यटन आने वाले समय में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करेगा । उपर्युक्त अध्ययन में मध्यप्रदेश के 7 राष्ट्रीय उद्यानों का संक्षिप्त अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इन राष्ट्रीय उद्यानों में रोजगार की अपार संभावनाएँ छुपी हुई है । ये राष्ट्रीय उद्यान काफी खूबसूरत एवं मन मोह लेने वाले है क्योंकि यहॉं प्राकृतिक वनस्पति के साथ–साथ वन्य जीवों का संरक्षण किया गया है जो कि पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है जो उन्हें विश्व के चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों में अपनी जगह बना सकें। हालांकि वर्तमान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में एक पर्यटन बोर्ड का गठन किया जायेगा, जो कि पर्यटन की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करेगा, साथ ही उनकी गुणवत्ता एवं विकास के लिए कार्य करेगा ।

निष्कर्ष :– उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश देश का पर्यटन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है जिसको पर्यटन का खजाना कहा जाता है। यहॉं पर्यटकों को अनेक प्रजातियों के प्राणी देखने को मिलते है जो कि पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ अन्य लोगों को रोजगार प्राप्ति का सहारा बन रहे हैं। यदि पर्यटन बार्ड का गठन हो जाता है तो निश्चित ही इस क्षेत्र में शासकीय एवं निजी सेवा के क्षेत्रों का व्यापक सृर्जन होगा। अंत में हम कह सकते है कि पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है तथा राष्ट्रीय उद्यानों के बिना पर्यटन अधूरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. द्विवेदी,ए.पी. ''प्रोटेक्टिड एरियाज ऑफ मध्यप्रदेश'' गवर्मेन्ट प्रिंटिंग प्रेस, भोपाल 2003.
2. कान्हा टाईगर रिजर्व : मध्यप्रदेश फारेस्ट डिपार्टमेंट, रिटरीब्ड 14 अप्रैल 2010.
3. चौधरी, एल.के.एण्ड अख्तर खान : बांधवगढ़ फॉर ऑफ द टाईगर बिल्ड एटलस बुक, भोपाल 2003.
4. बांधवगढ़ नेशनल पार्क : विकिपीडिया.
5. मिश्रा गिरिमा, ''ए डिनो एग्ग एण्ड अदर फॉसिल्स'' द इंडियन एक्सप्रेस, रिटरीब्ड 26 दिसम्बर 2012.
6. शुक्ला अनुमेहा, मेहरोत्रा आर.सी., त्यागी अंतरिक्ष, ''रिसर्च कम्यूनिकेशनस'' करेन्ट साइंस, वायल्यूम 103, नं. 1, 10 जुलाई 2012
7. मूर्थी आर.एस. 2012 ''पन्ना टर्नराउण्ड स्टोरी पन्ना'' पन्ना टाईगर रिजर्व पेज नं. 6.
8. 'पन्ना रिजर्व गेट्स अनादर टाईग्रेस'' द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया 28 मार्च 2011.
9. वन विहार नेशनल पार्क : ''एन इंट्रोडक्शन 2007'' आरचिव्ड फ्राम द ओरिजिनल ऑन 23 मार्च 2012.
10. MPT –''Madhya Pradesh Tourism''www.mp tourism.com retrived 11 June 2016.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

अकबर का विभिन्न धर्मों से सम्बन्ध

प्रवीण पाठक
पीएच.डी गांधी एवं शांति अध्ययन महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

सारांश :– अमरकोट के राजा वीर साल के यहॉ 15 अक्टूबर, 1542 ई. को [1], कार्तिक मास की छठ को हुआ। जन्म स्थल अमर कोट का दुर्ग था। मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति में अकबर की धार्मिक नीति को श्रेष्ठतम माना गया है। अकबर की नीति पूर्णतया धार्मिक सहिष्णुता की थी उसकी धार्मिक नीति 'सुलहकुल' (सभी के साथ शांति) के सिद्धान्त पर आधारित थी।

सभी धर्मो और आध्यात्मिक आन्दोलनों के पति उदारता और सकिय सहानुभूति एवं सहायता का प्रयत्न प्रान्तीय राज्यों के द्वारा कभी–कभी भी किया गया था।

अकबर प्रथम शासक था जिसने शासन के आरम्भ में धीरे–धीरे सभी धर्मो और आध्यात्मिक आन्दोलन के प्रति प्रगतिशील उदारता और सकिय सहानुभूति की नीति को अपनाया।[9]

मुख्य शब्द :– अकबर, हिन्दू धर्म, जोरोस्ट्रीयन धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म

अकबर का विभिन्न धर्मों से सम्बन्ध

प्रस्तावना :– केवल मुगल शासकों मे ही नही अपितु सम्पूर्ण मध्य–युग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मुगल– साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर का है इसके अतिरिक्त राजस्व और शासन में जिन नवीन और उदार सिद्धान्तों का उसने प्रतिपादन किया वह उसे भारत में ही नही बल्कि सम्पूर्ण विष्व के महान शासकों में स्थान प्रदान करता है। प्राय 350 वर्श का मुसलमानी शासक उस समय तक भारत में अस्थिर था और एक भी मुसलमान शासक न तो अपने राजवंश को स्थिरता प्रदान कर सका और न ही शासन के उन सिद्धान्तों को व्यवहार में ला सका था जिनके आधार पर एक विदेशी और भिन्न धर्म के मतावलम्बी एक अन्य देश में स्थायी रूप से निवास करने या शासन करने का अधिकार प्राप्त कर पाते। निःसंदेह, अकबर ने अपने राजवंश को स्थायित्व प्रदान किया और शासन के उन सिद्धान्तों का व्यवहारिक दृश्टि से प्रयोग किया। जिनके आधार पर मुगलवंष और इस्लाम के समर्थक शासकों को एक विदेशी देश अथवा अपने से पृथक धर्म के मतावलम्बियों पर शासन करने का नैतिक अधिकार प्राप्त हो सका।

अकबर ने अपने शासन काल में सभी धर्मो को समान स्थान प्रदान करके अपने अधीन राज्यतंत्र के स्वरूप को ही बदल दिया। अकबर की भसुलहकुल" (सभी के साथ शान्ति) की धार्मिक नीति ने राज्य और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया, धर्म को व्यक्तिगत बनाने का प्रयास किया, और इस प्रकार अपनी सभी प्रजा को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान मानने और समान सुविधायें देने का प्रयत्न किया।

मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति में अकबर की धार्मिक नीति श्रष्ठतम माना गया है। अकबर की नीति पूर्णतया धार्मिक सहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक नीति सभी के धर्मो को एक साथ लेकर चलने की थी दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों में इस नीति को आरम्भ करने वाला अकबर था। सभी धर्मो और अध्यात्मिक आन्दोलन के प्रति उदारता और सकिय सहानुभूति एवं सहायता का प्रयत्न प्रान्तीय राज्यों के द्वारा तो कभी–कभी किया भी गया था परन्तु दिल्ली और आगरा के बादशाहों ने यह प्रयत्न कभी नही किया गया था। अकबर प्रथम शासक था जिसने षासन के आरम्भ से ही धीरे–धीरे सभी धर्मो और आध्यात्मिक आन्दोलनों के प्रति प्रगतिशील उदारता और सकिय सहानुभूति की नीति को अपनाया।

जोरोस्ट्रीयन धर्म – अकबर ने जोरोस्ट्रीयन धर्म के समकालीन नेता मेहरजी से 1573 ई. में भेट की। वह उससे बड़ा प्रभावित हुआ धर्मनेता ने

इबादत खाने की बहस में भाग लिया और जो जोरोस्ट्रीयन धर्म के अच्छे सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया। अकबर जोरोस्ट्रीयन धर्म से बड़ा प्रभावित था। फलतः उसने पारसी पारसी धर्म के अनुकुल अपने महल में चौबीस घंटे आग जलाये रखने की अनुमति दी। अकबर सूर्य अग्निपूजा की ओर भक्षिाण रखने लगा। अकबर सूर्य की पूजा करने लगा।[1]

जैन धर्म – अकबर जैन धर्म से बड़ा प्रभावित हुआ उसने 1582 ई. में गुजरात के प्रसिद्ध जैन धर्मावलम्बी हीराविजय सूरि को आमन्त्रित किया[2] बाद में जिनचन्द्र सूरी, शान्तिचन्द्र, विजयसेन सूरी, आदि को अकबर ने दरबार में आमन्त्रित किया। अकबर जैन धर्म के हिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित किया 1581 ई में उसने भेड़ों और घोड़ों का वध निषिद कर दिया, उसन स्वयं वर्ष में ना माह मॉस खाना बन्द कर दिया उसने शिकार खेलना बन्द कर दिया और 1587 में उसने वर्ष में प्रायः छः माह पशुओं के बध किये जाने का निषेध कर दिया।[3] 1591 ई. में अकबर मैं जिनचन्द्र सूरि को निमन्त्रित किया वह उनके उपदेशों से बड़ा प्रभावित हुआ, जिनचन्द्र सूरि को युग प्रधान की उपाधि दी गई।[4]

हिन्दू धर्म – हिन्दु पुरूषोत्तम और देवी निरन्तर अकबर को हिन्दु धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया करते थे। उनके सम्पर्क में आकर में आने से अकबर हिन्दुओं के कर्म और जीवागमन के सिद्धांतो में विश्वास करने लगा[5] अकबर जानता था कि मुगल साम्राज्य की रक्षा हिन्दुओं के सहयोग और समर्थन पर ही आधारित हुआ। वह इसी प्रसंग में हिन्दु धर्म के निकट आया। वह हिन्दू धर्म के पर्व– त्योहारों जैसे, रक्षाबन्धन, दीपावली, होली, दशहरा में भाग लिया करता था। वह कभी–कभी माथे पर तिलक लगाया करता था। वह कभी–कभी' झरोखा दर्शन' भी दिया करता था। उसने अनुवाद विभाग से हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों जैसे ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, आदि का फारसी में अनुवाद कराया।[6]

ईसाई धर्म – अकबर सभी धर्मो के सार को जानना चाहता था, अतएव उसने ईसाई धर्म से भी कुछ सीखने का प्रयत्न किया। उसने गोआ से पूर्वगाली ईसाईयों को अपने दरबार में धार्मिक वाद–विवाद को लिए बुलाया। 1580 ई. में रिडोल्फी एक्वीना, एन्टीनिनो मान्सरेट तथा एरिन्ज की अध्यक्षता में तीन मिशन अकबर अन्य धर्मो की भॉति ईसाई धर्म से भी बड़ा प्रभावित हुआ। उसने ईसामसीह, मेरी तथा एण्टल की मुर्तियों को आदर भाव से देखा। वह चर्च भी जाने लगा अकबर ने आगरा और लाहौर में चर्च निर्माण की अनुमति भी दी।[7]

इस प्रकार अकबर का सम्बन्ध अच्छे रहे इन धर्मो से प्रभावित होकर अकबर ने जिस धर्म नीति का पालन किया सभी धर्मो की सामानता, सम्मान और सत्य के विश्वास पर आधारित इस प्रकार अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्म के प्रति सहानुभूति और वफदारी प्राप्त करके तथा उसके माध्यम से एक दृढ़ राज्य की स्थापना करने की इच्छा ने भी अकबर की उदार धार्मिक नीति के निर्माण में सहायता दी।[8]

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. राय, कौलेश्वर मुगलकालीन संस्कृति किताब महल इलाहाबाद 1991 पृष्ठ–125
2. वही पृष्ठ –125
3. शर्मा एल. पी मध्यकालीन भारत प्रकाशन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 1975 पृष्ठ–250
4. राय, कौलेश्वर मुगलकालीन संस्कृति किताब महल इलाहाबाद 1991 पृष्ठ–125
5. शर्मा एल. पी मध्यकालीन भारत प्रकाशन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 1975 पृष्ठ–250
6. राय, कौलेश्वर मुगलकालीन संस्कृति किताब महल इलाहाबाद 1991 पृष्ठ–126
7. वही पृष्ठ –126
8. शर्मा एल. पी मध्यकालीन भारत प्रकाशन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 1975 पृष्ठ–250

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

भारतीय परिपेक्ष्य में ग्राम्य जीवन का स्वरूप

डॉ. भगवत प्रसाद झारिया
अतिथि विद्वान हिन्दी, शास.स्नातक महाविद्यालय शहपुरा जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

सारांश :– भारत ग्रामों में निवास करता है, जहॉ एक ग्राम्य प्रधान भाषा, बोली, सस्कृति एवं कृषि की प्रधानता है। गांधीजी ने कहा था – "असली भारत गांवों में बसता है।" भारतीय ग्राम्य जीवन सादगी और प्राकृतिक शोभा का भंडार है। इस देश की भाषा का 70 प्रतिशत जनसमुदाय ग्रामों में रहता है। गांव के लोगों का मुख्य कार्य कृषि है, जो कि हमारे देश को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इस देश में कृषि कार्य मुख्यतः गांवों के लोगों द्वारा ही किया जाता है, जिस पर हमारे देश की दो तिहाई अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत में ग्रामों के विविध रूप है, जहॉ का जीवन सहजता व सरलता से परिचालित होता है। रीति–रिवाज व ग्राम्य परम्पराओं का विशेष महत्व है। ग्रामीण जीवन बड़ा ही मधुर व मनोहरकारी है।

इस महान भारत भूमि की वास्तविक छवि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में ही देखी जा सकती है। आज भारतीय ग्राम्य जीवन के विविध स्वरूपों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि गांवों का वास्तविक स्वरूप के अध्ययन से ही पता चलता है कि आज गांवों की स्थिति कैसी है ? इसके आधार पर ही सरकारे अपनी योजनाएँ तैयार करती हैं। सामाजिक सद्भाव यहॉ की महान संस्कृति श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों का सौंदर्य इसी ग्राम्य परिवेश में अभिरक्षित है।

सभ्यता के आदिकाल में न ग्राम में न शहर में अन्य पशुओं के समान मनुष्य भी जंगलों में रहता था और शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करता था। पशु–पक्षियों के मास के अतिरिक्त जंगलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द–मूल व अन्य सामग्री को वह भोजन के लिए प्रयोग करता था। प्राकृतिक प्रदत्ता वस्तुओं पर ही निर्भर रहता था। अन्य पशुओं की तुलना में मनुष्य का दिमाग अधिक विकसित था । वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करने को स्थिति में था, इसलिए शिकार करते हुए वह केवल अपने हाथों एवं पैरों पर ही निर्भर नहीं रहता था, अपितु अनेक प्रकार के औजार बनाकर उनका उपयोग करता था । शुरू में मनुष्य के औजार पत्थर हड्डी व लकड़ी के बने होते थे । धातुओं का प्रयोग वे नहीं जानते थे।

"जब मनुष्य अपनी आजीविका के लिए शिकार पर निर्भर था तो वह किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बस सकता था, तब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता था। जहॉ शिकार की सुविधा मिली वहीं अस्थायी रूप से डेरा डालकर इकट्ठा हो जाते थे।"[1]

मनुष्य गुफाओं में और वृक्षों के नीचे रहने की बजाय मनुष्य ने छोटे तम्बुओं का निर्माण शुरू कर दिया। धीरे–धीरे उसने पशुओं को पालना भी आरंभ कर दिया था। पहले वह जंगलों में उत्पन्न कंदमूल फल अन्न आदि को एकत्रित मात्र करता था। जब उसने उन्हे उत्पन्न करना शुरू कर दिया तब वह शिकारी के स्थान पर पशु पालक तथा कृषक बनने लगा। खेती के लिए यह आवश्यक था कि मनुष्य किसो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहे। इसके लिए मकानों का निर्माण करने लगा।

मकान घास, फूस, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि के बनाये गये और जगह–जगह उनकी बस्तियॉ डेरा व ग्रामों का विकास होने लगा। अभी मनुष्य को धातुओं का उपयोग ज्ञात नहीं था। अब भी उसके औजार लकड़ी, हड्डी इत्यादि के हाते थे पर कृषि के प्रारंभ होने के कारण वह एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा । धीरे–धीरे सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होता गया। साथ ही समूह गांवों के रूप में विकसित होते गये।"[2]

ग्रामों में मनुष्यों को धीरे–धीरे सभी आवश्यकताओं की चीजों का ज्ञान होता गया और वे उनका उपयोग करते गये । एक दूसरे के सहयोगी बनकर बस्ती बसा दिये और एक गांव का निर्माण कर उस गांव का नाम रख दिया गया।

शोध विधितंत्र – इस अध्ययन में वर्णनात्मक विधि को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत भारत के विविध गांवों के विकास का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके साथ–साथ विभिन्न उपयोगी आंकड़ों का सहारा लिया गया है जो कि विभिन्न संदर्भ पुस्तकों, रिसर्च जनरलों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए है।

ग्राम का शाब्दिक अर्थ – जिस प्रकार नगर की अपनी प्रकृति व विशेषताएं होती है उसी प्रकार गांव की भी अपनी प्रकृति होती है। ग्रामीण समुदाय का अपना विशिष्ट एवं पृथक अर्थ है। नगर को हम बड़े रूप में देखते है, लेकिन गांव की सीमा थोड़ी होती है। जनसंख्या शहर की अपेक्षा गांव में कम होती है।

गांव का शाब्दिक अर्थ साहित्यिक भाषा में यह है कि ''गांव वह बसाहट है जहॉ कुछ परिवार अपने स्थायी घर बनाकर निवास करते हो।'' गांव की कल्पना करते है तो हमारी आंखों के सामने विचित्र दृश्य उपस्थित हो जाते है। प्रकृति की हरी–भरी गोद के मध्य कस्वे खपरेल घर गाय, बैलों के चरते झुण्ड, छोटी–छोटी गलियां, गलियों के दोनों ओर घर पूरे गांव की घूमी हुई गली और दोनों तरफ घर देखने को मिलता है। स्मिथ के अनुसार–'' गांव का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्तियों के लिए आता है ।'' लेण्डिस ने ग्रामीण शब्द की विवेचना के लिए तीन तत्वों को महत्व दिया है जो–

क– प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर ।
ख– जिसका आधार सीमित हो ।
ग– जिसमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाये जाते है।

ग्राम्य सामाजिक जीवन – ग्रामीण सामाजिक जीवन निःसंदेह सादगी से पूर्ण जीवन है। समाज के नियमों का पालन ग्राम समाज में सभी करते हैं। शिक्षा की बात की जाय तो गांवों में आज पाठशालाएं खुल गई है, किन्तु साक्षरता का प्रतिशत कम ही है। समाज में नारी शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। गांव के परिवारों में संयुक्त प्रथा बनी हुई है जिसमें एक परिवार में 6–8 तक सदस्य होते हैं।

दहेज ग्रामीण जीवन का प्रमुख अंग है। वे अपनी बेटी को किसी के भी हाथ गरीबी के अभाव में शोषण करने के लिए बेच देते है। गांवों में गरीबी के कारण किसी वृद्ध के साथ कम उम्र वाली लड़की का विवाह कर देते है। अपने ही जाति में वैवाहिक कार्य होते हैं। यदि दूसरी जाति में वह विवाह करता है तो बिरादरी उसे बहिष्कृत कर देती है। हॉ जाति बिरादरी को कुछ खान पिलाने से बात बन जाती है।

ग्रामों का स्वरूप – ग्रामीण जीवन ''ग्राम'' इकाई में रहने वालों के मध्य आपसी स्नेह व्यवहार की संज्ञा है। ''ग्राम'' एक विशिष्टता का परिचायक है। ''ग्राम'' एक भौगोलिक इकाइ के रूप में नगरों से भिन्न है। किसी विशेष ''अंचल'' का योगदान रहता है।

पंत जी के शब्दों में–

''भारत माता ग्रामवासिनी
खेतों में फैला है श्यामल
धूल भरा मैला सा आंचल।''[3]

ग्रामीण जीवन की विशेषताएँ – भारतीय ग्रामों के स्वरूप को समझने के लिए गांवों की प्रमुख विशेषताओं को जानना आवश्यक है जो कि इस प्रकार है –

1. जीवन सरल एवं शुद्ध–भारतीय ग्रामीण जीवन एकदम सरल एवं शुद्ध रहता है । यहॉ की हवा, वातावरण शहरी जीवन की अपेक्षा प्रदूषण मुक्त होता है । यहॉ की ठण्डी और शीतल हवा ग्रामीण लोगों को प्राण वायु के समान है । यहॉ के लोगों रहन–सहन, खान–पान सरल एवं इको फ्रेण्डली होता है । ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उत्पादन होता है वह भी एकदम शुद्ध होता है जैसे–दूध, खोया, सब्जी इत्यादि।
2. ग्रामीण जीवन में आपसी संबंध–गांव के लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों के मध्य गहन रिश्ता, मित्रता, भाई–चारा एवं व्यवहार रहता है। इनके संबंध काफी मजबूत और विश्वास योग्य होते हैं। आपसी भाई–चारे के कारण गांव के लोग अपने सुख–दुःख एक–दूसरे को बांटते रहते हैं। शादी–विवाह आदि के कार्यक्रम में गांव

के लोग एक–दूसरे के सहयोगी बनकर काम करते हैं ।

3. संयुक्त परिवारों की बहुलता एवं परस्पर संबंध– ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवारों की अधिकता देखने को मिलती है। एक परिवार में 6–8 व्यक्ति तक पाये जाते हैं।यहां के लोगों का मानना है कि परिवार में अधिक लोग होगे तो मजदूरी एवं अन्य कार्य करने पर आय अधिक प्राप्त होगी। इनके परिवार में माता–पिता, भाई–बहन, बच्चे, दादा–दाई आदि होते हैं, और वे अपनी मर्यादा में रहकर जीवन–यापन करते हैं –

''पति की पैछर सुनकर धनियॉं, चुपके सॉंकल खोलती,
खड़ी कटोरा लिए दूध का , आखिर एक न बोलती ।।
सास–ननद देवर के डर से, चूड़ी खनकाती नहीं।
पति के पास खड़ी है गुमसुम, बहुत पास आती नहीं ।।''[4]

उपरोक्त पंक्तियों में ग्राम के परिवारों की मर्यादा एवं उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया गया है जो केवल भारतीय गांवों में ही दिखाई देता है।

4. जीवन–स्तर का निम्न होना–ग्रामीण लोगों की आय सीमित होती है । वर्ष में एक या दो बार अपने खेत की फसल उत्पन्न होती है जिसे बेचकर आय प्राप्त होती है । इस प्रकार छः–छः माह में आय प्राप्त होने के कारण इनका खर्च सीमित या कम होता है। ये इस राशि को छः माह तक चलाने का प्रयास करते हैं। जब यह राशि समाप्त हो जाती है तो ये लोग मजदूरी कार्य करते हैं। या फिर वनों पर आधारित वस्तुओं का संग्रहण कर आय प्राप्त करते हैं । जैसे–तेंदूपत्ता, माहुल पत्ता, महुआ फूल तथा महुआ गुली, गोंद, लकड़ी काटना, कत्था आदि।
5. धर्मों का अभाव– भारतीय गांवा में अधिकांशतः एक या दो धर्म के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार यहॉं धर्मो का अभाव सा होता है ।
6. अंधविश्वास का होना– अंध विश्वास भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है। जो क्षेत्र जितने पिछड़े हुए है एवं शिक्षा का अभाव है वहॉं अधिकांशतः अंधविश्वास लोगों के अंदर कूट–कूट कर भर जाता है। लोग जादू–टोना, भूत–प्रेत तथा झाड़–फूंक में अधिक विश्वास करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सर्वप्रथम उसे झाड़–फूंक कर उसका इलाज किया जाता है । जब उसको आराम नहीं मिलता तब लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं ।

ग्राम का वास्तविक स्वरूप :– ग्राम का वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन पंक्तियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाय तो गांव के सम्पूर्ण परिवेश की झलक सामने नजर आयेगी :–

''मक्का के पीले आटे–सी, धूप ढल रही सांझ की।
देवालय में शंख बज उठा, घंट–नांद ध्वनि झांझ की ।।
गाय रंभाती आती ग्वाला, सेंद चुरा कर खा रहा ।
पथवारी पर बैठा जोगी, गीत ज्ञान के गा रहा।।
कहीं अकेले, कहीं दुकेले, सारस पोखर में खड़े ।
पोखर के उस पार गांव में, घर–घर दीये हंस पड़े ।।
सर पर धरे घड़ा करी का, घर आ रहा किसान है।
बांये एक उदम्बर दाये, देवी मॉं का थान है।।
दोनों ओर अषाढ़ी धरती, बाट देखती बीज की।
आई याद बहु की जो पीहर गयी हुई है तीज की ।।
दिखे ज्वार के भुट्टे, दिखती, बाल बाजरे की भरी ।
दिखी छरहरो अरहर, रहती जो सौ दिन तक हरी।।
बन के खेत बाद है सन की, फेली–फूली तोरई ।
बेल या कि सूए में कोई सुतली हरी पिरो गई।।
छूटने को तैयार हार में, खेती मक्का की खड़ी ।
हरी–भरी सुंदरी इकहरी, काया मोती की लड़ी।।''[5]

गांवों में जातीय, भाषीय, व्यवसायिक, धार्मिक तथा सामाजिक सजातीयता का प्रभाव

होता है। भारतीय समाज में एवं ग्रामीण जीवन में सारे गांव की वह एक भाषा, एक ही वंश की सामाजिक विरासत गांव में एक जाति बिरादरी क लोग साथ–साथ निवास करते हैं।''4 सभी लोगों का आपस में एक दूसरे का सहयोग और बहुत घनिष्ट संबंध होते हैं । ये संबंध हमेशा गांव में पाया जाता है । सारा गांव हमेशा अपना एक परिवार हो जाता है । विचारों, रीति–रिवाजों, विश्वासों तथा आचरणों का एक दूसरे का परस्पर ध्यान रखते है । धर्म और जाति बिरादरी के भेदों के साथ भी गांवों के सामाजिक जीवन में भिन्नता नहीं आने पाती है।

निष्कर्ष – भारतीय गांव अपने इतिहास के प्रदीर्घ यात्रा में अनेक दौरों से गुजरता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है । आदिम संगठन की अवस्था सामान्तवादी युग का स्वरूप भौगोलिक परिवर्तन की प्रकिया और राजनैतिक परिवर्तनों का इतिहास में सब भारतीय गांव के स्वरूप में परिवर्तन तो करते है, किन्तु बाह्य सतह को ही इतिहास की कई विराट लहरों में जैसे गांव को हुआ ही नहीं है ।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ. अरूण मिश्र ''प्रेमचंद और उनके परवर्ती ग्राम जीवन''उपन्यास का तुलनात्मक अध्ययन ।
2. डॉ. ललित प्रसाद '' भारतीय नगर संस्कृति के दो रूप ग्राम और नगर''
3. सुमित्रानंदन पंत ''ग्राम्या''
4. प्रेमचंद –''गोदान''
5. पं. नरेन्द्र शर्मा ''बहुत रात गये'' कविता संग्रह से ग्राम चित्र

केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रम कल्याण रेलवे में कार्यशील महिलाओं हेतु

श्रीमति सुनीता कुमारी
अर्थशास्त्र शोधछात्रा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

प्रस्तावना :– भारत में सर्वप्रथम श्रमकल्याण कार्यो का प्रारम्भ प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ, परंतु केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही आकृष्ट हुआ सन् 1922 में एक अखिल भारतीय श्रम कल्याण सम्मेलन 'मुम्बई में हुआ जिसमें श्रमिकों के कल्याण योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। श्रमिकों के कल्याण के लिए उस समय 'श्रम हितकारी परामर्शदात्री परिषदों की नियुक्ति की। तत्पश्चात् सन् 1942 में केन्द्रीय सरकार ने श्रम हितकारी सलाहकार (Labour Welfare Advisor) की नियुक्ति कीं इसकी सहायता के लिए अनेक श्रम कल्याण अधिकारियों ;स्ंइवनत ॅमसंितम वंिपबमतेद्ध की भी नियुक्ति की गई।

श्रम संघों द्वारा श्रम कल्याण :– इस संघ ने चिकित्सा, शिक्षा, वाचनालय तथा मनोरंजन आदि सुविधाओं की व्यवस्था की है। मिल मजदूर संघ तथा इन्दौर मे भी श्रमिकों के लिये महिला मंदिर की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त रेलवे मेन्स यूनियन ने भी कर्मचारियों के कल्याण के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये है।

समाज सेवी संस्थाओ द्वारा श्रम कल्याण :– श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिनमें बम्बई प्रेसीडेन्सी महिला समिति – बम्बइ समाज सेवा लीग आदि संस्थाऐ प्रमुख है सेवा समितियाँ मुम्बई तथा पूना में स्त्रियों तथा बच्चों के लिये शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था करते है। श्रमिकों को शिक्षित करने के लिये रात्रि शालाएं कहलाती है। साथ ही मनोरंजन सहकारी समितियाँ, पुस्कालय तथा खेलों आदि की भी व्यवस्था करते है।

नगर निगम एवं नगर पालिकाओं द्वारा श्रम कल्याण – इन संस्थाओं द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये है। नगर निगम ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अलग मे श्रम कल्याण विभाग की स्थापना कर दी है। इसके अतिरिक्त प्रायः समस्त नगरपालिकाओं एवं निगमों ने श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रॉविडेन्ट फंड योजना भी लागू की है।

अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन – अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्य वर्गीकरण इस प्रकार है–

श्रमिको की वैज्ञानिक भर्ती – श्रमिको की भर्ती वैज्ञानिक आधार पर होना नितान्त आवश्यक है। वैज्ञानिक आधार पर नियुक्ति होने से श्रमिका अधिकतम कल्याण होता है। क्योंकि उससे उनकी नियुक्ति स्थायी तौर पर हो जाती है। श्रमिक अपनी पूर्ण कार्यक्षमताओं कार्य करे, उसके लिये आवश्यक है, श्रमिकों की भर्ती स्थायी रूप से वैज्ञानिक आधार पर की जाये। वैज्ञानिक आधार पर भर्ती होने से केवल योग्य व कुशल श्रमिकों की ही नियुक्ति होगी जिससे उद्योग लाभान्वित होगा।

औद्योगिक प्रशिक्षक :– श्रमिको की वैज्ञानिक आधार पर भर्ती होने के उपरान्त उन्हें कार्य करने का उपयुक्त प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। आधुनिक युग में बड़े पैमान पर उत्पादन होने के कारण बड़ी – बड़ी एवं जटिल मशीनों एवं उपकरणों का सहारा लिया जाता है। उन मशीनों एवं उपकरणों को प्रयोग मे लाने हेतु प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक होता है। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी जिससे न केवल श्रमिक वर्ग बल्कि नियोक्ता वर्ग भी लाभान्वित होगा।

स्वच्छता, प्रकाश एवं वायु की समुचित व्यवस्था : – श्रमिक जहॉ कार्य करते हैं। वहां का वातावरण स्वास्थ्यप्रद होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः कारखाने में स्वच्छता, उचित प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। कारखानो में समय–समय पर सफाई एवं पुताई होनी चाहिएं प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिएं सांस लेने के लिए श्शुद्ध वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही

उचित तापक्रम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कारखाने में स्वच्छ पेय जल स्नानगृह, शौचालय आदि का भी प्रबंध होना आवश्यक है।

दुर्घटनाओं से रक्षा :– कारखाने के अन्दर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए – उदाहरणार्थ – मशीनों के आस– पास आड (Fencing) लगाना, आग बुझाने के यंत्रो की व्यवस्था आदि। खतरनाक कार्यो हेतु श्रमिकों के लिये सुरक्षात्मक पोशाकों की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, कारखाने में एक डॉक्टर होने पर वही प्राथमिक उपचार किया जा सके।

उत्तम आवास व्यवस्था :– मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं में एक आवास भी है। श्रमिकों की कार्यक्षमता काफी सीमा तक आवास व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसके अभाव में श्रमिको का नैतिक, सामाजिक एवं श्शारीरिक पतन हो जाता है। जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। श्रमिक काम की तलाश में बड़े औद्योगिक नगरों में आ जाते है तथा यही बस जाते है, श्रमिको कों सस्ते किराये की दरों पर मकान उपलब्ध नही हो पाते। अतः केन्द्रीय श्रमिकों के लिए उत्तम आवास की व्यवस्था होनी चाहिए।

उचित चिकित्सा व्यवस्था – श्रमिकों की कार्यक्षमता उसके स्वास्थय पर निर्भर रहती हैं हमारे देश के श्रमिक निर्धन होने के कारण अपना इलाज कराने मे असमर्थ रहते हैं। अतः श्रमिकों के लिये चिकित्सा की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व नियोक्ताओं को अपने ऊपर लेना चाहिए। श्रमिकों के पूर्णस्वस्थ रहने से वे अपनी पूर्ण कार्यक्षमता से कार्य कर सकेंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी व उद्योगपति को अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा। अतः श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था :– श्रमिक दिनभर कारखाने में कार्य करने के उपरांत घर लौटता है तो काफी थकावट अनुभव करता है। इस थकावट को मनोरंजन के साधनों के द्वारा दूर किया जा सकता है जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता पुनः ज्यो की त्यों हो जाती है। अतः श्रमिकों के लिये स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यस्था करनी चाहिए जिससे थकान तो दूर हो ही, साथ ही उनका शारीरिक एवं मानसिक व बौद्धिक विकास भी हो। श्रमिकों के मनोरंजन के लिये सिनेमा नाटक, खेलकूद, पुस्तकालय, संगीत, व्यायाम, वाचनालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

सस्ते एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था :– श्रमिकों की कार्यक्षमता म वृद्धि के लिये इन्हें पौष्टिक भोजन, प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक हैं इसके अभाव में श्रमिकों का स्वास्थ प्रभावित होगा, उनकी कार्यक्षमता कम हो जायेगीं अतः कारखानो में जलपान गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही श्रमिकों के लिये सहकारी भंडारों की स्थापना की जानी चाहिएं जहां पर उन्हें सस्ती दर पर खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुए उपलब्ध करना चाहिए।

शिक्षा का प्रबन्ध :– अनेक श्रम समस्याओं का जन्म श्रमिकों की अज्ञानता के कारण होता हैं नियोक्ता व श्रम संघ उनका शोषण करते है। उत्पादन एवं किस्म में वृद्धि के लिए भी श्रमिको को शिक्षित किया जान अत्यन्त आवश्यक है। श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु रात्रि पाठशालाएं तथा प्रौढ़ व बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो । शिक्षा की सुविधा मुफ्त में दी जानी चाहिए।

प्रॉविडेण्ट फण्ड आदि को व्यवस्था :– श्रमिक वर्ग निर्धन रहता है आय कम होने के कारण उसके बचत के रूप मे धन नही रहता । अतः श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा के लिये प्रॉविडेण्ट फण्ड योजना लागू की जानी चाहिए। उससे श्रमिक अपने भविष्य के बारे मे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहेगा व कार्य मन लगा कर करेगा।

अन्य कार्य :– कारखाने के अन्दर श्रमिकों के लिये आराम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार कार्य करते रहने के कारण श्रमिक थकावट होने पर आराम कर सके। थकावट दूर होने पर उसी कार्य, क्षमता से करने लगता हैं अतः कारखाने मे महिला श्रमिक हेतु शिशु गृह, जलपान गृह आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपरोक्त क्षेत्र विभाजन के अतिरिक्त दूसरे प्रकार से भी श्रम कल्याण क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है –

A- कारखाने के भीतर किये जाने वाले श्रम कल्याण कार्य। (Intra mural activities)

B- कारखाने के बाहर किये जाने वाले कार्य (Extra- Mural- Activities)

कारखाने के भीतर कल्याण कार्य – कारखाने के अन्दर किये जाने वाले प्रमुख कल्याण कार्य निम्नलिखित हैं –

A. कारखाने के भीतर के कल्याण कार्य :–

1. प्रसाधन
2. शिशुगृह पालन घर
3. विश्राम स्थल और केन्टीन।
4. पेयजल का प्रबन्ध।
5. थकावट को रोकने के उपाय।
6. स्वास्थ्य सेवाएं व व्यवसायिक सुरक्षा।
7. कल्याण कार्यो की देखभाल के लिए संयंत्र में उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था।
8. वर्दी और सुरक्षा प्रदान करने वाले वस्त्र।
9. पारी भत्ता।
10. दुर्घटना से रक्षा।

B. कारखाने के बाहर कल्याण कार्य : –

1. प्रसूति हित लाभ।
2. सामाजिक सुरक्षा के उपकरण जिनमें उपदान पेंशन, भविष्य निधि और पुर्नवास आदि।
3. अनुग्रह निधियां।
4. उचित चिकित्सा सुविधाएं जिनमें शारीरिक आरोग्यता और कुशलता बनाए रखने वाले कार्यक्रम, परिवार नियोजन और बाल कल्याण आदि।
5. शिक्षा सुविधाएं जिनमें प्रौढ़ शिक्षा शामिल है।
6. उत्तम आवास व्यवस्था।
7. स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं जिनमे खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय, वाचनालय, आदि।
8. सस्ते अवकाश ग्रह और छुटटी यात्रा की सुविधाएं।
9. श्रमिकों की सहकारी समितियां जिनमे सहकारी उपभोक्ता भंडार, उचित दाम दुकान और सहकारी बचत उधार समितियाँ शामिल है।
10. श्रमिकों के आश्रितों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण।
11. स्त्रियों, युवकों और बच्चों के लिए अन्य कार्यक्रम तथा
12. कार्य के स्थान तक जाने और वहां से लौटने के लिए परिवहन।

श्रम कल्याण का उद्भव और विकास :– प्रारंभ मे मानवीय क्रियायें मानवहित के अनुसार रही। श्रम उत्पादन का प्रमुख साधन होते हुए भी सबसे अपेक्षित साधन माना जाता था। एक संपन्न वर्ग ने स्वतंत्र सौदागिरी के आधार पर एक कमजोर वर्ग, श्रम की कमजोरियां का लाभ उठाकर उसका शोषण किया। श्रमिकों को मशीन मानकर उनसे जितना हो सका कार्य लिया गया। निम्नतर जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये निम्नत्तम मजदूरी दी जाती थी, तथा किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं दी जाती थी । उद्योगपतियों का लाभ प्रधान था, श्रम का कोई स्थान नही था।

वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था तक पहुंचते–पहुंचते प्रबंध का विस्तार हो जाने के कारण उद्यागपति और श्रम का व्यक्तिगत संबध भी समाप्त हो गया। अव सारा कार्य प्रबंधक करता है, जो कि स्वयं भी श्रमिक है। आज उद्योगपति को यह मालूम ही नहीं होता कि उसके श्रमिकों की क्या समस्याएं है, उन्हे कैसे सुलझाया जाये तथा उन्हे कौन सी सुविधाए दी जाएं। इस परिवर्तन के कारण ही औद्योगिक बुराइयों का जन्म हुआ लेकिन एक निश्चित शोषण सीमा के पश्चात् – मानव कल्याण – हित सोचने को बाध्य हुआ, वह वास्तविकता से इन्कार न कर सका। ''भारत की महिला श्रमिक'' नामक पुस्तक में डा. पदमिनी सेन गुप्ता ने उसी तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया है। कारखाना पद्धति में बाध्य शक्ति का प्रवेश होने के पश्चात् ही उद्योगचक्र के संचालक श्रमिक को पूर्ण तथा भुला दिया गया लेकिनश्शीघ्र ही यह महसूस किया जाने लगा कि श्रमिकों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति

करने की सुविधाएं प्रदान कर उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तथा मशीनों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये भी श्रम कल्याण अपेक्षित है।[1] प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों की सरकारों तथा विनियोजकों ने विचार किया कि जीवन – मापन की दशाओं और औद्योगिक वातावरण में इतना परिवर्तन हो गया है कि औद्योगिक षांति, अधिक उत्पादन और द्रुत गति से विकास के लिये श्रमिकों के कार्य की दशाओं रहन – सहन के स्तर, वातावरण तथा कार्यक्षमता में वृद्धि व सुधार आवश्यक हो गया है युद्ध के बाद 'श्रम कल्याण' के विकास के मुख्य रूप से पांच कारण रहे हैं –

1. इसकी आवश्यकता युद्ध के समय अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये महसूस की गई। यह विचार किया गया कि यदि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो जायेगा। इनकी प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति हो जायेगी, तो निश्चय ही उनका ध्यान इन समस्याओं की ओर से हट कर उद्योगों के अधिक उत्पादन की ओर बढ़ेगा।
2. 'अधिक उत्पादन' और 'अधिक विक्रय' की नीति को सक्षम बनाने के लिये ''श्रम'' जो कि उत्पादन की एक मुख्यश्शक्ति है, उसको कल्याण कारी सुविधायें प्रदान करना आवश्यक समझा गया।
3. अर्थव्यवस्था में होने वाले नवीन अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबन्ध ने भी श्रमिकों के कल्याण कार्य के प्रति उन्मुख होने का प्रोत्साहन दिया।
4. सरकार के अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने के कारण कल्याणकारी राज्य की राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग बन गया। सरकार के प्रवेश के साथ ही वैज्ञानिक क्षेत्र में फैली हुई बुराइया भी समाप्त होने लगी, तथा श्रम कल्याण के प्रति व्यक्तिगत साहसी भी प्रयत्न शील बनने लगे।
5. साम्यवाद के उद्भव और प्रसार का भी श्रम कल्याण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा, पूंजीवादी देशो में श्रमिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का एक प्रमुख कारण साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव की आशंका भी है।

References :-

1. "Reports of the Royal Commission on Labour" Central Publications ,Calcutta,1931, p.p.10-12.
2. Hughes,A."reports on the Cost of Living of labourers in the Jharia coal fields".manager of Publications, Delhi ,1940.
3. Approaches of Social Security,ILO, Geneva , 1942.
4. Asian Conference , ILO, Reports- 2, p.3.
5. "Reports of the Labour Investigation Committee". Manager of Publications ,New Delhi ,1946. P.345.
6. National Commission on Labour Reports, "Reports of Study Group for Coal",Delhi Manager of Publications, 1968 , p.p.73-74 .
7. Reports of the Committee on Labour Welfare, 1969.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Current Effect of Saving in society

Neeraj Kaliya
Research Scholar, Dept. Rular Development, RDVV, Jabalpur

Saving is income not spent, or deferred consumption. Methods of saving include putting money aside in, for example, a deposit account, a pension account, an investment fund, or as cash. Saving also involves reducing expenditures, such as recurring costs. In terms of personal finance, saving generally specifies low-risk preservation of money, as in a deposit account, versus investment, wherein risk is a lot higher; in economics more broadly, it refers to any income not used for immediate consumption.

Saving differs from savings. The former refers to the act of increasing one's assets, whereas the latter refers to one part of one's assets, usually deposits in savings accounts, or to all of one's assets. Saving refers to an activity occurring over time, a flow variable, whereas savings refers to something that exists at any one time, a stock variable. This distinction is often misunderstood, and even professional economists and investment professionals will often refer to "saving" as "savings" (for example, Investopedia confuses the two terms in its page on the "savings rate").

In different contexts there can be subtle differences in what counts as saving. For example, the part of a person's income that is spent on mortgage loan repayments is not spent on present consumption and is therefore saving by the above definition, even though people do not always think of repaying a loan as saving. However, in the U.S. measurement of the numbers behind its gross national product (i.e., the National Income and Product Accounts), personal interest payments are not treated as "saving" unless the institutions and people who receive them save them.

Saving is closely related to physical investment, in that the former provides a source of funds for the latter. By not using income to buy consumer goods and services, it is possible for resources to instead be invested by being used to produce fixed capital, such as factories and machinery. Saving can therefore be vital to increase the amount of fixed capital available, which contributes to economic growth.

However, increased saving does not always correspond to increased investment. If savings are not deposited into a financial intermediary such as a bank, there is no chance for those savings to be recycled as investment by business. This means that saving may increase without increasing investment, possibly causing a short-fall of demand (a pile-up of inventories, a cut-back of production, employment, and income, and thus a recession) rather than to economic growth. In the short term, if saving falls below investment, it can lead to a growth of aggregate demand and an economic boom. In the long term if saving falls below investment it eventually reduces investment and detracts from future growth. Future growth is made possible by foregoing present consumption to increase investment. However savings not deposited into a financial intermediary amount to an (interest-free) loan to the government or central bank, who can recycle this loan.

In a primitive agricultural economy savings might take the form of holding back the best of the corn harvest as seed corn for the next planting season. If the whole crop were consumed the economy would convert to hunting and gathering the next season.

Policy makers and researchers have long been interested in how potential changes to the personal income tax system affect the size of the overall economy. In 2014, for example,

Representative Dave Camp (R-MI) proposed a sweeping reform to the income tax system that would reduce rates, greatly pare back subsidies in the tax code, and maintain revenue levels and the distribution of tax burdens across income classes (Committee on Ways and Means 2014).

In this paper, we focus on how tax changes affect economic growth. We focus on two types of tax changes – reductions in individual income tax rates and "income tax reform." We define the latter as changes that broaden the income tax base and reduce statutory income tax rates, but nonetheless maintain the overall revenue levels and the distribution of tax burdens implied by the current income system. Our focus is on individual income tax reform, leaving consideration of reforms to the corporate income tax (for which, see Toder and Viard 2014) and reforms that focus on consumption taxes for other analyses.

By "economic growth," we mean expansion of the supply side of the economy and of potential Gross Domestic Product (GDP). This expansion could be an increase in the annual growth rate, a one-time increase in the size of the economy that does not affect the future growth rate but puts the economy on a higher growth path, or both. Our focus on the supply side of the economy in the long run is in contrast to the short-term phenomenon, also called "economic growth," by which a boost in aggregate demand, in a slack economy, can raise GDP and help align actual GDP with potential GDP.

The importance of the topics addressed here derive from the income tax's central role in revenue generation, its impact on the distribution of after-tax income, and its effects on a wide variety of economic activities. The importance is only heightened by concerns about the long-term economic growth rate (Gordon 2016; Summers 2014) and concerns about the long-term fiscal status of the federal government (Auerbach and Gale 2016).

We find that, while there is no doubt that tax policy can influence economic choices, it is by no means obvious, on an ex ante basis, that tax rate cuts will ultimately lead to a larger economy in the long run. While rate cuts would raise the after-tax return to working, saving, and investing, they would also raise the after-tax income people receive from their current level of activities, which lessens their need to work, save, and invest. The first effect normally raises economic activity (through so-called substitution effects), while the second effect normally reduces it (through so-called income effects).

The financing of tax cuts significantly affects its impact on long-term growth. Tax cuts financed by immediate cuts in unproductive government spending could raise output, but tax cuts financed by reductions in government investment could reduce output. If they are not financed by spending cuts, tax cuts will lead to an increase in federal borrowing, which in turn, will reduce long-term growth. The historical evidence and simulation analyses suggest that tax cuts that are financed by debt for an extended period of time will have little positive impact on long-term growth and could reduce growth.

Tax reform is more complex, as it involves tax rate cuts as well as base-broadening changes. There is a theoretical presumption that such changes should raise the overall size of the economy in the long-term, though the effect and magnitude of the impact are subject to considerable uncertainty. One fact that often escapes unnoticed is that broadening the tax base by reducing or eliminating tax expenditures raises the effective tax rate that people and firms face and hence will operate, in that regard, in a direction opposite to rate cuts and mitigate their effects on economic growth. But base-broadening has the additional benefit of reallocating resources from sectors that are currently tax-preferred to sectors that have the highest economic (pre-tax) return, which should increase the overall size of the economy.

A fair assessment would conclude that well-designed tax policies have the potential to raise economic growth, but there are many stumbling blocks along the way and certainly no guarantee that all tax changes will improve economic performance. Given the various channels through which tax policy affects growth, a tax change will be more growth-inducing to the extent that it involves (i) large positive incentive (substitution) effects that encourage work, saving, and investment; (ii) small or negative income effects, including a careful targeting of tax cuts toward new economic activity, rather than providing windfall gains for previous activities; (iii) reductions in distortions across economic sectors and across different types of income and consumption; and (iv) minimal increases in, or reductions in, the budget deficit.

References :-

1. Dell'Amore, Giordano (1983). "Household Propensity to Save", in Arnaldo Mauri (ed.), Mobilization of Household Savings, a Tool for Development, Finafrica, Milan.
2. Modigliani, Franco (1988). "The Role of Intergenerational Transfers and the Life-cycle Saving in the Accumulation of Wealth", Journal of Economic Perspectives, n. 2, 1988.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

मध्यप्रदेश में गन्ने पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएँ

नरसिंहपुर जिले के विशेष संदर्भ में

Abhay Ghodke, SSNMIMT College Narsinghpur

हम गौरवान्वित है कि हम हिन्दुस्तान के हृदय स्थल मध्यपद्रेश के ऑचल में उसकी अनुपम प्राकृतिक छटा के सानिध्य में निवास करतें है। यहाँ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर अपने आप में विशिष्ट है। विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रंखलाऐं ताप्ती, नर्मदा, चम्बल, सोन, बेतवा, महानदी की उद्‌गम स्थली, महर्षियों की तपोभूमि है, मध्यप्रदेश की धरा को उपजाऊ बना, जीवन देने वाली ये पवित्र नदियाँ मध्यप्रदेश की सीमा से लगे प्रदेशों को आपस में जोड़ती है।

मध्यप्रदेश की स्थापना 1 नबम्बर 1965 को हुई, भोगोलिक स्तर पर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कहलाने वाला राज्य अपनी 44 वर्षगांठ पर बँट गया। 1 नबम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही मध्यप्रदेश दूसरी पायदान पर आ गया।

मध्यप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की 73.54 आवादी गाँवों में बसती है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि अथवा कृषि कार्य पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें गेंहू, सोयाबीन, गन्ना, चना व सरसों, दाल आदि है। गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है।

मध्यप्रदेश का गन्ना उत्पादन में 11वा स्थान है। राज्य में 201–15 में 59,900 तथा 2015–16 में गन्ने का उत्पादन 65,180 टन हुआ था।

मध्यप्रदेश के मध्यभाग में नरसिंहपुर जिला स्थित है। जिला और मुख्यालय दोनो का नाम नरसिंहपुर है । जो जाट जाति के सरदारों द्वारा निर्मित विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह के मंदिर के कारण पड़ा । मध्यप्रदेश में गन्ने को खेती जिले में सर्वाधिक होती है । यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कलमेटाहार के लिए एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

नरसिंहपुर जिले में 5 तहसीलों में वर्तमान में 4493 कुल्होरों में 4500 क्रेशर चल रहे है। जिनमें गुड़ एवं शक्कर बनाने का कार्य होता है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में शक्कर मिलों की संख्या 16 है। जिसमें से 7 शक्कर मिल नरसिंहपुर में पाई जाती है। जिनके द्वारा गन्ने पिराई की क्षमता 19,900 टी.सी.डी. है। मध्यप्रदेश में शक्कर का उत्पादन निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश में शक्कर का उत्पादन प्रतिवर्षानुसार विवरण
वर्ष 2012–13 से 2015–16 में

वर्ष	क्षेत्र हैक्टेयर सी.एल.आर.	फैक्ट्री का आरक्षित क्षेत्र (हैक्टेयर)	पेरा गया गन्ना लाख टन	निर्मित शक्कर क्विंटल में	रिकवरी	उचित कीमत दर
2012.13	64900	62256.00	21.300	2084565	9.60	170
2013.14	104400	72379.00	34.987	3443242	9.48	210
2014.15	110000	97163.86	42.699	4150837	9.63	220
2015.16	110000	103763.128	41.250	4040000	9.80	230

289300 335561.983 140.236 13718644 38.51

स्रोत :– उपसंचालक कृषि विभाग की सर्वेक्षण रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका के अनुसार मध्यप्रदेश में शक्कर मिल के द्वारा शक्कर उत्पादन वर्ष 2012–13 में 2084556 क्विंटल का निर्माण किया गया था। वर्ष 2015–16 में शक्कर का उत्पादन 4040000 क्विंटल उत्पादन हुआ है।

गन्ने का मुख्य उत्पाद शक्कर व गुड़ है, तथा गन्ना पेरने के उपरांत शेष बचे पदार्थ जैसे बगास, प्रेसमेड, खोई, अगोला आदि यह सभी गन्ने के सहउत्पादक है।

गन्ने की खोई का उपयोग मुख्य रूप से भाव जुटाने के लिए बॉयलर में ईधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देश में पाँच प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की चीनी मिलें राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में 2000 मेगावाट का योगदान कर रही है। जिसके लिए गन्ने की खोई का उपयोग किया जा रहा है। सेंटर फार साइंस एण्ड एन्वार्नमेंट के अनुसार 2000 मेगावाट बिजली हरियाणा में गुड़गाँव जैसे व्यापारिक केन्द्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। ये बिजली उ.प्र., आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू चीनी मिलों की खोई (बायोमास) से पैदा की जा रही है। भारत में चीनी मिलें पवन चक्की जैसी हरी ऊर्जा पैदा करती है। और वह भी उसकी आधी कीमत पर । चीनी मिलें राष्ट्रीय पावर ग्रिड को बिजली बेचकर लाभ भी कमा रही है।

भारत में चीनी मिलों की खोई से ऊर्जा निर्माण का कार्य सन 1990 से शुरू हुआ था।

गन्ने की खोई से कागज उद्योग :–

चीनी उद्योग भारत में सबसे बडा परंपरागत कृषि आधारित उद्योगों के बीच है। गन्ने के द्वारा सह उत्पाद खोई एक प्रमुख है। खोई मुख्य रूप से भाप जुटाने के लिए बॉयलर में ईधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

भारत में सालाना वर्तमान में कागज 1.8 मिलियन टन का उत्पादन होता है । जो अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग दो गुना की वृद्धि होने की संभावना है। कागज उत्पादन में आवश्यक कच्चे माल के रूप में 80 प्रतिशत बांस वृक्षों की लकड़ियों , घास, कपड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण वन क्षेत्र तेजी से घट रहा है। तथा पर्यावरण संतुलन विगड़ रहा है। कागज मिलों वनों पर कम दबाब करने के लिए कागज उत्पादन के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद बची हुई खोई का उपयोग करना चाहिए ताकि वनों को संरक्षण हो सके। खोई का उपयोग करने से वनों पर कम दबाब पड़ेगा। क्योंकि गन्ने की खोई में 48 प्रतिशत फाईबर, 28 प्रतिशत सेल्यूलोज लेगिन 20 प्रतिशत, 5 प्रतिशत चीनी, 2 प्रतिशत खनिज शामिल होता है। जिसके कागज निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप व्यवहार में लाया जाने लगा है। जिससे विभिन्न प्रकार के कागज एवं अखवारी कागज के निर्माण हेतु आदर्श कच्चा माल बन गया है।

सत्र 2007–08 में भारत में 4260 हजार मिट्रिक टन कागज का उत्पादन किया गया। जिसके निर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ने की खोई बांस, वृक्षों की लकड़ियां, घास कपड़े आदि का उपयोग किया गया।

पश्चिम बंगाल में स्थित टीटागढ़, काकीनाडा, नाईहाटी तथा रानी गंज तथा बिहार में डालमियानगर तथा उड़ीसा में ब्रजराजनगर में स्थित कागज के कारखानों से पूर्ती की जाती है। तथा शेष कागज की पूर्ती इन तीन राज्यों के अलावा सहारनपुर (उ.प्र.), जगधरी (पंजाब), सीरपुर (आन्ध्र) तथा नेपानगर (म.प्र.) में अखवारी कागज बनता है।काजग उद्योग में अचानक वृद्धि के कारण बॉस की कमी को दूर करने के लिए कागज और लुगदी बनाने के लिए गन्ने की खोई का उपयोग किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कारखानों में गन्ने की खोई से कागज का निर्माण करतें हैं।

गन्ने की खोई से पारर्टिकल बोर्ड का निर्माण :–

मध्यप्रदेश राज्य में गन्ने की खोई का उपयोग वॉयलर में ईधन एवं पार्टिकल बोर्ड बनाने

का कार्य किया जाता है। बोर्ड बनाने हेतु गाडरवारा में स्थित अष्टविनायक बोर्ड प्रा. लि. कारखाना है। जिसमें 1 टन खोई से 9 एम.एम. की 18 कि.ग्रा. की 8/4 की 26 नग एवं 26 एम. एम. की 11 नग के वोर्ड तैयार किए जातें है।

इन बोर्ड का उपयोग फर्नीचर आदि कार्य के लिए किया जाता है। इस वोर्ड बनाने के लिए खोई में फारमेलडिहाइड आदि केमिकल का प्रयोग करके वोर्ड शीट तैयार की जाती है। जिसकी लागत व्यय एवं आय का विवरण निम्नानुसार है।

बोर्ड की लागत /व्यय एवं आय का विवरण

क्रमांक	विवरण	राशि
1	एक टन बगास 1085 ग 2.2	2386
2	फार्मलिडीहाइड 78 किलोग्राम	1482
3	श्रमिक व्यय +विद्युत + मरम्मत व्यय + अन्य	3952
	कुल लागत	7820

स्रोत :– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

एक टन बगास से 9 एम.एम. की 26 बोर्ड शीट तैयार की जाती है। जिसके लिए 7820 रू की लागत आती है। जिसका थोक रूप में विक्रय मूल्य में प्रति बोर्ड शीट 330 /– रूपये होता है।

विक्रय मूल्य :– 26 ग 330 = 8580

आय = विक्रय मूल्य – लागत मूल्य

710 = 8530 – 7820

710 रू की आय होती है। इसके पश्चात इन बोर्ड में सनमाइका लगाकर इसका मूल्य अधिक हो जाता है।

गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन :–

भारतीय गन्ना एवं तकनीकी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि गन्ने का भुगतान किसानों देने के लिए गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन संयंत्र लगाकर बिजली का उत्पादन करके सरकार को बेचेगी।जो इसे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को बेचेगी। अध्यक्ष के द्वारा यह कहा गया कि प्रत्येक चीनी मिल में पेराई किए जाने वाले गन्ने की मात्र दस प्रतिशत खोई की बचत होती है। ईधन के रूप में प्रयोग कर बिजली उत्पादन कर सकतें है। भारत में वर्तमान स्थिति में 122 चीनी मिलों में से 58 मिलें गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन कर रहीं हैं। और इसे बेचकर गन्ने के मूल्य का भुगतान कर रही हैं। उत्तरप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा यह कहा कि देश में लगभग 7000 मेगावाट विद्युत तथा प्रदेश में लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश में लगभग 4500 करोड़ रूपये निवेश की आवश्यकता होगी।

देश की सबसे बड़ी चीनी उत्पादक कम्पनी बजाज हिन्दुस्तान ने उ.प्र. में अग्रणी बिजली कम्पनी बनने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस कम्पनी की पहली 660 मेगावाट ईकाई पहले से परिचालन कर रही है। लेकिन बाकी दो ईकाईयां स्थापित करने के लिए कार्य प्रगति पर है। अभी कम्पनी के पास 90 मेगावाट की पाँच प्रमुख ईकाईया है जो परिचालन कर रही है। जिसकी कुल क्षमता 450 मेगावाट है। कम्पनो ने इन्हे अपने चीनी संयंत्रो के नजदीक में स्थापित किया है। ये ईकाईयां पेराई सत्र के दौरान गन्ने की खोई का इस्तेमाल ईधन के रूप में करती है। जबकि अन्य मौसम में कोयले का उपयोग होता है। इससक पहले समूह ने उप्र में तीन चीनी मिलों बंद की थी और अब यह 12 चीनी मिलों का परिचालन कर रहा है। कम्पनी की मिलों की कुल पेराई क्षमता 1.36 लाख टन रोजाना थी जो 21000टन घटकर लगभग 1.15 लाख टन रह गई । बजाज समूह की सहायक ईकाई ललितपुर पावर जेनेरशन कंपनी लिमेटेड (एल. पी. जी. सी. एल.) में इस कंपनी के द्वारा जून 2015 में 660 मेगावाट क्षमता 3 ईकाई का कार्य शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ में रायपुर, कवर्धा जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम रामेपुरा स्थित भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना लोगों को मिठास के साथ एक बड़े क्षेत्र के लिए बिजली भी दे रही है। फैक्ट्री में पेराई के बाद बची गन्ने के बगासिस या खोई से पिछले 9 सालों से न सिर्फ कारखाना चल रहा है बल्कि कवर्धा शहर के करीब 25000 घरों को भी रोशन किया जा रहा है। वर्ष के 6 महिने यानि नबंवर से अप्रेल तक एक सीजन में भोरमदेव शुगर फैक्ट्री में हर दिन गन्ने के बगास से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित बिजली के करीब 30 फीसदी का उपयोग फैक्ट्री, ऑफिस और स्टाफ कालौनी में किया जाता है। जबकि 70 फीसदी का उपयोग इलेक्ट्रोसिटी पॉवर ग्रिड के माध्यम से समीपस्थ ग्राम जोराताल में स्थित सब स्टेशन में स्थानांतरित हो जाती हैं। यह बिजली शहर के लगभग 25000 घरों का रोशन करती है। वर्ष 2015–16 में 1050 मेगावॉट बिजली उत्पादित की गई थी। जिससे प्रबंधन को ढाई करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी गन्ने से बिजली पैदा करने का काम बड़े स्तर पर कर रही है। ताकि बेहतरीन तरीके से बिजली उत्पन्न हो सके । गन्ने से बिजली पैदा करके बिजली सप्लाई में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गन्ने से बिजली प्लांट के प्रोजेक्ट को देखते हुए मप्र ने गन्ने की पैदावार को बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस ओर बड़ी कामयाबी हासिल की है।

गन्ने के मोलासेस या शीरे से ऐथेनॉल बनाना :–

एथेनाल पेट्रोल का विकल्प है। एथेनाल गन्ने के अतिरिक्त उत्पाद शीरे से बनता है। और इसको बनाने की लागत सिर्फ 2/–रूपये प्रति लीटर तक आती है। शीला 30 पैसे प्रतिलीटर पड़ता है। और चार लीटर शीरे से 1 लीटर ऐथेनाल बनता है।

एथेनाल एक तरह का अल्कोहल है। जिसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में ईधन की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने से किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा 2002 में नौ राज्य और चार केन्दशासित क्षेत्रों में एक जनवरी 2003 से पाँच प्रतिशत ऐथेनॉल मिला पेट्रोल बेचने की मंजूरी दे दी थी । इसे धीरे धीरे बढ़तें हूए पूरे देश में दर प्रतिशत के स्तर तक ले जाना था परन्तु अनेक समस्याओं के कारण यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है।

ऐथेनॉल गन्न के अलावा शर्करा बाकी अन्य फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। जिससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। एथेनॉल को ऊर्जा का अक्षय स्त्रोत माना जाता है। क्योंकी गन्ने की फसल अनंत और अपार है। अन्य देशों में जैसे ब्राजील में लगभग 40 प्रतिशत कारों में सौ प्रतिशत ऐथेनॉल का उपयोग होता है। अन्य गाड़ियों में 24 प्रतिशत एथेनॉल का प्रयोग होता है। हमारे देश में रिलाइन्स कम्पनी ने ब्राजीन में जमीन खरीदी है और ऐथेनॉल उत्पादन में प्रयोग में लाने जा रही है। कंपनी द्वारा यह कहना है कि अगर पेट्रोल में 5 प्रतिशत ऐथेनॉल मिलाया जाता है। तो इस ईधन को ईएस कहते है। अगर पेट्रोल में 10 प्रतिशत ऐथेनॉल मिलाया जाता है। तो इस ईधन को ई10 कहते है अगर बगैर पेट्रोल के सिर्फ एथेनॉल का उपयोग किया जाता है तो इसे ई 100 कहतें है। हमारे देश में एथनॉल को 27 रूपये प्रति लीटर से सरकार किसानो और विक्रताओं से खरीदती है। और इसका समर्थन मूल्य पर रूपये प्रति लीटर है।

एथेनाल के उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र में शक्कर से ज्यादा एथेनॉल की माँग है। क्योंकि एक टन गन्ने से 110 –120 किलो शक्कर बनती है। जबकि 90 लीटर एथेनॉल निर्मित होता है। पेट्रोल की कीमत 85 रूपये प्रति लीटर है। जबकि ऐथेनॉल की कीमत 60 रूपये प्रति लीटर माने तो एक टन गन्ने से बनाए गए ऐथेनॉल को 5400 रूपये मिल सकते है। इस प्रकार कि प्रक्रिया मे खर्च छोड़कर किसानों का 4400 रूपये भाव देना संभव है।

इसी तरह पूर्वी उ.प्र. एवं म.प्र. में गन्ने का उत्पादन बढ़ाकर गन्ने चीनी मिलों में तैयार होने वाला मोलासेस या शीरे से एथेनॉल का उत्पादन करके किसानों की आय में से प्रतिवर्ष 8 हजार से 10 हजार करोड़ का ईजाफा कर सकतें है। जिससे किसानो का पिछड़ापन व गरीबी दूर

की जा सकती है। एथेनॉल पेट्रोल डीजल से कम धुँए वाला प्रदूषण रहित ईधन है। परन्तु हमारे देश में एथेनॉल निमार्ण हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह गन्ने के सहउत्पाद से ऐथेनाल, कागज, पार्टिकल बोर्ड, आदि उद्योगों को महत्व देकर उद्योगों के विकास के नए आयाम स्थापित हो सकतें है। मध्यप्रदेश सहित नरसिंहपुर जिले में गन्ने पर आधारित उद्योगों के विकास कि अनंत संभावना है। एवं वर्तमान सहायक उद्योगों में सुधार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षत्रों के विकास हेतु एवं कृषको एवं श्रमिकों को कि आर्थिक समृद्धि तथा जिले के सम्पूर्ण विकास हेतु गन्ने के आधारित उद्योगों का विकास सरकार कि प्राथमिकता में होना चाहिए। इसी प्रकार गन्ना नीति एवं शक्कर उत्पादन नीति की समीक्षा प्रति पाँच वर्ष में आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। जिससे प्राकृतिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के साथ समयानुकूल परिवर्तन किए जा सकें ।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

"Subaltern Journalism and Mobile Radio CG Net-Swara"

Mukesh kumar, Research scholar
School of communication studies, Panjab University, Chandigarh (India)

Abstract : The research paper is based on the case study of CG Net-Swara which is a mobile radio, which allows people in the Central area of India to report local news by making a phone call. The interface is freely accessible via mobile phone, which allows anyone to report stories and listen to them by giving a miss call. The stories are moderated by journalists and are available for playback over the phone. The endeavour is to address local problems and issues, as the main stream media is over occupied with issues of national and international importance. To raise their concern over the local issues, they can make a call using a mobile phone of fixed land line phone.

The research paper makes a moderate effort to depict the role of hyper local mobile radio in raising issues of growth and development in the rural area of Central region of India. Seventy percent of Indian population lives in villages, which has limited access to print and digital media. Through this mobile radio, effort has been made to collect grassroots communication. The local, regional economic and development issues which are unique to the region could be better expressed and explained by the local residents. In a county of one billion people still eighty million people lack access to any main stream media outlets. This often led to hindrance in socio- economic development because of which they fall prey to Maoist insurgency.

The paper is based on the principle of democratic participant media theory. Development issues rose with the help of CG-Net Swara, are more appropriate for inclusive development.

Researcher has adopted the case base study method for analysis of the impact and co-ordination between receiver and sender of message in order to gain a deeper insight into the mobile radio. The researcher will use the survey, interview and focused group discussion method, for completing the Case Study of CG-Net Swara.

Key words : -- CG-Net Swara, Hyper Local News Portal, Mobile Journalism

Introduction : "In the third world countries like India, the responsibility of media is not only providing news and entertainment but also development of analytical awareness among the masses as our society has been in the constant grip of slavery, poverty, illiteracy, inequality and hopelessness"(Joshi,2007).

The main objective of media is considered as information, education, awareness and entertainment. "Media, the concrete form of this expression has grown in power over a period of time. The fundamental objective of media is to serve the people with news, views, comments and information on matters of public interest in a fair, accurate, unbiased and decent manner and language. The media today does not remain satisfied as the fourth estate. It has assumed the foremost importance in acting as a communication link between the society and the government. Such is the influence of media that it can make or unmake any individual, institution or any thought. The media's impact on the society in today's scenario is very pervasive and extremely powerful. With so much power and strength, the media cannot lose sight of its privileges, duties and obligations" (Ray, 2010).

In the context of the present scenario in India, the mainstream media is more focused on

the urban India, where as in the rural area the role of mainstream media is very little in terms of information flow. In the present era of globalization where the whole world has become a global village, there is a question on whether the Media are working with the zeal and sensitivity towards the local issues or not? The reach of newspapers in India is more in urban areas as compared to rural areas.

The mainstream media is under the constant pressure of profits and economic growth, whereas the CG-Net Swara works with the objective of justice, development and democracy.

India is an agrarian rural society with around 65% people dependent on agriculture and the irony is that agriculture and rural India does not find any coverage in the mainstream media.

The Hoot did a quantitative analysis of the coverage of Indian states among five English News dailies- Times of India, The Indian Express, Hindustan Times, The Hindu, and The Economic Times. Delhi editions of these papers were taken. The period covered was April- May, 2012. News coverage was tracked for 50 issues, in 28 states.

A two-month scan of states coverage in 5 Newspapers shows that The Hindu does a better job than the others. INDIRA AKOIJAM finds that in some Newspapers some states were not covered at all. The figure shows top five issues raised by the above mentioned five newspapers.

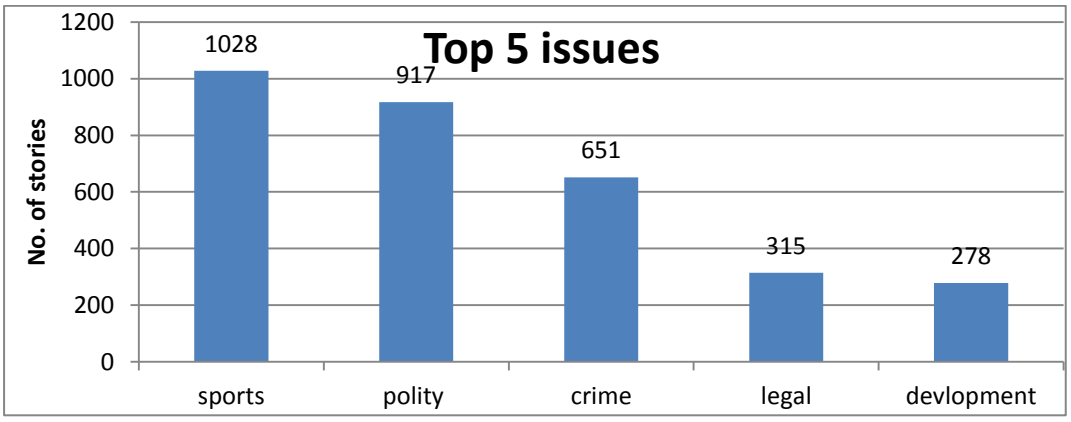

"India being the largest democracy in the world, it becomes very important that the citizens have access to information for proper functioning of its institutions. In the past, the print media shouldered the responsibility of disseminating information and news regarding the happenings within and outside the country" (Press in India 2009-10, 54th Annual Report, RNI). Grassroots Media are the pillars of democracy in this country as they cater to the needs of the majority of the Indian population and particularly those who live in the rural areas.

Grassroots Media are brought out by people with small means. They carry local news and cover problems concerning the local public.

The Grassroots Media generally speak the local language of the people and are read and understood by them and thus are capable of influencing or building up public opinion at the grass root level. They serve as a bridge between the people living at distant places in the interiors of the country on the one hand and the local administration, state, government and the central government on the other.

"The democratic form of society demands its members to participate actively and intelligently in the affairs of their community, whether local or national. Democratic society, therefore, needs a clear and truthful account of events; of their background and their causes; a forum for discussion and informed criticism; and

a means whereby individuals and groups can express a point of view or advocate a cause. The responsibility for fulfilling these needs unavoidably rests in large measure upon the press"(Royal commission on the press, 1947-49).

Grassroots Media serving their intimate involvement in the local scenario play a more direct role in the process of democratizing communication and motivating socio-economic transformation at that area.

CG Net-Swara : CG Net-swara aimed to address this need by providing a platform for members of tribal communities to report and discuss issues that are meaningful to them. Reports from such 'citizen journalist' flowed through personal communication to a CG Net-Swara moderator who broadcasted the story of discussion of the CG Net-swara website and mailing list.

The impetus behind CG Net-swara was to extend the reach of CG Net-swara to anyone with access to a mobile phone. In CG Net-swara callers can record stories and listen to other recordings by navigating a simple interactive voice response (IVR) system. Recordings which are maximum of 3 minutes long undergo moderation to ensure they are clear, audible and appropriate for dissemination. Once the moderator approves a post, It is available for listening on both the phone and the internet website. The website also includes the moderator's textual summary of each post. To keep the phone line available for multiple callers, only the four most recent posts are available for playback via phone.

CG Net-swara was deployed in February 2010. As of November 2011, CG Net-swara has received a total of 70,500 phone calls and has posted 1100 recordings and 240 calls per day.

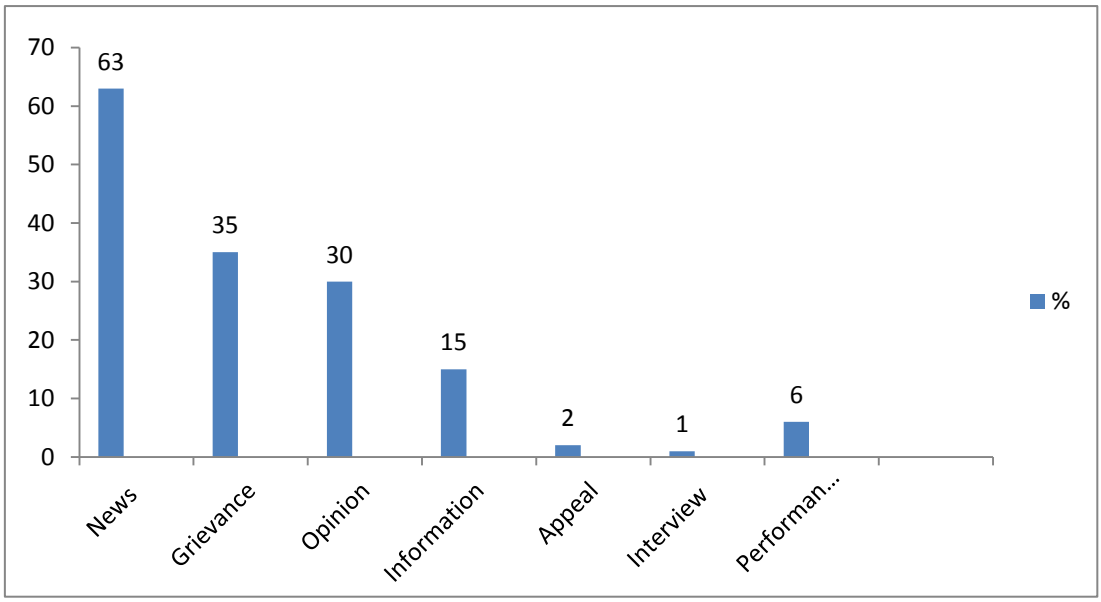

Diagram 6 -First 20 months of CG Net- Swara posts by type. A post May be assigned more than one type.

Currently it publishes 4-5 new posts per day and receives approximately 140 calls per day (In the basic of 01 January 2015 to 31 March 2015 post report).

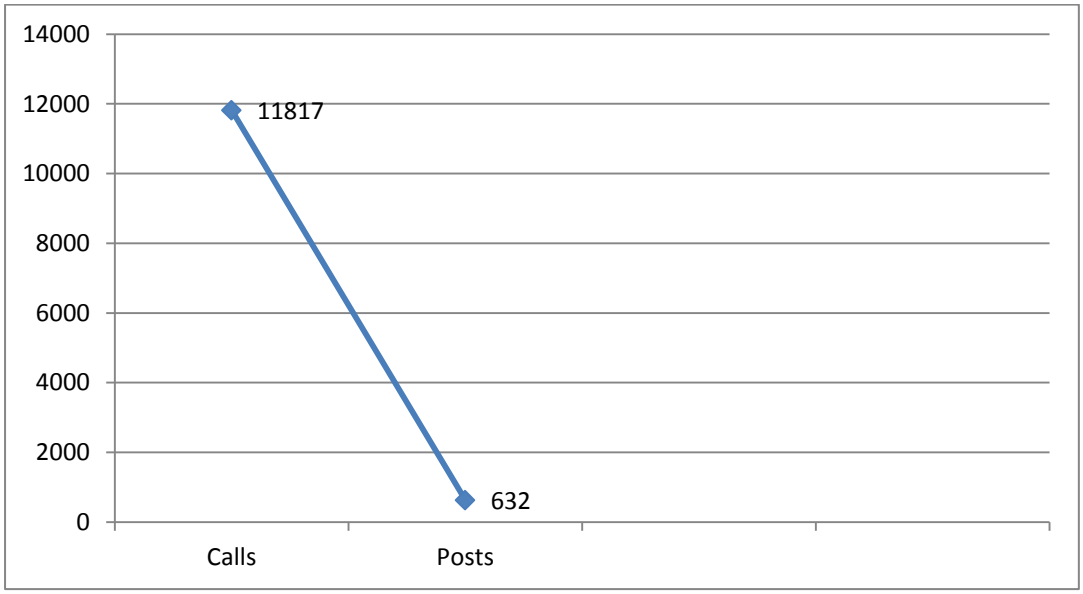

Diagram 8 The content of posts made on swara is quite diverse. 1013 posts of CG Net-Swara till October 2011. Each post was tagged into one or more of the categories, as shown in the table

Category	Number	Proportion of total categorized posts (%)	Proportion of total Posts (%)
Governance	660	41.22	65.22
Payment	126	7.89	12.48
Living Conditions	105	6.53	10.33
Event	58	3.65	5.77
Politics	420	26.21	41.46
Anniversary	4	0.25	0.40
Entertainment	75	4.66	7.38
Health	94	5.85	9.26
Education	60	3.75	5.90
Total	1601	100.00	

'The single biggest use of Swara is to report on issues of government in rural India. The grievances are all kinds- school not working, salaries not being paid, poor conditions in hospitals, allegations of corruption, complaints against private companies and authorities. Many of these are personal, affecting an individual, but symptomatic of greater institutional failure' (saha, 2012).

A total of 116 news items of 1013 published posts, mostly categorized under payment above were related to complaints in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) payments. The

volume implies the immense potential as well as serious mismanagement of the MGNREGA across rural India.

Another large proportion of posts are performances such as song under entertainment and in other case also event or anniversary. Adivasis have very strong oral traditions. Posts under this category are made in many different languages- Hindi, Chhattisgarhi, Gondi, Kurukh, and Santhali.

Adivasis in central India face many problems. There were other isolated incidents where communities were successful in combating official apathy to get results. Swara helps in bringing their communities together and allow learning from each other. In this context, CG Net-Swara has emerged as an example of "subaltern media" in India.

Significance of the Study : Due to lack of studies on rural grassroots media in Indians context, the problems faced by and the potential of rural grassroots media cannot be understood. This research will highlight the importance of Mobile Journalism for the development of rural areas. Lastly this will help in inclusive growth and also in attaining the true democracy which according to Gandhi jee cannot be attained unless the tears in the eyes of the last man standing in the last row cannot be wiped off.

Rationale of the study : Despite of the fact, 70 percent of Indian population lives in villages, the mainstream Indian media is urban centric. For the development of democracy inclusive growth is required. For inclusive growth it is necessary that the coverage of news from rural India finds more space in the media which can be achieved only through Mobile Radio these Radio raise issues pertaining local problems and sentiments. The sections of the society who are actually in dire needs of knowledge, information and development (rural masses) do not get the desired information as the mainstream media is urban centric. For these reasons it becomes important to study the relevance of rural Journalism like CG Net-Swara in the present scenario as Mobile Journalism are considered to be associated with the rural development and hence their role in the inclusive growth of the democracy can be studied.

THEORETICAL PERSPECTIVE :

1. Democratic Participant Media Theory : This theory strongly opposes the commercialization of modern media and its top-down non-participant character. The need for access and right to communicate is stressed. Bureaucratic control of media is decried. Mobile Radio CG Net- Swara provided a platform for the common man to put forward his or her opinion, news and views. Now millions of Indians are taking up through Mobile Radio CG Net- Swara and fighting for their rights. In rural areas Mobile Radio CG Net- Swara have set an example that how social participation helps in solving the regional problems and taking up developmental work. With the help of local newspapers, regional developmental issues can be raised by increasing the democratic participation through motivation. The Bolkar groups belong to the same community which is needed to be connected to development through news pieces. Hence, Mobile Radio CG Net- Swara has now become a voice for millions of people because of its role for their development.

2. Communication for social change: Communication for social change emphasizes the notion of dialogue as central to development and the need to facilitate poor people's participation and empowerment. It stresses the importance of horizontal communication, the role of people as agents of change, and the need for negotiating skills and partnerships. This theory focuses on dialogue processes through which people can overcome obstacles and identify ways to help them achieve the goals they set for themselves.

In the late 1990s, the Rockefeller foundations devoted significant resources to push a new concept called communication for social change. It argued that communication for

development needed to move beyond individual behavior change to instead focus on facilitating the conditions and an individual behavior change to instead focus on facilitating the conditions and an environment that would facilitate social change processes. This idea garnered support in the communication for development community.

Communication for social change is a process of public and private dialogue through which people themselves define who they are, what they need and how get what they need in order to improve their own lives. It utilizes dialogue that leads to collective problem identification, decision and community- based implementation of solutions to the developments issues. 'This is time of renewed interest in communication for developments and social change. The combination of innovations in information technologies coupled with widespread citizen mobilisation has emergised the debate about the role of communication in promoting social change" (Waisbord, 2014).

Developments communication/ communications and social change is about understanding the role played by information, communication and the media in directed and non-directed social change. According to (**Thomas, 2014**) there is a great variety of theoretical and practical approaches in development communications /communications and social change. It also includes a variety of practical applications based on the mainstreaming of communication as 'processes' and the leveraging of media technologies in social change.

RELATED WORK : 'Emergent Practices around CG net-Swara, A Voice Forum for Citizen Journalism in Rural India' in this research paper researcher Preeti Mudilar, Jonathan Donner, William Thies examine that CG Net Swara opened new avenues to participation in a digital public sphere.

'Cellphones as a Tool for Democracy; the example of CG Net- Swara' in this article Anoop Saha emphasizes that the social media revolution in the last decade was largely powered by communication technology advances, most notable by spread of the internet. Usear-genrated content which embodies the power of each individual to get his or her message across to the whole world has had a transformative quality that has made geographical and social boundaries irrelevant.

REVIEW OF LETERATE : Rogers M Everett (1974) Communication in development, this article describes what communication is doing and what it could do, in achieving developmental goals. The mass media plays a major role in creating a climate for modernization among villagers, but are less important in diffusing technological innovations although their potential for doing so is high. Jeffery (2000) 'India's newspapers revolution' which began in the seventies, created conditions for a new and expand 'democratic public'. The newspapers industry expanded dramatically at a rate faster than the country's population, mainstream newspapers started several local editions. New papers emerged in small towns and districts. Jeffery goes on to explore the role played by this expansion of print and newspapers in creating certain type of 'public sphere' or 'public space'. In a modification of Habermas's conception of the era of mass media, where mass media are not effortlessly manipulated, Jeffery proposes a new 'public space' one in which, masses are not effortlessly manipulated and the effects of mass media are unpredictable. As a consequence of India's newspapers revolution, 'people discovered ways to think about themselves and to participate a generation before'. Chaturvedi and Singh (2002) Stressed that in the present scenario, promotion of developmental work, social awareness and information and creation of active citizens are not the aims of media anymore as human beings are no more citizens but consumers or customers and the society a market. Natrajan (2002) writes in 'History of Indian journalism' that the fundamental objective of journalism is to serve the people with news, views and information on matters of public

interest. Information can be extremely instrumental in development. News is very powerful and shapes the society and can bring about any important change. Chopra (2006) emphasizes on the media imperialism in the third world countries in his book 'Media Aur Samaj.' Developed countries through their media try to establish their dominance in third world countries. Joshi (2007) stressed on the responsibility of media is not only providing news and entertainment but also development of analytical awareness among the masses. Media should focus on its developmental role in the third world countries. Parihar (2008) writes that media has an important role in the development of society and is thus an important agent for the growth of democracy and society. Media helps in identifying the factors behind the major social problems. Media can be instrumental in inclusive growth .Arun (2009) specifies that from last more than 20 years, globalization has led to qualitative change in the character and feature of media in India. Hence in a country like India the stress should be on the role of media in development. Chopra (2011)in his book 'Jansanchar ka Samaj Shastra' has studied media from a sociological perspective in the era of globalization. He emphasizes that media should be developed as the tool for the social development. Media should act as a public welfare and creative medium of communication. Chamadia (2009) emphasizes that media is not fulfilling social responsibility as it is mainly focusing on revenue generation. Main role of media in any democracy should be to act as a catalyst in development. Rao and Vasanti (2009) have highlighted the changing perspectives of media due to globalization. Their study emphasis on how developmental news in the media is declining.

OBJECTIVES OF THE STUDY

1. Does CG Net-Swara cover local issues?

2. Does CG Net-Swara cover developmental issues?

3. What type of developmental issues is raised by CG Net-Swara?

4. Does CG Net-Swara reveal administrative lapses?

5. Whether local language has any role in CG Net-Swara's popularity?

RESEARCH METHODOLOGY : This Research Paper has adopted Case Study Research Methodology in which various different techniques are used such as interview, focus group discussion and survey.

1. Focus group discussion – Team of CG Net-Swara.

2. Interview – Founder of CG Net-Swara.

3. Survey – Bolkar of CG Net-Swara and Administrative officers of related area.

A total of 50 interviews were conducted including that of CG Net swara founder of CG Net- Swara, 12 were content contributors, 31 were listener, and 2 were beneficiaries of the service and 4 bureaucrats. 25 interviews conducted via telephone. The other interviews were conducted face-to face.

Findings

Survey of Listener, Bureaucrats and Beneficiaries and its Findings : 31 listeners, 2 beneficiaries and 4 bureaucrats from Balrampur, Chhattisgarh were chosen for the survey as CG Net capacity building programme was being conducted in the afore said district of Chhattisgarh when the present study was being conducted.

The findings of the survey imply that all the 31 listeners came to know about CG Net through this capacity building programme only and that prior to this programme that had no idea about CG Net. It is only after the capacity building programme that they came forwards and recorded their problems through CG Net. The 2 beneficiaries surveyed implied that the reason behind people not come forwards to register their problems

through CG Net is lack of knowledge about CG Net as also the lack of technical knowhow as they don't know how to record their complaints using their phones. The 2 beneficiaries surveyed had registered problems regarding electricity and water through CG Net which were resolved within 14 days. Earlier that had tried many ways to solve these problems but had repeatedly failed despite all their attempts. The 4 bureaucrats surveyed revealed that they do not get information about the problems of rural areas through the mainstream media and they only get into action when they receive information about the problems faced by people in villages through CG Net or citizen journalists. They further revealed that social media also aids in building the pressure of citizen Journalists on them to work and take action.

The Survey further revealed that the CG Net has emerged as a platform to put forwards the local problems like MNREGA payment issues, Drinking water issues, Mid Day Meal irregularities, dearth of teachers in schools, health related issues and electricity problems. Owing to the fact that they can complain in their own local language by recording their voice, CG Net is gaining popularity.

Interview of Founder of CG Net-Swara: A Brief Summary : The world over, politics has democratised; it is time communication was democratised too. We can't have a better functioning democracy without a democratic media. Can people tell their own stories, can be not wait for a journalist to arrives, can media give access to the last person of our society. We trying to see with the help of new technology can be democratise journalism. Whether last person of the society will have equal rights to be heard, so we call it's the media dark zone. 100 millions of indigenous peoples live in India. They have no voice, they don't have a newspaper, no radio, no TV in their own language, and they are the poorest of the poor of our society of any social indication in India. This areas internet penetration is less than 1%, so it doesn't reach majority of people, but mobile phones reach more than 30%.Then we started looking mobile phone. Anybody and everybody who has a story tell anything share anything will pick up her phone tell her story in her own language, calling in the computer in the middle, now there is no need for a newsroom, Geography is now history. We go from market to market, village to village we do this drama, we do the puppet show, and we do dance that is our classroom for journalism and ask questions. This is a problem, u has a problem but it's coming on mainstream media it's not coming on TV. We have making capacity building and making citizen journalist, the new way teaching journalism because citizen should tell their own story. The only new thing I have found on my return here is that most people now have cell phones**.** Founder of CG Net- Swara, Choudhary used that cell phone knowledge to set up CG Net Swara in 2010. We are trying to create another 'development' paradigm; this communication system could well become the Google of the poor. We are extending our Swara system into a mobile-based voice portal.

Mobile phone gives us that opportunity which has reached the remotest parts of the country, even in adivasi area. And puppets are an entertaining way of teaching how one can use mobile phone to do journalism. It is important that people feel empowered and not fell handicapped while sharing their stories. Adivasis are oral communities. So, the mobile phone is a natural platform for them. This is the world's only website in Gondi script where people using their mobile phone the Gondi speaking area of five states where the yatra is travelling.

Focus Group Discussion of Team of CG Net-Swara: A Brief Summary : Team of the mobile radio stated in the discussion that they were informed about CG Net- Swara due to contacts with various workshops. Later they were selected as content contributors. Their educational qualification ranges from 8th pass to plus two levels. Though they know about the website of CG

Net-Swara and 90% reporters have the idea of Internet.

We notice that when any issue raised by villagers through their mobiles, many a time there is some action from officials often quite quickly. This is a new phenomenon which must be welcomed. it is important experiment of journalism and these kind of cultural yatras will take the information about platforms like CG Net-Swara to more people living in interior areas and they will be able to get their problems solved.

Content contributors of CG Net- Swara consider it as a movement. It helps weaker sections of the society and also creates awareness in rural areas. It raises such issues, which are generally not covered by any other medium, as there is hardly any presence of media in remote areas. Mobile Radio is instrumental is developing women efficiency such as increasing the literacy level. Further, it makes administration aware about the issues of road, electricity, drinking water, education, health and irregularity in government schemes. It also reveals deficiencies in the government schemes.

Conclusion : Mobile Radio CG Net-Swara has become a synonym for journalism of public matters in the rural areas of central In Mobile Radio in this region further indicates that it raises the livelihood problems of local people in their own language.

Bibliography

Arun, A. K. (2009, May). Bumandalikaran Ke Dhor Main Media. Yojna, pp. 13-15.

Joshi, R. S. (2007, January). Chalakh aur Hamlavar Media. Hans, pp. 130

India Ministry of communication and information Technology Broadband Services 2010

Mudliar,p and Donner,J and Thies,W(2012) 'Emergent Practices Around CG Net- Swara A Voice For Citizen Journalism In Rural India'

Rajgadhia, V. (2008). Jansanchar: Siddhant aur Anuprayog. New Delhi: Radha Krishan.

Rao N B and Basanti P N. (2009, May). Media Ke Nazareya main Parivartan. Yojna, pp. 5-8.

Ray,G.N. Print Communication In Rural India

Saha,A(2012)Cellophanes as a Tool for Democracy-The Example Of CG Net-Swara

Stanley, J. B and Dabis, D.K. (2012). Mass Communication Theory foundation, format and future. Boston, MA: Wadsworth.

Turner, J. H. (1998). The structure og sociological theroy. Belomont : wadsworth.

Wimmer,R.D and Dominick, J. R. (2011). Mass Media Research. Boston: Wadsworth.

Using Mobile Phones to Empower India's Poor-82U8uXMYGYA Swara Yatra _ BBC _ YouTube

CGNet Swara Mobile Application (Feature by Internet.org)-iyVYgq8o2-k (1)

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Development of Higher Education In India: Emerging Issues In Higher Education

Miss Kudshiya Raza
St. Aloysius (Auto.) College

Introduction : India's higher education system is the third largest in the world, next to the United States and China. The main governing body at the tertiary level is the University Grants Commission, which enforces its standards, advises the government, and helps coordinate between the centre and the state. Accreditation for higher learning is overseen by 12 autonomous institutions established by the University Grants Commission.

Indian higher education system has expanded at a fast pace by adding nearly 20,000 colleges and more than 8 million students in a decade from 2000-01 to 2010-11. As of 2011, India has 42 central universities, 275 state universities, 130 deemed universities, 90 private universities, 5 institutions established and functioning under the State Act, and 33 Institutes of National Importance. Other institutions include 33,000 colleges as Government Degree Colleges and Private Degree Colleges, including 1800 exclusive women's colleges, functioning under these universities and institutions as reported by the UGC in 2012. The emphasis in the tertiary level of education lies on science and technology. Indian educational institutions by 2004 consisted of a large number of technology institutes. Distance learning and open education is also a feature of the Indian higher education system, and is looked after by the Distance Education Council. Indira Gandhi National Open University is the largest university in the world by number of students, having approximately 3.5 million students across the globe.

Higher Education In India : If we see the educational history of india, it will be clear that in olden days india was an educationally most advanced country of the world in making contribution to the developments of mans knowledge and culture. Its seats of learning attracted scholars from all over the world. Vedas and dharmas sutras have discussion on parishads or assemblies of Brahmans. The most well organized centres of learning of the age were Takshshila and Nalanda. Vedas, upnishadas, Buddhism, journalism, philosophy and logic were the important subjects of study. Vallabhi in kathiwad and kanchi in south were also great centres of learning. There where the days when teachers and pupil where in close relation during medival period muslim rulers incourage the establishment of madras/ school at various selected places in the country. The important institution of this period where specialist in one or more branches of knowledge. The medium of instruction was mainly Arabic. The controversy to impart instruction through Arabic, Sanskrit or through English took place about 1835.

In 1844 government resolved that for public employment in every case preference would be given to those who had been educated in western science and were familiar with English language if we see twenty five year history(1857-1882) the growth was mainly in the number of colleges and students and no university was established in 1857 at Calcutta and was followed by Bombay and madras universities.

After achieving political independence in 1947 a great venture of over all development of national reconstruction with the objectives of economic and social freedom of equality, justice and dignity was launched. The progress of national economy and education were recognized interdependent and essential for cultural development of the country. Apart of its many other factors growing consciousness for reading, reach of education to untouched sections of the

society, technological application and reforms suggested by the experts of various discipline, realized that speedy growth of educational institutions and programmes will bring revolutionary changes in all parts of life.

These may be some of the reasons that education"continued to evolve, diversify and extend its reach to the society. Every country of the world is in practice of developing its system of education to express and to promote its unique socio-cultural identity and to meet challenges of the times". To achieve these objectives the existing educational conditions were reviewed time to time and suggestions were made by the various field specialists to identify the variety of new challenges and new dimensions of emerging subjects.

Development of Higher education : Higher education provides people an opportunity to react on the critical "social, economic, cultural, moral and spiritual issues facing humanity. It contributes to the national development through dissemination of specialized knowledge and skill. It is, therefore, a crucial factor of survival". According to amrik singh and Sharma higher education seeks to promote excellence, adventure of ideas and research for truth. It is to cultivate new knowledge and interpret old knowledge in the light of needs and discoveries. It is also to provide the right kind of leadership in all walks of life and identify gifted youth and help them to develop their potential to the full by cultivating physical fitness, developing the powers of mind, right interests, attitudes and values. It was realized in past that to meet the growing needs of developing society, the higher education should be given some direction. The schemes, therefore, were reviewed and some new one was introduced to accommodate rapid developing modern urban economy.

The courses offered by the institution of higher learning/universities have become almost obsolete. Since independence continuous efforts are being made to review the higher education system the number of commission, notably education commission 1948-49, education commission 1964-66, national policy on education 1986 and acharya Ramamurthy review committee have been constituted by the government to find out a national pattern of education for the whole country, the subject is being debated in conferences and workshops.

In this direction the first serious attempt was setting up of education commission under the chairmanship of Dr. sarvapalli radhakrishnan , the eminent educationist and philosopher. His report recommends the universities "have to provide leadership in politics and administration, the professions, industry and commerce. They have to meet the increasing demand for every type of higher education, literacy and scientific, technical and professional, etc. they must enable the country to attain, in as short a time as possible. Freedom from want, disease and ignorance, by the application and development of scientific and technical knowledge. It is for the universities to create knowledge and train minds who would bring together the two, material resources and human energies. If four living standards are to be raised a radical change of spirit is essential" "the universities as a maker of the future cannot persist in the old patterns, however, valid they may have been in their own day with the increasing complexity of society and its shifting pattern. Universities have to change their objective and methods, if they are to function effectively in our national life". The first prime minister, pandit Jawaharlal Nehru, therefore in this special convocation at Allahabad university expressed "a university stands for humanism, for tolerance for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onwards march of the human race towards even higher objectives. If the universities discharge their duty adequately, then it is well with the nation and the people".

Since the higher education is full of varieties, the government of india felt the need for

a comprehensive review of higher education system with a view to reconstruct it in the light of our social and political needs. As a result of it another commission was set up under the chairmanship of prof. D.S. Kothari.

The education commission 1964-66 constituted to hold a comprehensive review and to advise the government on national pattern of education and general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects. The commission recommended "radical reconstruction of education is essential for economic and cultural development of the country for national integration and for realizing the ideal of socialistic pattern of society. It was of the view that the education system must produce young men and women of character and ability committed to national service and development". Only then a sense of common citizenship, culture and national integration will prevail. Accordingly, governments resolved to promote free and compulsory education to all to fulfill the assurance of commission article 45.

The present system of higher education includes various types of institutions, universities and colleges. The universities are of various types- central, state and deemed. Etc. central universities are established by an act of parliament whereas state universities are by an act of state legislature. The colleges are also two types- private and government. In private colleges some are affiliated to universities and some are working without affiliation. Recently UGC has granted autonomy to a number of colleges. The academic institutions are increasing with the increasing population to extend teaching, research and examination facilities to the population surrounded to these.

Higher education in India has witnessed a phenomenal development– both in quantitative and qualitative terms, since independence. The Government has been steadily increasing the budgetary allocation for education and the country has also made significant strides in higher and technical education. From a brief analysis of the current Five Year Plan, one can infer that the government considers education as a main pillar for sustained economic growth & social welfare. Keeping this in mind, substantial financial resources have been allocated to education sector in the yearly budgets & subsequent 5- year plans. India's higher education system is the third largest in the world after China and United States. The main government body at the tertiary level is the University Grants Commission (UGC), which enforces its standards, advices the government and help coordinate between the center and states. Accreditation for higher education is overseen by 12 autonomous institutions established by UGC, including National Assessment and Accreditation Council (NACC).

The priorities for Higher Education in the XI Plan are :

(i) Expansion- stands for increasing the number of higher education institutions and for augmenting the capacity of the existing ones;
(ii) Excellence - stands for increasing the quality of higher education, notably by investing in physical infrastructure, quantity and quality of teachers, academic and administrative governance structure, and practices in universities and colleges;
(iii) Optimal use of information & communication Technology to promote achievement of these objectives, Enhancing public spending, encouraging private initiatives and initiating the long overdue major institutional and policy reforms;
(iv) To increase Gross Enrollment Ratio from 11% in 2006 to 15% by 2011-12 through rapid expansion of higher education system while ensuring quality and inclusion, and also restructure and re-orient higher education system to meet the requirements of a knowledge economy in a globalised world. The institutions of higher learning in India fall into the following broad categories; (i) central and state universities; (ii) deemed to be Universities (given deemed to be university status by the

Central Government on the recommendation of the University Grants Commission);(iii) private Universities (established by various State governments through their own legislation); (iv) Institutes of National Importance (declared as such by the Government of India by an Act of Parliament and are empowered to award degrees); and (v) Premier Institutes of Management (set up by the Central Government and are outside the formal university system. They offer Post-Graduate Diploma Programs equivalent to Master's Degree Programs in management). India has now a system of higher education with 460 plus degree awarding institutions apart from thousands of Diploma awarding establishments. In addition, there are colleges, which are affiliated to universities and provide undergraduate education. Some colleges also undertake post-graduate teaching and research. The affiliating universities oversee the standards of the affiliated colleges and hold examinations and award degrees to successful candidates. The college sector is managed both by the Government and Private bodies. There are some constituent colleges that are established and managed by a particular university. The UGC, on the recommendation of an Expert Committee and in consultation with the State Government and the University concerned, confers the autonomous status on colleges. Such institutions have the capability to design their own curriculum, evolve innovative teaching and testing strategies.

Issues and challenges of higher education Faculty improvement : Availability of educated and qualified faculty is a most important need for development of higher education. Due to restrictions on the recruitment of the faculty in the state universities and colleges in 1980's and 1990's by various states, we face a serious problems related to the availability of the faculty. Due to restrictions on recruitment, the universities and colleges have resorted to temporary and adhoc faculty. We don't have reliable data on the magnitude of the temporary faculty in colleges and universities.

Physical infrastructure : The policy for improving physical infrastructure includes increase in general development grants on existing schemes by substantial margin. This will induce a substantial improvement in the physical infrastructure.
There are three types of universities grade A, grade B and grade C. under 11th plan some schemes is proposed for providing financial assistance to filling the gape between A and C universities and colleges. For infrastructure development.

Policy for assessment and accreditation: At present universities and colleges follows some voluntary schemes like assessment and accreditation. There should be compulsory assessment and accreditation. UGC is already working on it.

Quality and Academic and Administrative Reforms of University and College System : Another important part of improvement of quality in higher education is the initiative for academic and administrative reforms of university and college system. The academic reform necessarily includes changes in admission procedures in various courses; amendment in assessment and examination methods; switch over from annual to semester systems; acceptance of grade and credit system; teacher's assessments; and other related reforms. With the help of these reforms definitely higher education system will improve.

Conclusion : In this introductory chapter I have tried to explain the growth of higher education, and secondary I have presented development of higher education. But as we know due to some issues development of higher education is not possible easier so I have discussed some essential issues on it. University grants commission is already working on it. UGC introduced some schemes for the development of higher education, hope it will work for the future.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN INDORE-REVIEW AND ITS IMPACT ON ENVIORNMENT

Divya Pande
AISECT College of Professional Studies Indore (Asst. Professor in Management)

Abstract : Municipal solid waste (MSW) is one of the major areas of concern all over the world. In developing country like India, there is rapid increase in municipal solid waste due to urbanization and population growth. Composition of waste varies with different factors like living standard, Climatic condition, socio-economic factor etc. This paper gives current scenario of Indore with respect to municipal solid waste quantity, quality and its management. We have presented a brief overview of MSWM in Indore.

Keywords : Municipal solid waste, urbanization, living standard, Climatic condition.

Introduction : Economic development, urbanization and improving living standards in cities, have led to increase in the quantity and complexity of generated waste. Indore Municipal Corporation (IMC) is responsible for solid waste management in Indore city. It has a population of 15.42lakhs (as per census 2001), with an area of 130.17km^2.The projected population of 2014 is 26, 49684 lakhs. City is divided into 85 wards. These wards have been clubbed under 15 zones. It is estimated that 1200 tons of solid waste is generated in the city each day which is to be collected from house to house and from Road side bins and waste dump location and transported to waste disposal site presently at Devguradiya. Till date waste is being dumped in this site and there is no other site available. The existing site of Devguradia has 140 acres of land is planned to be given on lease by IMC to a private operator to set up a waste processing and compost manufacturing facility .

Need of the Project : As per the new rules, all waste generators should start segregating their waste into three categories – Biodegradables, Dry Waste (Plastic, Paper, metal, Wood) and Domestic Hazardous Waste (diapers, napkins, mosquito repellents, cleaning agents) before they hand it over to the collectors.

OBJECTIVES : To understand the current scenario of waste generation and its handling in Indore.

To find the issues with the current system of solid waste management.

To find out its impact on environment.

Scope & Limitations of the study :

1. The study is limited to Indore Urban area only.
2. The study is limited to end of the disposal only.

SORTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE

Type of waste	Percentage by weight
Wood	5%
Glass	5.5%
Food waste	10%
Plastics	9%
Metals	7.7%
Paper/paper board	39%
Yard waste	13%
Others	10.8

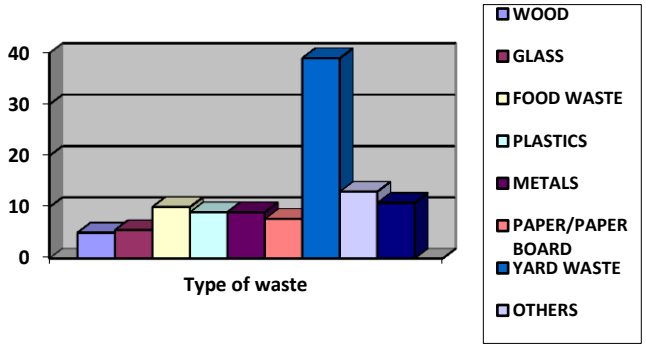

The major sources of solid waste in Indore are industrial waste, domestic waste and institutional waste but with increase population and changing lifestyle ,the rapid growth of municipal solid waste affect the environment which causes global warming, depletion of ozone layer, increase the level of CO2,pollution and human health.

Methods of Solid Wastes Disposal :

i. Sanitary Landfill

ii. Incineration

iii. Composting

iv. Recycling

I. **Sanitary landfill**-landfill is the method where the waste is covered and compacted with soil before the new layer is dumped on.

II. **Incineration :** The term incinerates means to burn something until nothing is left but ashes. An incinerator is a unit or facility used to burn trash and other types of waste until it is reduced to ash. An incinerator is constructed of heavy, well-insulated materials, so that it does not give off extreme amounts of external heat..

III. **composting :** Composting is a biological process in which micro-organisms, mainly fungi and bacteria, convert degradable organic waste into humus like substance. This finished product, which looks like soil, is high in carbon and nitrogen and is an excellent medium for growing plants. Organic matter constitutes 35%-40% of the municipal solid waste generated in India. This waste can be recycled by the method of

composting, one of the oldest forms of disposal. It is the natural process of decomposition of organic waste that yields manure or compost, which is very rich in nutrients

IV. Recycling : Recycling is the method which can be used to reduce the amount of garbage such a glass, plastics, iron scrap, aluminium, metals and other materials.

Finding and Conclusion : The current system, mainly involving the use of landfills, has manifested significant adverse environmental impacts caused by methane emissions from landfills and many other emissions from transfer stations. A short-term future scenario, where some of the landfills (which soon will reach their capacity because of rising amount of waste are substituted by incinerators with energy recovery, would not result in significant environmental improvement. This is primarily because of the low calorific value of mixed waste, and it is likely that the incinerators would require significant amounts of auxiliary fuels to support combustion of wet waste. As for the long-term future scenario, efficient source separation of food waste could result in significant environmental improvements, primarily because of increase in calorific value of remaining waste incinerated with energy recovery. Sensitivity analysis emphasized the importance of efficient source separation of food waste, as well as the electricity recovery in incinerators, in order to obtain an environmentally friendly waste management system. The irregular and non-normative development of cities and also weakness in the waste management system has created many problems especially in large cities. However, even many of the principles of engineering and environmental criteria about burying of wastes do not match in the landfill sites.

References :

1. **http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/Solid-waste-management-system-on-the-anvil-in-Indore/articleshow/47037352.cms**
2. www.iitk.ac.in/3inetwork/html/**reports**/IIR2006/**Solid_Waste**.pdf.
3. www.cpcb.nic.in/divisionsofheadoffice/pcp/MSW_**Report**.pdf.
4. www.cpcb.nic.in/MSWJodhpur.pdf.
5. www.dste.puducherry.gov.in/DPR-MSW.pdf.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

DIVERSITY ASSESSMENTS AND ABUNDANCE OF DRAGONFLIES AND DAMSELFLIES (ORDER-ODONATA) in NARMADA BASIN OF JABALPUR REGION, MADHYA PRADESH

Shradhanjali Koshta[1*], Dr. Sadhana Kesharwani[2], Dr. P.B. Meshram[3]

[1]Research Scholar, Department of Zoology, Govt. M.H. College, Jabalpur (M.P.) India.
[2]Assistant Professor, Department of Zoology, Govt. M.H. College, Jabalpur (M.P.) India.
[3]Scientist 'G' Tropical Forest Research Institute, Jabalpur (M.P.) India.

Abstract – The dragonflies and damselflies are a major insect group (Class Insecta: Order Odanata) associated with water courses. An opportunistic survey of Odonata diversity and distribution was done in along with river Narmada region of district Jabalpur to give updated list of species within the study. We recorded 46 species from Gour river and 27 species from Gwarighat region. 19 species were recorded in all two sites . Suborder Zygoptera was represented by the families Coenagrionidae, Lestidae, Protoneuridae, Platycnemididae, Chlorocyphidae and suborder Anisoptera by the families Gomphidae, Libellulidae and Aeshnidae. Libellulidae was the largest family with – species. In summer survey Orthetrum Sabina Drury, 1770 was the most abundant species, while in winter the most abundant was Agriocnemis pygmea Rambur, 1842. These data will be useful in future studies and conservation of biodiversity in the studied habitats.

Keywords : dragonfly; Anisoptera; Odonata; Insecta; Gauriyaghat region; Gour river; Diversity.

INTRODUCTION : Dragonflies and Damselflies are amongst the attractive of creatures on earth. They are well-known insects, and many people appreciate their striking colors and equilibristic flihght. Odonata (Dragonflies and Damseflies) constitute a small, well known order of insects that are widely distributed all over the world (Tillyard, 1917). The order Odonata includes dragonflies and damselflies, separated into three suborder, namely Anisoptera (Dragonfly) with 11 families, Zygoptera (Damselfly) with 24 families and Anisozygoptera. The third order, Anisozygoptera is represented by four species belonging to a single genus – Epiophlebia. Although only one family (Epiophlebidae) is now living, fossil evidence of 10 extinct families indicate considerable early diversity within this suborder (Williams & Feltmate 1992). About 5952 species of Odonata and subspecies belonging to 652 genra are document world-wide (Schorr & Paulson 2014). India harbors 474 species 50 subspecies belonging to 142 genra in 18 families (Subramanian 2014).

The life history of odonates is closely associated with wetland. Adult lay eggs in specific aquatic habitats. The Odonates have strong association with water because of their aquatic larvae (Corbet,1999). Dragonflies have been extensively used as indicators of evironmnetal quality in aquatic ecological units (Chovanec and Waringer, 2001). Dragonflies are key organisms of the food web as predators both as larvae and as imagoes (Benke, 1976). Odonates neither sting nor are bite and the entire species harmless. Naiads serve as food for growing freshwater fish, and the soft bodies of the teeneral are eaten by songbirds tasty snack (Jens and Runyan, 2006). They usually have definite habitat preference and territorial behavior (Corbet, 1999). Odonates are ecologically important as both predators and prey.

While both dragonflies and damselflies belong to the Odonata and share many common features then are a number of noticeable differences as well. Even before hatching from the egg, differences in morphology of the egg distinguish dragonflies (Anisoptera) from damselflies (Zygoptera).

Table 1. The observed species of Odonata and their Relative Status in Jabalpur district around river Narmada basin.

S.No.	Name of species	Common name	Satus
	Order- Odonata		
	Suborder – Zygoptera (Damselflies)		
	Family - Coenagrionoidae		
1.	Aciagrion pallidum (Selys, 1868)	Rusty Dart	R
2.	Agriocnemis pygmea (Rambur, 1842)	Pygmy Dartlet	VC
3.	Agriocnemis femina (Brauer, 1868)	White-backed wisp	C
4.	Agriocnemis pieris (Laidlaw, 1919)	White Dartlet	R
5.	Ceriagrion coromandelianum (Fabricius, 1798)	Coromondel Marsh Dart	C
6.	Enallagama parvam (Selys, 1876)	Azure Dartlet	R
7.	Ischnura aurora (Brauer, 1868)	Golden Dartlet	C
8.	Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)	Senegal Golden Dartlet	VC
9.	Pseudagrion decorum (Rambur, 1842)	Elegant Sprite	C
10.	Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842)	Blue Grass Dartlet	C
11.	Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876)	Saffron-faced Blue Dart	VC
12.	Pseudagrion spencei (Fraser, 1922)	Brook Sprite	C
13.	Rhodischnura nursei (Morton, 1907)	Pixie Dartlet	R
	Family – Protoneuridae		
14.	Disperoneura quadrimaculata (Rambur, 1842)	Black-winged Bamboo-tail	R
15.	Prodasineura verticalis (Selys, 1860)	Black Bamboo-tail	R
	Family – Platycnemidiae		
16.	Copera marginipes (Rambur, 1842)	Yellow Bush Dart	VC
	Family – Lestidae		
17.	Lestes elatus(Hagen in Selys, 1862)	Emerald Spreadwing	R
18.	Lestes umbrinus(Selys, 1891)	Brown Spread-wing	VC
	Family – Chlorocyphidae		
19.	Libellago lineata indica (Fraser, 1928)	Golden Gem	R
	Suborder- Aniosoptera (Dragonflies)		
	Family – Aeshnidae		
20.	Anax guttatus (Burmeister, 1839)	Pale Spotted Emperor	VC
21.	Anax immaculifrons(Rambur, 1842)	Blue Darner	C
22.	Gynacantha bayadera (Selys,1891)	Small Dusk Hawker	R
23.	Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)	Vagrant Emperor	R
	Family – Gomphidae		
24.	Ictinogomphus rapax (Rambur, 1842)	Common Clubtail	VC
25.	Macrogomphus annulatus (Selys,1854)	Keiser's Forktail	C
26.	Paragomphus lineatus (Selys, 1850)	Lined Hooktail	C

	Family - Libellulidae		
27.	Acisoma panorpoides (Rambur, 1842)	Grizzled Pintail	C
28.	Brachythemis contaminata (Fabricius,1793)	Ditch Jewel	VC
29.	Bradinopyga geminate (Rambur, 1842)	Granite Ghost	VC
30.	Crocothemis servilia (Drury, 1770)	Scarlet Skimmer	VC
31.	Diplacodes trivialis (Rambur, 1842)	Blue-Ground Skimmer	VC
32.	Neurothemis intermedia (Rambur, 1842)	Paddy Field Parasol	R
33.	Neurothemis tullia (Drury, 1773)	Pied Paddy Skimmer	VR
34.	Orthetrum glaucum (Brauer, 1865)	Blue Marsh Hawk	C
35.	Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868)	Slender Blue Skimmer	R
36.	Orthetrum pruinosum (Burmeister, 1839)	Crimson-tailed Marsh Hawk	C
37.	Orthetrum sabina (Drury,1773)	Slender Skimmer	VC
38	Orthetrum taeniolatum (Schneider,1845)	Small Skimmer	VR
39.	Pantala flavescens (Fabricius, 1798)	Globe Skimmer	VC
40	Rhyothemis variegate (Linnaeus, 1763)	Common Picture Wing	R
41.	Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)	Coral Tailed Cloud-wing	R
42.	Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 1805)	Red Marsh Trotter	C
43.	Trithemis aurora (Burmeister, 1839)	Crimson Mars Glider	VC
44.	Trithemis festiva (Rambur, 1842)	Black Stream Glider	VC
45.	Trithemis Kirbyi (Selys, 1891)	Scarlet rock glider	R
46.	Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889)	Long-legged Mars Glider	VC

MATERIAL AND METHOD Study area : Jabalpur is one of the famous district in Madhya Pradesh. It situated in the bank of the river Narmada basin lies between east longitudes 72° 32' to 81°45' and north latitudes 21°20' to 23°45'. The present study was carried out during year July 2015 to August 2016. Two study sites were selected for the investigation these were Gwarighat and Gour river.

Data Collection and Identification : The findings presented here are based on a biweekly random survey carried out from July 2015 to August 2016 during monsoon and post monsoon. The observation were made in the morning 8:00 am to 11:00 am which is a peak time for odonates. Identification of the odonates was primarily made directly in the field or, in difficult cases, following capture or photography. In critical condition specimens were collected only with handheld aerial sweep nets. Each specimens was placed in plastic bottle and carried them to the laboratory for further identification with the help of field guide (Wynter-Blyth 1957; Haribal 2002; Kunte 2000). All scientific names followed in the present study are in accordance to Varshney (1983). The observed odonates were categorized on the basis of their abundance in Gwarighat region and Gour river VC Very common (> 100 sightings), C Common (50-100 sightings), R Rare (2-15 sightings), VR Very rare (1-2 sightings) Tiple et al. 2006.

Table 2. Regional diversity of Odonata species in two sites in Jabalpur district around river Narmada basin.

S. No.	Name of species	Gwarighat	Gour river
Zygoptera (Dameselflies)			
1.	Aciagrion pallidum (Selys, 1868)	-	+
2.	Agriocnemis pygmea (Rambur, 1842)	+	+
3.	Agriocnemis femina (Brauer, 1868)	-	+
4.	Agriocnemis pieris (Laidlaw, 1919)	-	+
5.	Ceriagrion coromandelianum (Fabricius, 1798)	+	+
6.	Enallagama parvam (Selys, 1876)	-	+
7.	Ischnura aurora (Brauer, 1868)	+	+
8.	Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)	+	+
9.	Pseudagrion decorum (Rambur, 1842)	-	+
10.	Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842)	-	+
11.	Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876)	+	+
12.	Pseudagrion spencei (Fraser, 1922)	+	+
13.	Rhodischnura nursei (Morton, 1907)	-	+
14.	Disperoneura quadrimaculata (Rambur, 1842)	-	+
15.	Prodasineura verticalis (Selys, 1860)	-	+
16.	Copera marginipes (Rambur, 1842)	+	+
17.	Lestes elatus(Hagen in Selys, 1862)	+	+
18.	Lestes umbrinus(Selys, 1891)	-	-
19.	Libellago lineata indica (Fraser, 1928)	+	+
	Anisoptera (Dragonfly)		
20.	Anax guttatus (Burmeister, 1839)	+	+
21.	Anax immaculifrons(Rambur, 1842)	-	+
22.	Gynacantha bayadera (Selys,1891)	-	+
23.	Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)	-	+
24.	Ictinogomphus rapax (Rambur, 1842)	+	+
25.	Macrogomphus annulatus (Selys,1854)	+	+
26.	Paragomphus lineatus (Selys, 1850)	+	-
27.	Acisoma panorpoides (Rambur, 1842)	-	+
28.	Brachythemis contaminata (Fabricius,1793)	+	+
29.	Bradinopyga geminate (Rambur, 1842)	-	+
30.	Crocothemis servilia (Drury, 1770)	+	+
31.	Diplacodes trivialis (Rambur, 1842)	+	+
32.	Neurothemis intermedia (Rambur, 1842)	+	+
33.	Neurothemis tullia (Drury, 1773)	-	+
34.	Orthetrum glaucum (Brauer, 1865)	-	+
35.	Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868)	-	+
36.	Orthetrum pruinosum (Burmeister, 1839)	-	+
37.	Orthetrum sabina (Drury,1773)	+	+
38	Orthetrum taeniolatum (Schneider,1845)	-	+
39.	Pantala flavescens (Fabricius, 1798)	+	+
40	Rhyothemis variegate (Linnaeus, 1763)	+	+

41.	Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)	-	+
42.	Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 1805)	-	+
43.	Trithemis aurora (Burmeister, 1839)	-	+
44.	Trithemis festiva (Rambur, 1842)	+	+
45.	Trithemis Kirbyi (Selys, 1891)	-	+
46.	Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889)	+	+

RESULT AND DISCUSSION : The specimens were categorized into four groups based on their occurrence during the study period on the basis of frequency of sightings. During the intensive survey of Insects in Jabalpur district, 46 species were revealed among these a total of 8 families belonging to order Odonata recorded from selected sites. A total of 46 species of order Odonata, where suborder Zygoptera have 19 species under 5 families out of which Coenagrionoidae with 13 species is consisting of maximum number of species followed by *Chlorocyphidae and platycnemididae* with 1 species each. Anisoptera were comprise of 27 species under 3 families out of which *Libellulidae* or Skimmers are the most diverse and dominating family of dragonflies with 19 species that was followed by others such as *Aeshnidae* with 4 species and *Gomphidae* with 3 species (Figure 1.).

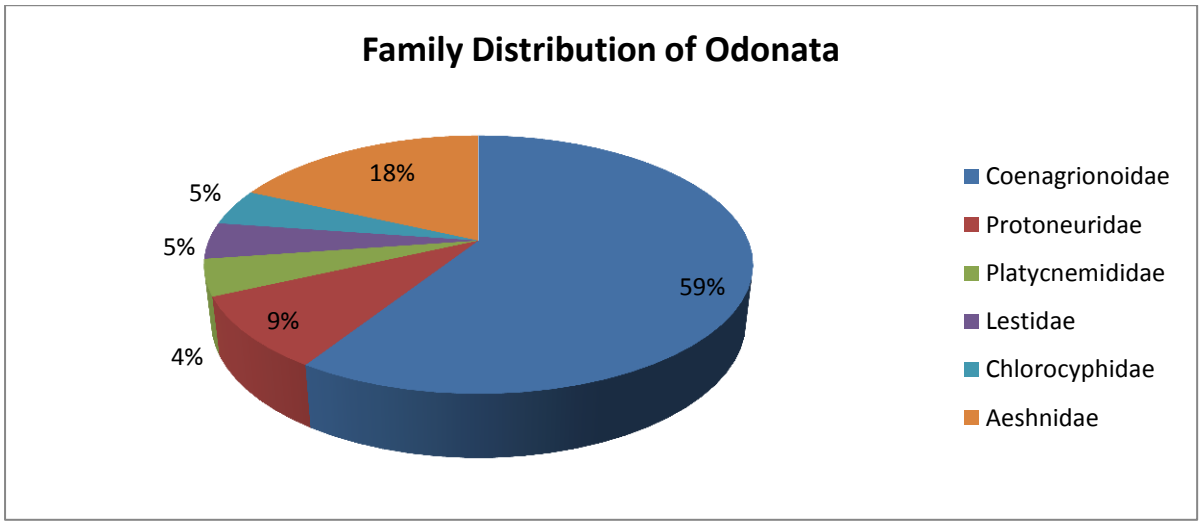

Figure 1. Families distribution of Odonata in Jabalpur region of river Narmada

Regional Diversity : Regional diversity of Anisoptera was considered as the most dominating group in compiling species of two study sites ((Fig. 2). Anisoptera was most abundant in Gour river with 25 species as compared to Gwarighat (13 species). Similarly Zygoptera constitute of 19 species of total 46 Odonata species in Jabalpur region of river Narmada basin while highest in Gour river (27 species) than Gwarighat (19 species).

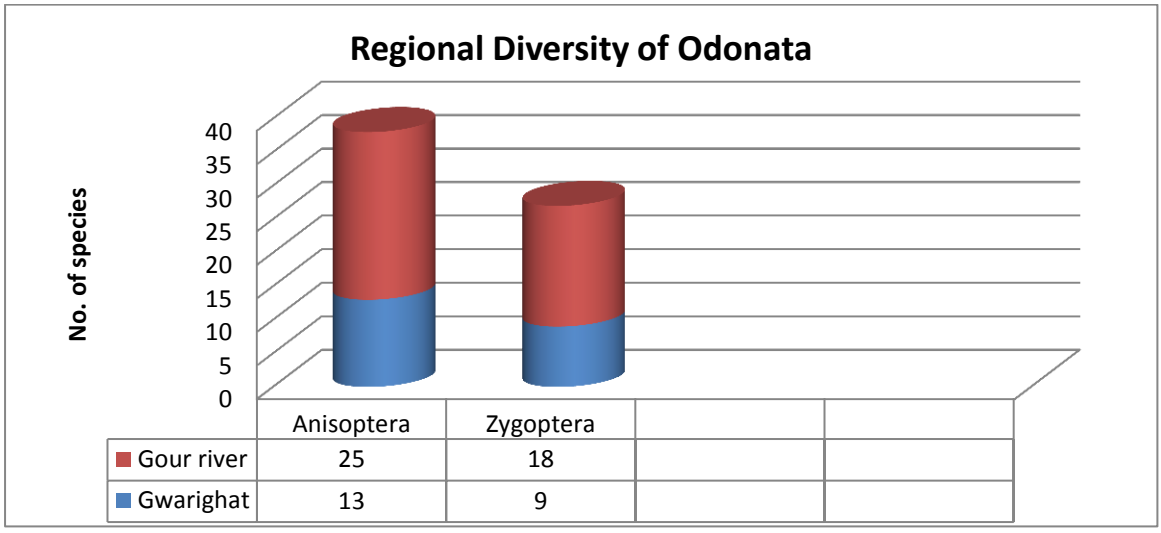

Figure 2. Regional Diversity of Odonata in Jabalpur region of river Narmada.

Relative Abundance : The relative abundance showed that among the 46 species of Odonata were recorded, 15 species were found to be very common, 14 species were common, 15 species were rare and 2 species were very rare were found to the study areas. (Figure 3.) These 33% species of Odonata from the study area were designated rare and 3% species as very rare, suggesting the need for strict conservation.

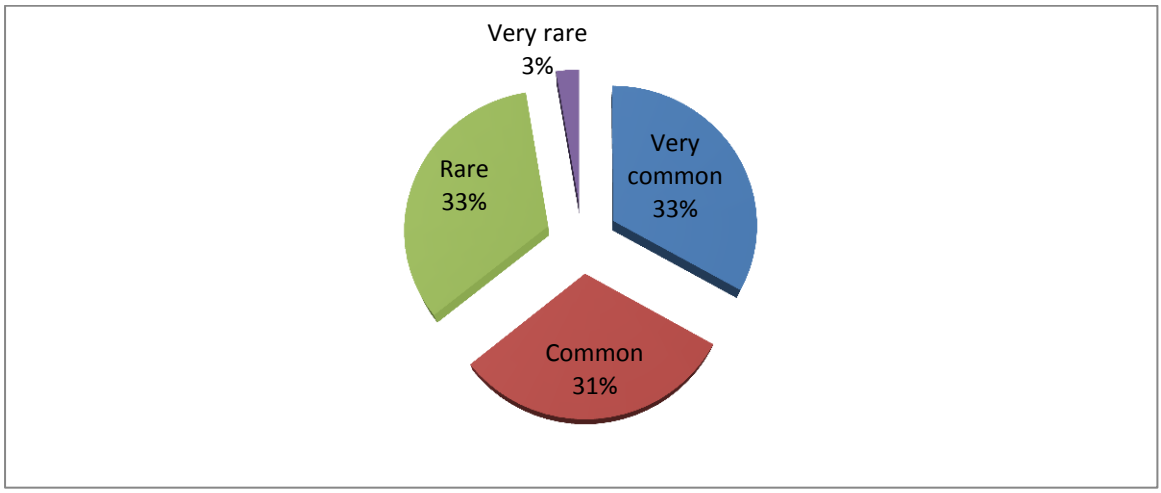

Figure 3. Relative Abdundance of Odonata

Subramanian, (2009) reported 11 dragonfliy families, of which 972 species with *Libellulidae* and 958 species with *Gomphidae* are major families throughout the world followed by 436 species in Aeshnida, 249 species in *Corduliidae* and 123 species in *Macromiidae*. Manwar *et al.,* (2012) in Maharashtra (India) recorded 22 species of dragonflies and damselflies of 4 families and 17 genera of which 50% species are of family *Libellulidae*. Tijare and Patil, (2012) were observed 21 species of dragonflies from Nagpur district and *Libellulidae* family has high species richness. Odonata are biological indicators as their species

composition and abundance changed in response to human disturbance.

Conclusion : The Odonata is an insect suitable for measuring the environmental quality of the Gwarighat region and Gour river. The detection of migratory and open habitat species like crocothemis servilla serves as an indicators of an anthropogenic change in habitats in the Narmada river.

Odonata is biotope characterization that shows different types of habits have characteristic species assemblages. Many species of Odonata as birds, but receive much less research and conservation attention. Many species have disappeared from water bodies worldwide. The observation recorded in the present study may prove valuable as a reference for assessing the change due to the environmental condition in the locality, in future. Continuous exploration in Narmada river could add many more new from the region.

RECOMMENDATIONS : This inventory has served as the baseline for Odonata communities along the Narmada basin hence can be a measure of monitoring in the near future.

Finally, there must be an increase in education on the importance of using local insect species as first level indicators of environmental health which improved upon can save the nation a lot of money otherwise used in the chemical evaluation and monitoring of water quality.

REFERENCES :

Armitage, S. 2012. Water quality assessment of river Narmada at M.P., India, American journal of soil and water, 2(4): 7-9.

A, Mitra, Dragonfly (Odonata: Insecta) Fauna of Trashigang Dzongkhag, Eastern Bhutan. In: Gyeltshen, T. & Sadruddin (ed.) "Environment and Life Support Systems of the Bhutan Himalaya, Vol. I", Sherubtse College, Kanglung, Bhutan: 40-70 (2002).

Corbet, P.S. 1999. Dragonflies: Behaviour and Ecology of Odonata. Harley Books, Colchester.

Chovance, A. and J. Waringer. 2001. Ecological integrity of river-floodplain systems- assessment by dragonfly survey (Insecta: Odonata). Regulated Rivers: Research and Manag. 17:493-507.

F. C. Fraser, The fauna of British India including Ceylon and Burma, Odonata, vol.I Taylor & Francis Ltd.,London.461pp .(1936) .

F. Johansson, & F. Suhling, Behaviour and growth of dragonfly larvae along a permanent to temporary water habitat gradient. Ecological Entomology 29: 196-202 (2004).

Kalkman V. J., Clausnitzer V., Dijkstra K. D. B., et al, 2008 Global Diversity of dragonflies (Odonata) in freshwater. Hydrobiologica 595:351-363.

Kiany M., Minaei K., 2009 The Dragonfly Family Libellulidae (Insecta: Odonata: Anisoptera) of Shiraz and its Vicinity (Fars Province, Iran). Iran Agricultural Research 28:65-79.

Klym M., Quinn M., 2003 Texas Parks and Wildlife. Introduction to Dragonfly and Damselfly Watching. Texas Parks & Wildlife Press, Austin. 21 pp.

Manwar, N.A., Rathod, P.P. and Raja, I.A. 2012. Diversity and abundance of dragonflies & damselflies of Chatri Lake Region, in Pohara–Malkhed Reserve Forest, Amravati, Maharashtra (India). International Journal of Engineering Research and Applications, 2(5): 521-523.

Mishra, S.K. 2009. Insect:Odonata. In: Fauna of Bandhavgarh Tiger Reserve (Madhya Pradesh). Conservation Area Series, Zool. Surv. India, 40: 25-38.

Mitra, T.R. 2005. Evolutionary Adaptations in Morphology and Ecology of Tholymis Tilliyard (Faricius) and Bradino pygageminata (Rambur) (Insecta: Odonata). Records of Zoological Survey of India; 104(1-2): 300pp.

Maiolini B., Carolli M., 2009 Odonata in Trentino (NE-Italy): historical and recent data. Studi Trent Sci Nat 84:11-18.

Nelson B., Ronayne C., Thompson R., 2011 Ireland Red List No. 6: Damselflies & Dragonflies (Odonata). National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage and Local Government, Dublin, Ireland. p. 4.

Raju, D.V. and Narayanan, S.P. 2008. Odonata fauna of Kanha National Park area in central India. Fraseria (N.S.), 7: 5-9.

Ramesh, T., Hussain, K.J., Satpathy, K.K., Selvanayagam, M. and Prasad, M.V.R. 2010.

Subramanian, K.A. 2009. A Checklist of Odonata of India. Zoological Survey of India, 36pp.

Talmale S.S. 2011. A Preliminary list of Odonata from the Singhori Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh. Bionotes 13(4): 159-160pp.

Tijare, R.V. and Patil, K.G. 2012. Diversity of Odonets in and around Gorewada National Park, Nagpur MS. (India). Bionano Frontier Special Issue, 9: 182-183.

Tiple, A.D., Khurad, A.M. and Andrew, R.J. 2008. Species Diversity of Odonata in and around Nagpur City, Central India. Fraseria (Proceeding of the 18th International Symposium of Odonatology, Nagpur) 7: 41–45.

Tiple, A.D., Kulkarni, N., Paunikar, S. and Joshi, K.C. 2010. Avian fauna of tropical forest research institute Jabalpur, Madhya Pradesh, India. Indian Journal of Tropical Biodiversity 18(1): 1–9.

Van Wrigh, R.I., Humphries C.J. and Williams P.H. (1991) What to protect? systematics and the agony of choice. Biological Conservation 55: 235-254.

Varshney, R.K. 1983. Index Rhopalocera indica part II. Common names of butterflies from India and neighbouring countries. Records of the Zoological Survey of India. Occasional Paper no. 47: 1-49.

Wilson, K.D.P. 1995. Hong Kong dragonflies. Urban Council.

Wynter-Blyth, M.A. 1957. Butterflies of the Indian Region. Bombay Natural History Society, 523pp.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

समाचार पत्रों में खेल समाचारों की कवरेज़ का विश्लेषणात्मक अध्ययन
(An Analytical Study on the Coverage of Sports News in Newspapers)

चेतन भट्ट,
शोधार्थी – पीएच.डी. जनसंचार विभाग, म.गां.अं.हिं.वि.वि.

प्रस्तावना (Introduction)

भारत में खेल समाचारों के सफर की शुरूआत 1982 में एशियाई खेलों के समय हुई थी जब देश में दूरदर्शन सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। आज कल लोग हिंदी समाचार पत्रों को सर्वाधिक रूप से पसंद कर रहे हैं। एशियाड खेलों के बाद 'क्रिकेट' विशेष रूप से उभर कर सामने आया जब 1983 के विश्व कप में भारत ने अपना परचम फहराया। प्रिंट मीडिया ने इस मायने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई। आज सभी समाचार पत्र लोगों की रूचि को ध्यान में रखकर खेल जगत से जुडी तमाम खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं। इतना ही नहीं आज के दौर में खेल समाचारों को ज्ञानवर्धक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। खेल मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कबड्डी से क्रिकेट तक की यात्रा का हर खेल मनुष्य की क्रियात्मकता का पहलू है। कोई 5 दशक पहले जब खेल की बड़ी स्पर्धाओं का पहली बार रेडियो पर खेल समाचारों का प्रसारण हुआ तो यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं इससे लोगों की खेल में दिलचस्पी कम न हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि इससे दिलचस्पी और बढ़ गई। अखबारों में खेल समाचारों के प्रकाशित होने से लोगों का खेल के प्रति रूझान और बढ़ा है। महिलाओं की भी खेलों में दिलचस्पी बढ़ी है और वे भी खेल समाचारों को देखना व पढ़ना पसंद करती हैं। दुनिया भर में खेलों ने मनोरंजन पहलू से अलग हटकर एक स्थान बनाया है। आज वैश्वीकरण, निजीकरण, डिजिटलीकरण और बाजारीकरण (Globalisation, Privatisation, Digitalisation and Marketisation) ने खेल समाचारों के प्रस्तुतीकरण का सिद्धांत पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। खेल पत्रकारिता भी पत्रकारिता का हिस्सा है जो खेल जगत से जुडी तमाम घटनाओं और जानकारियों को हम तक पहुँचाता है। यह किसी भी मीडिया ग्रुप का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है।

खेल पत्रकारिता, पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाले विविध आयामों में से एक महत्वपूर्ण आयाम है। आज के वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो पता चलता है कि सारी दुनिया में सैकडों तरह के खेल होते हैं लेकिन इन समस्त खेलों में वही खेल लोकप्रिय और प्रचलित हो रहे हैं जिनका कवरेज मीडिया में आए दिन पढ़ने व देखने को मिलता है। आज की भागमभाग भरी जीवन शैली के बीच भी खेलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जनसंचार माध्यमों का विकास भी बहुत तेजी से हुआ है। एक ओर जहाँ पहले क्रिकेट की प्रमाणिकता टेस्ट मैचो से आंकी जाती थी उसके बाद 60–60 ओवर के एकदिवसीय मैचों का आयोजन किया जाने लगा उसके बाद 50–50 ओवर का फॉर्मेट आया और अब पिछले एक दशक से क्रिकेट जगत में एक नया संस्करण जुड़ गया है जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है ये फॉर्मेट है टी–20। आखिरकार टी–20 ने खेल जगत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और इस फॉर्मेट ने जो परिवर्तन किये हैं उससे वर्तमान संदर्भ में खेल पत्रकारिता में जो बदलाव आये हैं वे इस शोध पत्र की प्रासंगिकता में प्रस्तावित हैं। खेल संस्करण में हुए तमाम तरह के बदलावों ने आज खेल समाचारां के प्रस्तुतीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है जिससे समाचार पत्रों के खेल पृष्ठों में एक नवीनता का उदय हुआ है। इस शोध पत्र के द्वारा हमें यही पता लगाना है कि आखिर क्या है ये नवीनता और किस तरह के बदलाव हुए हैं? प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से इस बात का पता लगाया गया है कि आज के इस तकनीकी युग में किस प्रकार प्रिंट मीडिया के अंतर्गत खेल पत्रकारिता की रिपोर्टिंग में तेजी से

बदलाव आये हैं। आधुनिकता के दौर में क्रिकेट के फॉर्मेट में आये बदलाव के साथ–साथ समाचारों के प्रस्तुतीकरण में भी बहुत तरह के बदलाव आये है।

शोध का उद्देश्य (Research Objectives)

हर कार्य और लक्ष्य का अपना एक उद्देश्य होता है जिसके द्वारा कार्य को पूरा करने में एक अलग तरह की ऊर्जा एवं प्रोत्साहन मिलता है। मेरे द्वारा किए जाने वाले शोध पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. वर्तमान परिदृश्य में मीडिया खेल को एक व्यवसाय के रूप में देखता है इस बात का अध्ययन करना।
2. खेल पत्रकारिता के प्रस्तुतीकरण में हुए बदलावों को समग्र रूप से प्रस्तुत करना।
3. खेल पत्रकारिता जो कि सूचना परक कही जाती है वर्तमान समय में कितनी समग्र खेल पत्रकारिता है और कितनी क्रिकेट पत्रकारिता इस बात का अध्ययन करना।
4. खेल पत्रकारिता कि भाषा शैली में आये बदलाव से होने वाले प्रभावों को जानना।

शोध की उपकल्पना (Research Hypothesis)

खेल से राष्ट्रीय भावना जुड़ी होती है एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास में लोगों की भागीदारी में मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। मीडिया के लिए खेल एक व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। समाचार पत्रों में विज्ञापन की अहम भूमिका नजर आ रही है जिसका सीधा प्रभाव प्रस्तुतीकरण पर हो रहा है। IPL और T&20 क्रिकेट के लिए 15 दिन पहले से ही अखबार विज्ञापनों से भरे रहते है। इस तरह की समग्र चीजों का, खेल के प्रारूप में आये बदलावों का, तथा व्यवसायीकरण की भूमिका से खिलाड़ियों पर मानसिक रूप से दबाव भी पड़ता नजर आ रहा है।

शोध का क्षेत्र (Research Area)

प्रस्तुत शोध का क्षेत्र नागपुर से प्रकाशित होने वाले दो हिंदी समाचार पत्र हैं। इसके अंतर्गत दैनिक भास्कर समाचार पत्र (15 सितम्बर 2012 से 10 अक्टूबर 2012) तथा लोकमत समाचार पत्र (15 सितम्बर 2012 से 10 अक्टूबर 2012) को ही शामिल किया गया है।

शोध की सीमा (Limitations of Research)

चूंकि खेल पत्रकारिता का दायरा बहुत व्यापक है ऐसे में पूरे विषय को समेट पाना शोध की गुणवत्ता के लिहाज से संभव नहीं है। इसलिए शोध को एक निश्चित सीमा के दायरे में विशेषतः क्रिकेट खेल के सभी प्रारूपों में आए बदलाव को ध्यान में रखकर अपने शोध को समग्र रूप में केंद्रित किया है। यह शोध नागपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर समाचार पत्र तथा लोकमत समाचार पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक प्रकाशित खेल समाचारों पर केंद्रित है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

शोध प्रविधि प्राथमिक और द्वितीयक होगी। प्राथमिक आंकड़ों के लिए विशेषज्ञों से बात करना तथा द्वितीयक श्रोत में इंटरनेट, समाचार पत्र–पत्रिकाएँ, लेख एवं पुस्तकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार जैसी विधियों का अनुसरण करते हुए विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का पालन किया गया है। इस शोध में मुख्य रूप से निम्न पद्धतियों का प्रयोग हुआ है–

1. अवलोकन 2. वैयक्तिक अध्ययन 3. साक्षात्कार 4. तुलनात्मक अध्ययन 5. अंतर्वस्तु विश्लेषण

अंतर्वस्तु विश्लेषण (Content Analysis)

शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित है–

दिनांक	खेल पृष्ठों की संख्या		कुल खेल समाचारों की संख्या		मुख्य पृष्ठ पर खेल समाचारों की संख्या	
	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार
15 सितंबर 2012	2	1	24	12	0	0
16 सितंबर 2012	2	1	12	13	1 (अन्य)	0
17 सितंबर 2012	2	1	17	9	1 (अन्य)	0
18 सितंबर 2012	2	1	22	10	0	1 (क्रिकेट)
19 सितंबर 2012	2	1	23	10	0	0
20 सितंबर 2012	2	1	20	13	0	0
21 सितंबर 2012	2	1	16	10	1 (क्रिकेट)	0
22 सितंबर 2012	2	1	19	14	0	0
23 सितंबर 2012	2	1	19	9	1 (क्रिकेट)	0
24 सितंबर 2012	2	1	17	9	1 (क्रिकेट)	0
25 सितंबर 2012	2	1	15	7	0	0
26 सितंबर 2012	2	1	22	12	0	0
27 सितंबर 2012	2	1	26	10	0	0
28 सितंबर 2012	1	1	11	8	0	0
29 सितंबर 2012	2	1	22	7	1 (अन्य)	0

30 सितंबर 2012	2	1	22	9	0	0
01 अक्टूबर 2012	2	1	29	9	2 (क्रिकेट+अन्य)	0
2 अक्टूबर 2012	2	1	23	12	0	0
3 अक्टूबर 2012	2	1	25	12	0	0
4 अक्टूबर 2012	1	1	15	10	1 (क्रिकेट)	0
5 अक्टूबर 2012	2	1	22	6	0	0
6 अक्टूबर 2012	2	1	27	9	0	0
7 अक्टूबर 2012	2	1	18	10	0	0
8 अक्टूबर 2012	2	1	22	9	2 (क्रिकेट+अन्य)	1 (क्रिकेट)
9 अक्टूबर 2012	2	1	23	19	0	0
10 अक्टूबर 2012	2	1	21	16	0	0
कुल	50	26	532	274	11 (क्रिकेट–6 / अन्य–5)	2 (क्रिकेट)

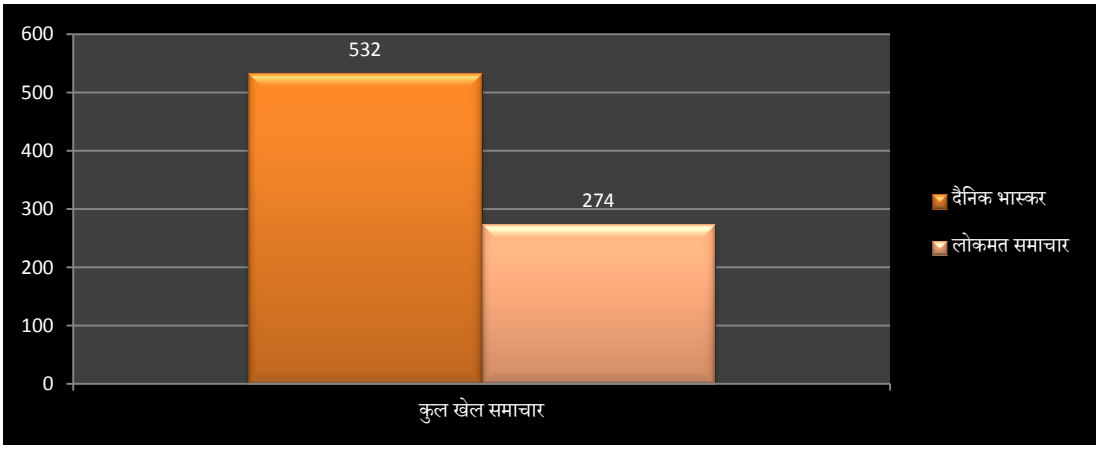

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि कुल खेल समाचारों की संख्या दैनिक भास्कर में 532 और लोकमत समाचार में 274 है वहीं नीचे दी गई सारणी से पता चलता है कि दैनिक भास्कर और लोकमत समचार में क्रिकेट से संबंधित कितनी खबरें हैं और अन्य खेलों से संबंधित कितनो खबरें हैं।

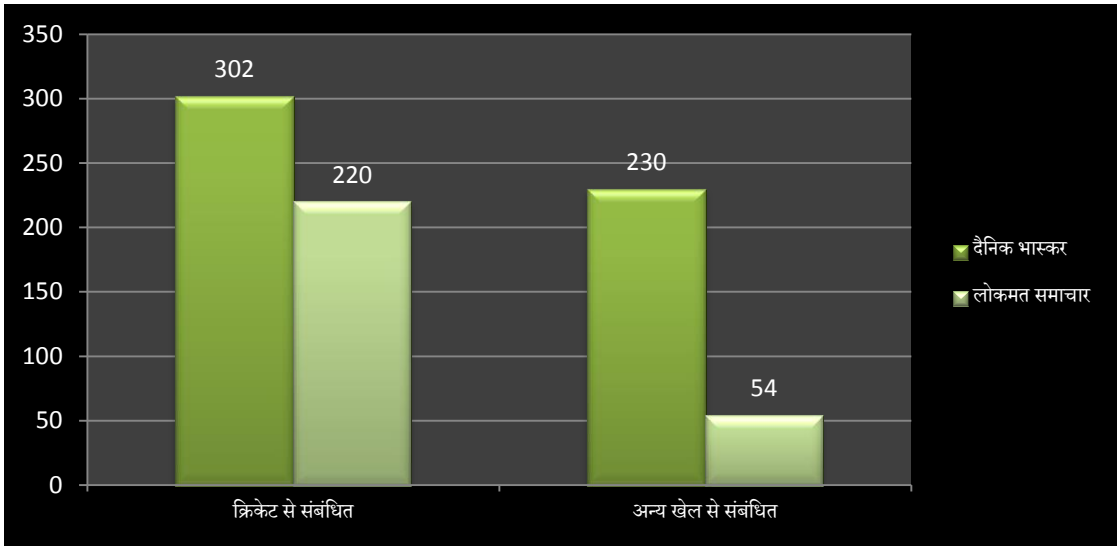

दिनांक	कुल खेल समाचारों की संख्या		मुख्य पृष्ठ पर खेल समाचारों की संख्या		पिछले पृष्ठं पर खेल समाचारों की संख्या	
	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार
15 सितंबर 2012	24	12	0	0	0	0
16 सितंबर 2012	12	13	1 (अन्य)	0	0	0
17 सितंबर 2012	17	9	1 (अन्य)	0	0	2 (अन्य)
18 सितंबर 2012	22	10	0	1 (क्रिकेट)	0	0
19 सितंबर	23	10	0	0	0	0

2012						
20 सितंबर 2012	20	13	0	0	0	31 (क्रिकेट+अन्य)
21 सितंबर 2012	16	10	1 (क्रिकेट)	0	0	1 (अन्य)
22 सितंबर 2012	19	14	0	0	0	4 (क्रिकेट)
23 सितंबर 2012	19	9	1 (क्रिकेट)	0	0	1 (अन्य)
24 सितंबर 2012	17	9	1 (क्रिकेट)	0	0	21 (क्रिकेट+अन्य)
25 सितंबर 2012	15	7	0	0	0	11 (क्रिकेट+अन्य)
26 सितंबर 2012	22	12	0	0	0	12 (क्रिकेट+अन्य)
27 सितंबर 2012	26	10	0	0	0	0
28 सितंबर 2012	11	8	0	0	0	1 (क्रिकेट)
29 सितंबर 2012	22	7	1 (अन्य)	0	0	1 (अन्य)
30 सितंबर 2012	22	9	0	0	0	1 (अन्य)
01 अक्टूबर	29	9	2 (क्रिकेट+अन्य)	0	0	3 (अन्य)

2012						
2 अक्टूबर 2012	23	12	0	0	0	11 (क्रिकेट+अन्य)
3 अक्टूबर 2012	25	12	0	0	0	13 (क्रिकेट+अन्य)
4 अक्टूबर 2012	15	10	1 (क्रिकेट)	0	0	3 (क्रिकेट)
5 अक्टूबर 2012	22	6	0	0	0	0
6 अक्टूबर 2012	27	9	0	0	0	1 (क्रिकेट)
7 अक्टूबर 2012	18	10	0	0	0	3 (अन्य)
8 अक्टूबर 2012	22	9	2 (क्रिकेट+अन्य)	1 (क्रिकेट)	0	13 (क्रिकेट+अन्य)
9 अक्टूबर 2012	23	19	0	0	0	11 (क्रिकेट+अन्य)
10 अक्टूबर 2012	21	16	0	0	0	1 (क्रिकेट)
कुल	532	274	11 (क्रिकेट–6 / अन्य–5)	2 (क्रिकेट)	0	46 (क्रिकेट–21 / अन्य–25)

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि समाचार–पत्र के मुख्य पृष्ठ पर और पिछले पृष्ठ पर दैनिक भास्कर और लोकमत समाचार में कितने खेल समाचार प्रकाशित हुए हैं साथ ही यह भी पता चलता हैं कि कितने क्रिकेट से और कितने अन्य खेल से संबंधित हैं।

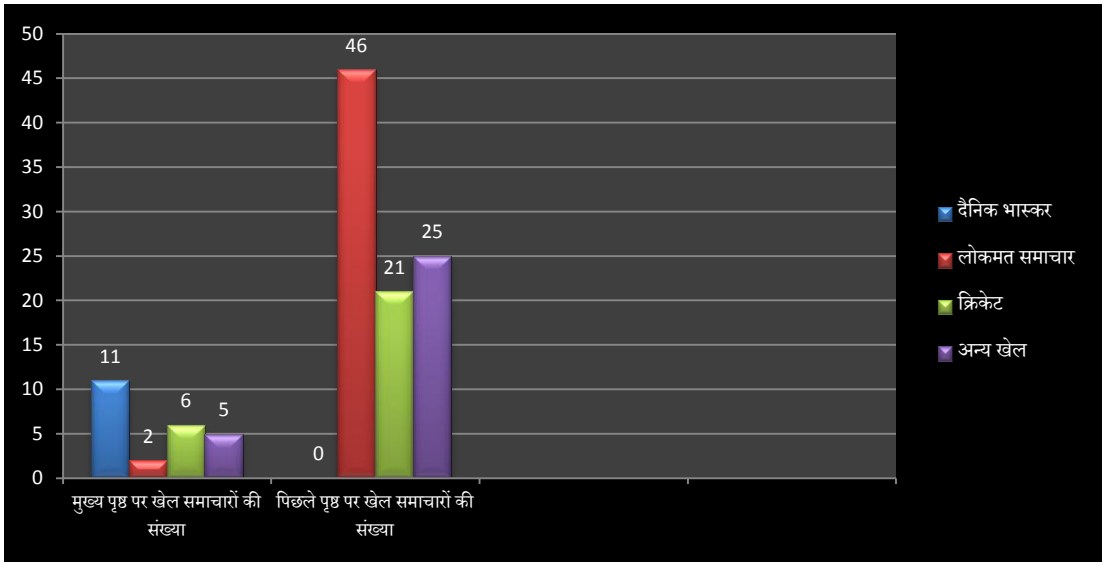

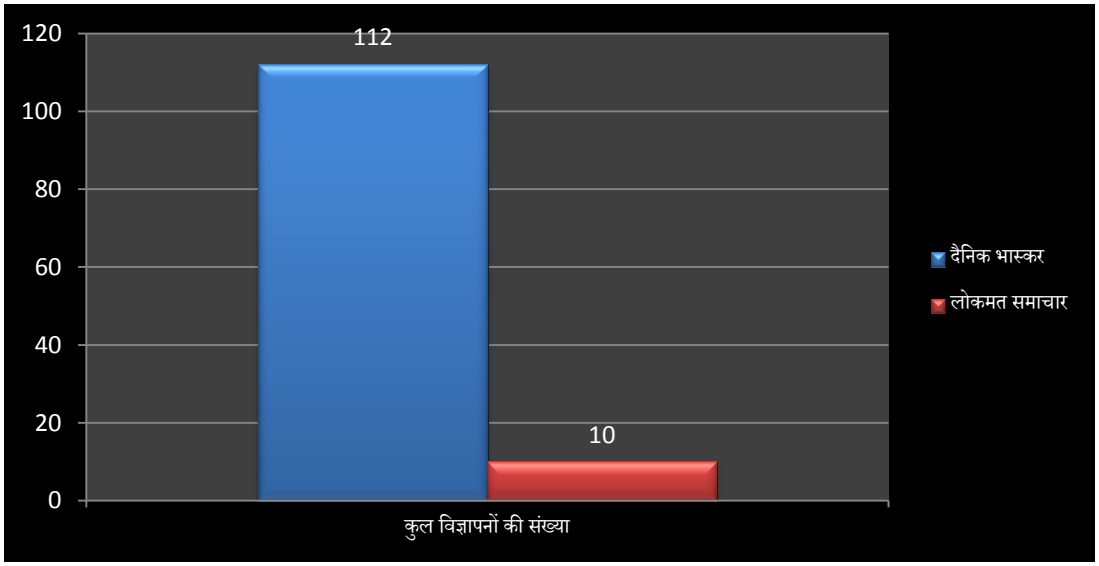

दिनांक	कुल खेल समाचारों की संख्या		विज्ञापनों की संख्या	
	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार
15 सितंबर 2012	24	12	4	2
16 सितंबर 2012	12	13	4	0
17 सितंबर 2012	17	9	4	1

18 सितंबर 2012	22	10	6	0
19 सितंबर 2012	23	10	5	1
20 सितंबर 2012	20	13	4	0
21 सितंबर 2012	16	10	4	0
22 सितंबर 2012	19	14	3	0
23 सितंबर 2012	19	9	4	1
24 सितंबर 2012	17	9	4	0
25 सितंबर 2012	15	7	7	0
26 सितंबर 2012	22	12	4	0
27 सितंबर 2012	26	10	4	0
28 सितंबर 2012	11	8	2	1
29 सितंबर 2012	22	7	4	0
30 सितंबर 2012	22	9	5	1
01 अक्टूबर 2012	29	9	4	0
2 अक्टूबर 2012	23	12	5	1
3 अक्टूबर 2012	25	12	4	0
4 अक्टूबर 2012	15	10	2	0
5 अक्टूबर 2012	22	6	5	0
6 अक्टूबर 2012	27	9	5	0
7 अक्टूबर 2012	18	10	6	2
8 अक्टूबर 2012	22	9	4	0

9 अक्टूबर 2012	23	19	4	0
10 अक्टूबर 2012	21	16	5	0
कुल	532	274	112	10

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि दैनिक भास्कर और लोकमत समाचार में छपे कुल विज्ञापनों की संख्या कितनी है। 15 सितंबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक के आंकड़ों से साफ नजर आ रहा है कि दैनिक भास्कर में कुल 112 विज्ञापन और लोकमत समाचार में मात्र 10 ही विज्ञापन छपे हैं।

दिनांक	कुल खेल समाचारों की संख्या		दैनिक भास्कर		लोकमत समाचार	
	दैनिक भास्कर	लोकमत समाचार	राष्ट्रीय खबरें	अंतर्राष्ट्रीय खबरें	राष्ट्रीय खबरें	अंतर्राष्ट्रीय खबरें
15 सितंबर 2012	24	12	7	17	0	12
16 सितंबर 2012	12	13	3	9	1	12
17 सितंबर 2012	17	9	2	15	0	9
18 सितंबर 2012	22	10	3	19	0	10
19 सितंबर 2012	23	10	5	18	0	10
20 सितंबर 2012	20	13	6	14	1	12
21 सितंबर 2012	16	10	7	9	1	9
22 सितंबर 2012	19	14	4	15	1	13
23 सितंबर 2012	19	9	5	14	0	8
24 सितंबर 2012	17	9	8	9	0	9
25 सितंबर 2012	15	7	3	12	1	6
26 सितंबर 2012	22	12	6	16	1	11
27 सितंबर 2012	26	10	5	21	0	10

28 सितंबर 2012	11	8	4	7	1	7
29 सितंबर 2012	22	7	6	16	0	7
30 सितंबर 2012	22	9	8	14	0	9
1 अक्टूबर 2012	29	9	6	23	3	6
2 अक्टूबर 2012	23	12	3	20	2	10
3 अक्टूबर 2012	25	12	6	19	1	11
4 अक्टूबर 2012	15	10	6	9	0	10
5 अक्टूबर 2012	22	6	4	18	0	7
6 अक्टूबर 2012	27	9	5	22	0	9
7 अक्टूबर 2012	18	10	4	14	1	9
8 अक्टूबर 2012	22	9	8	14	1	8
9 अक्टूबर 2012	23	19	2	21	3	16
10 अक्टूबर 2012	21	16	8	13	8	8
कुल	532	274	134	398	26	248

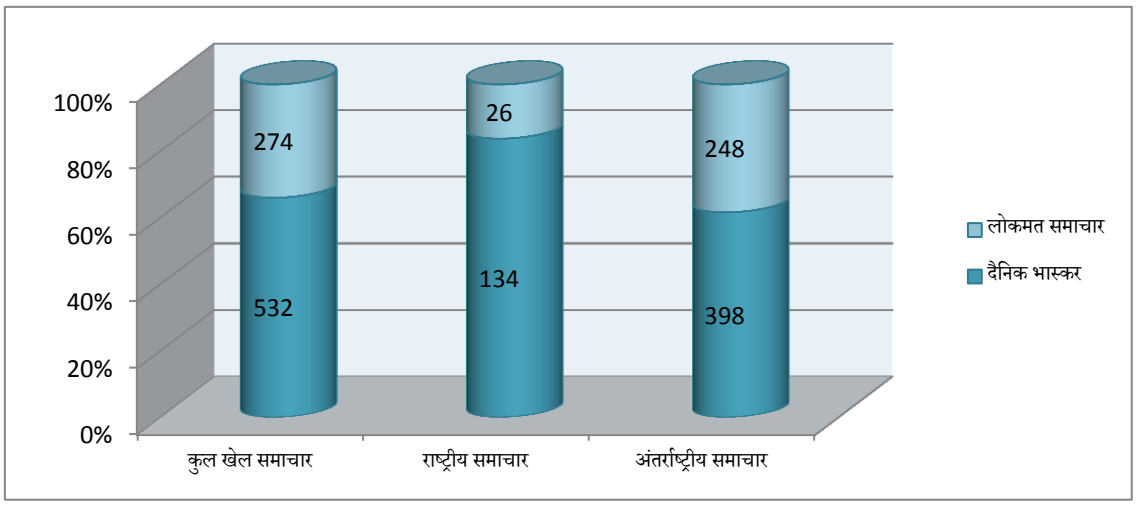

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि इन खबरों का प्रतिशत कितना रहा तथा नीचे दी गई सारणी से पता चलता है कि दैनिक भास्कर और लोकमत समाचार में 15 सितंबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक के बीच कुल कितने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल समाचार छपे।

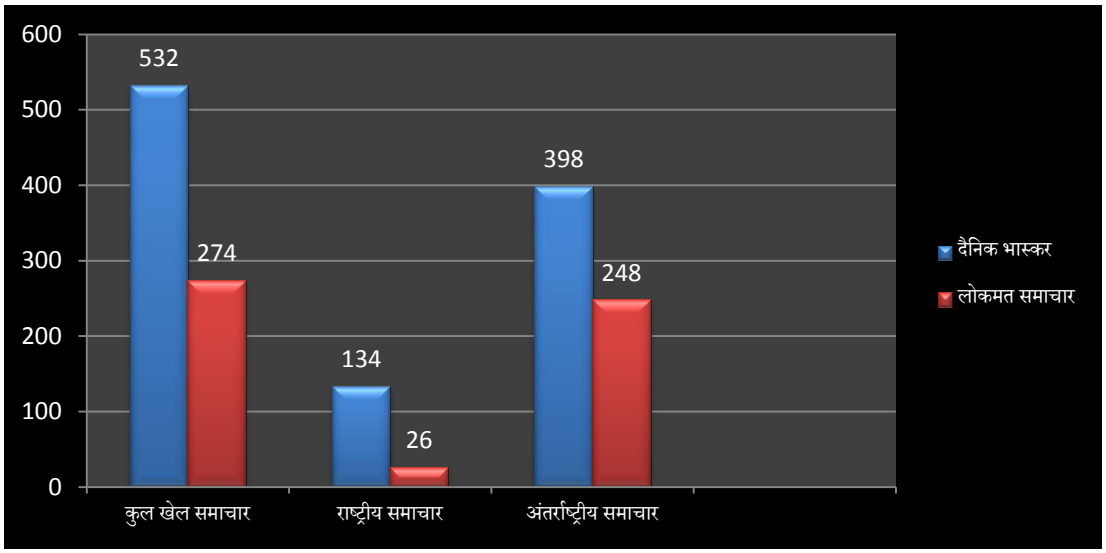

निष्कर्ष (Conclusion)

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जो रिपोर्टिंग दैनिक भास्कर तथा लोकमत समाचार में हुई वो वाकई आकर्षक, उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक रही जिसके द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया। इसके अलावा यह भी निष्कर्ष निकल कर आया कि लोकमत समाचार में 15 सितंबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक मात्र 10 विज्ञापनों को ही नगण्य रूप से खेल पृष्ठ पर स्थान दिया गया वहीं दूसरी ओर दनिक भास्कर में 112 विज्ञापन छपे जिनका साइज़ भी बहुत बड़ा था कहा जा सकता है कि इस समाचार–पत्र में विज्ञापन की प्रस्तुति पर अधिक ज़ोर दिया गया हालांकि यह भी है कि दैनिक भास्कर (532 खबरें) में लोकमत समाचार (274 खबरें) की अपेक्षा अधिक खबरों को प्रकाशित किया गया मगर यह भी ध्यान देना होगा कि दैनिक भास्कर में खेल पृष्ठों की संख्या 2 थी वहीं लोकमत समाचार में मात्र एक पेज का खेल पृष्ठ दिया गया।

इसके इतर यह भी पता चला कि दोनों ही समाचार–पत्रों में क्रिकेट की खबरों को अन्य खेलों की खबरों से अधिक स्थान मिला तथा खबरों के साथ–साथ चित्रों का भी समावेश अन्य खेलों की अपेक्षा क्रिकेट में अधिकाधिक व आकर्षक रूप से दिखाई पड़ा। यह भी नजर आया कि खेल पृष्ठ के अलावा मुख्य पृष्ठ व पिछले पृष्ठ पर भी खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया जिससे पता चलता है कि आज खेल पत्रकारिता का दर्जा हाशिए से निकल कर मुख्यधारा में आ चुका है ये अलग बात है कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज खेल पत्रकारिता समग्र न होकर मात्र क्रिकेट पत्रकारिता के रूप में नजर आ रही है।

आखिर में यह बताना भी आवश्यक है कि दोनों ही समाचार–पत्रों मं 15 सितंबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 के दौरान खेल पृष्ठ पर राष्ट्रीय खबरों से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खबरों को स्थान मिला दैनिक भास्कर में 134 राष्ट्रीय तथा 398 अंतर्राष्ट्रीय खबरों को स्थान मिला वहीं दूसरी ओर लोकमत समाचार में 26 राष्ट्रीय तथा 248 अंतर्राष्ट्रीय खबरों को स्थान मिला जिसके आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज की खेल पत्रकारिता विश्वव्यापी रूप से प्रस्तुत होती दिखाई दे रही है हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपेक्षा जरूर दिखाई पड़ रही है मगर उसके लिए भी काफी हद तक हमारे देश की

राष्ट्रीय खेल समीतिया और उनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं जिन्हें राष्ट्रीय खेलों की दयनीय स्थिति शायद नहीं दिखाई पड़ती।

सुझाव (Suggestions)

- उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य का धर्म ही है नित रोज गलतियां करना और त्वरित उनमें सुधार करना, यह एक मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि संसार में कुछ भी शत प्रतिशत नहीं होता हर अंत एक शुरूआत की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि खेल पत्रकारिता में क्रिकेट के साथ–साथ अन्य खेलों को भी समान दर्जा व स्थान देने की एक सफल कोशिश की जाए।
- कोशिश करनो चाहिए कि विज्ञापन को खेल पृष्ठ से यदि दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा और भी पेज हैं समाचार–पत्र में, इससे खेल–पत्रकारिता प्रभावित होने का खतरा टल सकता है। साथ ही खेल पृष्ठों की संख्या में इजाफा तो करना ही होगा जो कि आज समय की माँग भी है और यदि आप प्रतिस्पर्धा में बने रहना चाहते हैं साथ ही अंग्रेजी अखबारों की ताल से ताल बजाना चाहते हैं और उनकी तरह हिंदी खेल पत्रकारिता को ऊँचाई पर देखना चाहते हैं तो इतना तो करना ही चाहिए।
- अंत में सरकार से फिर से एक गुजारिश है कि राष्ट्रीय खेल को प्रमुखता से लिया जाए चाहे कुश्ती हो, हॉकी हो या फिर फुटबॉल तथा अन्य खेल ही क्यों न हों उनकी दयनीय स्थिति में यथाशीघ्र सुधार करने की जरूरत है तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल से जुड़ी नीतियों में बहु–स्तर पर सुधार लाने की आवश्यकता है।
- कुल मिलाकर हम यह भी कह सकते हैं कि अभी भी कुछ खेलों को लेकर स्थितियां साफ नहीं हैं। आज समय उपभोक्ताओं का है, खरीददारों का है, लिहाजा साथ भी उन्हीं का दिया जाता है जो उपभोक्ताओं को पसंद करते हैं, चाहे वह खेल हो या फिर खेल का पेज।

शोध अध्ययन का एक सकारात्मक प्रभाव (Implication of the Study)

वर्ष 2015 के फरवरी माह में शुरू हुए **ICC World Cup 2015 (13 Feb&29 Mar 2015)** तथा **ICC T&20 World Cup 2016 (08 March&03 April 2016)** के दौरान पाया गया कि लोकमत समाचार ने भी विश्व कप शुरू होने से एक हफ्ते पहले से ही खेल पृष्ठों की संख्या को बढ़ाते हुए दो पृष्ठों में खेल से जुड़ी ख़बरों को प्रकाशित किया बल्कि किसी–किसी दिन तो खेल समाचारों की कवरेज़ को दो से अधिक पृष्ठों में स्थान दिया गया। यही स्थिति कमोबेश **ICC CHAMPIONS TROPHY 2017 (01 June&18 June 2017)** के दौरान भी देखने को मिली। शोध के निष्कर्ष में पहले ही बताया जा चुका है कि दैनिक भास्कर में खेल पृष्ठों की संख्या बहुत पहले से ही दो पृष्ठों तक सीमित रही है मगर इन महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं **(Tournaments)** के दौरान किसी–किसी दिन तो खेल समाचारों को कवरेज़ को दो से अधिक पृष्ठों में स्थान दिया गया। इतना ही नहीं खेल समाचारों की कवरेज़ तथा पाठकों की रूचि को ध्यान में रखते हुए खेल पृष्ठों पर विज्ञापनों की संख्या पर लगाम कसने की एक सकारात्मक पहल भी हुई है।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1) Andrews, Phil. 'Sports Journalism: A Practical Introduction', Sage Publications Ltd., London
2) Beard, Adrian. 'Language of Sports', Routledge Publication
3) Buyant, Jennings. 'Handbook of Sports & Media', Routledge Publication
4) Boyle, Raymond. 'Sports Journalism: Context & Issues', Sage Publications Ltd., London

5) Jay, Kathryn. 'More than just a Game: Sports in American Life since 1945', Columbia University
6) Wenner, Lawrence A. (1989) 'Media Sports & Society'
7) चौबे, डॉ. कृपाशंकर, (1999) पत्रकारिता के नए परिदृश्य, मानक पब्लिकेशन.
8) मेहता, आलोक, (2008) भारत में पत्रकारिता, एन.बी.टी. भारत.
9) चतुर्वेदी, सूर्यप्रकाश, (2004) विश्व क्रिकेट और भारत, एन.बी.टी. भारत.

हिंदी समाचार–पत्र **(Hindi Newspapers)**

1) दैनिक भास्कर – 15 सितंबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक
2) लोकमत समाचार – 15 सितंबर 2012 से 10 अक्टूबर 2012 तक
3) दैनिक भास्कर तथा लोकमत समाचार (फरवरी से मार्च) 2015
4) दैनिक भास्कर तथा लोकमत समाचार (मार्च से अप्रैल) 2016
5) दैनिक भास्कर तथा लोकमत समाचार (मई से जून) 2017

पत्र–पत्रिकाएँ **(Magazines)**

1. क्रिकेट सम्राट दीवान पब्लिकेशन प्रा. लि. (सितंबर 2012 स नवंबर 2012 तक)
2. Cricket Today क्रिकेट टुडे (सितंबर 2012 से दिसंबर 2012 तक)

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

महाकाव्य की प्राचीन परंपरा

दौलत राम झारिया, शोधछात्र
संस्कृत, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पाणिनी ने अपने अष्टाध्यायी में शिशुकंदीय, यमसमीय तथा इंद्रजननीय इन काव्यों का प्रसंगवश सूत्रों में उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रबंधकाव्य की परंपरा में पाणिनी के पूर्व वाल्मिकी की रामायण या महाभारत के अतिरिक्त अन्य अनेक काव्य रचे गये थे। पर ये काव्य अप्राप्त हैं।

कालिदास के पूर्व महाकाव्य की रचना करने वाले दो महाकवियों के नाम प्राप्त होते हैं– पाणिनी तथा वरूचि या कात्यायन। इन दोनों के महाकाव्य लुप्त हो चुके हैं। ये दोनों व्याकरणशास्त्र के महान आचार्य के रुप में ख्यात हैं। जल्हण ने अपनी सूक्ति मुक्ताबली मं राजशेखर के कतिपय श्लोक उद्धत किये हैं, जिनमें से एक में बताया गया है कि पाणिनी ने व्याकरण के ग्रंथ के साथ जांब वतीजय महाकाव्य की भी रचना की थी –

''स्वस्ति पाणिनये तस्मै यस्य रुद्रप्रसादतः।

आदौ व्याकरणं काव्यमनु जांबवतीजयम्।।''

इसके आगे राजशेखर न पाणिनी की उपजाति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जैसे उद्यान की शोभा जाति (चमेली) के फूलों से होती है, उसी प्रकार पाणिनी के काव्य की श्शोभा उनकी उपजातियों स बढ़ी है –

''स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः ।

चमत्कारैकसारसाभिरुद्यानस्येव जातिभिः।।''

सदुक्तिकर्णामृत में उद्धत एक पद्य में दाक्षी पुत्र पाणिनी का नाम सुबंधु, कालिदास, भवभूति आदि कवियों के साथ लिया गया है। जाबंवतीजय महाकाव्य का नाम कहीं–कहीं पातालविजय भी मिलता है। अमरकोश के टीकाकार राममुकुट ने पाणिनी के जांबवतीयजय का यह श्लोकार्ध भी उद्धत किया है –

''पयः पृषन्तिभिः स्पृष्टा वांति वाताः शनैः शनैः।

नमिसाधु ने रुद्रट के काव्यालंकार की टीका मे पातालविजय से एक श्लोक उद्धत किया है। पुरुषोत्तम की भाषावृति तथा शरणदेव की दुर्घटनावृति में भी इस महाकाव्य का उल्लेख मिलता है। पं. बलदेव उपाध्याय के अनुसार आर्षकाव्यों के पश्चात जांबवतीजय या पातालविजय संस्कृत का प्रथम महाकाव्य हैं पाणिन के नाम से लगभग सत्रह पद्य प्राचीन सुभाषित संग्रहों में प्राप्त होते हैं, जिनसे विदित होता है कि पाणिनी एक उत्तम कवि थे। इन श्लोकों में सर्वाधिक संख्या उपजाति छंद में निबंध श्लोकों की है। क्षमेंद्र ने पाणिनी की उपजाति को विशेष सराहनीय माना है। यह महाकाव्य श्रीकृष्ण द्वारा पाताल में पहुंचकर स्यमंतकमणि का पता लगाना और जांबवती से उनके विवाह कथा पर आधारित रहा होगा यह अनुमान किया जा सकता है।

कात्यायन या वररुचि के महाकाव्य का उल्लेख महाभाष्यकार पंतजलि ने ''वाररुचं' काव्यम'' के नाम से किया है। वररुचि के नाम से भी अनेक पद्य सुभाषित संग्रहों में प्राप्त होते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि वररुचि के द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम 'स्वर्गारोहण' था।

कालिदास के रचे गये सात ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनमें से दो महाकाव्य हैं– रघुवंश और कुमारसंभव। दो खण्डकाव्य या गीतिकाव्य है– मेघदूत तथा ऋतुसंहार। तीन रुपक हैं– अभिज्ञानशाकुन्तलानाटक, विकमोर्वशीय त्रोटक तथा मालविकाग्नि मित्र नाटक। इसके अतिरिक्त कालिदास के नाम से अन्य अनेक काव्य मिलते हैं, पर ये परवर्ती कवियों ने कालिदास के नाम से लिखें अथवा कालिदास नाम के बाद में होने वाले अन्य किन्हीं कवियों ने, ऐसे काव्यों या ग्रंथों में श्रतुबोध, श्रृंगारतिलक काव्य, नलोदय काव्य आदि उल्लेखनीय है।

अश्वघोष के रचे दो महाकाव्य–बुद्धचरित तथा सौंदर्य तथा सौंदरनंद। इसके अतिरिक्त

अपूर्ण एवं खण्डित अवस्था में दो नाटक मिलते हैं। उनके अनेक शास्त्रीय ग्रंथ भी है। वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पादशास्त्र, सूत्रलंकार अथवा कल्पनामण्डितिका अश्वघोष के धर्म और दर्शन से संबध ग्रंथ हैं। उनके द्वारा रचित एक रुपक नाम ''शारिपुत्रकरण'' था।

कालिदास और अश्वघोष के महाकाव्यों में अनेकत्र पदावली और भावों की समानता मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि दोनों में एक अवश्य ही दूसरे का ऋणी है। जो विद्वान कालिदास को गुप्तकाल में मानते हैं, उकनी धारणा है कि कालिदास न अश्वघोष से भावों और अभिप्रायों को ग्रहण कर उन्हें और परिष्कृत और सुंदर बनाकर पुस्तुत किया। किंतु जो विद्वान कालिदास की स्थिति प्रथम शताब्दी ई.पू. में स्वीकार करते हैं, उनकी दृष्टि में अश्वघोष ही कालिदास के ऋणी हैं।

अश्वघोष के दोनों महाकाव्य नायक प्रधान है तथा नायक की आत्मसाधना पर केंद्रित हैं दोनों के नायक धीर प्रशान्त कहे जा सकते हैं। दोनों का लक्ष्य पाठकों को धर्म के प्रति उन्मुख करना हैं। दोनों में प्रतिनायक का चरित्र अनुपस्थित हैं। नायिकाओं को दोनो में पृष्टभूमि में रखा गया है, वे प्रायः विलाप करने के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण भूमिका कथा में नही निभाती। धर्म विषयक गंभीर विमर्श दोनों महाकाव्यों को संस्कृत महाकाव्य साहित्य में अलग पहचान देता है।

महाकवि बुद्धघोष का समय पांचवी–छटी शताब्दी है। ललितविस्तर तथा बुद्धचरित महाकाव्य में निरुपित भगवान बुद्ध के जीवन का चित्रण उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्तिपर्यन्त इस महाकाव्य में किया है। कुप्पु स्वामी शास्त्री के अनुसार पद्यचूड़ामणि कार बुद्धघोष अट्ठकथाओं के लेखक तथा प्राक्ष्यात दार्शनिक बुद्धघोष से भिन्न हैं और वे भारवि, भामह तथा दंडी के पूर्व और कालिदास के पश्चात हुए। पद्यचूणामणि में दस सर्ग तथा 641 पद्य हैं। इसके नायक बुद्ध हैं तथा नायिका के चरित्र का इसमें प्रायः अभाव है। मार को प्रतिनायक के रुप में कवि ने चित्रित किया है।

इस प्रकार संस्कृत महाकाव्य का उदय रामायण और महाभारत नामक दो आर्ष काव्यों की परंपरा में हुआ और कालिदास, अश्वघोष तथा बुद्धघोष जैसे महाकवियों की श्रेष्ठ रचनाओं में उसका स्वरुप और भी परिष्कृत रुप में प्राप्त होता है। इस प्रकार ईसा पूर्व की पांचवी शताब्दी से आरंभ करके ईसा की पांचवी श्शती तक के लगभग एक सहस्त्र वर्ष के समय को हम इस दृष्टि से संस्कृत महाकाव्य का स्थापना काल कह सकते हैं। इस काल में महाकाव्य की भावी समृति की दिशाएं उन्मीलित हुई।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

बैगा विकास प्राधिकरण का जनजातीय आर्थिक विकास में योगदान

प्रदीप कुमार द्विवेदी
शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र)

''अनुसूचित जनजाति'' भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रयोग की गई एक संवैधानिक शब्दावली है। आदिम बैगा जनजातियों को अनुसूचित करने का पहला प्रयास 1931 की जनगणन में किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 'पिछड़ी बैगा जनजातियों' के रूप में इनका नामोल्लेख मिलता है। 1936 मं ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तत्कालीन प्रांतों असम, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत और बरार की कुछ बैगा जनजातियों को ''पिछड़ी बैगा जनजातियों'' की श्रेणी में रखा गया था। डॉ. घुरिये ने इनके लिए ''अनुसूचित जनजाति'' नाम प्रस्तावित किया था जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। जनजाति मानवीय समाज का वह वर्ग है जो आज के इस सभ्य समाज में भी मानव के आदिकाल को चित्रित करता है। जनजाति समुदाय का मानव इस आधुनिक समाज में अपने पिछड़ेपन के कारण 'आदिमानव' के रूप में जाना जाता है। अत्याधिक प्रगतिशील समाज के सापेक्ष सामाजार्थिक रूप से स्थिर इस समाज को अपनी विशेषताओं के अनुरूप प्राक्साक्षर एवं प्राक्औद्योगिक भी कहा जाता है। जनजाति एक निश्चित भू–भाग में निवास करते हैं, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं, आदिकालीन धर्म प्रथा और परंपरा को मानते हैं तथा आदिकालीन आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत निवास करते हैं। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार ''जनजाति कई परिवारों या परिवार समूह का ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलता है, जो एक सामान्य भू–भाग पर रहने का दावा करता है और जो हमेशा अन्तर्विवाह नहीं करता, चाहे प्रारंभ में करता रहा हो।''[2]

मध्यप्रदेश बैगा जनजातियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 15316784 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। राज्य में बैगा जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत झाबुआ जिले में है जहाँ कि 86.85 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय है, जबकि सबसे कम जनजातीय प्रतिशत भिण्ड जिले में है जो जिले की कुल जनसंख्या का केवल 0.5 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से गोंड, भील, बैगा, सहरिया, भारिया, कोरकू, बंजारा, अगरिया, कोल, पनिका, पारधी इत्यादि जनजातियाँ निवास करती हैं। जनजातियाँ अधिकतर अपने पुराने रीति–रिवाजों के अनुसार जीविकोपार्जन का साधन अपनाए हुए हैं। ये सदियों से मुख्य धारा से अलग रहते रहे हैं। अतः बहुत सी सामाजिक कुरीतियों, आडम्बर, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास एवं मान्यताएँ आज भी फैली हुई हैं। इन कारणों से विभिन्न प्रकार की समस्याएँ इन्हें घेरे रहती हैं। जीविकोपार्जन के वर्षों पुराने साधन आज बढ़ती जनसंख्या एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। साथ–ही–साथ मुख्य धारा से कटे होने से विकास की रोशनी भी उन तक उस प्रकार नहीं पहुँच सकी जिस प्रकार पहुँचनी चाहिए। अतः विभिन्न प्रशासनिक योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल सका। ऐसी स्थिति में उनके बीच व्यापारियों, सूदखोरों, सत्ता के दलालों और असामाजिक कार्यकर्ताओं को घुसपैठ करने का पूरा अवसर मिला। मैदानी क्षेत्रों में व्यापारियों और सूदखोरों की पहुँच ने आदिवासियों की आर्थिक स्वतंत्रता में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी और व्यापारियों और सूदखोरों का अधिकार बढ़ता गया। धीरे–धीरे बाहरी व्यक्तियों ने बैगा जनजातियों की थोड़ी बहुत कृषि भूमि छलकपट से अपने अधिकार में कर ली और आदिवासी इनके हाथों शोषित होने को बाध्य हो गए।[3]

[2]. शिवकुमार तिवारी, ''मध्यप्रदेश की जनजातियाँ'' म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2005.

[3]. ए.डी. पाटिल, ''भील जनजीवन और संस्कृति'', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2004.

स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद आदिवासी विकास शासन की एक सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गए। ऐसे क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों ने भी अपना प्रचार करना प्रारभ किया। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी शिक्षा–स्वास्थ्य आदि पर विशेष जोर दिया और वे सफल भी रहे। ईसाई मिशनरियों के प्रचार–प्रसार के कारण वे बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने में भी सफल रहे। आदिवासी जहाँ एक तरफ पिछड़ी खेती करने, वहीं दूसरी तरफ किसी प्रकार के अच्छे किस्म के बीज और खाद नहीं करते। कम वर्षा की स्थिति में खेती में बहुत कम पैदावार होती है और ऐसी स्थिति में आदिवासी के समक्ष पेट भरने की समस्या खड़ी हो जाती है। आदिवासी समुदाय में मद्यपान का खूब रिवाज है। यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। मद्यपान का उनके विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में प्रचलन है। अतः मद्यपान कोई वर्जित वस्तु नहीं है, बल्कि इसे मान्यता प्राप्त है। मद्यपान आदिवासियों में विभिन्न प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है। आदिवासियों में शिक्षा का अभाव होने से वे विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार होते हैं। प्रशासन की पहुँच के साथ–साथ आदिवासी प्रचलित नियम और कानून के घेरे में आ गए हैं। इन चीजों के यदि कुछ अच्छे परिणाम रहे तो कुछ ने बैगा जनजातियों को बुरी तरह प्रभावित किया। इनमें से अधिकांश अधिनियमों ने तो उनके ऊपर काफी विपरीत प्रभाव डाला है। साथ–ही–साथ आदिवासियों को स्वयं की न्याय व्यवस्था के स्थान पर नई न्याय व्यवस्था की स्थापना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर रोक, बाजार में नई–नई चीजों ने इनकी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाला है। अन्य लोगों के साथ यौन संबंधों से उत्पन्न बीमारियों ने पूरे जनजाति समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया है। विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों और बुराइयों के कारण आज आदिवासियों के समक्ष निम्न समस्याएँ मुख्य हैं:–

1. ऋणग्रस्तता 2. भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण 3. शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर रोक 4. वन प्रबंध से उत्पन्न समस्याएँ 5. स्वास्थ्य समस्याएँ 6. आवास समस्या 7. पेयजल व्यवस्था 8. शिक्षा का अभाव 9. संचार व्यवस्था का अभाव 10. औद्योगीकरण। भारतीय बैगा जनजातियों की अर्थव्यवस्था आज भी मुख्यतः आदिकालीन व्यवस्था का ही आंशिक बदला हुआ स्वरूप है। यद्यपि आदिवासी आवश्यकतानुसार जीविकोपार्जन हेतु कई कार्यों पर निर्भर हैं फिर भी समुदाय विशेष की अर्थव्यवस्था कार्य विशेष पर आधारित है। यद्यपि वह आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी सम्पन्न कर लेता है। यदि आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करें तो आदिवासियों के आय के मुख्यतः निम्न स्त्रोत हैं:– 1. जंगल में भोजन 2. झूम खेती 3. स्थायी खेती 4. पशुपालन 5. शिल्पकारी 6. औद्योगिक एवं कृषि मजदूरी।

प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित बैगा जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु असंख्य योजनाएँ बनाई एवं लागू की गई हैं, इसके उपरांत भी यह आरोपित है कि बैगा जनजातियों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। जनजातीय विकास की समस्या आज न केवल म.प्र. राज्य व भारत देश में अपितु विश्व के अग्रणी संगठन यथा– संयुक्त राष्ट्र संगठन (न्छव्) एवं विश्व बैंक के लिए भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। अतएव बैगा जनजातियों के आर्थिक विकास की समस्या और उसके समाधान में शासकीय योजनाओं की भूमिका पर शोध–अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। ऐसे अध्ययनों की आज महती आवश्यकता अनुभव की जा रही है ताकि शोध–अध्ययन से यह ज्ञात किया जा सके कि विभिन्न शासकीय योजनाओं की असफलता के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं इसके साथ ही योजनाओं को सफल साध्य बनाने हेतु उपयोगी व सार्थक उपायों को सुझाव के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत विषय पर शोध–अध्ययन की महती आवश्यकता है।

''बैगा विकास प्राधिकरण का जनजातीय आर्थिक विकास में योगदान यह विषय इतना गंभीर, प्रासंगिक एवं औचित्यपूर्ण है डिण्डौरी जिला वनांचल तथा जनजातीय जनसंख्या बहुल जिलों में से एक है और बैगा जनजातियों के लोग वनांचलों में निवास करते हैं। स्वतंत्र भारत के 63 वर्ष पश्चात् भी जनजातीय लोग समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। अतः अब यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि शासकीय योजनाओं का जनजातिय लोगों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? उनके

आर्थिक विकास में शासकीय योजनाओं का क्या और कितना योगदान है? इन समस्त बातों का पता लगाना और समस्याओं के कारणों व निदानों को खोजने की दृष्टि से अकादमिक स्तर पर इस प्रकार के शोध–अध्ययन का अत्याधिक महत्व है। चूंकि डिण्डौरी जिला आदिवासी अर्थात् अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बहुल होने के साथ ही साथ मध्यप्रदेश राज्य के मध्य में स्थित है इसलिए बैगा जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु संचालित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यपद्धति को समझने, उनके योगदान का अवलोकन करने एवं उनकी समस्याओ से अवगत होने की दृष्टि से यह एक आदर्श शोध–क्षेत्र है और इस पर शोध–कार्य करना भी निःसंदेह आदर्श ही सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह आई.जे. एवं शर्मा जे.एस. – 'तराई आदिवासी आर्थिक विकास की समस्याएँ'; वर्ष 1970, पृ.क्र. 214, कृषिक आर्थिक विभाग, उ.प्र. कृषि वि.वि. पंतनगर (नैनीताल) त्रिपुरा में जनजातीय विद्रोह एवं ग्रामीण विकास, वर्ष 2000.

2. गोस्वामी पी.सी. एवं साहिया पी.डी. – 'आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास की समस्याएँ'; वर्ष 1970, पृ.क्र. 140, (उ.प्र., भारत में पूँजी अर्थव्यवस्था अनुसंधान केंद्र) असम कृषि वि.वि. जोरहाट (असम).

3. चक्रवर्ती एस.के. – 'बाध्य अकाकारण द्वारा आदिवासी ग्रामों का विकास एक समस्या का अध्ययन'; वर्ष 1970, पृ.क्र. 811.

4. गोस्वामी पी.सी. एवं साहिया पी.डी. – 'आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास की समस्याएँ'; वर्ष 1970, पृ.क्र. 140, (उ.प्र., भारत में पूजी अर्थव्यवस्था अनुसंधान केंद्र) असम कृषि वि.वि. जोरहाट (असम).

5. तिवारी शिव कुमार – 'मध्यप्रदेश में जनजातियों का अध्ययन'; वर्ष 1984, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ.क्र. 80.

6. डॉ. अम्बेडकर बाबा साहेब भीमराव : स्टेप्स एण्ड माइनोरिटीस; वर्ष 1985, पृ.क्र. 23.

7. पालीवाल चन्द्र मोहन : 'आदिवासी हरिजन आर्थिक विकास बस्तर जिले के संदर्भ में'; वर्ष 1986, नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली, 1986.

8. खान एम.जेड. एण्ड एम.ई. यादव : 'केरल में आर्थिक विकास के जरिए बदलता जनजातीय दृश्य', 1990 पृ.क्र. 75.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

IMPACT OF PRICING STRATEGIES ON PATIENTS SATISFACION IN RURAL AREA

Dr. Priti Singh, Professor, IIPS DAVV, Indore
Shikha Kumrawat, Research Scholar, Barwani

Abstract :- India is a price sensitive country. Every customer gave its first preference to price while approaching to product or service. Especially when we are tackling our rural market, pricing strategies become crucial as it is only element that going to capture market and can take competitive advantage. But when the services, relate to hospital industry is concern, this characteristics show deviation in rural market also. As hospital industry is only service industry which is highly people oriented. In this research paper we study the impact of pricing strategies of different private hospital which is measured by their patient's satisfaction especially in rural area. In this study both dependent and independent variables are present. Dependent variable is patient satisfaction and independent variable is pricing. In this research data is collected from 200 in-patients from 5 private hospitals of Barwani district. The data collected is through questionnaire and analyzed results are presented in the paper.

Keywords :- Pricing strategies, competitive advantage, patient's satisfaction.

Introduction :- We are living in a country whose approx 67% population (Rural population) belong to rural area. When such huge mass is rural, then it is important for any industry to understand the purchase behavior and expense power of people

The most basic feature of such market is Price sensitivity as they have limited resource so they want much in that limits itself. That is why both product and service industry tries to capture market on the basis of establishing most suitable Pricing Strategy.

It can be easy for any other service industry like hotel, education, tours and travel to lure the customers by providing different schemes for different types of services in it.

But when we tackle hospital industry the scenario is somewhat different than other service sectors. Hospital industry is one of most people oriented and crucial sector as people's trust and hopes are key element in their well being.

Hospital industry now-a-days have emerged as a complex sector especially in our country where it is performing on three different levels (Bhat, 1993) i.e.

- Public hospitals.
- Private hospitals
- Informal Private hospitals (clinics, dispensaries etc)

Almost all the facilities are available in Govt. hospitals yet people of even rural area approach private hospitals more as compare to government hospitals. The recent example is of Bihar where large rural population is approaching to Delhi to get basic treatment which they can easily get in Bihar itself. Such concern towards health related issues make health providers more conscious.

It makes industry more active to penetrate and develop in this sector. To sustain in present market and also to obtain competitive advantage, most marketers utilize Pricing strategy for this concern, that means by establishing and implementing effective Pricing strategy they can capture large market share. For this purpose different types of pricing strategies are used by marketers to enhance their profit like.

- Comparative Pricing
- Discount Pricing

- Image Pricing
- Others

But this strategy can only be fruitful if they can make their customer satisfy by their services in limited resource as if they fail, then customers have options of public hospitals. So, it is very important to set such strategies of pricing which can gain competitive advantage along with customer satisfaction.

In our study customers are patients whose satisfaction matters a lot than any other service user. Patient's satisfaction is always subject to unpredictable as because of the situation in which they are going through and also we can just measure their level of expectation.

So, we see two variables are working here i.e. one is Pricing Strategy and other one is customer (Patient's) satisfaction.

Pricing Strategy :- For pricing strategy it was said that "if effective product development, distribution and promotion sow the seeds of organizational success; efficient pricing strategy is the harvest."

While effective pricing strategy can never compensate for poor execution of the first three elements, ineffective pricing can surely avoid those efforts from resulting in financial success. (Nagle & Holden, 2012)

This means that Pricing decisions are most important for failure and success of any organization. Though it is essential but it is dynamic in nature as pricing is an independent factor and other variables work along with this variables. As pricing affecting factors changes, other component i.e. customer satisfaction have to respond along with it.

Patients Satisfaction :- Patient's satisfaction can be achieved by filling gaps between expectation and perceived service but in a very gentle way. Satisfaction usually depends on Pricing of any services as how much they pay gives them that much types of satisfaction. But when we observe this behavior in hospital industry it shows some deviation from traditional concept of price sensitivity.

As in rural areas also people in spite of how much they earn they want to be treated in private hospitals due to many reasons such as new and updated technologies of treatment, availability of doctors all the time, providing specialist doctors or staff on demand etc. These features make them to move towards private hospitals.

But it said that "nothing is free". Private hospitals charge more than that of public units because of these amenities they provided. So both variables work simultaneously here. To observe this impact of pricing on patient's satisfaction of rural area a series of questions is asked to out-patients to know their experience.

Objective of study :- The major objective of this research is to throw light on the anomalous behavior of rural market towards pre defined marketing mix concepts of present era. Considering one element ie pricing as centre we are observing different levels of satisfaction in hospital sector

Research methodology :- To understand the behavior of patients of rural area, Random sampling is done to collect data. The sample is collected from out-patients of 5 private hospitals of Barwani district as it is surrounded by rural area and most of the rural population comes to Barwani for the treatment. The technique used for data collection is semi interview type as mostly people are unable to fill the questionnaire due to literacy or situational problems. So questions are narrated to them to get their response. Total 200 responses are collected and this data is analyzed to get interpretation .

Data Collection :- Some of the interpretations which are obtained after data processing are –

The income group people belong :-

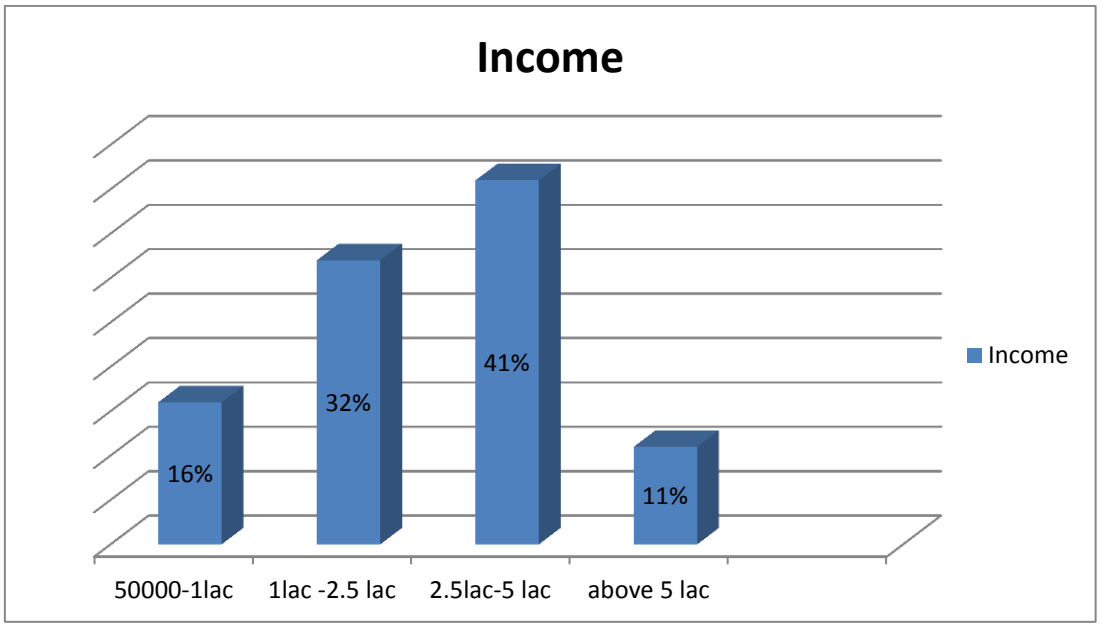

Inference- About 89% of people has their annual income less than 5 Lac.

Their first preference to get treatment :-

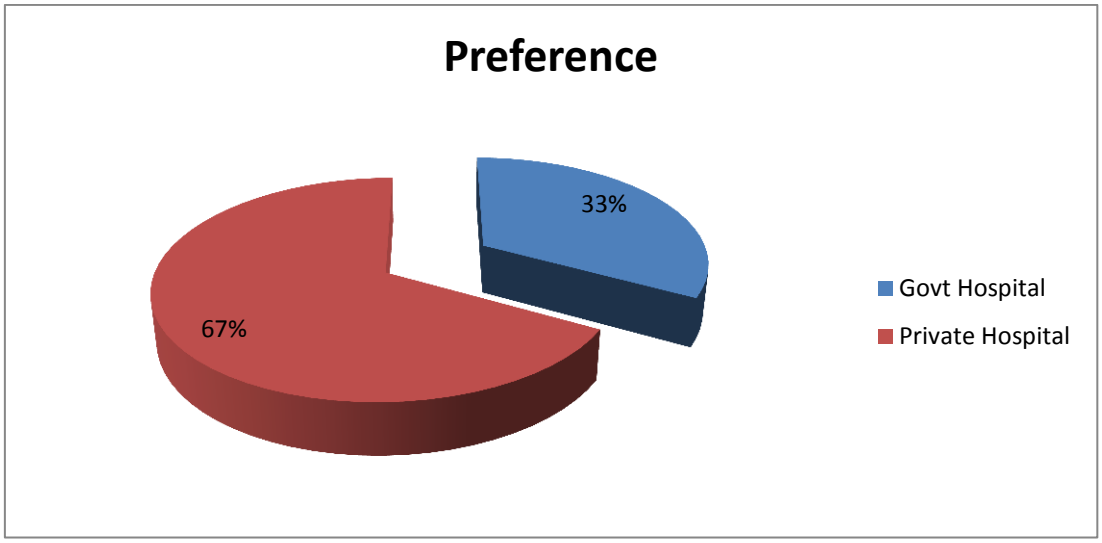

Inference- about 67% respondent prefer private hospitals as their first preference over public units.

The perspective towards fees of doctors/treatment of private hospitals as per their services :-

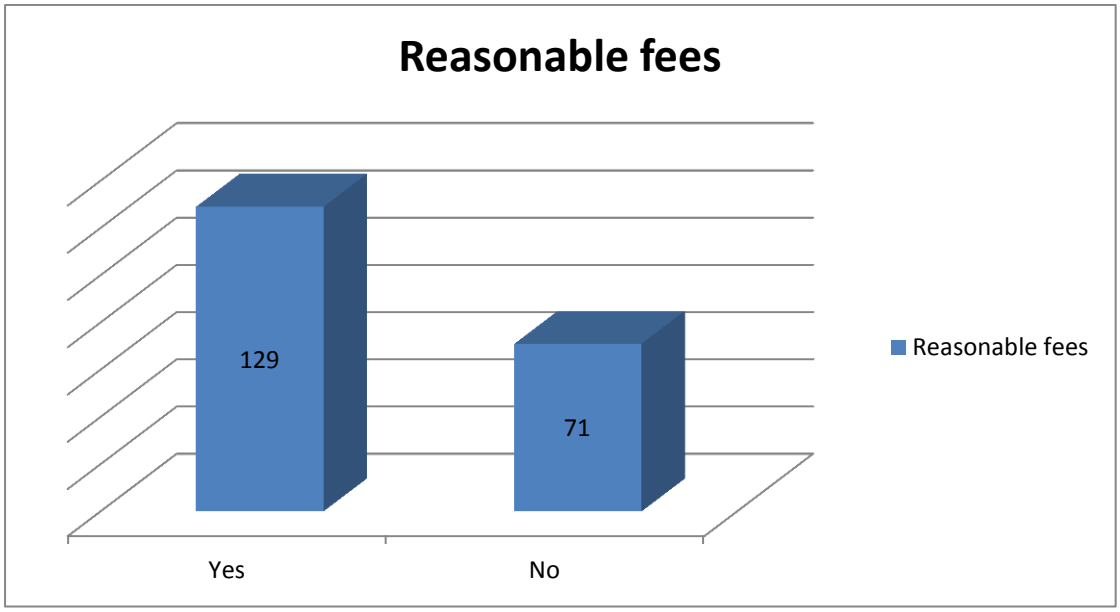

Inference- 64.5 % respondent recorded that the fees is charged according to the services provided by private hospitals not more than that.

Reasons behind choosing private unit over public sector unit :-

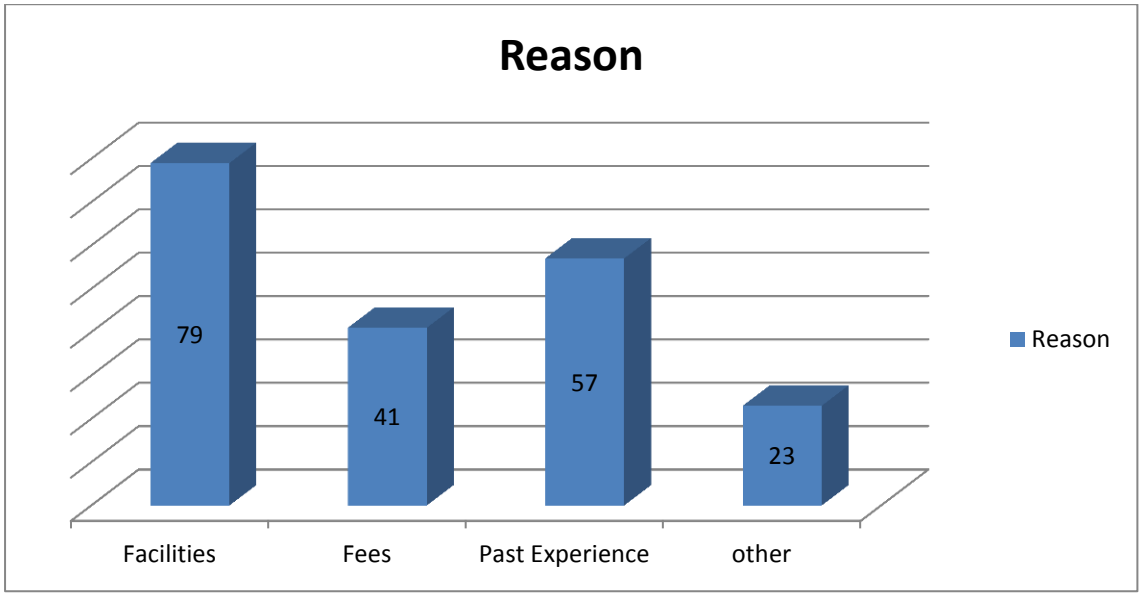

Inference- about 79 respondents say that they choose private hospitals because of its different facilities of treatment. After pass the second preference, fees is taken into consideration by 41 respondents

Interpretation :- From the data we obtain it can be seen that though prices of different facilities for treatment is more comparatively to public hospitals yet people who are not earning above5 lac gives their first preference to private hospital. It is noted here that they generally prefer private hospital for chronic treatment not for the acute one.

It is also interpreted that in spite of their low income they believe better treatment is first priority than other basic requirement. So they choose private hospitals also if they feel treatment in public units won't be as good as private one.

They are ready to take credits also for this purpose if they feel it is worthy for it.

The study gives various reason of why even low income person chooses more charged health units i.e. because of its treatment facilities also because of their or their related ones past experience of private units. Fees also take considerably share of about 41 respondent said that they do not think they are overcharged for something. They feel that little less will be charged in public facilities but that will risk their trust. So they are willing to pay some more fees in order to get trustworthy treatment.

The ultimate reason to spend on any private unit here is to get maximum satisfaction in any terms such as reliability, communication, friendly consultation and more over quick better of their pateints.

Limitation :- Some of the limitations of research are as follows-

1. The research is focused on only one component of marketing mix, while other elements have equal scope in rural area are not studied.
2. It is confined to a one district only due to availability of resources.
3. It can be further analyzed on different parametric and non parametric measures.

Conclusion :- This study shows that Pricing is crucial factor but when it comes to hospital industry even pricing can be ignored at some limit. Even population living in rural area are willing to pay more but not compromising in health issues.

Although we can't say that pricing does not make difference as data obtained is not fully one sided. Still people have much approach towards public unit.

But this study only represents rural population of one district that means may be most of semi urban population will prefer private ones. This led to scope for further research.

The key result is that private health care sector has great scope in this area if they formulate some better pricing strategy which would be beneficial for both users and providers as the market segment of rural area shows much potential and it would definitely have positive impact on its customer's satisfaction.

Bibliography :-

1. Bhat, R. (1993). The private/public mix in health care in India. *Health policy and Planning*, (pp. 43-56).

2. Nagle, T., & Holden, R. (2012). *The Strategy and tactics Of* Pricing. (E. Cliff, Ed.) NJ: Prentice Hall.

3. (2015). *Rural population.* World Bank. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator.

4. Palmer,A(2011). Principles of Services Marketing(6th ed).UK:McGraw Hill Publishing Company.

5. Lovelock,C.(2011). Services Marketing People, Technology, Strategy(6th ed.).Charlotte Prentice Hall.

6. Marlowe, D. Pricing Strategies for Health care services, Stratgic marketing Concepts,Ellicott City,Maryland.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

भाषा–व्यवस्था और समाज भाषाविज्ञान : एक अध्ययन

बृजेश श्रीवास्तव
शोधार्थी, हिंदी एवं भाषाविज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

भाषा व्यवहार मात्र व्याकरण द्वारा निर्दिष्ट नहीं होता वरन् सामाजिक सन्दर्भों एवं मूल्यों द्वारा भी निर्धारित होता है। यही नहीं कभी–कभी संदर्भ की जानकारी के बिना प्रेषित सन्देश को समझना भी कठिन होता है। संप्रेषण संघटना के तात्कालिक संदर्भ को जानने से पूर्व उस समाज विशेष की संरचना और उसके सदस्यों के मध्य घटित अन्तःक्रियात्मक व्यवस्था के नियमों को समझना आवश्यक होता है। ये नियम हमारे व्यक्तिगत चयन का प्रश्न नहीं हैं वरन् समाज विशेष के सदस्य होने के नाते हमें इनका पालन करना पड़ता है। इस प्रकार केवल भाषा की संरचना का ज्ञान व्यक्ति को एक सफल वक्ता या श्रोता नहीं बनाता है वरन् उसे सामाजिक प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने समाज भाषाविज्ञान को परिभाषा में बांधने का प्रयास करते हुए निम्नांकित विचार रखे–

एस. के. वर्मा एवं कृष्ण स्वामी के अनुसार&"Sociolinguistics is the study of lanugage in relation society: studies the interactions between language as a network of relations and society as a network of relations." [4]

रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार–''समाज भाषा विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन का वह क्षेत्र है, जो भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले हर प्रकार के सम्बन्धों का अध्ययन विश्लेषण करता है।''[5]

भाषाविद् हुडसन के शब्दों में–"We can define socilinguistics as the study of l anguage in relations to society.....(it) is party empirical and party theoretical-party as matter of going out and amassing bodies of fact and partly of sitting back and thinking." [6]

समाज भाषाविज्ञान के अंतर्गत भाषा का अध्ययन विश्लेषण समाज से उसके अंतःसंबंधों के आधार पर किया जाता है। समाज एवं भाषा की सह–संकल्पना है। इसका उद्देश्य इस तथ्य की व्याख्या करना है कि किसी भाषा के वक्ताओं को क्या जोड़ता है और किस आधार पर उन्हें दूसरी भाषा के मातृभाषियों से विकलग किया जा सकता है।

उदय नारायण सिंह के मतानुसार– "Soiolinguistics unravels,..... the misttery and teh alchemy of language synthesis and anlaysis."

1960 के लगभग समाज भाषा विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। इसका यह तात्पर्य नहीं है, वास्तव में बोलियों के अध्ययन की एक अत्यंत प्राचीन परम्परा मिलती है। साथ ही शब्द–अर्थ का संस्कृति से संबंध जैसे विषयों पर भी आरम्भ में चर्चा हुई। 1934 में जार्ज मीड ने भाषा को 'सामाजिक नियंत्रण के साधन' के रूप में परिभाषित किया। 1949 में लिण्ड स्मिथ ने 'सामाजिक मनोविज्ञानों' नामक पुस्तक में भाषा व्यवहार की मनोवैज्ञानिकों भूमिका के साथ–साथ उसके सामाजिक पक्ष की भी व्याख्या की।

1957 में प्रजनक व्याकरण के संस्थापक भाषाविज्ञान के क्षे में नवीन क्रांति भाषिक क्षमता (Competence) और भाषिक व्यवहार (Competence) नामक पारिभाषिक युग्मों की

[4] प्रो. कविता रस्तोगी–सम सामायिक अनुप्रयुक्त भाग विज्ञान, पृ. 27
[5] प्रो. कविता रस्तोगी–सम सामायिक अनुप्रयुक्त भाग विज्ञान, पृ. 28
[6] प्रो. कविता रस्तोगी–सम सामायिक अनुप्रयुक्त भाग विज्ञान, पृ. 28

संकल्पना प्रस्तुत की। भाषिक क्षमता व्यक्ति के मस्तिष्क में पूंजीभूत नियमों का एक समुच्चय है जिसे उसका भाषा ज्ञान कह सकते हैं और जिसकी सहायता से वह भाषा व्यवहार (नवीन वाक्यों को बोलना और समझना) करता है। भाषा व्यवहार भाषिक ज्ञान का किसी निश्चित स्थान और समय पर किया गया निश्चित प्रयोग है। चॉमस्की ने भी भाषिक क्षमता को ही अपने अध्ययन का लक्ष्य बनाया। समाज भाषाविज्ञान न भाषिक खमता के स्थान पर 'संप्रेषण क्षमता' (Communicative-competence) को अपने अध्ययन का क्षेत्र चुना। भाषिक व्यवहार के सामाजिक निर्धारक, वक्ता–श्रोता के अंतःसम्बन्ध आदि इसके अंतर्गत आते हैं। समाज में प्रभावशाली ढंग से सम्प्रेषण के लिए वक्ता को किन बिन्दुओ का ज्ञान आवश्यक है, उसे ही चॉमस्की सम्प्रेषण क्षमता का नाम देते हैं।

समाज भाषाविज्ञान के समानान्तर 'भाषा का समाज शास्त्र' (Socioloy of language) नामक संकल्पना का अध्ययन भी किया जा रहा है। किसी सामाजिक समुदाय की भाषिक अभिवृत्ति एवं अस्मिता, भाषा का मानक स्वरूप, राष्ट्रभाषा की व्यवस्था एवं आवश्यकता भाषा के सामाजिक आधार आदि अनेक विषय समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। इन्हीं विषयों का विश्लेषण एवं व्याख्या जब भाषिक के स्थान पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर की जाए तब वह 'भाषा का समाज शास्त्र' कहलाता है। स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत शोधकर्त्ता कोई भी शोधकर्त्ता समाज का अध्ययन भाषा से उसके संबंधों के आधार पर किया है।

फिशमैन के शब्दों में – "Socioloogy of language examins the interaction between..... the use of language and and te social organization of behaviour." [7]

भाषाविद हुडसन दोनों के लक्ष्य भिन्न मानते हुए उनके मध्य प्राप्त समानता की स्थिति को स्वीकार करते हैं। समाज भाषाविज्ञान भाषा को सामाजिक प्रतीकों की सम्प्रेषण व्यवस्था के रूप में देखता है। एक वास्तविक विषयरूपी भाषा इसी यथार्थवादी मत में रहने वाले लोगों के अनुभव एवं भावों को व्यक्त करती है। कह सकते है कि भाषा एवं समाज एक दूसरे के साथ इतनी जटिलता से गुँथे हैं। कि एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन संभव नहीं है। और इनके सम्मिश्रण से समाज भाषाविज्ञान के विषय क्षेत्र का विकास होता है। ध्यान रहे कि जहाँ एक भाषाविद् का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि–

- भाषा के प्रमुख घटक कौन से हैं?
- वृहत्तर इकाइयों के निर्माण और प्रजनन में इन घटकों की क्या भूमिका है
- इन घटकों की व्यवस्था का भाषिक संप्रेषण व्यवस्था में क्या स्थान है?
- वहाँ एक समाजशास्त्री निम्नलिखित प्रश्नों के समाधान खोजता है–
- समाज के प्रमुख घटकों का स्वरूप क्या है?
- घटकों द्वारा निर्मित वृहत्तर इकाईयाँ कौन–कौन सी हैं?
- सामाजिक व्यवहार में इन घटकीय व्यवस्थाओं का योगदान क्या है?

इन दोनों से एक समाजभाषाविद वास्तविक भाषा और यथार्थवादी समाज का अध्ययन विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है–

- रूपात्मक एवं समाज–सांस्कृतिक संघटना का सम्मिश्रण कैसे होता है?
- सामाजिक संबंध एवं व्यवस्थाएँ किस प्रकार भाषा व्यवस्थाओं को निश्चित स्वरूप प्रदान करती है?
- भाषा अभिरचनाएँ किस प्रकार सामाजिक संबंधों और व्यवस्थाओं को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है?

भाषा और समाज के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध मिलता है। भाषा समाज में जन्म लेती है और समाज ही उसका व्यवहार क्षेत्र है। यही नहीं भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विविध भाषिक समुदायों के निवासी इस दृश्य जगत का अपने–अपने ढंग से

[7] उदय नारायण तिवारी : हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, दूसरा संस्करण 1976

प्रत्यक्षीकरण करते हैं, भिन्न–भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं और इस जगत के विषय में उनकी अलग–अलग धारणाएँ और विचारधाराएँ हैं, जिनकी अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं की संरचनात्मक व्यवस्था में परिलक्षित होती हैं। यही नहीं एक ही भाषा–भाषी समुदाय में रहने और समान भाषा का प्रयोग करने वाले भी सदैव एक प्रकार से भाषा नहीं बोलते हैं। एक ही बात/भाव को एक ही भाषा में भिन्न–भिन्न तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे–

1. कितना बजा है?

2. क्या समय हुआ है?

3. तुम्हारी घड़ी कितना समय बता रही है?

4. बेटा, देखो जरा घड़ी की बड़ी और छोटी सुईयाँ कहाँ हैं?

5. कित्ता टैम हुआ है?

स्पष्ट है कि स्थान, प्रयोजन, सन्दर्भ के आधार पर एक ही भाषा के स्वरूप में अंतर मिलता है। समाज भाषाविज्ञान समाज–सांस्कृतिक प्रांचलों (पैरामीटर) के आधार पर इन विविधताओं का अध्ययन–विश्लेषण करता है। इस प्रकार भाषा तथा समाज के अंतःसम्बन्धों के समस्त पक्षों का अध्ययन सामाजिक समूहों की पहचान, मानक एवं अमानक भाषा रूप, भाषा के स्तर एवं सामाजिक विभेद, बहुभाषिकता का सामाजिक आधार आदि विषय समाज भाषाविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। जैसे–समाज भाषाविज्ञान (समाज शास्त्रीय), मनोभाषाविज्ञान (मनोविज्ञान), शैली विज्ञान (साहित्य) तथा नाजृति– भाषा विज्ञान (एथानोलिंग्वस्टिक्स, नृजाति विज्ञान) आदि। इनमें 'समाज भाषाविज्ञान पर यहाँ अत्यंत संक्षेप में विचार किया जा रहा है। यों इसे तथा कुछ अन्यों को आगे अलग–अलग लिया जा रहा है।

समाज भाषाविज्ञान (Socio-linguistics) –समाज के परिप्रेक्ष्य में भाषा का अध्ययन समाज भाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें भाषा और उसे बोलने वाले समाज के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन–विश्लेषण करते हैं। भाषा विज्ञान से इसका अंतर कई आधारों पर दिखाया जा सकता है। जैसे–

(क) शुद्ध भाषाविज्ञान भाषा को भाषिक प्रतीक के रूप में लेता है, किन्तु समाज भाषा विज्ञान उसे सामाजिक प्रतीक रूप में। (ख) भाषाविज्ञान में भाषा की सबसे बड़ी इकाई प्रायः 'वाक्य' मानी जाती रही है, किंतु समाज भाषाविज्ञान 'प्रोक्ति' को यह स्थान देता है। (ग) भाषाविज्ञान से प्रायः अलग रखकर भाषा की संरचना पर विचार करता है, किन्तु भाषाविज्ञान उस अध्ययन को अधूरा मानता है और उसके अनुसार समाज के परिप्रेक्ष्य मे भाषा का अध्ययन ही भाषाविज्ञान वेक्ताओं की दृष्टि में समाज भाषा विज्ञान ही वास्तविक भाषाविज्ञान है। (घ) मानक भाषा, अमानक भाषा तथा भाषा और बोली में अंतर दिखाना भाषाविज्ञान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यदि मात्र संरचना की बात लें (जिस पर भाषाविज्ञान का बल है) तो मानक भाषा अमानक भाषा एवं भाषा तथ्य बोली में कोई भी अंतर नहीं है। यह अंतर समाज भाषाविज्ञान ही दिखा सकता है और दिख पाता है।

समाज भाषा विज्ञान के प्रति इसके विद्वानों के दृष्टिकोण पूर्णतः एक नहीं है – (क) फिशमैन आदि इसके भाषा का समाज शास्त्र मानते हैं। राजभाषा किसे बनाएँ, भाषा का मानकीकरण कैसे करें तथा उसे आधुनिक कैसे बनाएँ जैसे बातों पर इस दृष्टिकोण वालों का अधिक बल होता है। (ख) गम्पर्ज तथा कर्ग्यूसन आदि समाज भाषाविज्ञान को समाजोन्मुख भाषाविज्ञान मानते हैं। ये भाषा को सामाजिक प्रतीक मानते हैं तथा भाषा के विषमरूपी रूप का जाति–वर्ग, धर्म आदि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। (ग) लेबॉव आदि समाज भाषाविज्ञान को ही वास्तविक भाषा विज्ञान मानते हैं तथा वास्तविक प्रयोग में प्राप्त विकल्पों को छोड़कर भाषा का एक आदर्श रूप मानकर मात्र उसकी संरचना का अध्ययन बहुत सार्थक नहीं है।

भाषा वेद को भली भाँति समझने के लिए भाषा–भाषी जनसमुदाय (Speech Community) की संकल्पना को जानना आवश्यक है। भाषा–भावी जन समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक भाषा या बोली का

प्रयोग करते हैं। हॉकेट के मतानुसार – "Each language defines a speech communiy: the whle set of people who communicate with each other either directly or indirectly via the common language".[8]

अमरीकी भाषाविद् ब्लूमफील्ड के शब्दों में, "A speech community is a group of people who interest by means of sppech".

आधुनिक समाजभाषाविद् लैबत की परिभाषा में साझे भाषिक व्यवहार के स्थान पर ज्ञान और अभिवृत्ति (व्यक्ति का रवैया/रुख) की साझेदारी को भाषा भाषी जन समुदाय की विशेषता माना गया। उनके अनुसार – The speech community is not defined by any marked agreement in the case, of language elements so much as by participation in a set of shared norms.

भाषा–भाषी जन समुदाय को कहीं सरल और कहीं जटिल आधार पर परिभाषित करने वाली उपर्युक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समुच्चय जो अंतः क्रिया के लिए समान भाषा या बोली या प्रयोग करें। भाषायी वैविध्य होने पर भी जिनके सदस्यों के मध्य सम्प्रेषण सम्भव हो और जिनके सदस्य एक प्रकार के सामाजिक नियमों, रीति–रिवाजों में बँधे हों। यही नहीं अपनी इन विशेषताओं के कारण जिसे अन्य भाषिक समुदायों से भिन्न ठहराया जा सके, उसे एक भाषा भाषी जन समुदाय कहा जा सकता है। एक समुदाय में व्यवहृत समस्त भाषिक रूपों को उस समुदाय का भाषिक भण्डार (Verbal repertoire) कहते हैं। इसके अंतर्गत भाषा के समस्त रूपों की गणना की जाती है। जिनकी सहायता से वक्ता समाज की विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न सामाजिक भूमिका निभाने में समर्थ होता है, जैसे–हिंदी भाषा–भाषी समुदाय के व्यक्ति जिन–जिन भाषाओं, बोलियों और शैलियों का प्रयोग करते हैं। उनका समुच्चय उनके भाषिक भण्डार का निर्धारण करता है।

अतः सामाजिक कार्यों को पूरा करने के उपरांत भी भाषा व्यक्ति के मस्तिष्क में अवस्थित रहती है। प्रसिद्ध समाजभाषाविद् लैबव ने इस बिन्दु पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा – "Language is not the property of the individual but of the community".

भाषाविद् रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव[9] ने भाषा और बोली के आधारभूत अंतर को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है–

1. भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है लेकिन बोली का क्षेत्र भाषा की तुलना में छोटा होता है।

2. सामाजिक प्रकार्य में स्वनिष्ठ एवं स्वायत्त होती है। लेकिन बोली किसी भाषा के अधीन एवं आश्रित रहती है।

3. साहित्य, शिक्षा, संचार, प्रशासन आदि क्षेत्रों में प्रयोग होती है, लेकिन बोली का प्रयुक्ति क्षेत्र सीमित होता है।

4. समाज में प्रतिष्ठा और प्रभुता की द्यातक होती है लेकिन 'बोली' समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती, यह आत्मीयता प्रदर्शित करती है।

5. इसका प्रयोग औपचारिक संदर्भों में किया जाता है लेकिन बोली का प्रयोग प्रायः अनौपचारिक संदर्भों में किया जाता है।

6. भाषा अधिक मानकीकृत होती है लेकिन बाली में सापेक्षतया अधिक विकल्प मिलता है।

7. भाषा अपनी विभिन्न बोलियों के प्रयोगकर्त्ताओं के बीच संपर्क भाषा का काम भी

[8] डॉ. सीताराम झा 'श्याम' : भाषाविज्ञान तथा हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण , बिहार ग्रंथ अकादमी, बिहार, 1985

[9] डॉ. रामदेव त्रिपाठी : हिंदी भाषा विज्ञान, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना 1985, पृष्ठ 22

करती है। लेकिन इसका प्रयोग बहुधा मातृभाषा के रूप में ही किया जाता है।

एक भाषा–भाषी जन समुदाय के वक्ताओं की भाषाओं में प्रयोग संदर्भ के कारण वैविध्य मिलता है। वे औपचारिक से लेकर अत्यधिक अनौपचारिक सभी संदर्भों में उस भाषा रूप का व्यवहार करते हैं। किसी विशिष्ट परिस्थिति में सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए वक्ता द्वारा प्रयोग की गई भाषा 'प्रयुक्ति' कहलाती है। हुडसन[10] के मतानुसार – "The term register is widely used in sociolinguistics to 'vuriesties according to use' in contruast with dialeets, defined as 'varieties according to user".

स्पष्ट है कि हुडसन प्रयोग के आधार पर प्राप्त रूप भेदों को 'प्रयुक्ति' तथा वक्ता के आधार पर प्राप्त रूप भेदों को 'बोली' की संज्ञा देते हैं। हैलिडे के अनुसार प्रयुक्ति भाषा की उन प्रयोगाश्रित विविधताओं को कहा जाता है जो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों अथवा विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा के रूपभेदों को प्रकट करती है। जीन एट्चियन का मानना है कि प्रयुक्ति भाषा की विशेषीकृत शैलियाँ है। जो भाषा प्रयोग परिस्थिति पर आधारित होती हैं। कह सकते हैं कि सामाजिक सन्दर्भों की विशिष्टता के अनुरूप भाषा मे विकसित व्यवहारपरक रूपभेद भाषा में विकसित व्यवहारपरक रूपभेद भाषा प्रयुक्ति निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हर भाषा में विज्ञान, विधि, व्यापार, विज्ञापन आदि के अपने–अपने विशिष्ट प्रयोग सन्दर्भ, शब्दावली और शैली होती हैं जो इन क्षेत्रों की भाषा को एक विशेष स्वरूप प्रदान करती हैं। इस तरह प्रयुक्ति किसी सामाजिक सन्दर्भ द्वारा निर्मित विशिष्ट भाषा रूप है।

[10] डॉ. उदय नारायण तिवारी : समाज भाषाविज्ञान, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1985 पृष्ठ 23

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Peace : Challenges to Peace

Dr. Sapna Gehlot
Assistant Professor (Pol. Science) Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur

Introduction : What is Peace ? How to define it? This word has a hoary ancestory. It originated in ancient Rome. The Romans defined it peace, as pax as absentia belli, which meant the absence of war. It was thus negatively understood and defined as cessation of hostilities. Today, peace is often understood as the absence of war between two or more states employing their Organized armies. Nonetheless the concept of peace also applies to the state of people with in their respective geopolitic entities. Civil War, state sponsored genocide, terrorism and other violence are all threats to peace. Peace also has a positive connotation. It is a celebration of life. Death is a denial of peace. The fundamental postulate of peace is the preservation of life human , animal and plant. It is a bulwark against human produced disabilities , threats of death and destruction. [1]

Peace as the presence of Justice and Development : Mahatma Gandhi suggested that if an oppressive society lacks violence , the society is not peaceful beacause of the injustice done to the oppressed. Gandhi articulated a vision of peace in which justice prevailed. A society is not peaceful if injustice is done to the oppressed. Gandhi articulated a vision of peace in which justice is inherent and necessary aspects of society. Such a peace requires not only the absence of violence but also the presence of justice.[2] Gaultang described peace with justice , as" positive peace" beacause hostility and further violence would would not flourish in this environment. During the 1950"s and 60"s when Martin Luther King Junior and the civil rights movement undertook various non - violent procession in USA, that were aimed at ending racial segregation and social presecution in America. They understood peace as more than just the absence of violence. They observed that while there was no open combat between the blacks and the Whites, there was an unjust system in which the government deprived African Americans of equal rights. While some of his opponents criticized his activists as disruptive of peace. Martin Luther King observed that 'True peace is not merely the absence of tension : it is the presence of justice."[2.] Galtung coined the term "structural violence " to refer to such situations, which though not violent, yet harboured systematic oppression and injustice. Oneconcept that often complements peace studies is development. In much of development discourse, it is assumed that economic, cultural and political development will take underdeveloped nations and people out of poverty , therby helping in bringing about a more peaceful world. As such , many international development agencies are carrying out projects funded by the governments of industrialized countries such as the U.S.A, Japan and Norway, designed to modernize poor countries.[3]

Peace in Conflict Resolution : Human capacity to kill has multiplied enormously with each level of human aggregation into large collectivists and each stage of technological sophistication. The conflict laden social existence necessitated the invention of the tools and techniques of conflict elimination, control and resolution. The primary and the most primitive instinctual technique was the direct killing of the competitor, The opponent or the deviant. As human that killing was not only counter – productive to the goal of Mutual collaboration for mutual advantage but also antithetical to the goal of conflict Management . Non – violent conflict inventions of values , consensus, regulations, rewards, non – capital punishment etc., as the instrument of conflict settlement. The result was the politicization of line

in society. Ever since life has become political politics has become the way of life; only the proposition have varied from time to time as the means of conflict control through non- violent methods. Politicisation is inversely proportional to the use of violence. The absence of physical violence, overt, direct and destructive, is the condition of peace.[4]

Parameters of Violence and Peace and dimensions of Peace : If peace is the absence of violence , then the measurement of peace should be inversely proportionate to the scales of violence. The scope of violence at the inter state level depends upon six aspects and the scope for peace among nations depends upon the opposite of those six aspects . The scale of violence and peace can be measures according to the following factors :

Violence : The size of the armed forces, types and numbers of weapons, types and levels of violence Involved , size of the territory over which violence is spread, the size of the territory over which violence is spread , size of the population affected by violence, the duration of violence.

Peace : The demobalization or reduction of troops ,elimination of the dangerous arms and reduction of the other weapons, elimination of danger of violence and the reduction of other weapons, elimination of dangerous violence and the reduction of the level of violence, reduction of the territory ablaze with violence and support to the creation of peace zones, number of persons protected or rescued or transferred from violent zones, times involved in negotiations for halting or ending violence; the duration of cease, armistice or truce.[5]

Dimensions : Peace , and its five dimensions of peace.

1. Non-violence - which aims at reducing and eliminating violence and the reduction of other weapons.
2. Economic Justice – the most immediate spark that ignites violence is economic deprivation.
3. Social Equality – discrimination , prejudice and power hierarchy, based on birth , sex , race , religion, wealth, generate inequalities, that can be exploitative and demoralizing.
4. Political Liberty – Slavery, serfdom, subordinations and denial right to petition , or protest – all based on prejudice and discrimination – reinforce inequalities and injustice and lead to violent protest for political rights and struggle to attain political freedom.
5. Psycological Fraternity - Legalistic liberty and equality and formalistic can become empty promise if they are not accompanied by community consciousness and feeling of fellowship Empty and ineffective guarantees can lead to frustration, cynicism and violence.[6]

Peace in Indian Tradition : In the classical Hindu caste system , the warriors , the kshtriyas were second to the Brahmin who were at the apex of hierarchy .This had at least three consequences ; war was conducted by a acaste, hence circumscribed by rules, not by development. This had a least three consequences : rules, not by development .This prevented it from becoming an all out warfare led by professional whose high position testified to the far from pacifist nature of Hindu Society. Not being on the top like the military feudal lords in Europe and the samurais in Japan., it opened the ways of harbouring belligerent thoughts and for thinking about peace which was different from peace as embodied in order and unity or absence of war. Thus the Hindu word for 'Peace' Shanti seems to be understood as well as everything Possess es a soul. Since the universe is an organic whole, governed by cosmic order, all the living universe is a sort of republic of souls, having no creator and no master except the moral laws that governs them.'" The Supreme virtue according to Jainism to non- injury to all living beings(ahimsa).[7] In the tradition of Buddhism a step forward was taken which was beyond ahimsa. It was interpreted as abstention

from injury to an interpretation in terms of compassion, good work and reconcialition of ahimsa with justice. For Gandhi, the Hindu seems to come closer to the Buddhist than the Jainists interpretation of ahimsa and it led to a positive interpretation of the method of Satyagraha . The oneness of all humans beings and indeed all life is the basic premise : not only that whatever good one does is done to us all. Wherever the Christianity the soul seems to be detached from each other, and is only attached to God , but in Jainism, Buddhism and the coupling is direct.[8]

Challenges to Peace : We can say that war can be seen as natural progression from inherent human, aggressiveness. Wars, riots and revolutions are perpetuated through divisive poitics and propaganda of fear. However , it is also true that human beings also exhibit generosity and altruism. So peace can also be an extension of human behaviour based on evolution of human knowledge, wisdom, compassion and insight. Sometimes peace and justice may be viewed as contradictions in practical terms. If one believes that the only way to prevent injustice and create justice is by force, then one believes , that ustice requires, hostilities, which precludes peace. Similarly, the clash of political interests has often been identified as justification of war. The desire for power and advantage puts groups in opposition. This opposition naturally escalates on one side and then the other tries to gain advantage, which sometimes culminates in violence and war. This effect is also seen in religious and ethnic groups. These groups see themselves as oppressed and violence and war have bee often been rationalized as justice in defence of a culture or religion. In India , there are some evils that pose contemporary challenges to democracy and peace.

1. Racial/ ethnic hatreds
2. Religious bigotry
3. Linguistic rivalaries
4. Separatist violence
5. Terrorism
6. Crisis of Industrialization Anyhow, inspite of all these challenges, in the arena of conflict resolution and peace building, Indian democracy has led us to the following conclusions:

1. Non – violence can b psychological, structural and physical. The practice of non- violence Can shape intellectual social, economic environmental and political aspects of human existence. In its essence, democracy is a system that rests on non-violence and as such the non-violent democracy is the best guarantee for conflict resolution and peace building .
2. Violent revolution cannot lead or to sustain meaningful democracy in the post revolution phase. Values, tools and techniques of revolutionary violence linger on for a long time.
3. Dictatorship however benevolent and well intentioned, cannot develop democracy or nurture non- violence.
4. Indian democracy has been largely successful in practising non- violent conflict resolution and in building peaceful civil society as indicated by unique experiments and unprecedent , such as non- violent revolution , peaceful ending of feudalism, combining democracy and industrialization, adoption of universal adult franchise in a highly illiterate society, conducting the world"s largest elections every five years, defusing cold war through non-alignment and sustaining more than 50 years without military coups, civil wars and political disintegration. India is the worlds biggest democracy without the most multiracial multireligious., multicultural population on planet earth.[9]

Conclusion : At last , it can be said that one should never give up the efforts and commitment for peace and preservence for peace can be achieved by remembering that love and hope are not only stronger nut even more effective and influential than the forces of distruction.

References :

1. Johan Galtung, Peace by Peaceful Means : Peace and Conflict Development and Civilization . Oslo : International Peace Research Institute, 1996. P.78

2. Ibid .P.78

3. http : // www.usaid.gov/about_usaid

4. M.V Naidu, Dimensions of Peace Multi disciplinary Investigative & Teaching Associations, Canada, 1996, p.25

5. Ibid ., P. 25

6. Ibid., P. 26

7. Darby John, The Effects of Violence on Peace Processes, Institute of Peace Press Washington, U.S.S 2001. P.120

8. Ibid., P. 121

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Chomsky on the Concept of Mind

Mudasir Ahmad Tantray
Ph.D. Scholar of Rani Durgawati University Jabalpur M.P.

Abstract : The prime aim of this paper is to define the mind, its nature, structure, and its mental processes. It also examines the relationship of mental processes; innate and acquired with the universal grammar. This paper tries to show the correspondence of Chomsky's Concept of mind with the primordial and grand theories of knowledge; rationalism, empiricism and criticism. This paper also shows the structure of mind, its existence and its dimensions. Chomsky explains the role of logic in the processing of mental processing and judgment. His concept of mind as the computer metaphor, eulogize the structure of the thought. This papers also describes the theories that are connected with the field of mind i.e. theory of language, linguistic mentalism, mind-body problem, generative grammar, and thought processes like perception and reflection.

Key words : Mind, Chomsky, Language, logic, innate, acquired, universal language, generative grammar.

Objectives : The objective of this research paper is to explore the nature of mind, its structure, I.e. internal or external. This research shows the role of reasoning and its relation with the mind. Following are the main objectives of this research work.

1. How mind operates from the principles of innate truth and acquired truths which are fundamental in logical enquiry (deductive and inductive).

2. What is the task of language in the domain of mind?.

3. Chomsky revision and synthesize of ideas from the rationalistic, empricistic and critical arenas.

4. Contribution of Chomsky in the field of mind (philosophy of mind).

5. Role of philosophical grammar with the contents of mind and mental processes.

Introduction : Mind is described as 'capacity to acquire intellectual skills' (Otero, 1994, p. 410). Asa Kasher writes in 'The Chomskyan Turn' that 'since knowledge presupposes mind and the mind did not exist in the early behaviorist philosophy of language but Chomsky put the mind back into the brain, exposed the fallacies of the simplistic mechanistic and empiricist view of science, and substituted theory for procedural methods, it was possible to ask the kinds of questions which would make it possible for linguistics to become a theoretical and explanatory science.[11] Bloomfield defined language as 'the totality of utterance that can be made in speech community'.[12] Chomsky's philosophy of mind rests directly on philosophy of grammar, in which the term 'grammar' was used, in the 1960s, to refer not simply to a linguists description of a language, but to the basic knowledge of linguistic structures; that every speaker of a language has acquired in infancy. The central issues of linguistic theory are then imposed as follows. First, we must ask what grammars are like: what form does a speaker basic knowledge of a language take? Second, we have to ask how speakers do in fact acquire this knowledge. Chomsky's answer to the second question largely reflects his answer to first, and both are central to

[11]. V. A. Fromkin, Language and Brain: Redefining the Goals and Methodology of Linguistics, 'The Chomskyan Turn', ed., ASa Kasher (Oxford: Basil Blackwell, 1991), p.82-83.

[12]. See Noam Chomsky, Knowledge of Language: its Nature, Origin, and Use, Edited by R. N. Anshen, New York: Praeger Publishers, 1986, P, 16.

his view of mind in general.[13] According to Chomsky, 'certain well-founded conclusions about the nature of language are relevant to the problem of how knowledge is acquired and how the character of human knowledge is determined by certain general properties of the mind'. Chomsky elsewhere claims that these conclusions support 'what might fairly be called a rationalist conception of the acquisition of knowledge', as opposed, in particular, to an empiricist one. More specifically, he suggests that 'contemporary research (in linguistic) supports a theory of psychologically a-priori principles that bears a striking resemblance to the classical doctrine of innate ideas'. Katz, among others, joins Chomsky in making such claims, declaring that 'enough is now known in the theory of language to afford a substantial basis for deciding between the empiricist and rationalist hypothesis', and concluding that such a decision favors a rationalist account of human learning. Cooper has argued, for instance, that Chomsky's neo-rationalism is dissimilar enough from the rationalism of Descartes and Leibnitz so that 'there is little of philosophical contention in Chomsky's doctrine'. The debate of Empiricists and rationalists merely emphasized on existence of innate ideas and innate knowledge.[14] We don't have a language n our heads. Rather, what we have in our heads is some kind of system of rules that determines the properties of expressions over an indefinite range.[15] It seems to me that individual is an active interpreter, rather than a merely passive recipient, of sensations. Sensations can exist only because of the agent[16] . The capacities of human mind are in fact capacities of the human brain.[17] He believes that human knowledge of the language can be studied on the basis of the computer metaphor of the mind[18]. Chomsky used the term "mind/brain, it seems to me that either mind-brain problem is a mystery or it these terms are used an analogous to one another[19].

Further, Mind is a software part of brain which is its hardware part. Mind can't think in empty and can't work without rules and laws. Mind is a three dimensional entity and a relative software operates in categories of time and space. Logic acts as a bridge between thought and language. Mind[20] works on the principles of logic and causation. Synthesis, memories, association, analysis of thoughts, production, retention, simple, complex ideas, subjective and objective ideas, all these concepts have their affinity with mind. Mind is concerned with all mental phenomena, where "mental phenomena" is to be understood as all phenomena that exclusively involve beings capable of consciousness. It would be useful if we could say that all mental phenomena fall into some manageable number of categories. It has been suggested, for example that the mind has three basic capacities or "faculties" as they were called; namely, "Cognition" (Knowing), "Affection" (Feeling) and "Volition" (Willing); each mental phenomenon was supposed to be the result of the operation of these faculties. Thus under cognition, we would have sense perception, memory, introspection, intuition, inference and other sources of knowledge. Mind is the operations or process of brain. Mind cannot be touched or visualized but can be inferred. Brain is the physical part which can be touched or visualized directly

[13]. P. H. Matthews, Language as a Mental Faculty: Chomsky's Progress, in C. P. Otero (ed.), Noam Chomsky Critical Assessments, vol. II, Philosophy: Tome II, New York: Routledge, 1994, p. 550.
[14]. F. D'Agostino, Chomsky's System of Ideas, Oxford: Clarendon Press, 1986, p. 61-65.
[15]. See N. Chomsky, Modular Approaches to the study of the Mind, California: San Diego, 1984, p. 26.
[16]. Ibid., p. 65.
[17]. N. Chomsky, On Nature and Language, A. Belletti & L. Rizzi, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 64.
[18]. See Noam Chomsky and Language Descriptions, ed., J. O. Askedal, I. Roberts, T. Matsushita, Vol. 2, (Amstergam/Philadelphia: John Benjamins Publishing company, 2010), p. 2.
[19]. N. Chomsky, Language and Problems of Knowledge, Cambridge: The MIT Press, 1988, p. 35, 40, 55,
[20]. The concept of mind is has been explained systematically in its own filed known as philosophy of mind where, Philosophy of mind is the branch of philosophy that studies the nature of the mind, mental events, mental functions, mental properties, consciousness, and the role of induction and deduction in the innate and acquired processes of mind.

and is a physiological part of human being. The brain, which directs the activities of the nervous system, contains billions of nerve cells. Neuroscience is an interdisciplinary science which studies the human brain. According to scientists mind exists somewhere within the brain. Mind as the software part of the brain has its own world. Physically, the brain is a somewhat nondescript, walnut-shaped tissue mass. However, its complex structure contains billions of neurons. The neurons are intricately connected and function collectively to control all aspects of behavior. Mind is the input operators which operate on the data, data is collected by sense organs and the mind used to interpret it. The internal concepts in mind cannot be deleted or erased from it but, the external concepts which came in through experience or sensations can be erased or avoided. Brain is a digital computer as early computers were often called "electronic-brain". Human mind has characteristics of functions like thinking, doubting, and its modifications are feelings, volitions, desire and judgments. While, modifications of brain are position, figure and motion. There are many different views on the concept of mind i.e.

1. Descartes defined it as, "mind is thinking thing"
2. Gilbert Ryle termed it as, "the mind is one's ability and proneness to do certain sorts of things"
3. Armstrong, "the mind is the Brain"
4. William James: "the mind is stream of consciousness"
5. Chomsky: "The mind is the capacity and container of mental processes"
6. Hobbes: Mind is the interaction of material components. (Heil, 1998).

Mind and its nature and structure : Mind is a set of programs and the pivotal for the consciousness, sensations, feelings, imaginations etc. Mind works on the principles of causation. Mental causation is inductive in its nature while innateness of truths are deductive in its process but deductive truths play their role naturally without any transformation. Mental causation is a cause-effect relationship which is concerned with the events of the mind. Does mind has causal power? This question was a key issue in the modern philosophy although most of the dualist philosophers want to solve the question of how mind influence the body and body influence the mind. Mind is a software part of brain. The concept of mind was coined by the Greek philosopher Anaxagoras who used it in the form of Nous. Mind and soul was used synonymously in ancient times. We can't perceive mind but we can inference it by outputs of sensation. Mind is defined as the series or stream of thoughts, consciousness, experiences, and ideas or we can say that it is the stream of perceptions. Mind alone was not the only problem which was discussed and exaggerated in Greek tradition, although, it came before us in the shape of Mind-body problem. The fundamental qualities or attributes of mind are thinking, doubting, willing, etc and the fundamental properties of body are extension, motion, solidity, shape and size. The world of mind is also called the realm of understanding and the world of body is also called realm of matter. Mind-body problem is the interesting and critical problem starts from Greek philosophy, simplified and analyzed in modern philosophy, separated in psychology (Cognitive) and science. Logic plays an important role in the operations and structure of the mind, Where as deductive logic which is natural to mind makes causation and sequence of events possible and inductive logic which formulates and creates new thoughts from the arguments of observation and calculation makes acquired ideas possible. Immanuel Kant synthesized Inductive and deductive process in order to put forward his theories like sensation, reflection and categories of understanding. Everything in the universe according to Kant is the combination of subject and predicate. Language is the symbolic representation of thoughts, thought is the mental process. Language may be symbolic, non-symbolic, verbal or non-verbal, figurative or mathematical. Only patterns of language are inherent to mind. Mind can't thought in emptiness it has power to analyze, simplify, repeat, synthesize, production,

destruction, abstraction so, it demands data on which mind with the help of logic and by the aid of language makes its process of operations. Many philosophers concerned with linguistic mentalism have accepted Ryle's claim that knowledge is a matter either of knowing how to do something or of knowing that something is the case. Chomsky has refused to accept the claim that the dichotomy between knowing how and knowing that is exhaustive of the various kinds of knowledge a person might be said to have. He suggests that we might, in addition, have tacit knowledge – propositional knowledge which we are unaware of having and cannot report having which nevertheless guides our behavior. It is this kind of tacit knowledge of grammars which linguistic mentalism attributes to language users. According to most linguists, language users have intuitions about properties of and relations between the sentences of their language, on the basis of which they are able to make intuitive judgments about those sentences.[21] It is important to note that there are many different types of mental states, processes and activities. Just as there is no thing or substance called 'the mind', so, there is no simple definition or essence of mind or mentality. Chomsky's description of the mental structure that he investigates introduces an irrelevant metaphysical element at the interface between physiology and psychology. I intend to justify this complaint by a detailed examination of some crucial passages in Chomsky's latest books 'Rules and representations'. But before doing so let me, in order to avert misunderstanding, list a number of points on which philosophers have picked quarrels with Chomsky and on which I think it is he, and not his philosophical critics, who is in the right. Anthony Kenny said that I have no quarrel with the idea that there are faculties of the mind, and that the mind in that sense has a modular structure. I have no quarrel with the notion of deep structures, or mental representations, in the only sense in which these are really relevant to the exciting empirical enquiries that Chomsky and his associates are engaged in. I have no quarrel with the idea that in using language we display tacit knowledge, operating rules and principles that cannot in the normal way be brought to conscious formulation. Finally, I have no objection to innate mental structures on the grounds of their innateness. Obviously, human beings are born with certain abilities, including abilities to mature as well as abilities to learn. Whether the ability to acquire grammars of a certain kind is an ability to learn or an ability to mature under certain conditions seems to me a philosophically open question, capable in principle of being settled by empirical enquiry. The mind is the capacity to acquire intellectual skills. The chief and most important intellectual skill is the mastery of language. Others, such as knowledge of mathematics, are acquired by human beings through the languages that they have mastered. So the study of the acquisition and exercise of language is the way par excellence to study the nature of the human mind. The human mind is the capacity that human beings have to acquire intellectual abilities; a capacity is itself an ability, but a second order ability, the ability to acquire abilities. The vehicle of the human mind is, very likely, the human brain. Human beings and their brains are physical objects; their minds are not, because they are capacities. This does not mean they are spirits. A round pegs ability to fit into a round hole is not a physical object like the round peg itself, but no one will suggest it is a spirit. It is not any adherence to spiritualism, but simply concern for conceptual clarity, that makes us insist that a mind is not a physical object and does not have a length and breadth.[22] If a mind is not a physical object, can it have a structure at all? Yes, it can. The set of abilities through which the mental capacity is exercised have relationships to each other. There are relationships, for instance, between the ability to multiply and the ability to

[21]. F. D'Agostino, Chomsky's System of Ideas, Oxford: Clarendon Press, 1986, p.68-75.

[22]. A. Kenny, Language and reality. Noam Chomsky Critical Assessments, ed. by C. P. Otero, Vol. II: Philosophy: Tome II, New York: Routledge, 1994, p.409-10.

take square roots and these relationships between abilities from the structure of the mind. Not only human beings have abilities that are structured in this way; we can discover the structure latent in the operations of a pocket-calculator by identifying the algorithms that it uses. To discover the algorithm that a calculator uses, say, for the extraction of square roots calls for mathematical, rather than electronic enquiry. When considering the human mind, the physiologist is in the position analogous to the electronic engineer. To show that it is possible to know a language without having the capacity to use it, Chomsky offers the following argument: Imagine a person who knows English and suffers cerebral damage that does not affect the language centers at all but prevents their use in speech, comprehension, or let us suppose, even in thought, suppose that the effects of the injury recede and with no further experience or exposure the person recovers the original capacity to use the language. In the intervening period, he had no capacity to speak or understand English, even in thought, though the mental (ultimately physical) structures that underlie that capacity were undamaged. Did the person know English during the intervening period? The answer, Chomsky says, is 'yes': that is shown by the fact of recovery. In the intervening period, he had no capacity to speak or understand English.[23] The question-begging nature of Chomsky's procedure is marked by his use of expressions such as 'mental' (ultimately physical) structures' and 'mental (ultimately physical) states'. Chomsky uses such expressions to indicate that his mentalism does not involve any sort of immaterialism: mental structures are simply physical structures described at a certain level of abstraction. But the expressions are ill-chosen, whatever one may think of immaterialism, because they conceal the fact that the criteria of identity for a mental state are not the same as those for a physical state. Two people can be in the same mental state while being in a different physical state, and can be in the same physical sate while being in a different mental state. To say this does not beg any question about materialism, since it is equally true of computers that there is no one-one correlation between software structures and hardware structures.[24] The root of Chomsky's confusion in his failure to distinguish between two different kinds of evidence that we may have for the obtaining of states of affairs: to distinguish between criteria and symptoms (to use the terminology introduced by Wittgenstein). Where the connection between a certain kind of evidence and the conclusion drawn from it is a matter of empirical discovery, through theory and induction, the evidence may be called a symptom of the states of affairs; where the relation between evidence and conclusion is not something discovered by empirical investigation, but is something that must be grasped by anyone who possesses the concept of the state of affairs in question, then the evidence is not a mere symptom, but is a criterion of the event in question. A red sky at night may be a symptom of good weather the following morning; but the absence of clouds, the shining of the sun, etc, tomorrow are not just symptoms but criteria for the good weather. Similarly, the occurrence of certain electrical brain patterns may be, or may someday come to be, symptoms of the presence of knowledge of English in the person whose brain is in question. But his ready use of English is not just a symptom of, it is a criterion of, a knowledge of English.[25]

Language has to provide two kinds of information, as required by the "thought system" with which it interacts that is locally related thematic relations (theme, patient etc) and another is edge related information (such as new/old information topic, focus, specificity, etc.), which are traditionally called the 'deep' and 'surface' properties, respectively.[26] But in place of the terms "deep structure" and "surface structure"

[23]. Ibid., p. 411-12.

[24]. Ibid., p. 413.
[25]. Ibid., 415.
[26]. Chomsky, N. The Generative Enterprise Revisited. New York: Mouton de Gruyter, (2004), p. 162.

one might use the corresponding Humboldtian notions "inner form" of a sentence and "outer form" of a sentence. Noam Chomsky was a central figure in the development of the concept of Mind and its relation to logic and language. According to him; Language is not innate but language learning process is innate .a child can learn both the English and Japanese, we can't attribute the knowledge of English to the child as innate property. It seems reasonable to postulate that the principles of general linguistics regarding the nature of rules, their organization, the principles by which they function, the kinds of representations to which they apply and which they form all constitute part of the innate condition that "puts a limit on admissible hypothesis.[27]

Deep structure – inner form

Surface structure – outer form

"the term depth grammar and surface grammar are familiar in modern philosophy in something roughly like the sense here intended as Wittgenstein described as 'operations of mind and objects of operations'[28].

Chomsky's arguments on rationalistic, empricistic, and critical views (Kant) on Mind : Chomsky accepted the rationalistic argument or Cartesian doctrine that mind is governed by innate structure or mechanism that in many places he imposed critique to empiricist doctrine.[29] Nativists or Rationalists are opposed by empiricists, who argue that the mind comes equipped with relatively little innate structure, and this structure is relatively unimportant in explaining our mature cognitive capacities and abilities. For example, one particularly extreme version of empiricism, sometimes attributed to the British Empiricists of the 18th century such as Locke and Hume, claims that the newborn infant's mind is a 'tabula rasa', or blank slate. According to these theorists, experience is the source of almost all of our mature concepts and beliefs as well as our mature cognitive abilities and capacities. It's important to recognize that even extreme empiricists don't claim that the mind possesses no innate structure whatsoever. Rather, empiricists attempt to explain the development of our mature cognitive repertoire by adverting to a minimum of innate structure. Thus, empiricists typically assert that the mind comes equipped with just a few learning mechanisms and these mechanisms are 'domain-general', that is they operate over a wide variety of cognitive domains. During the first half of the Twentieth century, empiricist ideas dominated psychology and other sciences of human behavior. As we saw in the previous section, behaviorist psychologists such as Watson and Skinner emphasized the role of learning, and in particular, histories of conditioning or reinforcement, in the explanation of behavior. A similar picture prevailed in the social sciences. Empiricism no longer enjoyed a position of unquestioned dominance as psychologists increasingly began to emphasize the innate basis for a number of cognitive capacities. Descartes, a good explorer of deductive logic argued that the truths which are innate in mind are deductive[30] in nature. Rationalists presented their philosophical views which are based on deductive reasoning also rationalists grounded most of their thoughts either on mathematical or on natural science like physics. Empiricists are critiques of rationalists they grounded their philosophy purely on inductive logic[31]. According to John Locke mind is a tabula

[27]. N. Chomsky, Mind and Language, 3rd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 152-53.
[28]. Chomsky, Aspects of the theory of Syntax, p. 199-200.
[29]. G. Cinque, "On the connections between Chomsky's work in linguistics and cognitive science, and his social views and attitudes", Noam Chomsky: Critical Assessments, ed. C. P. Otero, Vol. III: Anthropology: Tome II. (London: Routledge, 1994), p. 340.
[30]. Deductive reasoning is a type of reasoning in which premises claims for conclusion. Premises are more general than conclusion and the conclusion is true, provided the premises are true. Arguments based on rules, laws or axioms are best expressed deductively.
[31]. Inductive logic is a type of logic in which conclusion is different from what the premises claims. Conclusion is more general than premises and arguments based on

rasa (blank slate). There is nothing deductive in mind. No ideas are innate to mind. Ideas are acquired in the processing of mind claimed john Locke. John Locke believed that knowledge comes from the sensation or ideas furnished to the mind by experience. Immanuel Kant a great logician and a champion of Mind and logic argued that in mind there are some universal characteristics (cause-effect principle) of experience which are found in all mental experience, Kant called them categories the important among the twelve are quantity, quality, relation, existence, probability and causality. In the absence of these categories of knowledge, no thinking is possible. Now because these categories do not come from outside but are found to be present before experience, it can be said that while the material of knowledge come from outside the mind gives form to it. In Kant, logical analysis, reason is the faculty inference and as there are three kind of inference, so corresponding to them there are three ideas. From the categorical syllogism has been derived the idea of an absolute subject which can be identified with the immortal soul. The hypothetical syllogism yields the idea of the final synthesis of all phenomenon called the world. From the disjunctive syllogism is derived the idea of an absolute unity of all phenomenon called God. Kant has distinguished between two fundamental aspects of experience perceptual and conceptual. The former based on experience and latter on intellect. Kant also argued that space and time are mental concepts not objects themselves and causality was one of the categories (a synthetic a priori concept) that we bring to experience and which make experience possible without such categories. The 'Cartesian linguists' who appeared after Descartes might have had little direct interest in Descartes' work, or might like Chomsky himself have disagreed strongly with some of the details of Descartes' view of the mind. But they had similar insights about creativity and its connection with innateness, and they directed their study of language and the mind towards dealing with the issues these pose. These points about creativity and innateness and their explanation are related to Chomsky's distinction between two kinds of approaches to the study of the mind, rationalist and empiricist.[32]

Logic and Mind : Logic is a science of reasoning or argumentation, derived from the Greek word "logos" which means reasoning or thinking. Aristotle is called as the founder of logic. He wrote a work known as "Organon" which was translated by Zeno of Elea as logic. So logic is the science or art of reasoning. Reasoning is of two types; inductive reasoning and deductive reasoning. Language and thinking together constitute reasoning. Our mind thinks in terms of propositions or categories while arrangement, syntatics, capacity to act, sequence are deductive to mind and what senses collects and mind learns from the experience of the society are inductive in mind. Further inductive reasoning and deductive reasoning are illustrated as:

Inductive reasoning : deductive reasoning Plato, Aristotle, Kant are mortal All chilies are bitter Plato, Aristotle, Kant are human beings Peppers are chilies Therefore, All human beings are mortal. Therefore, Peppers are bitter.

Lay-man, s argument for mind : Does mind exists? Of course, it does not! We can, t see it, touch it, or locate. it?

Logicians argument for mind : All bodies which exists are perceivable. Mind is not perceivable. Therefore, Mind is not a body which exists.

Conclusion : Chomsky is a great exponent of analytical philosophy and the philosophy of mind. He gave the concept of mind; a definite and a determinate form which it had lost some two hundred years back. Chomsky's all the works in the field of philosophy of mind reflects the three central theories; rationalism, empiricism and

observation and calculation are best expressed inductively.

[32]. N. Chomsky, Cartesian Linguistics, p.10

criticism. He argued that there are some innate truths which he called the inner structure, cooperates with the outer makes the mind. Chomsky accepts the Descartes view that 'mind is active and ideas are innate' and rejects the Locke's view that 'no ideas are innate while accepts that 'knowledge begins with experience proceeds to understanding and end in reason'. Some scholars have a view that it is very difficult to understand the philosophy of Chomsky without understanding the works of rationalists, empiricists and Kant. Chomsky has intensive influence of Kant's view regarding mind, i.e. mind is the combination of sensation and reflection or we can say mind is the collective name for various mental processes included outer ones. Chomsky showed the intense role of mind and its modules and processes in the selection of grammars. He believed that every language possess innate grammar mechanism and potentiality.

References :

1. V. A. Fromkin. (1991). Language and Brain: Redefining the Goals and Methodology of Linguistics, 'The Chomskyan Turn', ed., Asa Kasher (Oxford: Basil Blackwell,
2. 2. P. H. Matthews. (1994). Language as a Mental Faculty: Chomsky's Progress, in C. P. Otero (ed.), Noam Chomsky Critical Assessments, vol. II, Philosophy: Tome II, New York: Routledge.
3. F. D'Agostino. (1986). Chomsky's System of Ideas, Oxford: Clarendon Press.
4. Noam Chomsky. (1984). Knowledge of Language: its Nature, Origin, and Use, Edited by R. N. Anshen, N See N. Chomsky, Modular Approaches to the study of the Mind, California: San Diego.
5. N. Chomsky. (1986). On Nature and Language, A. Belletti & L. Rizzi, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. ew York: Praeger Publishers.
6. Noam Chomsky and Language Descriptions, ed., J. O. Askedal, I. Roberts, T. Matsushita, Vol. 2, (Amstergam/Philadelphia: John Benjamins Publishing company, 2010), p. 2.
7. N. Chomsky. (1988). Language and Problems of Knowledge, Cambridge: The MIT Press.
8. A. Kenny. (1994). Language and reality. Noam Chomsky Critical Assessments, ed. by C. P. Otero, Vol. II: Philosophy: Tome II, New York: Routledge.
9. Chomsky, N. (2004). The Generative Enterprise Revisited. New York: Mouton de Gruyter.
10. N. Chomsky. (2006). Mind and Language, 3rd ed., Cambridge: Cambridge University Press.
11. N. Chomsky. (1969). Aspects of the theory of Syntax, Cambridge: MIT Press.
12. G. Cinque. (1994). "On the connections between Chomsky's work in linguistics and cognitive science, and his social views and attitudes", Noam Chomsky: Critical Assessments, ed. C. P. Otero, Vol. III: Anthropology: Tome II. (London: Routledge,).
13. N. Chomsky. (2002). Cartesian Linguistics, A Chapter in the History of Rationalist Thought, with edited and introduction by James Mcgilvray, New Zealand: Cbereditions Corporation.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

सामाजिक पर्यटन– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. श्रीमती अर्चना शुक्ला
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सामाजिक पर्यटन की परिभाषा :– पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यात्राएं निष्पादित की जाती हैं। घरेलू पर्यटन में पर्यटक देश के अन्दर यात्रा करते हैं, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में पर्यटक अन्य देशों की यात्राएं करते हैं। पर्यटन का प्रारंभ किसी आकर्षण से होता है पर्यटक उस आकर्षण के कारण उपलब्ध यात्रा के साधनों का उपयोग करते हैं। इस क्रिया के लिये धन एवं समय की आवश्यकता होती है। पर्यटक या तो अपनी आय या बचत से इस व्यय की पूर्ति करते हैं। पर्यटन के लिए अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों से अवकाश लेते हैं। इस प्रकार पर्यटन केवल धनी वर्ग तक ही सीमित रह गया है। निर्धन वर्ग जो यात्रा के व्यय नहीं वहन कर सकता है तथा अपने कार्य से अवकाश भी नहीं ले सकते वे पर्यटन के बारे में केवल सोच ही सकते हैं। क्योंकि आर्थिक एवं अन्य संसाधनों की कमी उन्हें यात्राओं का अवसर प्रदान नहीं करती हैं।

सामाजिक पर्यटन का प्रारंभ इस विचारधारा से हुआ था कि पर्यटन सभी नागरिकों का अधिकार है। यह केवल धनी व समर्थ व्यक्तियों का हक नहीं है, अतः समाज विशेष रूप से सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह 'Tourism वित All' सभी के लिए पर्यटन दृष्टिकोण का अनुपालन करे।

सामाजिक पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवकाश, पर्यटन स्थल, पर्यटकों के समूह सम्मिलित किये जाते हैं। सामाजिक पर्यटन व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक एवं सरकारी तथा निजी संस्थानों द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्न आय वर्ग में बच्चों के लिए अवकाश आयोजित करने के लिए छोटे अनुदान से लेकर सरकार द्वारा विभिन्न होटलों में ठहरने की सुविधा सम्मिलित हो सकती है। इन समस्त गतिविधियों में एक तथ्य आवश्यक है कि इन सभी का उद्देश्य ऐसे लोगों को पर्यटन क्रियाओं से जोड़ना है जो बिना सहयोग के इनसे अछूते रह जाते हैं।[1]

विश्व के विभिन्न देशों में विशेष रूप से यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम आदि में सामाजिक पर्यटन के अंतर्गत राष्ट्रीय अवकाशा में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये सरकार के आर्थिक सहयोग से पर्यटन क्रियाएं आयोजित कराई जाती हैं, परन्तु अमेरिका व ब्रिटेन में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये सरकार के सहयोग से बहुत ही कम सामाजिक पर्यटन की क्रियाएं की जाती हैं। बिट्रेन में यद्यपि सामाजिक पर्यटन के लिए कुछ धर्मार्थ संस्थायें सहयोग देती है।

फ्रांस में 1945 में (NATU) National Open Air Tourism Union की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 58 गैर लाभ पर्यटन संगठनों को सामाजिक पर्यटन में सम्मिलित किया गया, जिनके द्वारा 242000 न्यू बिस्तरों की व्यवस्था की गई जिसमें से 160000 गॉव में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए (Holiday Village) अवकाश ग्राम की स्थापना की गई।

इसी प्रकार एक अन्य गैर लाभ संस्था VAL अपने अन्य सहयोगी संगठनों से मिलकर विभिन्न अधिकृत पर्यटक स्थलों को विकसित करते हैं एवं अवकाश के समय पर्यटकों को ठहराने की व्यवस्था करते हैं। इन स्थानों पर पर्यटकों के लिए सामाजिक, ज्ञानवर्धक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद जैसी सभी क्रियाएं आयोजित कराई जाती हैं। सार्वजनिक पर्यटन कई उपेक्षित तंत्रों के विकास की कुंजी है इसका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर विकसित करना है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य एक तरफ आकर्षक मूल्य पर स्तरीय पर्यटन सुविधायें प्रदान करना तथा दूसरी ओर निर्धन वर्ग के लोगों को पर्यटन क्रियाओं से लाभान्वित करना है कई स्थानों पर सरकार अपने बजट से नागरिकों को

अवकाश व्हाउचर (Holiday Vouchers) प्रदान करती हैं।[2]

मानव अधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम के निश्चित घण्टों के अतिरिक्त अवकाश एवं आराम का अधिकार है। यद्यपि यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं है जिससे कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्से को विकासशील देशों में यात्रा एवं आराम के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। विकसित देशों में ऐसे व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए सामाजिक पर्यटन के दृष्टिकोण का विकास किया गया है। वर्तमान में विश्व भर के करोड़ों व्यक्तियों ने सामाजिक पर्यटन का स्वागत किया है जिसमें सभी आयु वर्ग के तथा सभी आय के व्यक्तियों के लिये पर्यटन की व्यवस्था की जाती है। सामाजिक पर्यटन आर्थिक विकास की गति होता है तथा इसमें क्षेत्रीय विकास के लिये धनी अर्थव्यवस्था से गरीब अर्थव्यवस्था के लिए साधनों के हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए समस्त नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।[3]

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा सामाजिक पर्यटन के आस्तित्व के काफी समय पहल से ''सतत् पर्यटन'' की अवधारणा अपनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उपेक्षित क्षेत्रों में स्थानीय सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन क्षेत्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, परन्तु इसे उस क्षेत्र की संस्कृति के विनाश एवं अनियंत्रित पर्यटकों का आगमन एवं वहां की स्थानीय जनसंख्या का शोषण आदि घटनाओं का घटक नहीं बनने दिया जा सकता है। पर्यटन को उस क्षेत्र के व्यक्तियों एवं संसाधनों के आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक वातावरण पर हानि पहुंचाने का एक उपकरण बनने से बचाना सरकार का उत्तरदायित्व है।

हनजिकर ने 1951 में सामाजिक पर्यटन को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य प्रकार से उपेक्षित व्यक्तियों की यात्राओं में भागीदारी के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं एवं उनके सम्बन्धों के रूप में समझाया है। हनजिकर के अनुसार, ''सामाजिक पर्यटन एक विशेष प्रकार का पर्यटन है जिसमें निम्न आय वर्ग के लोगों को विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं।''[4]

सामाजिक पर्यटन के सिद्धान्त

यूरोप में सामाजिक पर्यटन योजनाओं को मुख्य रूप से चार विशेषताएं हैं :–

भागीदारी सिद्धान्त **(Participation Model)**

सामाजिक पर्यटन आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के पर्यटन में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक पर्यटन ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय या स्वास्थ्य कारणों से पर्यटन के अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिये पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराती हैं। एसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, जिसमें बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित है उनकी शारीरिक क्षमता एवं स्वास्थ्य परिस्थितियों के अनुसार पर्यटन सुविधायें प्रदान की जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं को (Participation Model) भागीदारी सिद्धान्त कहते हैं।

समावेशी सिद्धान्त **(Inclusion Model)**

इस प्रकार के सिद्धान्त मे सभी की पर्यटन में भागीदारी प्रोत्साहित की जाती है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े एवं कमजोर व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। समावेशी सिद्धान्त के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिये पर्यटन के विकास से सभी को लाभ प्राप्त हो ऐसे प्रयास किये जाते हैं परन्तु विशेष रूप से इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मिले। इस सिद्धान्त के अंतर्गत विभिन्न Subsidised योजनाएं जैसे Holiday Vouchers आदि प्रारंभ की जाती हैं।

अनुकूलन सिद्धान्त **(Adaptation Model)**

इस सिद्धान्त के अतर्गत सामाजिक पर्यटन की ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं, जो विशेष रूप से सामाजिक पर्यटन के उपयोगकर्ताओं के लिए ही होती है। इसके अंतर्गत पर्यटन के लक्षित व्यक्तियों की पहचान

कर उनकी क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप योजना बनाई जाती है। यदि किन्हीं व्यक्तियों को चलने फिरने में कठिनाई होती है तो उन्हें उसी प्रकार की योजनायें प्रारंभ कीं जाती हैं इसके अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार आवास सुविधाएं जैसे बजट होटल तथा सस्ते भोजन एवं परिवहन सुविधायें दी जाती हैं।

प्रोत्साहन सिद्वान्त **(Stimulation Model)**

इस सिद्धान्त के अंतर्गत समुदाय को मुख्य रूप से आर्थिक लाभ प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं। सामाजिक पर्यटन के इस सिद्वान्त के द्वारा विभिन्न पर्यटक स्थलों में व्यस्त समय के अतिरिक्त अन्य समय में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। उदाहरण के लिये किसी पर्यटन स्थल पर सभी पर्यटक अवकाश के समय जाते हैं परन्तु वरिष्ठ नागरिक अन्य समय में भी वहां जा सकते हैं। इसके लिए पर्यटकों का विशेष दल बनाकर उसे विशेष सुविधायें देकर प्रोत्साहित किया जाता है। कइ पर्यटक जो सामान्य समय में मंहगाई में उच्च दरों के कारण पर्यटन क्रियाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते इन सुविधाओं का लाभ उठाकर पर्यटन का आनन्द ले सकते हैं।

पर्यटक उत्पाद	पर्यटक	
	केवल सामाजिक पर्यटक उपयोगकर्ताओं के लिये	सामाजिक पर्यटक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के लिये
सामान्य प्रावधान	भागीदारी सिद्वान्त **(Participation Model)**	समावेशी सिद्धान्त **(Inclusion Model)**
विशिष्ट प्रावधान	अनुकूलन सिद्धान्त **(Adaptation Model)**	अनुकूलन सिद्धान्त **(Stimulation Model)**

Model of Social Tourism :

Source: Lynn Minnaert, Maitland,R. & Miller G., What is Social Tourism, Current Issues in Tourism, Vol. 14, No.5, July 2011 p.405

सामाजिक पर्यटन का प्रारम्भ

किसी भी देश के नागरिकों के लिए क्या पर्यटन की सुविधा दिया जाना एक आवश्यक संवैधानिक दायित्व है। इस संदर्भ में बहुत सारे विचार हैं। वर्तमान समाज में जब सभ्यता की पराकाष्ठा हो रही है। पर्यटन की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है, परन्तु पर्यटन को नागरिक के अधिकार के रूप में प्रदान किये जाने की मांग कई यूरोपीयन देशों में हो रही है। वर्ष 2006 में यूरोपियन आर्थिक एवं सामाजिक संगठन सामाजिक पर्यटन को नागरिकों के अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार ''प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक, साप्ताहिक एवं वार्षिक आधार पर आराम का अधिकार है और इसी प्रकार से सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास में एवं सामाजिक विवरण के लिये विकसित करने के दृष्टिकोण से अविकास के समय का भी अधिकार है। स्पष्टतया प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इस अधिकार का उपयोग करने

का अधिकार है। पर्यटन का अधिकार एक सामाजिक अधिकार की अभिव्यक्ति है एवं सामाजिक पर्यटन इस अधिकार को सार्वभौमिक रूप से उपयोग में लाये जाने व सुनिश्चित करने का एक माध्यम है।'[5]

यद्यपि यूरोपियन आर्थिक एवं सामाजिक संगठन पर्यटन के अधिकार का प्रस्ताव कर सकती है परन्तु यह संस्था इसे वैधानिकता प्रदान नहीं करवा सकती। वास्तव में पर्यटन क्रिया को सार्वभौमिक रूप से नागरिकों का एक अधिकार न मानकर अभी भी इसे विलासिता के अंतर्गत रखा जाता है। यह एक ऐसी ऐच्छिक क्रिया है जिसके लिये कोई अधिकार नहीं है। यदि इसे अधिकार के रूप में माना जाए तो कई लोग खेलों को, परिवहन को एक अधिकार के रूप में दिये जाने के लिये मांग कर सकते हैं। वास्तव में पर्यटन नागरिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, उनके व्यक्तित्व में विकास करता है, उनका ज्ञानवर्धन करता है एवं अवकाश के समय को आनन्दपूर्वक व्यतीत कर अधिक कार्यक्षमता से अपने सामान्य क्रियाकलापों में संलग्न है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार एवं अन्य वे सामाजिक संस्थाओं का दायित्व हो जाता है कि वे समाज के निर्धन एवं उपेक्षित व्यक्तियों को भी पर्यटन की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने में मदद करें।

वार्षिक अवकाश एवं वेतन सहित अवकाश सामाजिक पर्यटन की पृष्ठभूमि का आधार है। वर्ष 1936 में विभिन्न ट्रेड यूनियन ने कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश की मांग की, जिससे श्रमिक अपने कठिन दैनिक जीवन से उस समय के लिये मुक्ति पा सकें। विभिन्न स्थान पर अवकाश केन्द्र प्रारंभ किये गये जिसमें कर्मचारियों को उचित मूल्य पर अवकाश के समय ठहरने की अनुमति भी इस प्रकार से प्रथम अवकाश का अनुभव कर्मचारियों में समूह पर्यटन के रूप में दिया गया।[6]

बेल्जियम में सरकार द्वारा विभिन्न अवकाशगृह स्थापित किये गये व उन्हें कम कीमतों पर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया। धीरे–धीरे समाज में परिवर्तन एवं प्रगति होती रही एवं समाज का एक वर्ग धनी व्यक्ति की श्रेणी में आ गया तथा उसने इस सरकारी अवकाश केन्द्रों को छोड़कर अपने सामर्थ्य के अनुसासर नये पर्यटन स्थल जाने की इच्छा जागृत की। इस प्रकार से व्यक्ति समूह अवकाश से व्यक्तिगत अवकाश की श्रेणी में आ गया परन्तु सभी व्यक्ति धनी नहीं हुए कुछ व्यक्ति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ गये एवं किन्हीं में शारीरिक अक्षमता रही जिससे कि वे पर्यटन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सके। वर्ष 1990 में सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता कम होने लगी तथा अवकाश केन्द्रों का संचालन कठिन हो गया। इन केन्द्रों में आने वाले व्यक्तियों की विविधता भी बढ़ गई। 1 अक्टूबर 1999 में विश्व पर्यटन संगठन ने सभी व्यक्तियों के लिये पर्यटन के अधिकार का महत्व समझा और इसके लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। वर्ष 2003 में सभी के लिये पर्यटन ज्वनतपेउ वित All की अवधारणा विकसित की गई।

अवकाश विभिन्न व्यक्तियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं एवं इनका परिवार के विकास में धनात्मक सम्बन्ध है परन्तु ब्रिट्रेन के 25 प्रतिशत जनसंख्या अवकाश पर नहीं जाती जिसका मुख्य कारण निम्न आय, लम्बी बीमारी, शारीरिक अक्षमता एवं पारिवारिक मतभेद हैं।[7]

Family Holiday Association (FHA) के एक शोध के अनुसार ब्रिट्रेन सरकार ने सामाजिक पर्यटन को प्राथमिकता नहीं दी जबकि अन्य पड़ोसी देशों में सरकार ने इस क्षेत्र में प्रयास किये। यूरोप में विभिन्न सरकारों ने पिछले 50 वर्षों में अपनी सामाजिक कल्याण नीति को सामाजिक पर्यटन के साथ एकीकृत किया है। जिसके अंतर्गत सरकार ने अवकाश एवं मनोरंजन की विभिन्न योजनाएं जो सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगीं प्रारंभ की गई हैं। फ्रांस में वर्ष 2004 में सरकार द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये चलाई जा रही पर्यटन योजनाओं से 63 मिलियन व्यक्ति लाभान्वित हुए। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये विभिन्न अवकाश चैक दिये हैं जो 135000 जगहों पर प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जिसमें Holiday Parks Camping तथा Sports की सुविधाएं सम्मिलित हैं। यह सरकार द्वारा रियायती दरों पर दी जाती है। बैल्जियम में Fladevs पर्यटक कार्यालय के 10000 अलग

व्यक्तियों को पर्यटन क्रियाओं में मदद की FHA के निर्देशक Johan McDonard ने मांग की है कि ब्रिट्रिश सरकार को भी सामाजिक पर्यटन क विकास हेतु प्रयास किये जाने चाहिये, उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किये गये प्रयास अक्षम लोगों के लिए केन्द्रित रहे हैं परन्तु निर्धन व्यक्तियों हेतु अधिक प्रयास नहीं किये गये हैं।

सामाजिक पर्यटन के लिए प्रयास सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है परन्तु सरकार केवल सीमित मात्रा में सुविधायें प्रदान कर सकती है। सरकार मुख्य रूप से नेतृत्व प्रदान कर सकती है आवश्यकता इस बात की है कि सामुदायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जायें। विभिन्न उद्योग अपने कर्मचारियों के लिए पर्यटन के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं एवं कई सामाजिक संस्थाएं गैर सरकारी संस्थायें एवं धर्मार्थ संस्थाएं भी सामाजिक पर्यटन की ओर ध्यान दे रही हैं।

भारतवर्ष में सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की योजना संचालित करती हैं। इसी प्रकार पर्यटन की सुविधाएं भी कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार कर्मचारियों को एल0टी0सी0 की सुविधा देती है। रेलवे द्वारा भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रियायती टिकिट प्रदान किये जाते हैं। राज्य सरकारें भी पर्यटन विभाग के माध्यम से निम्न आय वर्ग के व्यक्तियां के लिये भ्रमण आयोजित करते हैं। मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तीर्थ दर्शन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सरकार हज यात्रियों के लिये भी सुरक्षा एवं सुख–सुविधायें प्रदान करती हैं। अमरनाथ एवं मानसरोवर यात्रियों को सुरक्षा एवं सुविधायें सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। सामाजिक पर्यटन का विकास देश के समन्वित विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा।

References :

1. Minnaert, L., Maitland, R. & Miller, G. (2009),Tourism and social policy – The value of social tourism, 'Annals of Tourism Research' Vol. 36 no.2 p. 316
2. Bolland Patrick, (2006), The Benefits of Social Tourism in www. humanitemenglish.com.
3. www.syl.com/travel/The concept of social tourism_html.
4. Lynn Minnaert, Maitland, R. andMiller G., What is Social Tourism,Current Issues in Tourism, Vol.14, No. 9, July 2011,p.403.
5. European Economics and Social Committee, Opinion of the Economic and Social Committee on Social Tourism in Europe Binssels EESC/2006, p.68.
6. Modi, Shalini, Tourism and Society, Rowat Publications, Jaipur, 2001.
7. Government urged to back social tourism in www.Inandian.co.uk/ society/2005/pop/08/social exclusion. politics.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

ग्रामीण विकास मे प्रौद्योगिकी की भूमिका : रीवा जिले के विशेष संदर्भ मे

डॉ हरीश केशरवानी
यू जी सी नेट एवं जे आर एफ एम ए, डिफिल भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोध सारांश **(Abstract) :-** वर्तमान मे विकास का मुद्दा बहुविषयक और सभी क्षेत्र कों से जुड़ा हुआ एवं व्यापक मुद्दा है। भारत जैसे देश मे आज भी दो–तिहाई से ज्यादा जनसंख्या गांवां मे रहती है परंतु गांवों का आर्थिक विकास, रोजगार, आय और जीवन की गुणवत्ता का स्तर नगरों से अपेक्षाकृत कम है। तुलनात्मक रूप से उत्पादन प्रणाली, आय और संसाधनों के वितरण जैसे सभी स्तरों मे असमानता देखने को मिलती है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र मे प्रतिव्यक्ति उत्पादन, आय और उत्पादकता सभी मे कमी देखी जा सकती है जिसके कई कारण हो सकते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र मे आधारभूत संरचना का विकास तथा तकनीकी हस्तांतरण जैसे नवाचार को कियान्वयन किया जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों का न केवल विकास होगा वरन् रोजगार के अवसर मे वृद्धि, आय और उत्पादन मे वृद्धि, सेवा क्षेत्र के दायरे मे विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर होने वाला पलायन भी रुकेगा। हाल ही मे सरकार द्वारा किये गये आर्थिक सुधारों का प्रयास भी सफल होगा जिसका सीधा लाभ सामान्य नागरिकों को होगा।

शोधकार्य मे अध्ययन क्षेत्र के रूप मे मध्य प्रदेश के रीवा जिला को लिया गया है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। भौगोलिक रूप से रीवा जिला मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग मे स्थित है जिसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमे उत्तरी हिस्से मे विन्ध्य का कगारी क्षेत्र है और कई सारे जल प्रपात विद्यमान हैं। रीवा जिला मे ग्रामीण विकास के संदर्भ मे प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कई सकारात्मक विकास के पहलू देखे जा सकते हैं जो इस शोधकार्य के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। साथ ही वहां पर विकास की अन्य संभावनाओं को शोध के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्रादेशिक नियोजन और संसाधन प्रबंधन के साथ समावेशी एवं त्वरित विकास को प्रोत्साहित कर सकेगा।

शोध पत्र **(Research Paper) :-** सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण और जीवन स्तर मे सुधार विकास का मुख्य मानक होता है। जिससे सामाजिक सुधार, आर्थिक सुरक्षा, सुविधाओं मे विस्तार, अभिगम्यता, रोजगार, आय और उत्पादकता सभी मे सुधार होता है। भारत के संदर्भ मे विकास का मुद्दा सबस महत्वपूर्ण है। वर्तमान मे भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर विश्व की 17: जनसंख्या निवास करती है और इस जनसंख्या का 67: हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिवासित है। भारत के संदर्भ मे ग्रामीण और नगरीय विषमता को आसानी से रेखांकित किया जा सकता है एक ओर नगरों मे रोजगार, आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र का विकास, परिवहन की सुगम उपलब्धता, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं इत्यादि के संदर्भ मे नगरों को अपेक्षाकृत समुन्नत माना जाता है जबकी गॉवों मे आर्थिक सुरक्षा का आभाव, प्रतिव्यक्ति उत्पादकता और आय मे कमी, रोजगार के सीमित अवसर जैसे पहलू देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों मे बेहतर प्राकृतिक संसाधन, खुला पर्यावरण, विस्तृत भूमि, सस्ते श्रमिक इत्यादि प्रचुर मात्रा मे रहते हैं परंतु परंपरागत उपकरणों, सीमित तकनीकी के कारण ग्रामीण विकास का वास्तविक गति और दिशा नही दी जा सकती है। भारत के विकास के संदर्भ मे ग्रामीण क्षेत्रों मे यदि प्रौद्योगिकी और समुन्नत तकनीकी का उपयोग और अनुप्रयोग किया जाए तो विकास की दशा और दिशा दोनों मे तेजी से बदलाव होगा। यह बदलाव आय, उत्पादकता, आधारभूत सुविधाओं के साथ–साथ जीवन स्तर के सुधार के रूप मे भी आगे आएगा जिससे देशो के समग्र विकास के साथ पर्यावरणीय मित्रवत विकास को सामवेशी रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।

वर्तमान मे ग्रामीण विकास के संदर्भ मे प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कुंजी के रूप मे होगा जो विकास के सभी रास्ते को खोलेगा तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास के साथ–साथ मानव संसाधन विकास को और अधिक गति और सुधार की ओर प्रोत्साहित करेगा। ग्रामीण क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है तथा लाभ को बढ़ाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आर्थिक सुधार के साथ–साथ सामाजिक स्तर मे उत्थान आधुनिक विचारों का अनुपालन तथा नवाचारों के प्रसरण को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र भारत के विकास के अदृश्य स्तंभ हैं जिसमे प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इस अधिक चमकदार बानाया जा सकता है। उपर्युक्त शोध शीर्षक के महत्व के रूप मे व्याख्या किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्र मे बहुआयामी आर्थिक विकास, उत्पादन मे तीव्र वृद्धि, औद्योगीकरण को बढ़ावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संकुल इत्यादि को विस्तृत किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मानव संसाधन की क्षमता मे विस्तार किया जा सकता है जिससे कम समय, मेहनत और लागत के साथ अधिकतम उत्पादन, लाभ और आय प्राप्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के आगमन से आर्थिक संरचना मे सुधार हागा जिसमे कमबद्ध रूप से अनौपचारिक क्षेत्रक से औपचारिक अर्थव्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी का उपयोग समग्र प्रशासन के रूप मे किया जा सकता है। जिससे विकास की योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिल सकेगा और पारदर्शी प्रशासन का विस्तार होगा। इससे जनता मे प्रशासन और लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति अधिक विश्वास होगा तथा इसकी आधारभूत अवधारणा मे पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार की योजनाएं और विविध विकास कार्यकम का सीधा लाभ जनता को होगा और बिचौलिए, दलाल तथा तथा नकारात्मक पक्षों का विलोपन होगा।

अध्ययन का उद्देश्य :– ग्रामीण विकास मे प्रौद्योगिकी की भूमिका के संदर्भ मे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास के लिए अब तक किये गये कार्यों का मूल्यांकन करना तथा उन सभी पहलुओं को पता लगाना है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से क्या–क्या लाभ प्राप्त किये जा सकते है? इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों मे हो रहे सामाजिक आर्थिक सुधार के आयाम को व्यवस्थित रूप से दर्शाना है। जिससे समावेशी विकास की संकल्पना को प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों मे उपलब्ध संसाधनां के संदर्भ मे यह पता लगाना है कि की प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किस प्रकार से संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी दोनों का आयाम व्यपक और विस्तृत है परंतु इनका ज्यादा से ज्यादा सह–संबंध और अंतरसंबंध स्थापित करने वाले पक्षों का मूल्यांकन कर सुझाव के रूप मे प्रस्तुत करना है जिससे ग्रामीण विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। समय और स्थान के साथ प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व मे बदलाव होता है इसलिए इन पहलुओं का आनुप्रयोगिक रूप से उपयोग करना है जिससे नकारात्मक प्रभाव से भी बचा जा सके इसके साथ ही अध्ययन का उद्देश्य है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पर्यावरण की गुणवत्ता और उसके मानकों मे कोई गिरावट न हो वरन् उसके स्तर मे सुधार ही किया जाए।

विधितंत्र :– शोधकार्य को कमबद्ध अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमे प्राथमिक ऑकड़ों के रूप मे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रभाव मूल्यांकन और विविध प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है जिससे अध्ययन क्षेत्र का सूक्ष्म और सत्यता के साथ परीक्षण किया जा सके और परिणाम स्वरूप शोधकार्य को अधिक से अधिक तार्किक एवं वैज्ञातिक बनाया जा सके। इसके अलावा शोधकार्य मे द्वितीयक ऑकड़ों का भी प्रयोग किया गया है जिसमे विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, समाचार पत्रों का अध्ययन, शोध पत्रिकाओं का विश्लेषण ऑकड़े तथा तुलनात्मक अध्ययन को लिया गया है। जिससे ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी के संदर्भ मे सांख्यकीय विश्लेषण एवं व्यवहारिक पक्षों मे सामंजस्य बनाया जा सके। शोधकार्य मे जटिलता और दोहरेपन की समस्या से बचने के लिए विधितंत्र का भी प्रयोग किया गया है जिसमे ऑकड़ों के कमबद्धीकरण,

तुलनात्मक अध्ययन और विभिन्न सांख्यकीय विधियों को शामिल किया गया है। इससे अध्ययन को सैद्धान्तिक उपागम के साथ–साथ व्यवहारिक पक्षों मे भी अनुप्रयोग किया जा सके और निष्कर्ष के रूप मे ग्रामीण विकास को त्वरित गति और दिशा दी जा सके।

अध्ययन क्षेत्र :– ग्रामीण विकास म प्रौद्योगिकी की भूमिका के संदर्भ मे इसके व्यवहारिक परीक्षण और अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मे है जो प्रायद्वीपीय पठार का बघेलखण्ड क्षेत्र मे स्थित है। प्रशासनिक रूप से रीवा जिला 11 तहसील, 9 विकासखण्ड और 710 ग्राम पंचायत मे विभक्त है। रीवा जिला मध्य प्रदेश का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ मे यह राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। रीवा जिला प्राकृतिक और मानव ससाधन से प्रचुर है परंतु विकास और अर्थव्यवस्था के संदर्भ मे इसका स्थान राज्य मे नीचा है। रीवा जिले मे पठारी क्षेत्र होने के कारण कृषि का पूर्ण विकास नही हो पाया है तथा यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 7 गुजरता है जो अन्य महानगरों से जोड़ता है। रीवा जिले की साक्षरता 72.6: है जो राष्ट्रीय साक्षरता अनुपात (74.14:) से कम है यहां का लिंगानुपात 931 है जो राज्य लिंगानुपात के बराबर परंतु राष्ट्रीय लिंगानुपात (943) से कम है। इसके अलावा सीमान्त किसान, दैनिक श्रमिकों की संख्या ज्यादा है तथा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्स अनौपचारिक कार्यों मे संलग्न है। रीवा जिले मे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यो मे महिलाओं की भागीदारी सीमित है तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं के प्रति भेदभाव देखा जा सकता है।

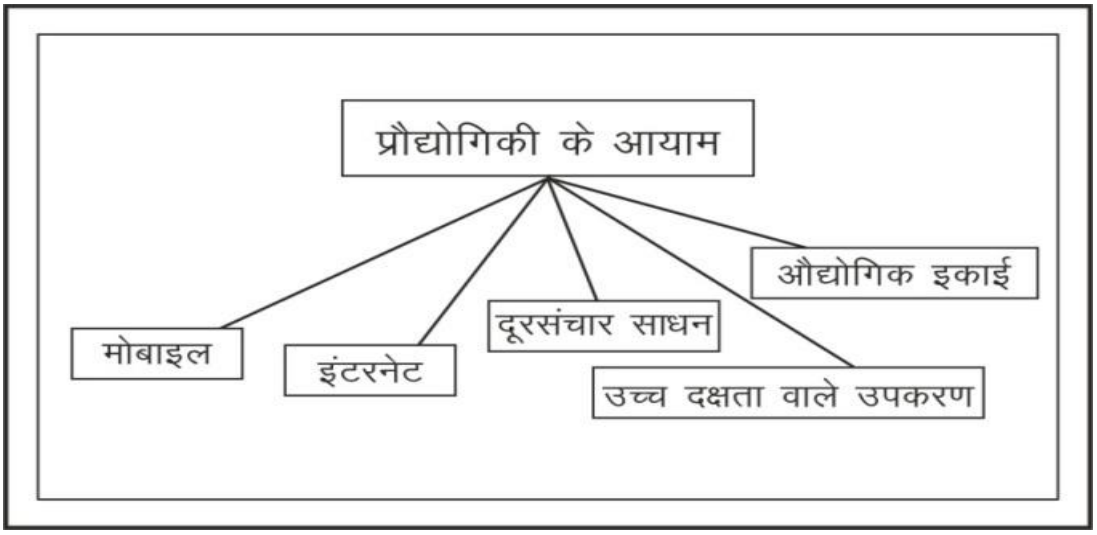

चित्र कमॉक–1

ग्रामीण विकास मे प्रौद्योगिकी की भूमिका :– विकास और सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण के लिए तकनीकी का प्रयोग आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। तकनीकी के प्रयोग से कार्यों को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। तकनीकी का प्रयोग दक्षता मे विस्तार लाती है, किसी भी देश, समाज या समुदाय के विकास के स्तर को तकनीकी विकास के स्तर से ही मापा जाता है। वर्तमान मे इसका प्रयोग समाज के सभी क्षेत्र मे हो रहा है तथा इसका दायरा भी बढ़ रहा है। तकनीकी विकास और विस्तार समाज के सभी क्षेत्र मे विविधता और सामंजस्य स्थापित होता है। ग्रामीण विकास के संदर्भ मे प्रौद्योगिकी का प्रयोग और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्यों कि यहां पर अपेक्षाकृत रूप से प्रौद्योगिकी का प्रयोग सीमित मात्रा मे होता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य

है कि ऐतिहासिक रूप से भारत मे 1960–70 के दशक मे कृषि क्षेत्र मे नई प्रौद्योगिकी के समावेश से देश मे पहली हरित कांति आयी और देश अपने खाद्यान जरूरतों के हिसाब से आत्म निर्भर हो गया। 1980–90 के दशक के दौरान टेलीवीजन और दूरदर्शन के क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी के समावेश से ही कांतिकारी बदलाव आए और देश मे अगले 20 वर्षों मे टेलीवीजन देखने वालों की संख्या 7: से 42: तक हो गई जो अब 2010 के दशक मे इसका दायरा 85: तक हो गया है। 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक मे दूरसंचार प्रौद्योगिकी मे विकास और विस्तार से इस क्षेत्र मे कांतिकारी बदलाव आया तथा 2015 तक देश मे मोबाइल फोन उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 70: तक हो गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी ने अलग–अलग क्षेत्र मे यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासन, रोजगार, वित्तीय लेनदेन सामाजिक विकास योजनाओं मे उपयोग से इनमे व्यापक सुधार और विकास हुआ।

ग्रामीण विकास मे तकनीकी के प्रयोग का व्यापक प्रभाव अध्ययन क्षेत्र रीवा जिला मे भी देखने को मिला है जिसमे लगभग सभी क्षेत्र मे इसका प्रभाव देखा गया। रीवा जिले मे कृषि क्षेत्र मे लगातार प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ रहा है जिसमे कृषि उपकरण, बुवाई साधन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, भंण्डार सुविधा मे विस्तार, परिवहन साधन मे त्वरित विकास न कृषि के उत्पादन प्रणाली मे मूलभूत रूप से बदलाव देखा गया। रीवा जिले मे प्रौद्योगिकी प्रयोग का ही परिणाम माना जाएगा कि यहां पर कृषि क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है जिसका सीधा और व्यापक लाभ किसानों, उपभोक्ताओं और श्रमिकों को हो रहा है। मौसम पूर्वानुमान और मृदा गुणवत्ता परीक्षण जैसे प्रौद्योगिकी ने किसानों की असामयिक नुकसान को नियंत्रित करने का कार्य किया है। किसानों से ऑनलाइन नीलामी, ई–बाजार और उनकी कीमत सीधी बैंक खाते मे आने से पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार जैसे पहलू को नियंत्रित किया जाने लगा।

सूचना प्रौद्योगिकी ने रीवा जिले मे विशेष रूप से ग्रामीण विकास को गति प्रदान किया है। वर्ष 2000 तक जिले मे इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या नगण्य थी परंतु 2010 मे यहां 12: किसान इंटरनेट से जुड़ गए थे तथा 2015 के ऑकड़े के अनुसार 48: किसान सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़कर विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेट के विस्तार ने ग्रामीण जीवन मे अमूलचूक परिवर्तन किया है जिसमे ऑनलाइन वित्तीय लेन–देन 20: की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। बैंकिंग प्रणाली मे नई प्रौद्योगिकी इंटरनेट बैंकिंग मे 10: किसान उपयोग करने मे दक्ष हैं इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे कुल बैंक खाता धारकों मे से 90: के पास ए टी एम कार्ड धारक है और व लगातार के साथ इसका प्रयोग भी करते हैं। सरकार द्वारा हाल ही मे किये गये विमुद्रीकरण और नई मौद्रिक योजनाओं का प्रभाव भी रीवा जिले मे देखा जा सकता है। लोगों मे इंटरनेट बैंकिंग के प्रति रुझान बढ़ा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्राथमिकता मिलने लगी है। विभिन्न प्रकार के सहायकी को लाभार्थियों के बैंक खाते मे सीधे राशि मिलती रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे रीवा जिले के साथ–साथ पूरे भारत मे 2010 तक कुल आर्थिक कार्यों का 90: हिस्सा आनौपचारिक क्षेत्रक के रूप मे था जो नई प्रौद्योगिकी और नीतियों के परिणाम स्वरूप इसमे तेजी से गिरावट हुई है। वर्तमान मे ग्रामीण क्षेत्रों मे तकनीकी सुधार, ऑनलाइन रिकार्ड और आधार कार्ड से जोड़ने के परिणाम स्वरूप ग्रामीण उपभोक्ताओं मे नियम कानून और वित्तीय लेनदेन के संदर्भ मे जागरुकता देखी जा रही है। पिछले एक वर्श मे ही अनौपचारिक क्षेत्र मे 15: की गिरावट दर्ज की गई।

प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हाल ही मे सरकार की विकास आधारित योजनाएं जिसमे प्रधानमंत्री जन–धन योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मोबाइल बैंकिंग, प्रशासन इत्यादि क्षेत्र मे पारदर्शिता बढ़ी है। प्रौद्योगिकी विकास के संबंध मे आधार नंबर की विशिष्ट पहचान और बायोमिट्रिक पहचान प्रणाली ने ग्रामीण विकास को कई कीर्तिमान स्थापित किये तथा भविष्य मे इसके कई लाभ और देखे जा सकते हैं। सभी विभाग, सरकारी योजनाएं, व्यवसाय को आधार नंबर से जोड़ने के परिणाम स्वरूप व्यापक पारदर्शिता आई तथा कई

गैरकानूनी कार्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। यह तकनीकी व प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे आधार पंजीयन और उसका प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण, सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण पक्षों मे सुगमता से किया जा रहा है। रीवा जिले मे वर्तमान मे 98ः आधार पंजीयन का स्तर प्राप्त कर चुका है जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धी है इसके साथ ही जिले मे सरकारी योजनाओं की लाभार्थियों मे 60ः तक वृद्धि अंकित की गई जो इसी आधार नंबर का ही परिणाम है। इसी प्रकार आधार कार्ड का सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैस कनेक्शन, रोजगार पंजीयन और छात्रवृत्ति वितरण मे 98ः तक की पारदर्शिता प्राप्त की जा सकी है।

रीवा जिले मे प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई–गवर्नेंस और विभिन्न प्रशासन मे प्रयोग किया जा रहा है। जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता मे वृद्धि, सामाजिक और आर्थिक अंकेक्षण मे विस्तार तथा समय की सीमित अवधि मे सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे जिले के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है जो शिक्षण के क्षेत्र मे पारदर्शिता और शिक्षा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण साधन बन रहा है।

रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी का प्रभाव महिलाओं पर भी देखा जा सकता है लगभग 30ः महिलाएं मोबाइल फोन का प्रयोग करती हैं। जनधन याजना के माध्यम से 40ः महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है का बैंक मे खाता संचालित करती हैं। तकनीकी के प्रयोग से ही जिले मे वर्तमान मे 1300 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह संचालित है जो महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, बचत और सामाजिक उत्थान का माध्यम के रूप मे काम कर रहा है। महिलाओं मे साक्षरता के साथ–साथ डिजिटल साक्षरता को बल मिला है तथा नवाचार और नये जीवन शैली को प्रोत्साहन भी देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने स्त्री–पुरुष के बीच सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक भेदभाव कम करने का काम किया है तथा महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन स्तर सुधारने और ग्रामीण विकास मे योगदान दे रहा है। चित्र कमांक 2 के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर दिए गए बिन्दुओं से देखा जा सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय व अन्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हो रहा है जिसमे रीवा जिला के साथ–साथ भारत के लगभग सभी क्षेत्रों मे इसका पभाव देखा जा सकता है।

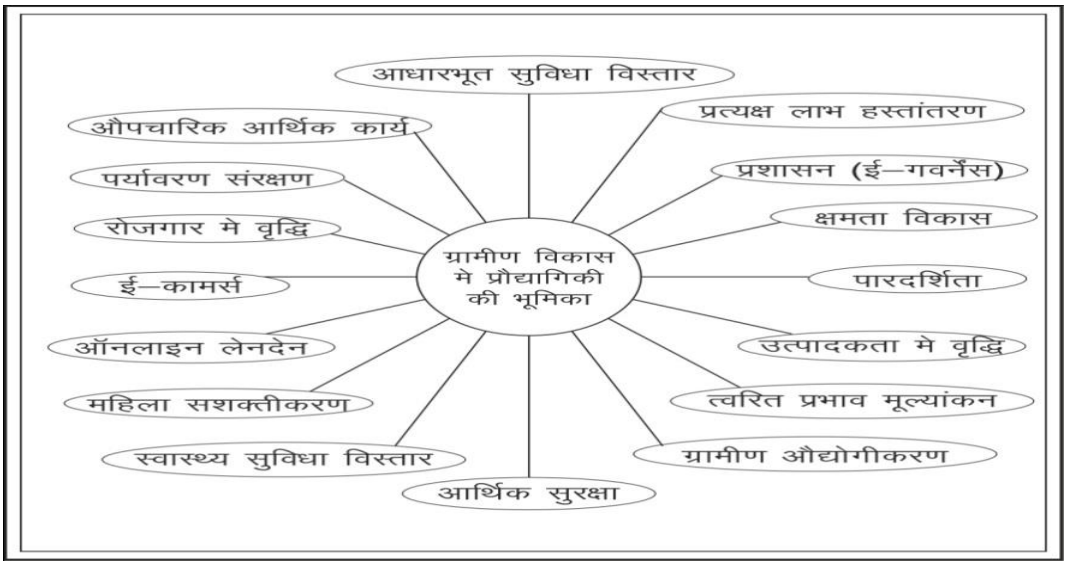

चित्र कमॉक–2

तकनीकी का प्रयोग किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वरदान हो सकती है लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से तथा उसमे सुधार कमबद्ध रूप से और नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। जिससे उसका सकारात्मक लाभ समयानुसार प्राप्त किया जा सके। प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपने आप मे एक नवाचार का प्रसारण और आधुनिकता का वाहक होती है परंतु इसके स्थानांतरण के माध्यम मे शिक्षा, परिवहन प्रणाली, स्वास्थ्य, तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि के रूप मे होता है जो चित्र कमांक 3 मे स समझा जा सकता है। आधारभूत संरचना विकसित होना प्रौद्योगिकी के लिए नितांत आवश्यक है तभी विकास को सशक्त दिशा प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग का प्रशिक्षण एवं उसके कार्यकुशलता पर दक्षता होनी चाहिए तभी अधिकतम लाभ को प्राप्त किया जा सकता है।

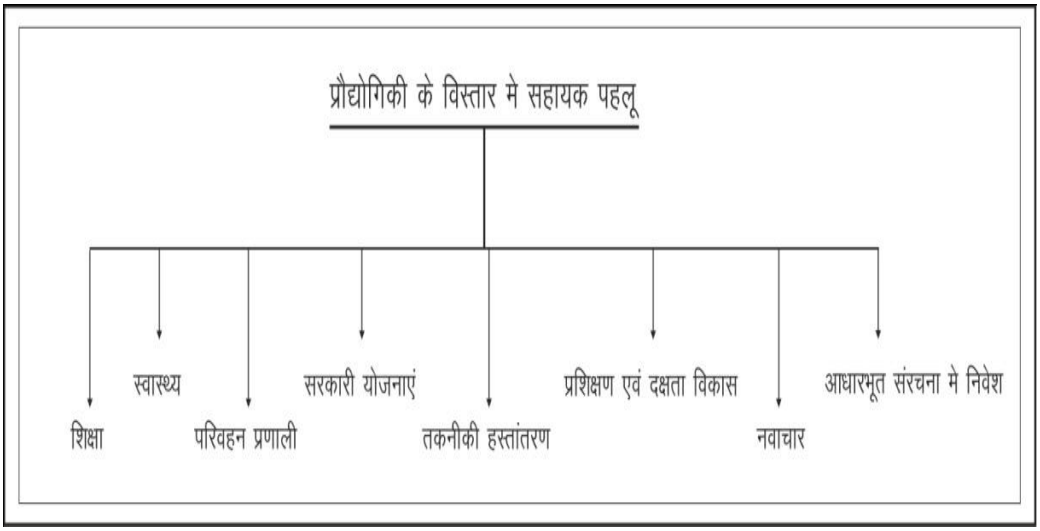

चित्र कमॉक–3

निष्कर्ष एवं सुझाव :– ग्रामीण विकास के संदर्भ मे प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक सबल और सशक्त माध्यम हो सकती है परंतु इसके व्यवहारिक कियान्वयन और परिणाम मे कई प्राकृतिक और मानवीय अवरोधक भो देखे जा सकते हैं। भारतीय समाज मे ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः परंपराओं, रूढ़ियों, पुरानी मान्यताओं और सीमित संसाधनों के वजह से प्रौद्योगिकी का पूर्णतः प्रयोग नही हो पाता इसके अलावा उचित देखरेख, विद्युत का आभाव तकनीकी क्षमता वहन करने मे असमर्थता भी इसके प्रति बाधक के रूप मे होती है। रीवा जिला मे मुख्य अवरोधक घटकों मे उपरोक्त सभी पहलू आसानी से देखे जा सकते हैं जो इसके सकारात्मक प्रभाव को सीमित करता है। रीवा जिले मे लोगों के दिमाग मे नई प्रौद्योगिकी के प्रति संशय और अविश्वास बना रहता है इसके अलावा लोगों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औषत से काफी कम है जिसमे लोग नई प्रौद्योगिकी को वहन कर सकने मे असमर्थ होते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारी युवा जनसंख्या शहरों की ओर नियमित काम की तलाश मे पलायन करती है जिससे नवाचार के प्रसारण का दायरा काफी सीमित हो जाता है तथा रोजगार सुरक्षा का आभाव, निम्न आय कृषि कार्यों मे संलग्नता स्वंय तकनीकी प्रयोग को सीमित कर रहा है। यद्यपि मध्य प्रदेश भारत के सभी राज्यों मे लगातार बिजली आपूर्ति करने वाला देश का अग्रणी राज्य है इसी प्रकार रीवा जिले मे भी विद्यत आपूर्ति होती है परंतु ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर 97: है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि रीवा जिले के मात्र 72: ग्रामीण मकान विद्युतीकृत हैं जिससे प्रौद्योगिकी के प्रयोग और उसके लाभ के दायरे को सीमित करता है। आमतौर पर मोबाइल उपयोगकर्ता 60: से ज्यादा हैं परंतु इसके बाद

बिजली कनेक्शन न होना इसके लिए प्रौद्योगिकी के अन्य पक्ष महत्वपूर्ण अवरोधक है। इसके अलावा ग्रामीण परंपराएं, मान्यताएं और शिक्षा का सीमित साधन प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सीमित करता है।

किसी भी समाज, सरकार या संस्थान का आखिरी उद्देश्य है विकास एवं सामाजिक कल्याण। इस संदर्भ मे प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विकास के सारे रास्ते खोले जा सकते हैं तथा जीवन स्तर मे सुधार लाया जा सकता है। ग्रामीण विकास के संदर्भ मे प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है और इसके प्रभाव त्वरित रूप से देखे जा सकते हैं परंतु वास्तविक रूप से रीवा जिला मे ग्रामीण विकास के लिए कई रणनीतिक सुधार और उपाय करने होंगे जिससे विकास को प्रोत्साहन मिल सके। इन सुधार मे आधारभूत सुविधा विस्तार, शिक्षा और साक्षरता मे वृद्धि, तकनीकी हस्तांतरण और कुशल तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही सभी क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, सब्सिडी, समय–समय पर निगरानी और इसके प्रभाव मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए तभी प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय स्तर पर भी चरितार्थ किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :–

- Asia Development Bank, (2001): Growth and Change in Asia and the Pacific, (key indicators), Oxford University press, London.
- Baboo, Balgovind (1992): Technology and Social Transformation: The Case of the Hirakud Multi-Purpose Dam Project in Orissa, Concept Publishing Company, New, Delhi.
- Bresnahan, Timothy and Manuel Trajtenberg (1995): General Purpose Technologies: “Engines of Growth”, Journal of Econometrics, pp. 65 & 83-108.
- Brown, Lester R., (1971): Social Impact of the Green Revolution, Carnegie, New York.
- Desai, D.K. (1966): Technological Change and its diffusion in Agriculture, Indian Journal of Agriculture Economic, No. 1, Vol. XXI.
- District handbook (2105): Rewa, Statistical Department Madhaya Pradesh
- Economic Survey (2006-07): Government of India, Ministry of Finance, Economic Division, New Delhi
- Mcmith, D.R. (1953): Rewa: Its history, geography and political scenario, Bilmuth Publication, Prinseten.
- Mishra, R.P. & Sundaram, K.D. (1979): Rural development- Perspective and Approaches, Sterling Publication, New Delhi. p425.
- Raddy, V. and Yadagira, M., (2008): Rural development in India: Policy and initiatives, New Century Publication, New Delhi.
- Singh, Nirvikar (2004): Information Technology and Rural Development in India, in Integrating the Rural Poor into Markets, Bibek Debroy and Amir Ullah Khan, eds., New Delhi: Academic Foundation, pp. 221-246.
- Verma, Vandana and Indu Grover, (2006): Science and Technology in Rural Homes, Daya Publishing House, New Delhi.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Problems and Prospects of Industrial Establishments in Telangana State

Dr. S. Lingamurthy
UGC-Dr. S. Radhakrishnan Post Doctoral Fellow at CESP, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi

Abstract : This paper endeavour to make an attempt on problems and prospects of industrial establishments in Telangana State using Sixth Economic Census Provisional results and brief industrial profile of all districts of Telangana for Registered Industrial Units provided by Ministry of Micro Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India. To analyze the status of industrial establishments, variables like type of establishment, area wise distribution, regional disparity, employment and investment have been used. To examine the performance of establishments, ratios such as district-wise share in total establishments and employment, employment share per unit of establishment, status of industrial estates, average annual growth rate of establishments and employment over Fifth Economic Census have been covered. Compound Annual Growth Rate (CAGP) is also used for different regions within the state for registered industrial units and its employment over the period.

The analysis shows that, 20.86 lakh establishments have been employing about 56.12 lakh persons which show less than three persons per establishment by engaging 56.3 percent of the hired workers in the State. Out of total establishments, 56.6 percent operating in rural areas with 41.9 percent share in total employment. 31.4 percent of the establishments operate from outside household without fixed structure.

The Growth rate in number of establishments in Sixth Economic Census reveals 77.82 percent in Telangana against to 41.73 percent at All India, where as the growth of employment in the state is 37.78 percent against to 34.35 percent in All India. The Compound Annual Growth Rate for registered industrial units in the State during FY 1996-97 to 2011-12 accounted for 3.24 percent with significant variation among the regions, i.e., 3.94 percent in Region-I and 2.48 percent in Region-III.

Key Words : Micro, Small Scale, Industries, MSME, Economic Census, Growth and Performance.

Problems and Prospects of Industrial Establishments in Telangana State :

Introduction : Micro and Small Scale Enterprise sector always plays an important role in providing employment comparatively with lower capital of investment, high standard of living, and balanced economic growth in rural and backward areas and these enterprises are complementary to large industries as ancillary units. Micro and Small scale sector contributes enormously to the socio-economic development of the country[33]. The National Manufacturing Policy of the Twelfth Five Year Plan of India aims at increasing the share of manufacturing in Gross Domestic Product (GDP) from the present 16 percent to 25 percent by 2025[34]. In achieving the stated goal, Government of India and policy makers consistently made their efforts. Though, the growth performance of the manufacturing sector in the recent period is not seems to be in line with the goal achievement. The low growth of the manufacturing sector has led to strengthen the low employment profiled service sector. Growth of productivity is an important source for manufacturing growth, but there are

[33] See, Brief Profile of Telangana Industries, Ministry of MSME, Government of India (GoI)
[34] Twelfth Five Year Plan (2012-17) Economic Sectors – Volume II, Planning Commission, Government of India, 2013

many evidences after reviewing several studies showing that decline of productivity after the introduction of economic reforms. However, some studies showed revival in the second decade of economic reforms[35].

However, over the periods, despite having manufacturing policies for India as well as States on their own, this sector has been facing severe constraints in achieving high growth owing to power shortage, limited opportunities for technological modernization, insufficient availability of cheap credit and bias in the financial sector reforms in favour of larger firms[36].

Definition of Micro and Small Scale Enterprises : These units consists of many enterprises engaged in production and rendering services, subject to limiting the factor of investment in plant & machinery and equipments respectively as defined by MSME Act, 2006, Government of India. For manufacturing sector, an enterprise is classified as: a) micro enterprise, if investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees; b) small enterprise, if investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; In case, enterprise is engaged in providing or rendering of services, it is classified as: (a) micro enterprise, if investment in equipment does not exceed ten lakh rupees; (b) small enterprise, if investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees[37].

Micro and small scale sector has it's significant footprint on Telangana development and it is home for several major manufacturing industries such as bulk drugs, pharmaceuticals, agro-processing, cement & mineral-based industries, high precision engineering, textiles, leather, apparels, automobiles and auto components industry, spices, horticulture, poultry farming, biotechnology, defence equipment etc. Manufacturing sector contributes above 55 percent in total industrial sector Gross Value Addition (GVA) but the pattern of investment is concentrated in only few industries such as pharmaceuticals, other non-metallic mineral products, rubber and plastic products, electrical equipments and food products which account for about 54 percent in fixed capital within total manufacturing sector of Telangana State.

Methodology : This paper is analysed both Sixth Economic Census (EC) and Brief Industrial Profiles of Telangana State provided by Micro Small and Medium Enterprises (MSME) – Development Institute, Ministry of MSME, Government of India, Hyderabad where the data has been adopted from the District Industrial Centres (DICs).

Sixth EC (2013) brought out on number of enterprise establishments[38] and persons usually working in respect of all the sectors of economy excluding crop production, plantation, public administration, defence & compulsory social security services activities. By using this 6th EC, the growth performance of establishments and employment over 5th EC; distribution of establishments across the districts of Telangana State and per unit of employment has been examined.

For registered industrial units and their employment and investment, brief industrial profiles data has been considered. There are total 10 districts (Of course these are further divided into 31 districts which came into function on 2nd October, 2016) in Telangana state. All these 10 districts have been formed into three regions based on their geographical locality and industrial penetration. They are namely, Region-I formed

[35] See, Goldar, 2014
[36] See, Thomas, 2014
[37] See, Annual Report, 2014, M/o. MSME, GoI

[38] the establishments are entrepreneurial units situated in a particular location in which predominantly focus on one kind of economic activity carried out like part of the goods and/or services produced by the unit goes for sale. The activity may be carried out within fixed premises i.e., permanent structure or without having any permanent structure.

with Hyderabad and Ranga Reddy districts where the predominant share of industries took place. Region-II consist Medak, Karimnagar, Nizamabad and Adilabad districts based on their geographical area. Remaining four districts such as Mahabubnagar, Nalgonda, Warangal and Khammam covered under Region-III. The growth performance of registered industrial units, employment and triennium share of investment along with its change in percentage has been analysed district-wise by considering 16 years of time series data from 1996-97 to 2011-12. However, for the analysis of employment and investment it is being used only 13 years of data from 1996-97 to 2008-09 owing to non-availability of further data for some districts.

This paper has been presented in five sections; section-I covers with the background of the micro and small scale industrial sector and its significance in Telangana State, section-II elaborates methodology; section-III covers the results of Sixth EC and Registered Industrial Units; section-IV explains the status of industrial estates and clusters; section-V concludes with existing problems and policy suggestions.

Structure of Establishments, Registered Industrial Units and Employment : The total number of establishments in Telangana State is estimated about 20.86 lakh units engaged in different economic activities other than crop production, plantation, public administration, defence & compulsory social security services by providing employment to 56.12 lakh persons. Though, majority of the establishments located in rural areas (56.61 percent), predominant share of employment provided by urban areas about 58.12 percent engaging with 3.6 persons of employees per unit of establishment. The average size of employment per unit is very low in rural areas accounted for less than two persons where the state average for the same is 2.69 persons per unit (Table–1 & Graph–1).

There is a significant disparity in number of establishments and employment among the districts in the State. Graph-2 & Table-2 shows that urban areas are in better position for attracting high number of establishments and employment and also in hiring more workers rather than rural areas with evidenced in Hyderabad and Ranga Reddy districts. Hyderabad district stands first in terms of both sharing in establishment with 16.97 percent and employment with 26.27 percent by hiring more than four persons per unit of establishment. Adilabad district forms least number in sharing mere 5.29 percent of establishments and 3.92 percent of employment by hiring less than two persons per unit. It is examined that, only Hyderabad and Ranga Reddy districts are above the State average in providing per unit of employment and remaining eight districts engaging with slightly below two or just above it in per unit of employment in the state.

Table – 1: Area-wise Establishments and Employment in Telangana

Item	Rural	Urban	Total
No. of Establishments	11,81,123 (56.61%)	9,05,146 (43.39%)	20,86,269 (100%)
No. of Persons Employed	23,50,588 (41.88%)	32,61,612 (58.12%)	56,12,200 (100%)
Employment Share Per Unit	**1.99**	**3.60**	**2.69**

Source: Sixth Economic Census, Provisional Results

Graph – 1: Share of Establishments and Employment in Rural and Urban Areas

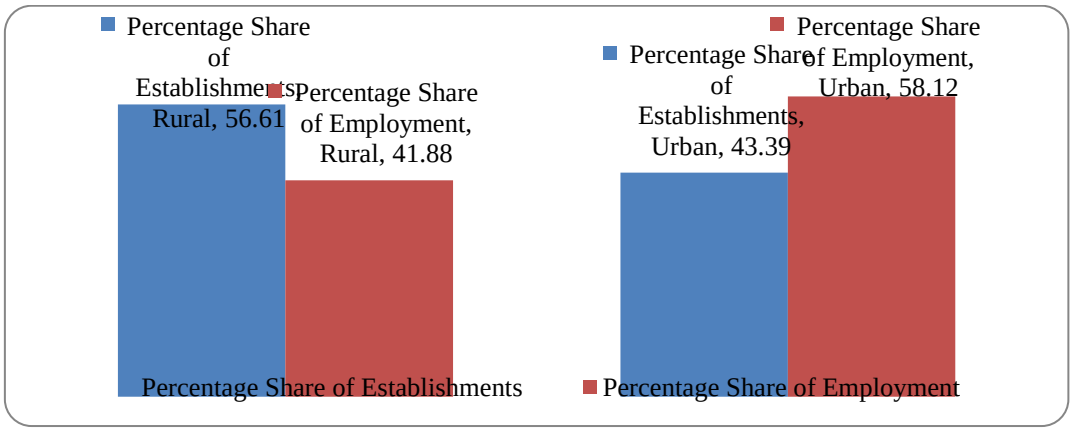

Graph – 2 : District-wise Share of Establishments and Employment

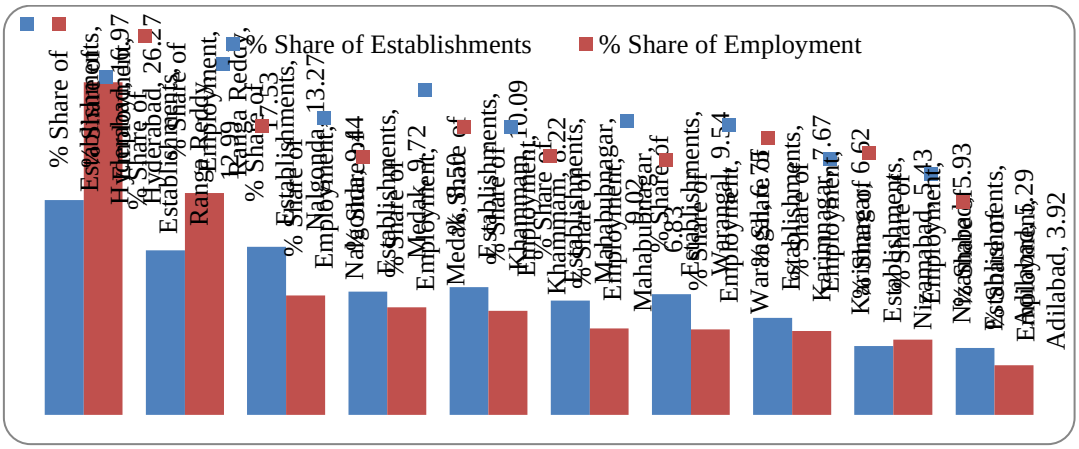

Table – 2 : Distribution of Establishments and Employment in Telangana

S. No.	District	No. of Establishments	No. of Persons Employed	Employment Per Unit
1	Hyderabad	3,54,047	14,74,118	4.16
2	Ranga Reddy	2,71,033	9,84,011	3.63
3	Nalgonda	2,76,912	5,29,643	1.91
4	Medak	2,02,883	4,76,959	2.35
5	Khammam	2,10,414	4,61,249	2.19
6	Mahabubnagar	1,88,199	3,83,184	2.04
7	Warangal	1,99,065	3,78,712	1.90

8	Karimnagar	1,60,054	3,71,512	2.32
9	Nizamabad	1,13,357	3,33,056	2.94
10	Adilabad	1,10,305	2,19,756	1.99
Telangana State		**20,86,269**	**56,12,200**	**2.69**

Source: Sixth Economic Census, Provisional Results

Establishments by Its Nature : It is observed that (Table-3 & Graph-3), the majority of the establishments 7.47 lakh forms 35.79 percent in total establishments found to be operating in inside household; 6.85 lakh establishments with 32.84 percent operating from outside household with fixed structures and remaining 6.54 lakh establishments with 31.37 percent operating from outside household without fixed structures in the state. Thus, it can be said that, majority of the establishments (43.76%) operating in inside household and 36.74 percent outside household without fixed structures are found to be in rural areas. The majority of the establishments operating from outside household with fixed structures are found in urban areas with 49.47 percent in the state. Out of 6.54 lakh establishments operating from outside household without fixed structures, about 4.27 lakh (65.23%) establishments are found to be in rural areas and 2.27 lakh (34.77%) establishments are in urban areas. Khammam district with 15.81 percent stands first by holding highest number of Establishments and Adilabad district (2.37 percent) with least number of Establishments in the same category in the state.

Table – 3: Distribution of Establishments by Its Nature

Area	Outside HH With Fixed Structure	Outside HH Without Fixed Structure	Inside HH	All
Rural	2,37,401 (34.65)	4,26,810 (65.23)	5,16,912 (69.23)	11,81,123 (56.61)
Urban	4,47,799 (65.35)	2,27,550 (34.77)	2,29,797 (30.77)	9,05,146 (43.39)
All	**6,85,200**	**6,54,360**	**7,46,709**	**20,86,269**

Source: Sixth Economic Census, Provisional Results

Graph - 3: Distribution of the Establishments by its Nature and Area

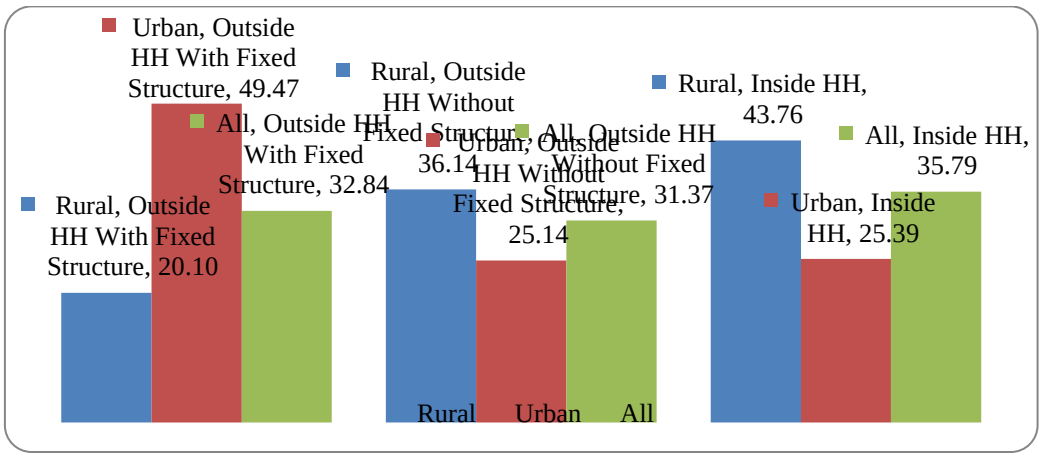

It is observed that in Table – 4, the establishments predominantly run by male workers. In rural areas, most of the establishments operate by household members with least hired workers, where it is just opposite in urban areas. At the state level, hired workers account for about 56.25 percent of the total employed persons and the corresponding figures in the rural and urban areas are 39.89 percent and 68.04 percent respectively. In a similar way, majority of the non-hired workers engaged in rural areas with above 60 percent as against to 43.75 percent for state average. As it is discussed, the major share of establishments run by male workers is evidenced with 72.69 percent in urban areas which are greater than the state average 67.89 percent and corresponding results for rural areas is found to be 61 percent.

While female workers account for about 32.11 percent of the total persons employed and the corresponding figures in the rural and urban areas are found to be 38.77 percent and 27.31 percent respectively. Therefore, it can be argued that even in urban areas also it is far away in providing employment to female workers in this sector.

Table - 4: Structure of Employment by Establishments in Telangana

Percentage of Employment	Hired	Non-Hired	Male (H+NH)	Female (H+NH)
Rural	39.89	60.11	61.23	38.77
Urban	68.04	31.96	72.69	27.31
Combined	56.25	43.75	67.89	32.11

Source: Sixth Economic Census, Provisional Results

Growth in Establishments and Employment : The overall growth rate in number of establishments in Telangana State during Fifth EC (2005) and Sixth EC (2013) found to be 77.82 percent as against to 41.73 percent growth of All India. Similarly, the growth rate in Employment in the state is observed 37.78 percent as against to 34.35 percent of All India. The dramatic upsurge in growth performance in number of establishments is found to be about 112 percent in urban areas, where it is around 58.3 percent in rural areas. In the same pattern, the percentage growth rate in total employment in urban areas of the State found to be 54.35 percent and in rural areas it is observed near about 20 percent shown in Graph-4.

Graph – 4: Growth Rate (%) of Establishments and Employment over Fifth Economic Census

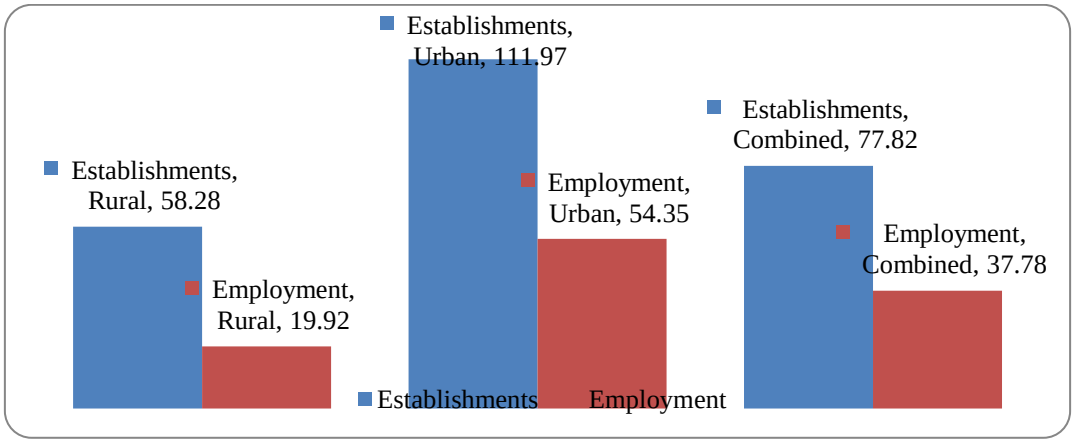

Table - 5: Growth Rate (%) of Establishments over Fifth Economic Census

District	Rural	Urban	Combined
Adilabad	118.98	91.52	110.09
Nizamabad	26.77	48.15	31.26
Karimnagar	16.60	90.04	29.74
Medak	85.87	128.28	93.49
Hyderabad	0.0	96.36	96.36
Ranga Reddy	29.09	167.19	108.94
Mahabubnagar	34.82	121.18	47.72
Nalgonda	113.03	172.12	121.26
Warangal	25.03	63.85	33.98
Khammam	113.74	143.35	121.50
Telangana	**58.28**	**111.97**	**77.82**

Source: Sixth Economic Census, Provisional Results

Table-5 shows the district wise corresponding growth rates in number of establishments and graph-5 for employment growth rate in the state. It has been evidenced in Khammam, Nalgonda, Adilabad, Ranga Reddy, Hyderabad and Medak that the growth rate is higher than the state in number of establishments with corresponding results 121.5%, 121.26%, 110.09%, 108.94%, 96.36% and 93.49% respectively. In the same pattern with slight change in the order, the growth rate in employment is also observed more than the state average growth rate with corresponding results in Ranga Reddy (90.5%), Khammam (69.56%), Nalgonda (53.96%), Adilabad (44.47%), Medak (42.43%) and Hyderabad with 30.32 percent. It is also being noticed that the negative (-8%) growth rate in employment in rural area of Warangal district and very insignificant growth rate in rural areas of Ranga Reddy, Karimnagar and Nizamabad districts with 0.25 percent, 0.82 percent and 3.29 percent respectively.

Graph - 5: Growth Rate (%) of Employment over Fifth Economic Census

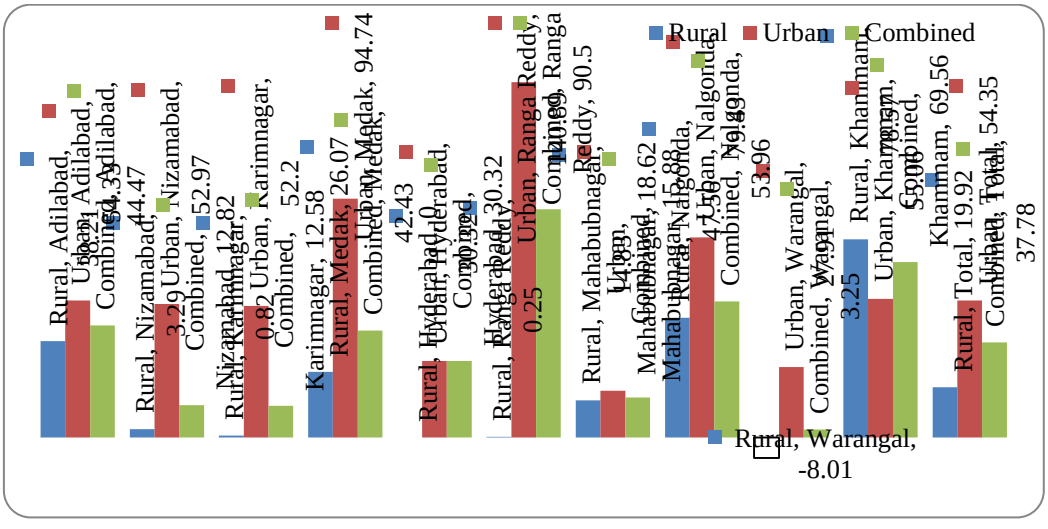

The Regional Level Analysis of Regestered Industrial Units in Telangana : Registered industrial units are such that the enterprises registered with District Industries Centers (DICs) in the State under the coverage of section 2 m(i) and 2 m(ii) of the Factories Act 1948, Government of India[39]. The annual average growth rate of registered industrial units among the regions has been examined in below graph-6. It is found that, the annual growth performance of Region-I has been drastically declined to just 2.8 percent during the recent period where the state average accounted for the same is 5.47 percent. However, the Region-I hold greater share of growth performance in the State during 1997-98 to 2008-09. The annual growth performance of the Region-II and Region-III have been improved significantly and over crossed the Region-I during 2008-09 onwards where these regions accounted for 7.34 percent and 8.42 percent respectively.

During 2000-01 to 2005-06 the annual growth performance has been registered just below 2 percent in all regions and particularly just 0.28 percent in Region-III.

The average annual growth rate has been shown in Graph-7 reveals that the average growth performance of employment by registered industrial units found to be about 9 percent from below 2 percent in all three regions during 2001-02 to 2008-09. There is significant fluctuation in growth of employment during the early period i.e., 1997-98 to 2001-02 accounted for more than 200 percent of growth to negative 45 percent in Region-I and the same has been reflected in the state growth performance.

Graph – 6: Region-wise Distribution of Annual Growth Rates in Industrial Units

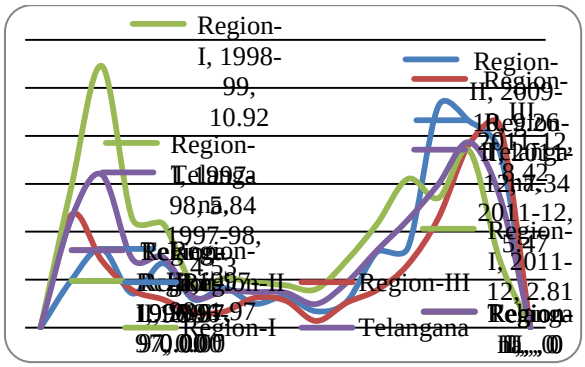

Graph – 7: Region-wise Annual Growth Rate (%) in Employment during 1997-98 to 2008-09

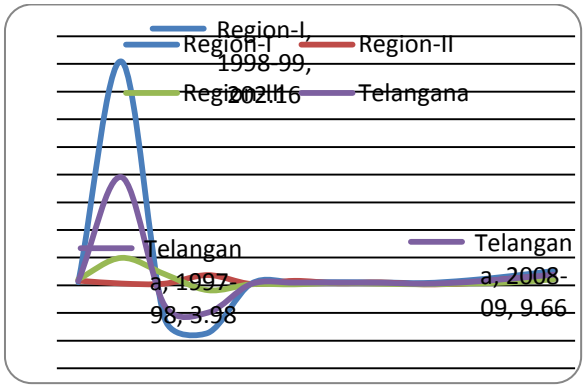

The share of registered enterprises depicted below graph-8. It is found that more than 45 percent of the enterprises located in region-I i.e., Hyderabad and Ranga Reddy districts only. The remaining 55 percent of enterprises shared by eight districts comes under region-II and region-III. The employment share for these regions in registered industries is almost stagnant in entire period except during FY 1997-98 to 199-2000 which shown in Graph-9 with near about 48 percent in Region-I, 28 percent in Region-II and about 24 percent in Region-III.

The share of employment per unit of industry has been shown in Graph-10. It is noticed that the highest number of employment per unit in Region-II which increased from near about 9 persons to around 11 persons during 1996-97 to 2008-09. The remaining regions are engaging

[39] see, Annual Report-2014, M/o. MSME, Government of India

merely below 10 persons per unit of industry in the state.

Graph – 8: Region-wise share of Registered Enterprise units in Telangana

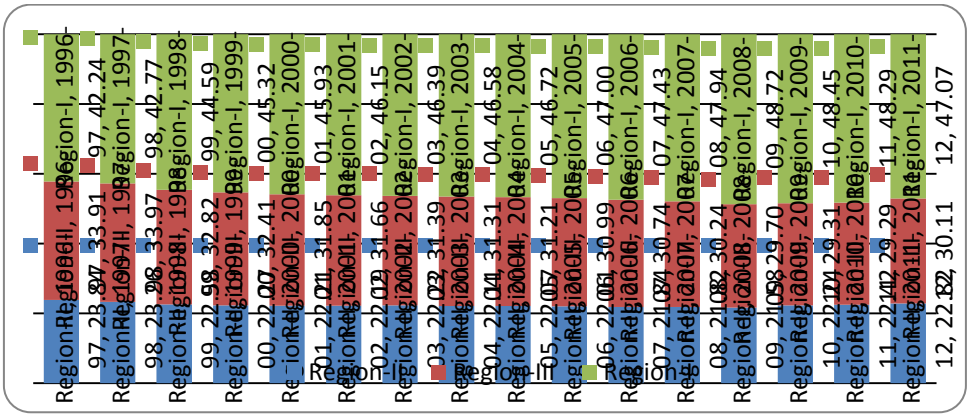

Graph – 9: Region-wise distribution of Employment Growth Shares in Telangana

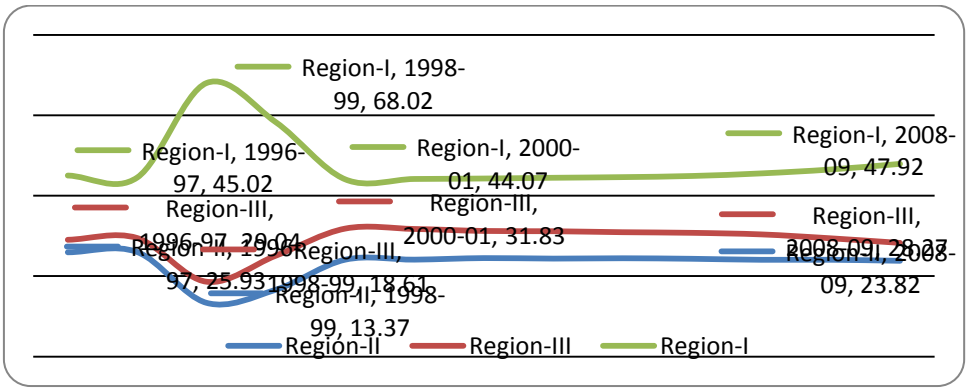

Graph - 10: Share of Employment Per Unit of Industry in the State

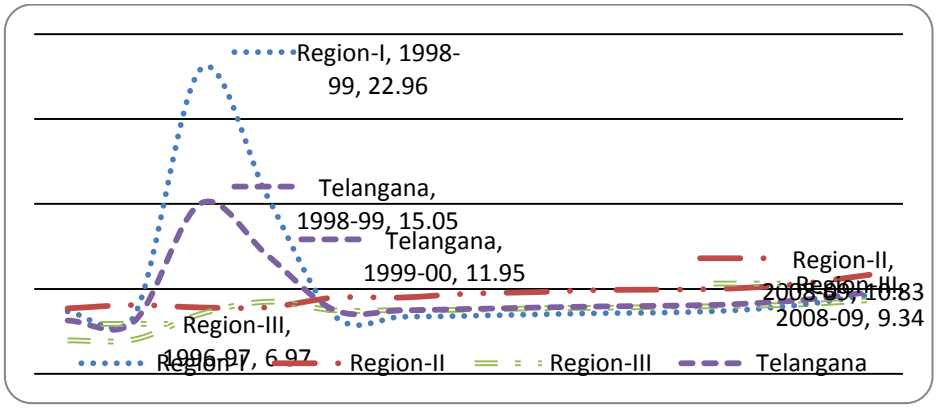

Region-wise Analysis of Compound Annual Growth Rate in Percentage (CAGP) for Industries and Employment : The CAGP is calculated for the registered industries for 16 years of period i.e., from 1996-97 to 2011-12. Region-I shows its perform with about 4 percent against to 3.2 percent of the State Growth. The growth performance of the Region-III is accounted for very low 2.5 percent where Region-II performs slightly less than the state which accounted for 2.96 percent (Graph-11).

The employment growth rate for these regions are shown in below (Graph-12). It is observed that the growth performance is almost followed with same pattern of the growth rate of industries in all three regions. Region-I stands with highest growth rate accounted for 3.94 percent against to the state growth 3.24 percent. Region-II and Region-III performed less than the state average accounted for 2.96 percent and 2.48 percent respectively.

Graph – 11: Region-wise Compound Annual Growth Rate (%) for Registered Industries

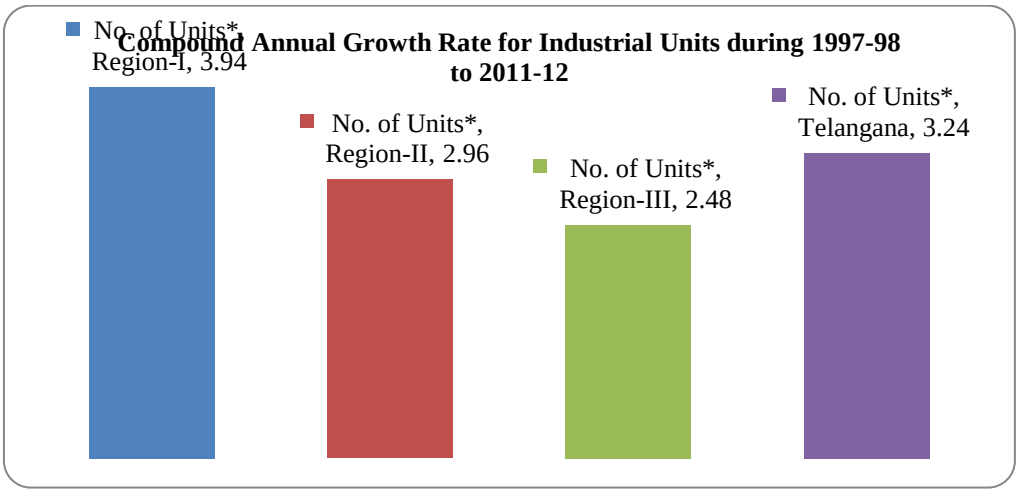

Graph – 12: Region-wise Compound Annual Growth Rate (%) for Employment

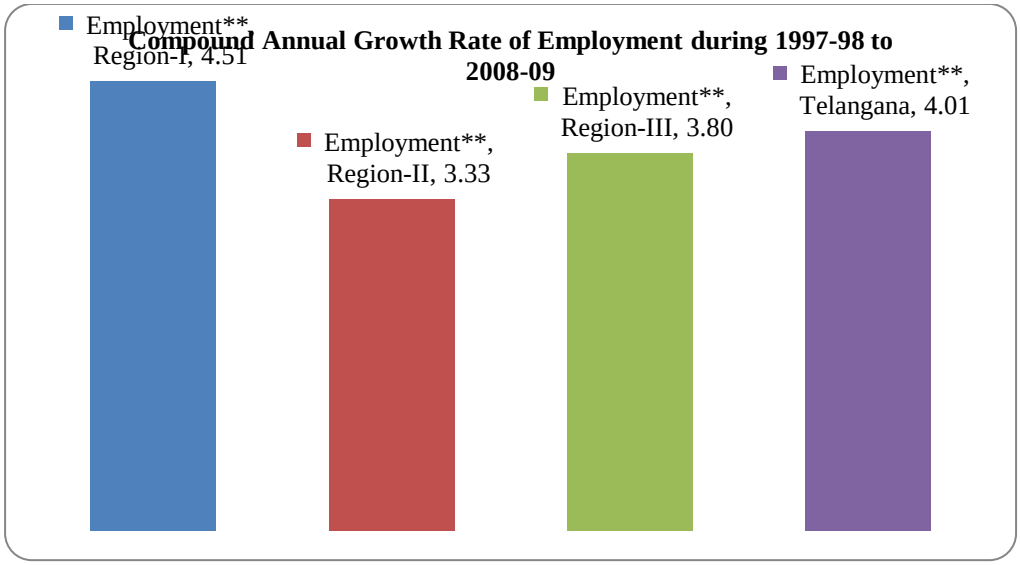

Graph – 13: District-wise Compound Annual Growth Rate (%) for Registered Industries

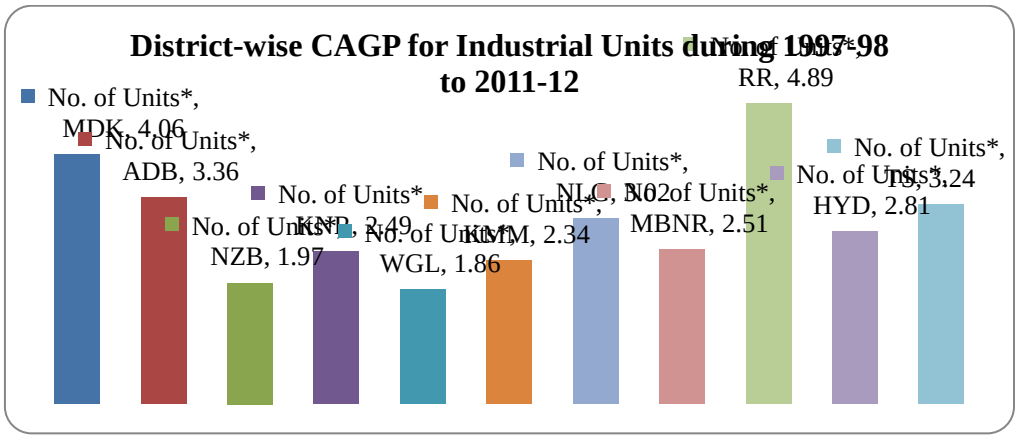

Graph – 14: District-wise Compound Annual Growth Rate (%) for Employment

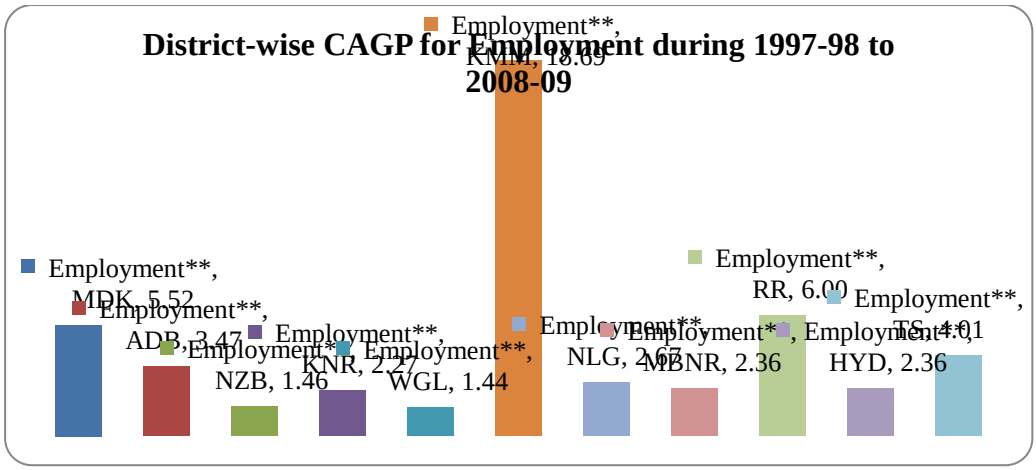

Investment : Investment is also known for capital expenditure by firms towards plants & machinery and buildings for productive purposes. It is depended on many short term and long term factors such as demand of products or services by firms and rate of returns over investment. With this background, region-wise triennium averages of investment by industrial units during 1996-97 to 1998-99 and 2006-07 to 2008-09 is examined along with the changes in investment shown in table-6.

Region-wise analysis reveals that there is a tremendous decline in investment share in region-III from 29.72 percent to 20.87 percent which is accounted for negative change with about 9 percent in the total investment. In the same way, region-I accounted for negative 0.4 percent during the same period which declined from 54.37 percent to 53.98 percent in total share. It is noticed that the share of investment is increased in region-II with 9.25 percent in total investment of the state.

The investment at district level has been observed in table-7 during 1997-99 triennium end and 2007-09 TE. The total share of investment declined in Hyderabad (-3.35 percent), Khammam (-11.48 percent) and Warangal (-0.61 percent). The only district which has attracted significant

amount of investment is Medak with 8.15 percent and followed by Ranga Reddy 3 percent, Mahabubnagar 2 percent, Nalgonda 13.3 percent. Karimnagar, Nizamabad and Adilabad forms share mere with less than 1 percent.

Table – 6: Region-wise share of Investment in Telangana

Region	1997-99 E	2007-09 E	Change
Region-I	107294.67 (54.37)	228801.33 (53.98)	121506.67 (-0.39)
Region-II	31385.00 (15.9)	106597.67 (25.15)	75212.67 (9.25)
Region-III	58657.33 (29.72)	88440.00 (20.87)	29782.67 (-8.86)
Telangana	**197337.00**	**423839.00**	**226502.00**

Graph – 15: Table – 6: Region-wise share of Investment in Telangana

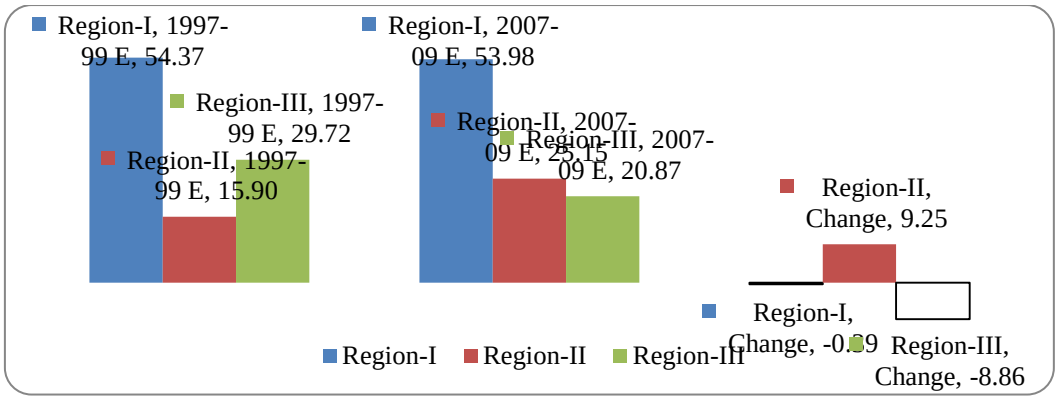

Table – 7: District-wise share of Investment in Telangana

Triennium Share of Investment (Rs. In Lakhs)			
Year	1997-99 E	2007-09 E	Change
Adilabad	2731.67 (1.38)	6775.33 (1.60)	4043.67 (0.21)
Nizamabad	4846.33 (2.46)	13439.67 (3.17)	8593.33 (0.72)
Karimnagar	8157.33 (4.13)	18236.33 (4.30)	10079.00 (0.17)
Medak	15649.67 (7.93)	68146.33 (16.08)	52496.67 (8.15)

Warangal	6534.67 (3.31)	11439.67 (2.70)	4905.00 (-0.61)
Khammam	34463.33 (17.46)	25352.00 (5.98)	-9111.33 (-11.48)
Nalgonda	13140.33 (6.66)	33866.00 (7.99)	20725.67 (1.33)
Mahaboobnagar	4519.00 (2.29)	17782.33 (4.20)	13263.33 (1.91)
Ranga Reddy	91839.67 (46.54)	209799.00 (59.50)	117959.33 (2.96)
Hyderabad	15455.00 (7.83)	19002.33 (4.48)	3547.33 (-3.35)
Telangana	197337.00	423839.00	226502.00

Graph – 16: Table – 7: District-wise share of Investment in Telangana

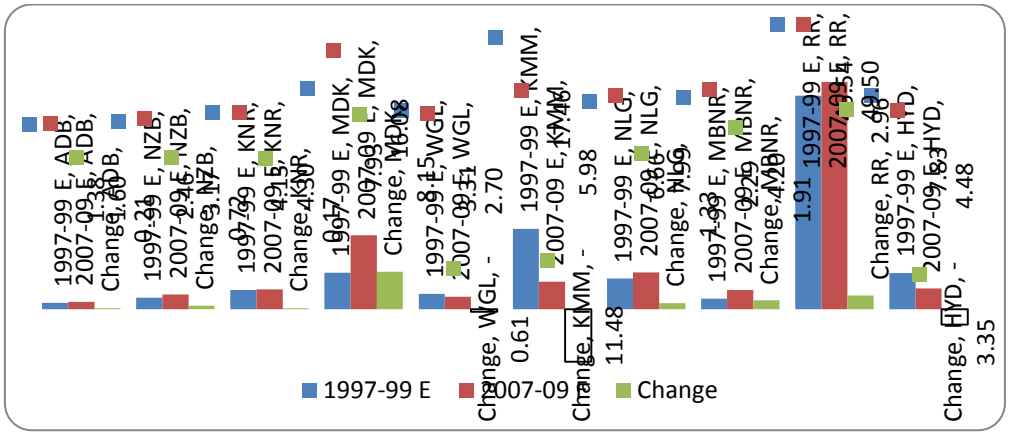

Status of Industrial Estates and Clusters in Telangana State : An industrial estate is a place where the required facilities are provided by the Government to the entrepreneurs to establish their industrial units in a particular area or region. Industrial estates have been utilized as an effective tool for the promotion and growth of micro and small scale enterprises to decentralise the entrepreneurial activity i.e., rural areas and backward areas by providing incentives, tax soaps and institutional support. The availability of developed industrial plots, ready built industrial structures in preferably convenient locations with basic infrastructure facilities like, better roads, water, electricity, availability of raw material, un-interrupted communication facilities, market facilities, credit facilities with banking services are prerequisite to attract and to encourage industries in a particular region.

In Telangana State, the industrial estates area ranges from 15 acres to 2500 acres with fully equipped internal roads, water supply, and uninterrupted electricity and approved layouts[40]. There are around 140 total industrial estates operating in Telangana State occupied in more than 25.3 thousand acres of acquired land which is developed by Andhra Pradesh Industrial

[40] See, tsiic.telangana.gov.in/industrial-parks/

Infrastructural Corporation (APIIC) (Table-8 & Graph-17). Among the total industrial estates, around 70 percent of the estates located in only two districts i.e., Ranga Reddy forms 50.36 percent and Medak with 19.42 percent and remaining minor 30 percent of the estates scattered majorly in eight districts of the state which ranges from 5.76 percent in Nizamabad and Warangal districts to 2.16 percent in Adilabad and Karimnagar districts. And it is very important to observe that Hyderabad as a district forms minuscule share in total industrial estates with just 1.44 percent. However, it is also important to notice that the greater share of industrial estate districts such as Ranga Reddy and Medak are sharing the boundaries with Hyderabad district or just adjacent.

Land acquired status also followed the same pattern with industrial estates which accounted for more than 84 percent share in both Ranga Reddy and Medak districts only. There are around 10,497 total numbers of plots with 2,536 industrial structures existing in Telangana state.

Table – 8: District-wise Industrial Estates of Telangana State

Sl. No.	District	No. of Industrial Estates	Percent	Land acquired (acres)	Percent	Total No. of Plots	Total No. of Structures	Units in Production
1	Hyderabad	2	1.44	116.82	0.46	62	45	74
2	Adilabad	3	2.16	104.55	0.41	84	53	84
3	Karimnagar	3	2.16	104.77	0.41	252	47	245
4	Mahabubnagar	6	4.32	1379.75	5.45	789	131	292
5	Khammam	6	4.32	1236.26	4.88	299	52	164
6	Nalgonda	6	4.32	279.7	1.10	520	74	295
7	Warangal	8	5.76	503.84	1.99	826	145	548
8	Nizamabad	8	5.76	202.53	0.80	655	93	372
9	Medak	27	19.42	5764.29	22.76	1832	166	1099
10	Ranga Reddy	70	50.36	15633.38	61.73	5178	1730	5595
Telangana		**139**	**100.00**	**25325.89**	**100.00**	**10497**	**2536**	**8768**

Source: APIIC, 2012; Compiled from Industrial Profile of Districts, M/o. MSME, Govt. of India

Graph - 17: Percentage of Industrial Estates in Telangana

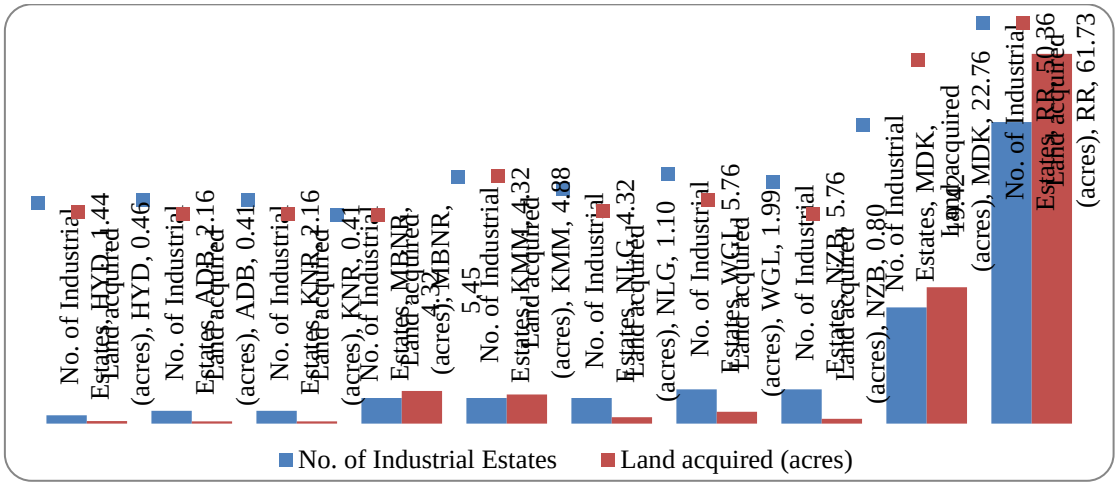

Industrial Clusters : Industrial clusters are known for inter-related industrial activities which can drive massive manufacturing production and employment in a particular region aimed at primarily export of goods and services. In Telangana, majority of the manufacturing units highly concentrated in urban areas such as Hyderabad and its adjacent area and some industrial clusters because to reduce their cost of production, transportation, electricity and availability of raw material.

It is noticed from the brief industrial profile of the Telangana districts (Table-9), there are more than 23 industrial clusters existing for Micro and Small Scale Enterprises. More than 7,400 industrial units functioning in these state sponsored clusters, providing employment to more than 2.1 lakh people. Majority of these clusters are belonged to Rice Mills, Leather Products, Powerlooms, Fan and Fan components, Granite, Bricks, Slab Cutting, Plastic, Pharma and Electronics. Rice Mill units from Khammam, Warangal and Nizamabad districts exporting their produce significantly to Bangladesh, Singapore, Thailand, Nepal and Gulf Countries. In a similar way, Granite from Khammam district exporting to developed countries such as the United States of America (USA), China, Japan, Taiwan, Germany and Australia. Slab Cutting Units from Ranga Reddy district also exporting their products to the USA, Australia, Switzerland and the Gulf Countries, etc.

Table – 9: Distribution of Clusters among the Districts of Telangana

Sl. No.	Name of the Clusters	Districts	No. of Functional Units in the Cluster	Turnover of the Clusters (Million)	Employment in Clusters	Exporting Countries
1	Rice Mills	Karimnagar, Khammam, Nalgonda, Nizamabad and Warangal	1112	18000	34700	Gulf Countries, Bangladesh, Singapore, Thailand and Nepal
2	Agri. Seed	Ranga Reddy	70	1250	12000	NA
3	Powerloom	Karimnagar and Nalgonda	834	970	24768	NA
4	Cement Plants	Nalgonda	18	4000	2000	NA
5	Plastic	Hyderabad and Nalgonda	150	3500	5000	NA
6	Granite	Khammam	600	3500	25000	USA, China, Japan, Taiwan, Germany and Australia
7	Leather	Hyderabad	1530	10200	20000	NA
8	Pharma	Ranga Reddy	391	81870	20000	US, European countries
9	Fabrication	Ranga Reddy	400	1000	4000	NA
10	Fiber Glass	Ranga Reddy	300	10000	5000	NA
11	Electronics	Ranga Reddy	250	1500	3000	NA
12	Foundry & Fan and Fan components	Ranga Reddy	700	4200	10400	NA

13	Slab Cutting	Ranga Reddy	500	650	30000	USA, Australia, Switzerland, Gulf Countries, etc
14	Bricks	Nalgonda	550	3000	15000	NA
Total			**7405**	**143640**	**210868**	**NA**

Source: Compiled from Industrial Profiles of the Districts, M/o. MSME, Government of India

Summary and Policy Suggestions : The growth of industrial sector is a key for solving the problem of unemployment and rural-urban imbalances in Telangana State. It is evidenced that there is a high fluctuation in growth of registered industrial sector in recent years across the districts and regions of Telangana. Besides, majority of the industries located in urban areas with low level of employment for female workers.

However, the State Government of Telangana has taken major steps to strengthen micro and small scale sector through loan weaving scheme for handloom & textile sector and other incentives to MSME sector. The newly State has come out with Telangana Industrial Policy-2015 which focused on infrastructure, market and institutional credit development. The Telangana State Industrial Project Approval and Self Certification (TS – iPASS) Act, 2014 is formed for single window clearance system for approval of the industrial projects within the stipulated time. Industrial Infrastructure Development Fund (IIDF) scheme is launched to provide better infrastructural facilities and Telangana State Programme for Rapid Incubation of Dalit Entrepreneurs (T-PRIDE) scheme has been initiated to boost the industrial sector to make Telangana a business friendly state by providing various kinds of incentives to encourage the first generation entrepreneurs by providing additional incentives to SCs, STs and Women entrepreneurs in the State.

Though there is a momentous effort from the Government functionaries and policy makers to the development of the Micro and Small Scale sector, still there are many considerable problems prevailed in Telangana industrial sector particularly in rural areas such as working capital, infrastructural, skilled labour, and product innovation & branding, industry up-gradation and marketing problems. Therefore, the study has been suggested to focus on the following points based on the findings;

1. The Government of Telangana has to be given more concentration on rural industries by providing working capital, un-interrupted electricity supply, highly equipped infrastructure facilities such as roads, water, market so as to provide more employment to the locale in general and women in particular.
2. Most of the manufacturing units lacking by skilled labour. Therefore, it is required to more emphasis on vocational training courses for its youth and skill up-gradation for labour as well as management of the enterprises.
3. The activities like textiles need to be introduced new technologies and equipment as the productivity of workers is very low despite high per capita intensity.
4. In conclusion, it is suggested that rural enterprises should be examined closely and interventions have to be made after identifying their problems. The DICs have to organize workshops for the entrepreneurs to identify their problems and take remedial measures particularly in the area of government schemes, subsidies and incentives.

References :

1. Annual Report, 2014, M/o. of MSME, Government of India, New Delhi
2. Government of India (2013); 'Twelfth Five Year Plan 2012-17: Economic Sectors – Volume-II', Planning Commission, Government of India, Sage Publications
3. Telangana Planning Department (2016); 'Reinventing Telangana: The Way Forward',

Socio Economic Outlook – 2016, Government of Telangana State, Hyderabad, pp - 55
4. Goldar Bishwanath (2014); 'Productivity in Indian Manufacturing in the Post-Reform Period: A Review of Studies', in Productivity in Indian Manufacturing: Measurements, Methods and Analysis, by Vinish Kathuria, Rajesh Raj S.N. and Kunal Sen (Ed.), Routledge Taylor and Francis Group Publications
5. Brief Profile of Telangana Industries, M/o. of MSME, Government of India, New Delhi
6. Thomas Jayan Jose (2014); 'Manufacturing in India: Has There Been a Revival since the 1990s', Productivity in Indian Manufacturing: Measurements, Methods and Analysis by Vinish Katuria, Rajesh Raj S.N. and Kunal Sen (Ed.), Routledge Taylor and Francis Group Publications
7. Sixth Economic Census (2013), Directorate of Economics and Statistics, Government of Telangana, Hyderabad.

Annexure:

Annexure – 1: Structure of Employment in Telangana

	Hired			Non-Hired			All		
Employment	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Rural	5,59,978	3,77,705	9,37,683	8,79,305	5,33,600	14,12,905	14,39,283	9,11,305	23,50,588
Urban	15,68,179	6,50,945	22,19,124	8,02,658	2,39,830	10,42,488	23,70,837	8,90,775	32,61,612
Combined	21,28,157	10,28,650	31,56,807	16,81,963	7,73,430	24,55,393	38,10,120	18,02,080	56,12,200

Source: Sixth Economic Census, Provisional Results

Annesure - 2: Growth Rate (%) of Employment over Fifth Economic Census

District	Rural	Urban	Combined
Adilabad	38.2	54.33	44.47
Nizamabad	3.29	52.97	12.82
Karimnagar	0.82	52.2	12.58
Medak	26.1	94.74	42.43
Hyderabad	0	30.32	30.32
Ranga Reddy	0.25	140.9	90.5
Mahabubnagar	14.8	18.62	15.88
Nalgonda	47.6	79.43	53.96
Warangal	-8.01	27.91	3.25
Khammam	78.6	55.06	69.56
Total	**19.9**	**54.35**	**37.78**

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Financial Inclusion and Economic Empowerment- A Gender Analysis

Dr. Neeta Tapan
Govt. Girls P.G. College (A Centre for Excellence) Ujjain (M.P.)

Introduction : Poverty is characterized by vulnerability, powerlessness and dependency apart from lack of income. Moreover, poverty has its own culture. Social systems and sub-systems of this culture are built on exploitation everywhere. However, the vicious circles of poverty in rural areas become perpetual due to the dependence of the poor on non-institutional sources of credit for a variety of purposes. Another fact, which has been well established, is that poverty is often engendered. In spite of contributing very significantly to family, society and economy, a gender analysis of most social and economic data reveal that women continue to be disadvantaged in every aspect of life. In spite of contributing significantly to family, society and economy, a gender analysis of most social and economic data demonstrates that women in India continue to be relatively disadvantaged in every aspect of life. They do not have decision-making power regarding the factors affecting the quality of life in terms of population dynamics, health and nutrition, education and employment, housing and environment despite having greater association and responsibility towards these. Apart from several other factors, one of the most important reasons behind women's subordination in all spheres of life is their economic dependence in some cases and uncounted economic status in other cases.

The participation of women in the workforce, the quality of work allotted to them and their contribution to the GDP are indicators of the extent of their being mainstreamed into the economy. On all these parameters women in India fare worse than men and the challenge is to bridge the inequality. The gender-imbalance is even more pronounced in rural areas of the country. As per National Sample Survey (68th Round), the worker population ratio for females in rural sector was 24.8 in 2011-12 while that for males was 54.3. In Urban sector, it was 14.7 for females and 54.6 for males. In the rural sector, 59.3% females were self-employed, 5.6% females had regular wage/salaried employment and 35.1% females were casual labour compared with 54.5%, 10.0% and 35.5% males in the same categories respectively in 2011-12. A total of 20.5% women were employed in the organized sector in 2011 with 18.1% working in the public sector and 24.3% in the private. The labour force participation rate for women across all age-groups was 25.3 in rural sector and 15.5 in urban sector compared with 55.3 and 56.3 for men in the rural and urban sectors respectively in 2011-12 (NSS 68th Round). In 2011-12, the average wage/salary received by regular wage/salaried employees of age 15-59 years was Rs. 201.56 per day for females compared with Rs. 322.28 per day for males in rural areas. For urban areas, it was Rs. 366.15 and Rs. 469.87 per day for females and males respectively.

The census does not accurately identify many activities as work that women actually do to enable their families to survive collecting fuel, fodder or water, keeping poultry, working on family land etc. Women also work in home-based industries, bidi and agarbatti-rolling, bangle-making, weaving, etc. They do not get social security benefits and are paid very low wages for this informal work. One-third of agricultural workers are women. On an average, their wages are 30% lower than men's wages. One of the major reasons behind the eternity of the vicious circle of poverty in rural areas is the poor coverage of credit needs of the rural poor by formal banking system. Moreover, the bleak employment scenario worsens the plight of the marginalized sections of

the population. Women are once again comparatively in a more disadvantaged position as more than 90% of women are unskilled, restricted to low-paid occupations, have no control over land and other productive assets and hence are dependent on the informal channels of credit for consumption or production needs.

Economic empowerment is the capacity of women and men to participate in, contribute to and benefit from growth processes in ways which recognise the value of their contributions, respect their dignity and make it possible to negotiate a fairer distribution of the benefits of growth. Economic empowerment increases women's access to economic resources and opportunities including jobs, financial services, property and other productive assets, skills development and market information. Women's economic participation and empowerment are fundamental to strengthening women's rights and enabling women to have control over their lives and exert influence in society. It is about creating just and equitable societies.

Conceptual Framework and Methodology : The economic empowerment of women is a prerequisite for sustainable development, pro-poor growth and the achievement of all the Millennium Development Goals (MDGs). Gender equality and empowered women are catalysts for multiplying development efforts. Investments in gender equality yield the highest returns of all development investments. Women usually invest a higher proportion of their earnings in their families and communities than men.

Women find it difficult to get credit from banking institutions because they are often unable to provide collateral. They get much smaller loan amounts even though their repayment record is much better than that of men. Women's right to land and other assets is weak. Though legislation has been introduced to ensure that women share equally in ancestral property, enforcing such rights in a patriarchal society requires resources that poor women may not have. Women, as half of the human capital of India, will need to be more efficiently integrated into the economy in order to boost India's long term competitive potential. Thus, empowerment of women is fundamental to reduce poverty, hunger and malnutrition. Gender equality and women's empowerment are important factors for the social and economic development of a nation. In addition to decent work and inclusion of women's work in the economy, another area of concern is the financial inclusion of the marginalised, which is crucial for their integration into the economy. Micro-finance – including micro-credits – is often considered as an instrument that promotes empowerment. Whilst it can stabilise livelihoods, broaden choices, provide start-up funds for productive investment, help poor people to smooth consumption flows and send children to school, it can also lead to indebtedness and increased exclusion unless programmes are well-designed. Providing supplementary services – such as training, working through groups rather than individuals, or alongside other investments in awareness raising – has been shown to increase women's direct control over resources.

At the same time, the failure of institutional initiatives of rural credit and the disenchantment with the rural development programmes led to the innovation of self-help approach. This approach propagates the notion that the involvement of poor in an ownership of a successful institution enhances their collective strength and empowerment that comes with organization. The new participatory paradigm is based on the ideology of building social capital as assets for community development. Rural Development has transcended the earlier boundaries of agricultural development and has been redefined as a widely participatory process of rural transformation, intended to bring about social and material advancement including equality and freedom for majority of the people through gaining greater control over the environment. The most important innovation in

the context of this new approach is the launching of self-help groups.

The Self-Help Group approach advocates not only pro-poor but also pro-gender strategy where women are treated as active partners in the process of development contrary to the early welfare approach. This programme definitely gives an opportunity to women for expanding abilities in context of regular saving, credit, bank linkage, income generation, and collective action and thereby enables them to make strategic life choices about quality of life. These interventions lead to economic empowerment in a way that the women are treated as managers and producers rather than as mere beneficiaries. The SHG also offers the canvas to conduct social mobilization, and use awareness, solidarity and collective action to gain autonomy. The group cohesion and social interaction are seen as crucial to the empowerment of women as especially rural poor women draw strength from numbers. The Group provides confidence and mutual support for women striving for social change. Through a group, women get a framework for awareness raising, confidence building, dissemination of information and delivery of services, and for developing communal self-reliance and collective action.

This paper attempts to evaluate the field realities of the credit dealings of Self -Help Groups on the micro level with the major objective of assessing the status of financial inclusion and reduction of the dependence of the members on informal sources of credit. The area of study was Ujjain district, which is a District of Ujjain Commissioner's Division in the North Western part of Madhya Pradesh. The Self-Help Groups under Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) are formed under the Rural Development Policy of the Government of India. In Ujjain district, these groups are formed through various government departments like Zilla Panchayat Rural Development Department, District Women and Child Development Department, District Literacy Mission and Rajiv Gandhi Watershed Mission. For administrative purpose, Ujjain district has been divided in 7 tehsils and 6 blocks. The rural SHGs under SGSY are being run block-wise in Ujjain district. Therefore, all the 6 blocks formed the area of study.

Firstly, purposive sampling was used to select only women SHGs being run by district agencies under SGSY. For cluster sampling, the block-wise lists of SHGs being formed by different government agencies were obtained. Further, the SHGs were classified on the basis of their stage of working to derive the three strata of thrift and saving, bank linkage and income generation. These groups were then mapped across the villages to cover the range of all blocks. Proportionate stratified sampling was used to select the groups in the three strata. In this way, total 150 SHGs were covered for the purpose of the study. Since each group involves 10-20 members, therefore, applying disproportionate sampling, 2 members were selected from each group. From these two members, one member was purposely selected from the office bearers and the other one was randomly selected from the group. Thus, in all 300 women were selected to get their responses.

Data and Analysis : A comparative picture of the sources of loan before and after association with SHG can show whether the respondents reveal any diversion from informal sources of credit towards formal credit sources. This fact is shown through the access details of loan before and after group membership as shown in table 4:

Table 1
Source of loan prior to and post SHG membership

Post SHG Membership Source of Loan	Source of loan prior to shg membership				Total
	Sahukar	Relatives/ Friends	Bank	Nowhere	
Sahukar	18 (15.9%)	4 (7.0%)	-	1 (.8%)	23 (7.7%)
Relatives/Friends	9 (8.0%)	8 (14.0%)	-	1 (.8%)	18 (6.0%)
Group	28 (24.8%)	23 (40.4%)	-	48 (37.2%)	99 (33.0%)
Bank	2 (1.8%)	1 (1.8%)	1 (100.0%)	2 (1.6%)	6 (2.0%)
Multiple Sources	51 (45.1%)	16 (28.1%)	-	22 (17.1%)	89 (29.7%)
Nowhere	5 (4.4%)	5 (8.8%)	-	55 (42.6%)	65 (21.7%)
Total	**113 (100.0%)**	**57 (100.0%)**	**1 (100.0%)**	**129 (100.0%)**	**300 (100.0%)**

Source: Primary Survey

Table 1 shows that out of 113 respondents who were taking loan from local sahukars or local mahajans before joining the SHGs, 15.9% are still approaching the same source for their credit needs, 45.1% of the respondents have opted for multiple sources of credit and 24.8% have borrowed from group only after associating with SHGs. The remaining few respondents belonging to this category approached relatives/friends or bank or did not take loan at all. On the other hand, 57 respondents took loan from their relatives and friends before joining SHGs. In the post SHG membership period, 14% of these respondents still approached their relatives/friends, while, 40.4% of these respondents have taken loan only from SHGs, 28.1% of the respondents have contracted loan from multiple sources, and the remaining few have borrowed loans from sahukars or bank or have not taken loan at all. Whereas, there is only one person who had taken loan from bank before joining the group and once again approached the same channel for her credit needs after becoming a member of SHG. On the other hand, there was a

large category of respondents who did not take loan from anywhere before becoming a member of SHG. After becoming members of SHG, out of such 129 respondents 33% took loans from the groups, 29.7% approached multiple sources to fulfill their credit needs, 21.7% still do not access any source of credit and the remaining few took loans from *sahukars*, relatives/friends or bank. On the whole, out of the total 300 respondents, as SHG members 33% of the respondents borrowed money from the groups, 29.7% of the respondents contracted loans from multiple sources, 21.7% of the respondents did not access any source of credit, 7.7% of the respondents approached *sahukars t*o fulfill their credit needs, 6% of the respondents borrowed money from their relatives/friends and 2% of the respondents took loan from only bank.

The unique feature about the multiple sources is that it includes group as one of the sources of credit in case of all the 89 respondents who accessed these channels. Out of these 89 respondents who contracted loans from multiple sources, 42 respondents approached group and bank; 24 respondents borrowed money from group, relatives/friends; 18 respondents took loan from *sahukars*, and 5 respondents accessed group, relatives/friends as well as *sahukars* to fulfill their credit needs.

This portfolio of credit sources accessed before and after SHG membership shows that SHGs have been successful in bringing about a phenomenal change in the borrowing profile of the SHG members. A shift from informal sources of credit to formal channels like group and bank is clearly evident in the post-SHG membership borrowing. Group has emerged as a newly found source of credit, which is accessed by the maximum number of SHG members. Moreover, rural women could access an institutional credit channel like bank, which is known for its varied formalities. Equally remarkable observation is that out of 129 respondents who had no history of borrowing prior to group membership 74 respondents contracted loans from different sources among which group was the most significantly accessed source of credit.

Conclusion : It can be concluded that if the activities of saving, internal lending, bank linkage and income generation activities go on without throwing the SHG members into a debt trap, these can surely reduce the vulnerability of the women. However, regular and/or improved savings, access to credit and even involvement in income-generation may not necessarily pull the SHG members out of poverty, but the portfolio of economic activities of women without accessing the informal channels of credit definitely improves causing a positive change in their economic condition. Therefore, regular grading and monitoring of saving and lending status of groups are of utmost importance before the groups graduate to the levels of bank linkage, income generation and tools of micro credit.

On the other hand, even as the country considers a Bill to regulate Micro-finance institutions, the micro-credit and SHG movement as the sole panacea for addressing poverty and women's empowerment is increasingly coming under critical review. The focus on credit provisioning for micro-enterprises has increased but the challenge in the micro credit movement is to reach out to the poorest and most vulnerable and marginalized populations like SC/STs, single women and other socially excluded communities. Many of these SHG groups have low levels of credit absorption, low skill base and low asset base, and find it hard to create economic enterprise. At the heart of the problem lies the need for appropriate institutional mechanisms to address illiteracy, lack of investment, poor credit worthiness, poor mobilization, and other structural exclusions. These will need to be addressed to realise the vision of financial inclusion.

As per the country's policy on the Right to Livelihood, all human beings irrespective of gender must have equal opportunities to seek out economic opportunities. It is critical that

during the XII plan period women were to be enabled to exercise this right. Women should be able to access resources and livelihoods for survival and sustenance. But beyond this the economic power should help them acquire capabilities that enlarge their choices for satisfying and creative lives. This is critical as a growing body of evidence has shown that gender equality is good economics.

References :

- Ashok Dasgupta (2013) NSSO data analysis: high time political parties took the economy towardhighergrowthhttp://www.thehindu.com/news/national/nsso-data-analysis-high time-political-parties-took-the-economy-toward-higher-growth/article4843888.ece
- Census of India 2011,Primary Census Abstract, Data Highlights
- Karmakar K.G. (1999), Rural Credit and Self-Help Groups (Micro-Finance Needs and Concepts in India. Sage Publications, New Delhi.
- World Bank: Engendering Development Through Gender Equality in Rights, Resources,andVoiceSummary,Washington,2001.www.worldbank.org/gender/prr/engendersummary.pdf

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Title of the Paper - 'Awakened Leadership- A new generation leadership

Dr. Yogita Mandhanya
Faculty Human Resource Management School of BSFI and Retail Symbiosis University of Applied Sciences Indore (M.P.)
Dr. Swati Oza
Faculty Finance School of BSFI and Retail Symbiosis University of Applied Sciences Indore (M.P.)

Abstract : Leadership as we all are aware is ever changing concept from different avenues. Leadership qualities are the topics of every management discussions. The present paper conceptually defines the framework on the new generation leadership style namely Awakened Leadership, marked by context, motion and followership. This style of leadership is highly flexible and can be applied on all types of followers and in all types of situations. The paper highlights some important qualities of awakened leaders, in commensuration with the traditional theories and traits of leader. Awakened leadership can also be described as the leader of twenty first century. The paper also seeks to highlight some skills and situations which make awakened leaders so outstanding.

Key Words : Trait, Leadership, Zeal, Humility, Creativity.

Origin : Leader is a back bone of an efficient and effective management. He strives for success as well as harmony. The awakened-leadership framework is designed to provide direction, course and impetus across organisational lines that progresses into a shared course of action, cohesion of purpose among people who are doing what may appear to be very different work. This style of leadership has been originated through a lot of surveillance and study of leaders in situation of crisis. The origin was in US during September 11 attacks. It throws light upon traditional leadership by reframing and providing :

- A comprehensive organizing framework for understanding and integrating the number of facets of leadership;
- A method for catalysing collaborative activity;
- A focus on improving function and performance across the framework and boundary of organisational setting.

The framework was developed by Leonard J. Marcus and Barry Dorn of the National Preparedness Leadership Initiative (NPLI), a joint program of the Harvard School of Public Health and Harvard's John F. Kennedy School of Government and Joseph M. Henderson Chief of Staff at the Centre for Disease Control and Prevention and first published in 2006. Increase in complexity of manmade and natural dangers facing the economy and organisations urged the need for such type of leadership. Marcus, Dorn, and Henderson in their research ventured that commonly as understood leadership, focuses to build up the capacity within organizations. They evidence here that altogether a different brand of leadership is necessary to get beyond that silo thinking to achieve cross-agency and cross-government coordination of strategy and effort.

In the very beginning articles it was defined that the effectiveness of this style is very much dependent upon the ability of distinct leaders to imagine a new framework of effort and strategy further finding different ways to converse, stimulate and motivate more participation.

Introduction : In medieval times, leadership has been described in numerous ways. An extensive demonstration of the ories have been developed about this concept, all stressing the fact that there is no one leadership style suitable to all situations. In the present research the concept of leadership is presented in a different way namely awakened

leadership, a way of leading and living in altogether a different atmosphere applicable in all spheres and interactions touching all the aspects of a leaders life : self-concept, leading concept and the diversity concept of followers. Although there is no connection specified or projected toward any religion or philosophy, the term was derived from a leader who surpassed time and existing boundaries with his wisdom and heritage. A very good example from ancient times which highlighted the sparks of awakened leader is no more other than Buddha. (An awakened Leader).

A situation and the types of followers are two concepts which play a significant role in the success of a leadership style. A successful leadership style is always denoted by the situation and the type of behaviour and reactions the followers generate in it. A general thinking says that the situation and the types of followers play a significant role to make a leadership style successful. Awakened leadership is a concept focusing on the two aspects namely situation and followers. Situation and followers are the two prerequisites for this type of leadership style. Awakened leadership is not a new Occurrence. Glimpses of this style have been observed in teachings of Buddha, Jesus Christ and even Mahatma Gandhi and Mother Teresa.

Leadership is an emerging and dynamic concept as human psychology and environment wherein they work is also dynamic. Previously we have witnessed a number of leadership styles from participative to coercive and engulfed with new linings namely management by walking around. The new extended dynamism can be defined as awakened leadership style. The reason why the above changes are labelled 'incomplete' is, because leadership is highly dynamic and continuously evolving topic which entails that new definitions and styles of leadership are continuously developed.

Pierce & Newstrom (2003) in their book on leadership concluded that it is a dynamic concept. All the theories of leadership encompass and move around a simple word that is cognizance that is being awake. A leader has to review the existing styles prevalent, along with his dynamism and understand that the success of all these leadership styles is more focused upon applicability aspect. The success of a leader is on what he does and not what he is.

Various researchers have concluded in the past that there is no common leadership style emerging to be successful at all situations and circumstances. Hughes, Ginnet and Curphy(2002) in their study focused on the aspect that leadership is determined by several factors, including situation as well as the followers, and not just a leader's skill, quality or characteristic. They further added in their study that when you observe a leader's behaviour, one should not reach the conclusion about something good or bad about his nature, or the right or wrong way a leader should have behaved. The concept to be noticed is the effectiveness of his behaviour with respect to the context or situation available or impact on followers.

Dr. Joan F.Marques, School of Business, Woodbury University and Dr. Satinder Dhiman, Woodbury University, in their research paper titled The Making of an Awakened Leader, concluded that a true leader, if the test of being a true leader is being a good human being, then awakened leadership provides the most persistent platform to harmonize life, learning and leadership. The qualities described here provide a clear picture of what will be needed to make a positive difference in the workplace of the future, and in the world at large. Although these qualities represent only a part of what constitutes an Awakened leader, conquering these skills will firmly put us on the path of awakened leadership.

According to Joan F. Marques in his research paper Awakened Leaders: Born or made? Concluded that awakened leadership can be considered difficult and easy at the same time. Difficult because society, with its ongoing codes of conduct, and particularly its ingrained sense of

individuality, may not yet be as widely prepared to embrace the awakened leader and his or her sense of unity and ,mutuality in moving ahead; and easy, because the awakened leader, once accepted, does not have to remember different environments. This leader remains the same, whether alone with a small or large group of people. He embarks his style with skills to be graceful, kind, empathetic, respectful and down-to-earth.

Rosner (2001) in his research defines awakened leaders, actually are those who always lead from heart and soul. They are the community, corporate and down to earth (household) leaders, official or unofficial, who do not agree to put on different faces when it comes to their personality. They do not believe in hanging out emotions outside the gates of the organisation.

They always try to practice a universal and realistic approach at every time in every environment. The rise of global economy leading to dynamic organisational structure have created greater and bigger challenges to be faced in by top management. Due to massive changes and consequential high demands of todays' increasingly diversifying workforce, the need for diversity leaders has tremendously augmented. Managing a heterogeneous workforce is defined as diversity leadership. Traditional leaders who face these demands of the economy has given rise to a new set of leadership i.e. awakened leadership. The logical question that arises while talking about awakened leadership is that what does this concept actually comprises with? The answer would be every possible leadership style, trait and skill developed till now, along with developments in future, as long as these skills and traits fulfil the criteria of being advantageous and applicable to all parties involved.

What it means to be an Awakened Leader : So, Awakened Leader? ------What does it mean??? An awakened leader is one who cherishes a certain set of values in his or her dealings, communications with other human beings. Some of these values are: self-awareness, knowledge about oneself, self-reflection, presence of mind, insight, thoughtful, equability, recognition, non-judgment, honesty, genuineness, modesty, unselfishness, kind-heartedness, empathy, impartiality, impulse, zestfulness, harmony, and serenity. For the purpose of this article, we will focus on a few of these values as symbols of an awakened leader:-

1. Presence of Mind
2. Awareness about one self
3. Reception
4. Non-judgmental
5. Inventiveness
6. Empathy
7. Self-effacement
8. New Learning
9. Bonding
10. Morale

Presence of Mind : It involves acceptance, meaning that one pays attention to his / her thoughts and feelings nonjudgmentally. In the context of awakened leaders they bring their attention to the present experience on a moment to moment basis.

Awareness about one self : Self-awareness is the capacity for introspection and the ability to recognize oneself as an individual separate from the environment and other individuals. Awakened leader possess a down to earth quality which makes him self-aware and fair irrespective of the position to which one belongs.

Reception : The act of taking or receiving something offered. In the context of awakened leadership it refers to listening to everyone and taking the thing as they are instead what the leader wants to listen. Putting yourself in the shoes of others instead of putting them in your shoes makes an awakened leader different.

Non Judgemental : It refers to being not judged or judging on the basis of one's personal opinion or standards. An awakened leader exhibits an attitude of not judging on the basis of good or bad concepts. He is unbiased in these situations. Non judgement and Acceptance they both go hand in hand.

Inventiveness : It is the ability to perceive the world in new ways. To look out new ways, to try to make connections between something unusual and find out soloutions. An awakened leader definitely should be inventive, creative and should always be trying to find out solutions for problems. Making a way out for new to enter into the current scenario.

Empathy : If someone sows kindness, caring, and a willingness to help others, they're showing compassion. It expresses a feeling of deep sympathy and sorrow for another. An awakened leader extends kindness to all irrespective of their creed, caste etc.

Self-effacement : Quality of being humble and modest. It is a leader's biggest trait of being humble and kind to all he deals with. An awakened leader is characterized by a humble and modest attitude and behaviour.

New Learning : To begin with, unlearning conveys an image of forgetting the old pattern of learning and doing things, a perceptual and behavioural as the means to change. A leader to take something new has to first wash out the old.

Bonding : A feeling of belonging to or having affinity with a particular person or group. It can be defined as the most important quality of an awakened leader where cohesiveness is being built up by him in the very beginning.

Morale : a leader has always to be full of Zeal and enthusiasm to always try new thing, find new solution, generate new ideas, provide new techniques etc. it is a remarking trait to create a line of differentiation between a leader and an employee.

Conclusion : The dynamic 21st century encompasses within itself a number of expectations from leaders to manage their organisations. It engulfs a wide picture of an independent world, lined by wider understanding, flexibility and of course acceptance to this new world. Awakened leader can be successful in this scenario if he develops within himself the qualities discussed above, to make a positive difference, and which can be worldwide accepted. Mastering these skills will provide a platform for acceptance of leaders by anyone and anywhere. Awakened leadership is circumferenced by its multi-applicable and dimensional approach never the less what are the circumstances and who are the followers. An inference can be drawn for this concept as to a style which is a simpler format of conventional leadership styles and creates a happy environment around.

If becoming a true human being is the litmus test of being a true leader, then awakened leadership presents one of the most stable ways to harmonize life, learning and leadership.

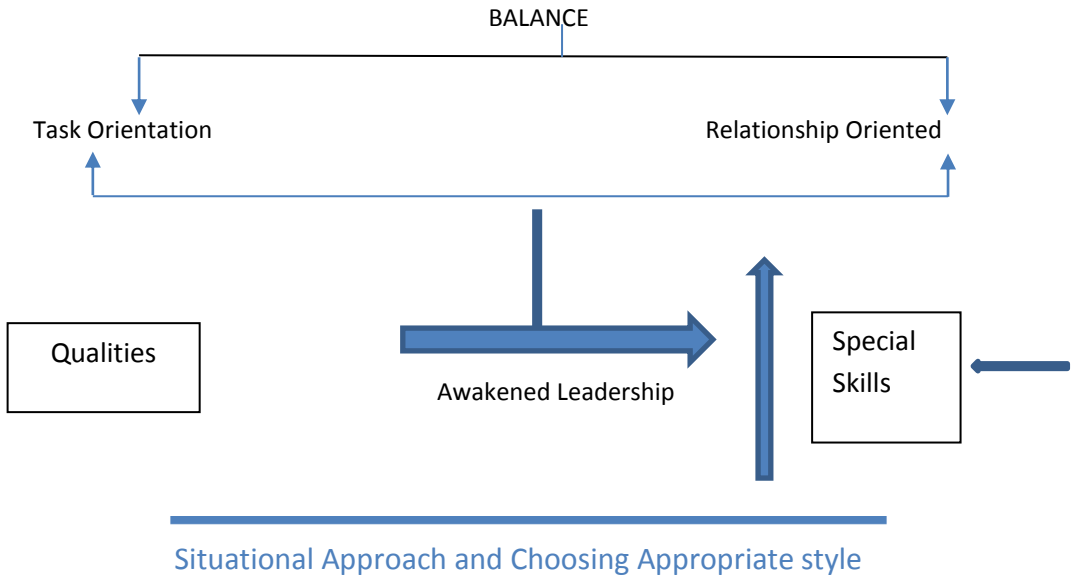

Source : Awakened Leadership by Jaon F. Marques, Edd.

References :

- Hughes, R. L., Ginnett R.C. & Curphy, G. J. (2002). Leadership: Enhancing the Lessons of experience. Mc. Graw Hill.
- Kornfield, J. (1999), Teachings of the Buddha, Barnes & Noble Books, New York, NY.
- Marcus, L.J., Ashkenazi, I., Dorn, B., & Henderson, J.M. (Spring/Summer 2008). "Meta-Leadership: Expanding the scope and scale of public health". Leadership in Public Health, 8 (1&2)
- M Joseph et al (2006). "Meta-Leadership and National Emergency Preparedness: A Model to Build Government Connectivity". Vol 4 (2) pg 128–134.
- Marques Joan F (2009). Awakened Leaders: Born or Made? Leadership and Organisation Development Journal, Emerald, Vol31, No-4. Pp-307-323.
- Marques.J, Dhiman S. (2006). 'The Journal of Human Resource and Adult Learning', The Making of an Awakened Leader, pg.16-22.
- Pierce, J.L., & Newstrom J.W. (2003).Leaders and the leadership process. New York McGraw Hill.
- Rosner, B. (2001), "Is there room for the soul at work?" Workforce, Vol. 80 No. 2, p. 82.
- www.wikipedia.com.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

"A STUDY OF AGRICULTURAL START UPS IN INDIA : PROSPECTS & CHALLENGES"

ATUL KUMAR
Assistant Professor, Department of Business Management, Shri Ram College, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

ABSTRACT : This paper presents the burgeoning growth of startup ecosystem in Agricultural sector and the study of potentials of agritech and agripreneurship with special emphasis on innovation in agriculture. A shift from agriculture to agribusiness is an essential pathway to revitalize Indian agriculture and to make more attractive and profitable venture. It has the potential to contribute to a range of social and economic development such as employment generation, income generation, poverty reduction and improvements in nutrition, health and overall food security in the national economy. Innovative and advanced approach towards agriculture has potential to generate growth, diversifying income, providing widespread employment and entrepreneurial opportunities in rural areas. This paper mainly focused on studying the potential of agricultural sector in recent positive shift in creating start up eco system in India the outcomes of innovation influence in agriculture with an outlook of making it a customized and exclusive business and the challenges that lie ahead start ups in agriculture.

INTRODUCTION : India has to support 17 per cent of the world's population on just 2.4 per cent of its geographical area. Agriculture continues to be a vital component of India's economy contributing over 14.2 per cent of India's GDP and providing employment to the majority (55%) of its population. Indian agriculture has achieved self-sufficiency and today takes pride in not only meeting the needs of our population but also playing a major role in agricultural trade. Ensuring farmer's security is far more vital for the nation to ensure food security to the country. Agriculture needs continuous infusion of innovation and technology in ensuring global food security, poverty reduction and environmental Sustain ability. Socio- Economic and Caste Census (SECC) 2011, released in 2015 also indicates that out of 24.39 crore households in the country, 17.91 crore lived in villages and among these, 10.69 crore were considered as deprived households. Agriculture is still the backbone of rural India as the data of SECC indicates that 31.26 per cent of the total rural households are still broadly identified as poor where the main earner has an insecure and uncertain source of income. Increasing urbanization, globalization and demand for high-value products have dramatically changed the global context for agriculture. Agriculture is critical for those who live below the poverty line, as there is an uncertainty from the harvesting point of view. Propelling growth in agriculture is critical as research has revealed that GDP growth originating in agriculture is at least twice as effective in reducing poverty as GDP growth originating outside agriculture (World Development Report, 2008). In that sense alone, true inclusiveness of Indian growth model can come true only when agriculture does better than what it has done in the past. In this context, it is important to explore all possibilities to ensure prosperity of farmers and agriculture. Transformation of Agriculture to Agri-business is one of the important strategies where enterprising farmers practice profitable agriculture. Farmers' suicide, droughts, debt, crop failure, and poverty—these words echo the massive scale of problems faced by the agrarian community in India. However, technological innovations, agriculture startups and aggregators, primarily driven by the youth, have helped the farmer community to mitigate some of these challenges.

AGRICULTURAL START UPS : POLICY DIMENSION : Government support is crucial not only for product development and proof of concept but

also for initial operations before these enterprises look to raise commercial investments. Government of India is implementing schemes for Start-ups, including Agro Start-ups through Schemes such as Start-up India Scheme of Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) and A Scheme for Promotion of Innovation, Entrepreneurship and Agro-Industry (ASPIRE) scheme under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). One of the most significant of programmes is AGRI UDAAN Managed by India's premier farm research body, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the food and agri-business accelerator programme. Under the programme, start-ups will get incubation space to run their businesses and have access to research laboratories and libraries. AGRI UDAAN will also help the selected start-ups with regulatory services like company registration and environmental compliances. NABARD-DST and government support to private incubators in recent time have been proved to be of great help. Collaboration of incubators, agricultural universities, CSIR labs, engineering institutions, chemical laboratories and biotechnology labs can also help agricultural start-ups in terms of handheld support to the farmers. NABARD is also playing a key role in terms of providing finance to these start-ups. Moreover, R&D labs in agriculture have also come forward to incubate agricultural start-ups. Government bodies provide R&D and training support to the agripreneurs. There are various govt schemes that provide ecosystem building and incubation support to the agri entrepreneurs via the schemes of Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) and Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA). Government has provided significant support for providing solutions like crop insurance, farm mechanization, information dissemination, subsidies for innovation and research which is providing an impetus to the sector. However, lot needs to be done to improve infrastructure, connectivity and also increased support to young start-ups which are back bone of most of the innovations in this sector.

OPPORTUNITIES FOR AGRICULTURAL START UPS :

Opportunities lie in areas like how to increase crop production, improving the nutritional value of the crops, reduction in input prices for farmers, improving the overall process-driven supply chain, reducing wastage in the distribution system, making easy farm mechanization available and enabling connectivity of farmers with the masses by interlinking the consumer and producer. Agricultural startups are also leveraging technology in the area of market inkages such as retail, B2C and B2B marketplaces and digital agronomy platforms. Agritech startups are now able to provide correct information, techniques and efficiencies to farmers both for pre harvest applications and post harvest use cases. Agriculture industry specifically in India is at the crossroad of a new revolution. The entire food chain is supposed to be modernized and the production is expected to be doubled in the coming 10 years. Apart from domestic demand, this industry brings in huge export prospects. At present agri-business may involve either an input or a produce or service and encompasses items such as :

1. Productive resources (feed, seed, fertilizer, equipment, energy, pesticides, machinery, etc.)
2. Agricultural commodities – (raw and processed commodities of food and fiber)
3. Facilitative services (credit, insurance, marketing, storage, processing, transportation, packing, distribution, consultancy, soil testing etc.).

AGRI START UPS : a helping hand to farmers :

Public generated investment, either by direct purchase of farm goods without the intervention of middle men or by providing access to the agriculture hardware with the village community, is a tiny step but will empower the farmers. Technological intervention is the need of the hour to mitigate farm crises and help provide financial security through risk estimation and crop insurance. Given the massive scale of issues faced

by the agrarian community today, it is essential for more technology and IT based services to address these growing challenges. Advent of startups in agriculture has revolutionized lives of farmers by helping them gain better access and facilities at various levels. Some of the examples in favor of the the fact are as follows-

- Online web portals/ Mandi
- Technological assistance to mitigate agri crisis
- Promotion of organic farming
- Water resources and soil health awareness
- Incorporation of solar energy in farming methods.

AGRI START UPS : CHALLENGES : A drop in landholdings (average 1.4 hectares), small and fragmented land holdings a decreasing agricultural land versus a growing population, decreasing ground water levels, poor quality of seeds, lack of mechanization, low yield per unit crop and a dependence on middlemen are some of the challenges for the growth of agriculture in India. Added to that, an absence of an organized marketing structure for produce, malpractices in the existing unorganized agricultural markets, inadequate facilities for transportation and storage, scarcity of credit, and limited access to superior technology to get timely information is some of the many afflictions which obstruct the Indian agricultural sector. A recent study has the following findings about agri start ups-

- Nearly half the startups face challenges in finding adequate talent.
- 25% Crop Production Agriculture startups need support in Technology.
- 45% startups catering to farmers feel they lack adequate government support.
- About 32% expected help in the form of funding or marketing enablement.
- Nearly half the startups expect more ecosystem support in incubation and growth.
- Agriculture startups are realizing that they need adequate talent and support to cater to their consumers with better products and solutions.

Infrastructural Challenges : Regarding the issues associated with transportation facilities, many of the Indian cities have imposed truck curfews, barring them from entering the city during day time. The trucks have to be parked outside the city, during which there is a long delay which causes fruits and vegetables to go bad. This accounts for a loss of over 20% of the produce during transit. The railway network is not suitable for the transit of food items as it does not provide end-to-end delivery in many cases. So the absence of organised logistics paves way for the delay in transportation of food from farms to the end consumer. There are a lot of middlemen involved which increases the time taken for the produce to reach the end consumer resulting in food wastage and price hike.

Absence of adequate warehouses is the most prominent issue that farmers face. There are two types of warehousing that are essential for the food produces. One is the sheltered warehouse type, used to store food grains like rice, wheat and cereals; dry produce. The other one is the cold storage facility which is used to store fruits and vegetables; wet produce. Across the country, there is insufficient warehousing capacity. Though the crop production has gone up significantly over the years, the number of warehouses has not increased. In 2010-2011, the food grain produced was 233 million metric tons. The storage capacity owned by the government was only 91 million metric tons. As a result, many crops had to be stored in the open space, exposed to the elements. Also due to the absence of pest control mechanisms, 20% of the food grains are destroyed by rodents every year.

Systemic Issues : Farmers do not have facilities to store the food produce in places they own. This is where middle men come in. In India, farmers get 33.33% of the final price as compared to 66% in western countries. Cold storage facility is important for storing fruits, vegetables and milk. The existing cold storage facilities are not enough to store the produce. Approximately a third of the

food produce goes waste each year due to the absence of storage facilities. The absence of private players in warehousing is also a main concern. Most of the warehouses are controlled by the government and are not able to expand as per the demand. Government storage facilities are poorly maintained, which further contributes to loss of food produce.

Cold storage facilities are technically a little more challenging to build. They require continuous power supply and HVAC systems that can handle the cooling requirement. With the rise in solar energy, a self contained system might be a great solution in rural locations where power supply may not always be consistent.

The other main problem is pricing. Price of any commodity is determined by the actual demand and supply situation in the market. Commodity prices in India are influenced by various factors. Generally, the markets are far from most of the villages and therefore, the small and medium level farmers find it economic to sell their produce to the local intermediaries. Thus, intermediaries are an integral part of the supply chain of the agricultural produce.

This unreasonably long supply chain results in the steep escalation of the total cost, owing to procurement, transit and other taxes and service charges levied at various stages. There are other intermediaries like Commission Agents, wholesalers, retailers under different marketing channels, through which the produce reaches the consumers. This results in low revenues to the farmers.

Financing : The government funding of farmers is still in its nascent stage and most of the small farmers still depend on local moneylenders, who charge high rates of interest. There are too many middlemen that disrupt the benefits that the farmers are supposed to get. Although technology has improved, it has not reached the rural areas. There is no organized and regulated system for marketing the agricultural produce.

Providing loans to the farmer at low rate of interest is necessary to free them from the clutches of local moneylenders. It is said that a farmer is born into debt, lives in debt and dies in debt. Right from the beginning of the life, poor farmers approach money lenders for getting money to invest in cultivation. These money lenders levy high rates of interest and take away a huge share of the income.

In case the crops fail due to natural calamities, the situation worsens, as the farmers will not be in a position to pay their loans. And ultimately, they are forced to sell their lands at throw away prices to the money lenders. It is essential to provide subsidized power supply and loans to the farmers as the expenses towards power consumption take considerable amount of investments. There should be stringent actions against black marketers and hoarders who buy the stocks from farmers at cheap prices and create artificial demand and then sell the stocks at higher prices.

As the literacy level among farmers is low, they still hold on to the old cultivating and farming techniques, which finally results in low production rate. There is a need to share the knowledge to farmers and introduce them to the more productive side of agriculture with the help of science and technology. Polyculture practices like crop rotation, soil amendment and other methods like Sustainable Intensive Farming can actually increase the crop yield. Technology has developed an easy way to replenish the soil health. Soil steaming with the help of MSD (moeschle steam boiler) can be used to kill pathogens and pests of soil by increasing the temperature, which is an ecological alternative to chemicals for soil sterilization. Production techniques like vertical farming and roof-top farming can also be implemented.

Cultivating perennial crops once in a year can really prevent soil erosion, reduces compaction and enrich the quality of the soil. Keyline Subsoiling is the latest technique which is potentially very powerful in the places where there is less availability of water. Practicing Keyline Subsoiling in off-seasons can hold the land piece with soil nutrients than drying it up. Other organic farming techniques Green Manure, Compost, Biological Pest Control are to be practiced to harvest and cultivate best quality crops.

Considering and implementing the above mentioned ideas can light up the lives of farmers, but there is a lack in initiation on the Government's part. On the brighter side, there are many instances out there where young as well as experienced minds of the country have found support and are revolutionizing the agriculture sector through their start-ups.

Conclusion : There is no doubt that in any marketing scenario, profit maximisation is of essence. At the same time, marketing needs to be based on certain values, principles and philosophies such as offering fair prices to the farmers. Bringing necessary reforms coupled with proper price discovery mechanism through regulated market system will help streamline and strengthen the agricultural marketing.

Startups seek opportunities in areas which are critical for the user group that they seek to cater. Farming and agriculture is critical for the Indian economy. It has been functioning in the absence of efficiency for years. There is great value to be created if this efficiency could be imbued into the system. There are several opportunities that wait to be exploited.

Small scale farmers need to be knowledgeable of the market conditions, fluctuations, demand and supply concepts which are the core of any economy. Agricultural marketing can be made effective by the collective and integrative efforts from various quarters by directly addressing farmers, middlemen, researchers and administrators. It is high time we brought out effective strategies in agricultural marketing with innovative and creative approaches. It is imperative that the Government help emerging start-ups to revolutionise Indian agriculture. India can develop once the farmers are free from oppression and are thanked for their service to the nation.

REFERENCES :

1. Bell, D E, N Sanghavi, V Fuller, and M Shelman (2008): Hariyali Kisaan Bazaar: A rural business initiative, HBS Case No. 9-508-12.
2. Hatten T S (1997): Small business-Entrepreneurship and beyond, Prentice Hall, NJ.
3. Alex, Lwakuba (2011) A Review and Analysis of Policies on Farmers' Entrepreneurship Development, A publication of PELUM, Misereor, pp. 1 – 55.
4. Bairwa, S. L. and Kushwaha S. (2012) Agro Industry scenario in India In Edited by Prof. S. P. Singh "Agricultural research and Sustainable development in India", Bharti Publications, New Delhi, 110093, pp 159- 182.
5. Global Agrisystem (2010) Evaluation Study of Agriclinics and agribusiness centre Scheme, Global Agrisystem Private Limited, New Delhi.
6. Chandra shekhra, P. (2003) Third wave in Indian agriculture: introduction to Agriclinics and agribusiness centre scheme. MANAGE Ext. Res. Rev., pp. 10-20.
7. Kumar, Anjani, Harbir Singh, Sant Kumar and Surabhi Mittal (2011), "Value chains of agricultural commodities and their role in food security and poverty alleviation: A synthesis", Agricultural Economics Research Review, Vol. 24, January-June 2011, pp 169-181.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Artistic Excellence of Katherine Anne Porter

Dr. Preet Negi

Guest Faculty (Deptt.of English) Govt. College Sleemnabad Katni (MP)

No exploration of Katherine Anne Porter's 'personality' can explain the success of her art; the scrupulous and expressive intricacy of structure, the combination of a precision of language, the revealing shock of precise observation and organic metaphor, a vital rhythmic felicity of style, and a significant penetration of a governing idea into the remotest details of a work.

The importance of Katherine Anne Porter is that she has created oeuvre a body of work including fiction, essays, letters and journals that the stamp of a personality distinctive, delicately perceptive, keenly aware of the depth and darkness of human experience, delighted by the beauty of the world and the triumphs of human kindness and warmth, and thoroughly committed to a quest for meaning in the of the ironic complexities of man's lot.

Her work is the result of a life time of devotion artistic honesty. Now here can she be said to exploit effects for their own sake. Through in ability to compromise and sheer endurance, Miss Porter who is an artist, has come to represent art, and though the role has never obscured that quality of her work, it has shifted attention away from the content of the work itself. The first concern of her stories, of course is not aesthetic. Observed life is the generating factor, and though it may connect with a large metaphor, it is rooted in the everyday realities of people, situations and places.

Katherine Anne porter enjoyed the reputation of a writer who had never failed in public. What she had published had proved her a master craftsman in the art of the short story, the sketch and the short novel. Even such a critic as Edmund Wilson was driven to admitting that he could not formulate his praise.

Edward Schwartz in "The fictions of Memory" says that Miss Porter's art is an art of remembering, its subject the artist's personal recollections. Miss Porter looks within, regards with steady eye the one reliable reality, the writer's self." 1

The artist's job is to deal with the true and human world he himself knows. He does this not as that "Parochial visitor, Mr. Eliot legislates for the edification of his audience, in the regions, of art as religion, edification is not the highest form of intellectual or spiritual existence".2

The artist's creations, Miss Porter believes is are considerably richer, invoked out of deeper sources in human consciousness more substantially nourishing than his lukewarm word can express.3

Thus her own work has been an attempt to discover and understand human motives and human feelings to make a distillation of what human relations, and experience my mind has been able to absorb.4 Miss Porter begins with an image, an incident, a character, " a section here and a section there has been written little general scenes explored and developed or scenes or sketches of characters which were never intended to be incorporated in the finished work have been developed in the process of trying to understand the full potentiality of the material.4

Miss Porter's aesthetic bias, has one aim and it is to tell a straight story and to give it a true testimony. 5 she is convinced that the artist must retain a close vital connection with society. She agrees with Diego Rivera's objection to early Mexican artists who believe that they " were still in thrall to the idea that the artist is an entity from the human world about him mysteriously set apart from the community, they still regarded painting as a priestly function Miss Porter considers the artistic obligation to society to be the plain and simple responsibility of any other human being for I refuse to separate the artist from the

human race'.6 The artist should expect no special privileges from society, no guarantee of economic security; for he cannot be a hostile critic of society and expect society to feed (him) regularly. The artist of the present is demanding that he be given free a great many irreconcilable rights and privilages'.7

To the reviewer Miss Porter is baffling because one cannot take hold of her work in any of the obvious ways. She makes none of the melodramatic or ironic points that are the stock in trade of ordinary short story writers, she falls into none of the usual patterns and she does not show anyone's influence. She does not exploit her personality either inside or outside her work and her writing itself mabes a surface so smooth that the critic has title opportunity to point out peculiarities of colour or weave. It he is tempted to say that the effect is pale, he is prevented by the realization that Miss Porter writes English of a purity and precision almost unique in contemporary American fiction.

Miss Porter's singularity as a writer is in her truthful explorations of a complete consciousness of life. Her prose is severe and exact, her ironies are subtle but hard. If she is arbitrary it is because she identifies a conservative with a classical view of human nature. Her stories are thoroughly planned. It is true that she is chastely on the edge of her subjects, that one catches the wild look of the runway in her eye.

She is an important writer in the genre because she solves the essential problem; how to satisfy exhaustively in writing briefly.

Reference :-

1.Edward Schwartz, The fictions of Memory.

South West Review, 45:204-15, Summer1960

2.Notes on a criticism of Thomas Hardy, P.154

3.ibid P .154

4. The situation in American writing, P.39, cf Transplanted writers, P.274

5. Partisan Review, VI, Summer 1939.

6. Autobiographical Sketches, P.539

7. "The Situation in American Writing; P.39,

Ct. Transplanted Writers, P.274

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

The music journey of famous Indian music maestro Sachin Dev Burman

Paheli Gope and Utpal Biswas
Tripura University, Suryamaninagar, Tripura

Abstract : Sachin Dev Burman was a famous music director of Indian film industry in nineteenth century. He had so many contributions in the film industry for about 30 years. He had created a new style of song by mixing East Bengal (Bangladesh) folk song with classical song. With this style, he composed many tunes in polligeeti, folk and modern song which had been used in many songs of Indian film industry. With these songs, he became famous in Indian film industry and the audience also became very much pleased. For this unique style of his music as a music director, Jakhir Hossain, the president of India awarded him Padma Shri. He achieved 'Asian film society award' for his extra ordinary contribution in the film 'Piyasa' as a music director. For his extreme knowledge in music, he was invited as judge in international singing competition at Helsinki, Finland. He had rolled out the career of many famous singers of Indian film industry. Though he was very successful in his career, he faced a lot of difficulties in his career starting from his childhood. This paper has given the whole biography of his life, focusing on his music career. This investigation includes his family background, his education, his music learning, his music career and his contribution to the career of other famous singers.

Keywords : Nineteenth Century, Cultural history, Biography, Folk Music, Indian film industry.

Introduction : Sachin Dev Burman (S. D. Burman) was born on 1st October, 1906 in Comilla, Bangladesh. He was scion of Tripura's royal family; presently it is a state of India. Burman's father Nabadwipchandra was an eminent singer of dhrupad and sitar player. He was the son of Ishanchandra Manikya Dev Burman, Maharaja of Tripura. He was living at Comilla in his own house with his family. Comilla was a part of Tripura at that time, presently it is in Bangladesh. Burman's mother Nirupamadevi was the princess of Manipuri royal family. She died when S. D. Burman was 2 years old. He had been grown up under the caring of dhai maa. S. D. Burman had five brothers and one sister. Sachin was youngest among of all his brothers and sisters. Among of his four brothers, Kiran Kumar was most favourite to Sachin; they had very good understanding. He was 6 years older than S. D. Burman and Sachin used to call him 'Chorda'. In 1911, S. D. Burman started his schooling at a boarding school named 'Kumar Boarding' in Agartala. His father took him from Kumar boarding and admitted him at Yusuf School (Comilla) in 1912. When he was in class V, he was shifted to Comilla Zilla School. His talent in music was revealed from his childhood, when he was studying in school. His music learning was started from his father. Later, he learnt music from different gurus who were very famous musician of India's music world. A detailed of his music learning from different people has been presented in this paper.

Burman completed his matriculation from Comilla Zilla School in 1920 at 14 years of age. After that he had taken admission in Victoria Government College and passed IA in 1922 and BA in 1924. In Comilla, there was a club called 'Young Men's Club' at the south of Katyayani Kalibari. Sachin Karta was regular visitor in that club and there he met with different poets, musicians, singers, lyricists and players. Famous persons Sanjay Bhattacharjee, Ajoy Bhattacharjee, Nazrul Islam, R. Purkayastha, Subir Sen were also there in that club. Famous and blind singer Krishna Chandra Dey (K. C. Dey) was also known to him. K.C. Dey came to Comilla on Burman's invitation. For the higher study, S. D. Burman left Comilla and came to

Calcutta (Presently Kolkata) to take admission at Calcutta University for master degree in English on 1925. At Calcutta, his new address was Tripura palace at Ballygunj circular road. In Calcutta, he was not feeling comfort because he spent his whole childhood in village. He could not adjust with the environment of Calcutta and left university without completing master degree. Then his father wanted him to study law from London, but he had refused as he was not interested in law. He was very much interested to learn music. He was fond of K. C. Dey's music.

After his father died in 1930, he became very poor and was helpless. At that time he started his music career with tuition. Later he got chance in radio, then Hindustan Musical Products (HMV). Later on he worked in Indian film industry as a music director. The complete music career of Burman has been given in this paper. Many famous singers and artists of Indian film industry made their career under the guidance of him. These are also given in this paper.

The paper is organized in five sections. The next section contains how Burman has become interested in music. The third section includes his music learning from different gurus. The fourth section has given a brief overview of his music career. The career building of different singers and artists has been given in fifth section. In section six, a conclusion has been drawn.

Childhood attention in music

S. D. Burman said about his father Nabadwip Chandra Dev burman that he has been built up according to his father's rules, his father's lessons are his backbone, his father was a perfect man to him, loved him so much. Nabadwip Chandra was really a quality artist. He was also very expert in painting and in making sculpture. In their home festivals like Durga puja, Swarasati puja, kali puja he used to make sculpture of god and goddess by himself. He would write articles regularly in famous newspaper named 'Rabi'. He had also written one book named 'Abarjanar jhuli'.

At Comilla Zilla School, during the lunch hour, S. D. Burman used to organize musical sessions in the school. S. D. Burman said that when he was in class V, he sang a song at Saraswati puja in his school. That song had been taught by his father. All the audience had very much appreciated him for that song. Being happy, school headmaster had sent an appreciation letter to his father. He would like to play flute in his early childhood. Later days he mentioned the flute in many of his composed songs. Such as Bashi de mor hatete, O bashi, allhar dohai, Bashi sune aar kaj nai, Sei je din guli bashi bajanor din guli, Baje na bashi go and Bashi aaj kede koi tabu seto dure noi. During that time, Shyamacharan was a famous dhrupad and khayal singer in Comilla. Nabadwipchandra wanted S. D. Burman to learn music from Shyamacharan. However, Sachin did not agree with that and he started learning music from his father. Day by day his study and music learning progressed simultaneously.

Music learning of S. D. Burman:

Sachin was very much interested in Folk song. In his childhood, he got inspired in folk music from Madhab and Anwar. They were working as servant in their house. He was very close to Madhab, who would recite Ramayana and Mahabharata for him. On Sunday, Madhab would hum passages from the Ramayana without any Taan Khatki. He used to sing without any Ustadi. Burman was fond of his simple music style. His another guru, Anwar used to sing Bhatiyali at night playing his Dotara instrument. Burman would lost himself into that song leaving all his study. They used to talk with each other by singing across the ponds and gardens. There was no constraint of Sargam, Taal, Laya, Meer, Gamak in his song. Later, Burman said about Anwar that explanation of Dehatatwa, Ishwartatwa and Radhakrishna Milan Biraha in his simple song style would give him a tinge that he cannot explain.

In 1925, when he was in Calcutta (Tripura Palace), he started learning music from K. C. Dey. He was S. D. Burman's first guru in classical music. Burman used to call him 'Kestababu'. Burman organised different programmes in Comilla and Agartala and brought K. C. Dey to those programmes. Up to

1930, he had taken music lessons from K. C. Dey. Then he started his lessons from Bishwadev Chatterjee in 1932. He was 3 years senior to him. After that he also learnt music from famous sarangi master khalifa Badal Khan and Sarod Maestro Allauddin Khan. He also learnt Banarashi Thumri from harmonium player Shyemal Khetri. He also took lessons from Abbaj Uddin Ahmmed who was famous singer of Bhauaiya song.

Music career of S. D. Burman in Calcutta

In 1930, his father died. Then he broke down and became helpless. Slowly, he understood the reality of the world. He had to leave the palace due to scarcity of enough money. Then he had stayed in a rented room at 1A Basanta Roy road, Calcutta. There he started a music school named Surmandir and started earning.

With a constant effort, he got chance to record music in Calcutta radio. For the first time, in 1926 his voice was heard on radio. He got 10 rupees for this recording. With this money, he was feeling so happy that he thought himself as 'lakhpati'. He wanted to record his song in Hindustan Musical products (HMV). But HMV was not impressed with his vocal cord voice and rejected him. Because according to HMV, his voice was not suitable for recording.

Later on, HMV gave him chance in 1932 and with this his professional career had been started. At his 27 years of age, his music recording was first released. Sachin Karta composed two songs 'Dakle kokil roj bihane' and 'Ei pathe aaj eso priyo'. The first one was sung by Hemendra Kumar Roy and it was in folk style. The second one was in Kajri style and sung by Sailen Roy. In his first record, he had shown two different types of quality in music. Expert musicians such as Amiyanath Sanyal, Dhurjti Prasad Mukhupadhyay, Khagendranath Mitra congratulated him for these songs. From 1930-36 he developed a music by using folk music in his own music style.

S. D. Burman had contributed music in theatre such as Satitirh and Janani. He became famous by composing tune in theatre world. He acted as a beggar in movie 'Salima' produced by Madhu Basu. In 1934, Burman was invited in all India music conference organised by Allahabad University, outside of Calcutta. He performed his Bengali 'Thumri' in front of illustrious audience and they became very pleased by listening his song. There he first time met with Abdul Karim Khan of Kirana Gharana and has been blessed by him. Sir Tej Bahadur Sapru, Vijoy Laxmi Pandit, Dr. Kailash Nath Karju were also present in this conference. It was the first-time, S. D. Burman participated in all India music conference. After that he had been invited by this conference three times consecutively. In 1935, he attended music conference in Calcutta, inaugurated by Rabindranath Tagore. Here he met with Ustad Faiyaz Khan. Burman would like his song. In that conference, he presented Thumri in front of him. Slowly his popularity was increasing. He used to sing on radio regularly.

S. D. Burman married Mira Das Gupta from Dhaka. Her grandfather Raibahadur Kamalnath Das Gupta was judge in high court. Her mother was a graduate from Dhaka University. From 1937, Meera Devi started learning music from S. D. Burman. On 10th February 1938, they got married. Meera Devi recorded some songs in the tune of S. D. Burman. Burman had also given tune in her lyrics. He sang total 16 songs written by Mira Devi. Among of them 6 songs were recorded in HMV. Mira Devi was also expert in music composing. They both sang together in 4 songs. She also got chance to sing in Allahabad music conference. Burman said that Meera's success, inspiration, cooperation, motivation and self-sacrifice were always behind of his success. He always felt himself lucky by getting Mira as his wife. On 27 June, 1939 they gave birth their only child named Rahul Dev Burman. In the same year D.M. library had published a book 'Surer Likhan' written by S. D. Burman. He had dedicated this book to his father. This book contains total 25 songs including swaralipi.

He built a house at Southend Park, Ballygunge in Calcutta. S. D. Burman started his filmy career with Bengali films in 1937. In Calcutta, he had given tune in 10 films. The name of the films are Rajgi

(1937), Rajkumarer Nirbasan (1940), Jibon Sangini (1942), Chadwabesi (1943), Matir Ghar (1943), Abhoyer Biye (1944), Matir Ghar (1944), Ashok (1944), Swami Stri (1944), George Saheber Natni (1944) .He could not achieve so much popularity in Bengali film industry. However, he was so much popular for Bengali songs.

Career with Indian film industry in Bombay

In 1942, he got a call from Ranjit studio, Bombay to work as a music director. Chandulal Shah was the owner of this studio. But he did not accept this proposal. He kept hope that someone from Bangladesh will invite him. However, nobody did it. Again, He got invitation in 1944 from Chandulal shah and Sasadhar Mukharjee of Mumbai Filmistan. Then he did not make any delay to accept this invitation. There was also another reason to accept this invitation was that his one friend Sushil Majumder from Bangladesh was also working there. In 1944, he moved to Mumbai with his family to work as a music director.

In Mumbai, the first Hindi movie he worked as a music director was 'Shikari' (1946). The music of the film became very much popular. By this film, he became familiar to Indian film industry. Then he got chance to direct music in another five Hindi movies. The name of those movies are 'Eight Days' (1946), 'Do Bhai' (1947), 'Shabnam' (1949), 'Paying Guest' (1957) and 'Munimji' (1955). All the songs of the film 'Shabnam' became hit. However, he was not satisfied with that. Because his concept was that any song will be accepted by the audience if they can sing it. In 1948, he met with Devananda who was fond of Burman's songs. They used to get together in Devananda's house. Music director Guru Dutta would also join them. Burman said that in Mumbai they were the best fan of him. Devananda had proposed him to compose music for the film 'Afsar' (1950) in his production house 'Navketan'. The music of this film became hit, though the movie was not that much hit. He had also given tune and lyrics in the next film 'Baazi' (1951) in the same production house. He had also given his contribution in the film 'Taxi Driver' in 1954. With this film he became famous. Some other film which music has been directed by him and also became much hit are 'Guide', 'Bandini', 'Ziddi' etc.

In 1969, S. D. Burman was awarded 'Padmashri' for composing music in 'Aradhana' film directed by Shakti Samanta. He also received the national award for composing song in the film 'Zindagi Zindagi' in 1972. He got second film fare award for the film 'Abhiman' (1973). Another award, the Sangeet Natak Akademy award is received by him in 1958. S. D. Burman and Rahul Dev Burman both were honoured Asian Film Award for the film 'Pyasa'. In 1964, he received Santa Haridas award for the film 'Kaise Kahoon'. For his enormous knowledge in music, he got invitation to perform as a judge in international singing competition on 1962 held in Helsinki of Finland.

In his last days he got offer to direct music in film 'Chupke Chupke' and 'Mili' in 1975, but he could not complete the work of 'Mili'. His son Rahul who later became a famous music director himself, completed the incomplete project left by his father. At the age of 69 years the bright star of the musical world S. D. Burman breathed his last in Bombay. Till the last day, his passion was remain in music.

Contribution of S. D. Burman in the career of different famous singers

In Mumbai, many great singers have been succeeded in music world under his guidance. The contribution of S. D. Burman in the career of different singers has been described below.

1. Kishore Kumar – Kisore Kumar was very famous singer in Indian film industry. In his childhood, he used to come at studio with his brother Ashok Kumar, who was working as an actor. At that time S. D. Burman had noticed the extra ordinary talent of Kishore Kumar in singing. According to him, the voice of Kishore Kumar was God gifted. Burman had given him chance to sing a song in the film 'Eight Days'. After that according to Burman's advice he enter into music field leaving his college. Then Kishore Kumar established himself as a playback singer in Hindi

film. The song of 'Aradhana' film in Kishore's voice became very much hit, which had been directed by S. D. Burman. All the song of Kishore Kumar directed by Burman became very much hit. Kishore Kumar would consider him as his guide. A list of few popular songs of Kishore Kumar directed by S. D. Burman are:

(i) Mere labon pe dekho aaj bhi tarane hain from the film Baazi in 1951.
(ii) Dukhi man mere sun mera kahna from the film Funtoosh in 1956.
(iii) Ek ladki bheegi bhagi si from the film Chaltika naam gaadi in 1958.
(iv) Khwab ho tum ya koi haqeeqat from the film Teen deviyan in 1965.
(v) Ye dil mna hota bechara from the film Jewel thief in 1967.
(vi) Mere sapnon ki rani kab ayegi tu from the film Aradhana in 1969.
(vii) Badin soon hair zindagi ye zindegi from the film Mili in 1975.

2. Lata Mangeshkar – Lata Mangeshkar was also very much famous as a playback singer. According to S. D. Burman her voice was perfect for mike, no one was like her in past and will come in future. She could sing any song of different tune in different mode. S. D. Burman had given tribute to Lata for his success in so many songs. In 1963, Lata sang a song in the film 'Bandini' under the direction of Burman. A list of few songs by Lata and S. D. Burman are given below:

i) Aaj nahi to kal bikhar jayenge ye badal from the film Mashal in 1950.
ii) Jhan jhan jhan jhan payal baaje from the film Buzdil in 1951.
iii) Dil se mila ke dil pyar kijiye from the film Taxi driver in 1954.
iv) 1957. Chand phir nikalaa magartum na aye from the film Paying guests in 1957.
v) Jogi jabse tu aya mere dware from the film Bandini in 1963.
vi) Kanton se kheench ke ye anchal from the film Guide in 1965.
vii) Mera antar ek mandir from the film Tere mere sapne in 1971.

3. Asha Bhoshle – Asha Bhoshle was also a very high quality singer. Her voice had an energetic nature. Later, she became daughter in law of S. D. Burman. Some songs by both of them are listed below:

(i) Phool gendwa Na maro dar jaungi from the film Funtoosh in 1956.
(ii) Nazar lagi raja tore bangle par from the film Kala pani in 1958.
(iii) Kali ghata chhaye mora jiya tadpaye from the film Sujata in 1959.
(iv) Sach hue sapne tere jhoom le o man mere from the film Kala bazaar in 1960.
(v) O panchhi pyare sanjh sakaare from the film Bandini in 1963.
(vi) Tum jiyo hazaron saal saal ke din ho pachs hazar from the film Sujata in 1959.

4. Manna Dey – Manna dey was favourite to S. D. Burman for classical song. He was nephew of Burman's guru K. C. Dey. He was assistant of S. D. Burman at the time of production of film 'Samar' (Bengali film) and 'Mashal' (Hindi film). Burman was always impressed on Munna Dey as he used to do vocal practice regularly within his busy schedule. In 1961 S. D. Burman's composed song 'Poocho na kaise maine rain bitayi' for the film 'Meri surat teri aankhen' was sung by Manna Dey. It was very heart touching to the listeners. Few other hit songs of Manna Dey directed by Burman are given below:

(i) Upar gagan vishal from the film Mashal in 1950
(ii) Hato kahe ko jhoothi banao batiya from the film Manzil 1960.
(iii) Mat ro mata laal tere bahutere from the film Bandini in 1963.
(iv) Poocco na kaise maine rain bitaayi from the film Meri surat teri ankhen in 1963.

(v) Hey ram hamare ramchandra from the film Guide in 1965.
(vi) Tere naina talash karein from the film Talash in 1969.
(vii) Mere sab kuch mere geet re from the film Zindagi zindagi in 1972.

5. Geeta Dutta – Geeta Datta was a playback singer of Hindi cinema. She became famous by singing 'Mera sundar swapna beet gaya' in film 'Do Bhai; under the direction of S. D. Burman. In the film 'Bazi', S. D. Burman also gave her chance to sing 'Tadbir se bigri huyi tagdir banale'. That was also a hit song. Some other songs of Geeta data with S. D. Burman are as follows:

(i) Mera sundar swapna beet gaya from the film Do bhai in1947.
(ii) Mera dil tadpa kar kahan chala from the film Shabnam in 1949.
(iii) Aaj ki raat piya dil na todo from the film Baazi in 1951.
(iv) Aaj sajan mohe ang laga le from the film Pyasa in 1957.
(v) Nanhi kali sone chli hawa dheere ana from the film Sujata in 1959.

6. Mohammad Rafi – Mohammad Rafi was also a playback singer in Hindi film industry. Rafi and Burman had worked together in 37 movies. Among of them some popular movies are 'Aradhana', 'Chupke Chupke', 'Abhiman', 'Anurag', and 'Jewel thief ', 'Guide'. Some popular songs by them are listed below :

(i) Duniya mein meri aaj andhera hi andhera from the film Do bhai in 1947.
(ii) Ye mahlon ye takhton ye taajon ki dubiya from the film Pyasa in 1957.
(iii) Hum bekhudi mein tumko pukare chale gaye from the film Kala pani in 1958.
(iv) Dekhi zamane ki yari bichhade sabhi baari baari from the film Kagaz ke phool in 1959.
(v) Khoya khoya chand from the film Kala bazar in 1960.
(vi) Nache man mora magan tig da dhigi dhigi from the film Meri surat teri ankhen in 1963.
(vii) Dil mein ek jaane tamanna ne jagah payi hai from the film Benazir in 1964.
(viii) Din dhal jaye aur raat na jaye from the film Guide in 1965.

Many other prominent singers also worked with S. D. Burman and gave successful contribution in music industry. Some of them are Sandha Mukharjee, Hemanta Mukhopadhyay, Ashok Kumar, Amirbai Karnataki, Samsad Begam, Rajkumari, Suraiya, Parul Biswas, Suman kalyanpur, Mubarak Begam, Hemlata, Mukesh, Surendra and Batish, Talat Mamud.

Conclusions :

This paper describes a complete details of S. D. Burman about his music career. His contribution in Indian film industry, Bengali film and the music world is explained briefly in this paper. From the childhood, he was very much interested in music. The growing interest in music from his childhood has been explained in this paper. For his incredible contribution he got lots of awards. Those things are explained in this paper. His contributions to the career of different famous singers of Indian film industry are also explained in this paper. With all these investigations, it can be concluded that S. D. Burman was a star of Indian film industry and for his enormous contributions, Indian music world rises very high.

Reference :

1. Chakroborty S. Bhatigangabaiya - Sachin kartar jeeban-o-gan, Akshar publishers. Kolkata, 2001.
2. Sarkar A. Sachinkarta amader gorbo, Kumar Sachin Dev Burman Jonmo satabarshiki smarak grantha, Deptt. of Information and Cultural Affairs & Tourism publishers. Tripura, 2007, 2, 21-22.

3. Chowdhury HQ. Incomparable Sachin Dev Burman, Toitomboor publishers. Bangladesh, 2011.
4. Dev Burman K. Sachin Kartar ganer bhuban, Prantik publishers. Kolkata, 2006.
5. Roy P. Sachin karta, Parul prakashani. Agartala, 2005.
6. Majumder G. Ganer Koli surer durite, Kumar Sachin Dev Burman - Jonmo satabarshiki smarak grantha. Deptt. of Information and Cultural Affairs & Tourism publishers. Tripura, 2007, 2, 240-249.
7. Dev Burman K. S.D Burman - The world of his music, Rupa publications. New Delhi, 2013.
8. Songs of yore - A tribute to old Hindi film music, http://www.songsofyore.com, accessed on 15th August 2017.
9. Dev Burman S. Sargamer Nikhad, Kumar Sachin Dev Burman Jonmo satabarshiki smarak grantha. Deptt. of Information and Cultural Affairs & Tourism publishers. Tripura, 2007, 2, 289-310.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

J B Patnaik : An Odia Freedom Fighter

Gopinath Das
[1]The Author is a Ph. D. Research Scholar in Political Science, Department of Social Science, Fakir Mohan University, Balasore, Odisha

Abstract : Hailing from humble a background, Janaki Ballav Patnaik not only provided his abilities in politics nd role as editors. Eventually he took up leadership to lit up candle in freedom fighting in Odisha. Janaki Ballav Patnaik learnt the need for freedom while he was still a boy. He was influenced by the spirited words of Gandhiji. His association with congress leaders dragged him into politics. He delighted the people by his youthfulness of spirit and body and the people were attracted to his spontaneity and utter freedom from pompousness. As a conscious leader he could inspire and motivate the masses for freedom fighting. He occupies a place for himself in the history of Odisha for his contributory work for independence and progress of the nation with his multi dimensional approach. He was a great freedom fighter, socialist, writer, philosopher and an abled freedom fighter. He was a political genius and his diplomatic tactics made him to be ahead of many people in politics and excelled with supremacy for many decades.

Introduction Orissa had witnessed glorious periods during the Kalingan Empire and Kharavela reign. Since then invisible, but unbreakable cultural, philosophical and ethical bonds have united this state and kept it alive and vibrant. Soon after the formation of Orissa and impressing upon the continuity of democratic system, it followed by a period of degradation and corruption. But true to the statement of Bhagavad Gita, "Whenever corruption appears overwhelming, the community at large, some religious, philosophic and social rebels born and starts a new cult and gives a new turn to the Hindu way of life."

During the pre Independence era, when Orissa was struggling for a special identity in India, a humble boy from an obscure village, Rameswar, near Khurda, rose to political eminence, popularly known as Janaki Ballav Patnaik a popular Chief Minister of Orissa. Thus, Janaki Ballav Patnaik created an irrevocable history stamping behind a glorious example for the people of Orissa.

Background Morning shows the day. Janaki Ballav Patnaik grew dynamic since his childhood days. The brilliant memory power that he had cherished during his student days was highly acclaimed and acknowledged by his teacher and contemporaries. Under the sturdy guidance by his father, Janaki Ballav Patnaik developed keen interest in the study of Sanskrit, the root of all Indian languages. Possessed with the quality of independent thinking, undaunted spirit and indomitable personality Janaki Ballav Patnaik had allured any of his friends and associates.

During the pre Independence era, when Orissa was struggling for a special identity in India, a humble boy from an obscure village, Rameswar, near Khurda, rose to political eminence, popularly known as Janaki Ballav Patnaik a popular Chief Minister of Orissa. Thus, Janaki Ballav Patnaik created an irrevocable history stamping behind a glorious example for the people of Orissa.

During 1803, British invaded Orissa. The sturdy British rule ad administration was very much predominant in Orissa. The rules were subjugated and forced to accept the British Policy. But notwithstanding to this, ironically Dala Behera, the ruler of Rameswar was given special treatment for his stuff and gallant. As an example British colonel Sir Harcourt, the Governor General had

arranged a special honor when Dal Behera paid visit to Puri. Thus, admittedly, Rameswar, the birth place of Janaki ballav Pattanik holds a special position in history which needs a mention. Further, when the Britisher attacked on Mukunda Dev, the last Hindu king of Orissa, and confronted the 'Khurdha Gada from east west at north side and blockade all the sides of Khurdha Gada they left untouched the southern way. Getting this opportunity from the southern side, Mukunda Dev escaped and took shelter in his son-in-laws house. Thus, Rameswar Gada remained unattacked.

Janaki Ballav Patnaik was also well known for his true humility and simplicity. The germination of political activity and organization was found right from his school career. He had actively associated himself with colossal volunteering organization with a view to imparting the quality of leadership ad strong sense of patriotism for India's struggle for freedom through awareness and motivation, every day the sense of dedication, sacrifice and ser ice to mother land was exerted into the minds youngster for the case of India's Independence.

Janaki Ballav Patnaik moved by the ideas and ideologies of Gandhiji. Gandhiji's charismatic personality had a deep impact on Janaki Ballav Patnaik. When the whole world was busy in favouring the Second World War, Janaki Ballav Patnaik had opposed to war. Young Janaki Ballav Patnaik had echoed the ideologies of Mahatma Gandhi and very often urged infavour of peace. For him war and peace are two contradictory words go parallel to each other. He had condemned and reacted against the war procession and dissuaded his friends not to organize meeting infavour of war. Love for peace was the greatest motto of Janaki Ballav Patnaik. When the whole of India was surcharged politically with Mahatma Gandhi's call for 'Quit India Movement', during 1942 Janaki Ballav plunged himself into the main stream of struggle for independence he took active part in quit India movement and organized student volunteers to otivate the villagers against the mighty British force.

Subsequently, he argued for withdrawal of British from India. While addressing the All India Congress Committee meeting held at Bombay the greatest slogan of 'do or die' was vibrate by Mahatma Gandhi to demoralize the British. The immoral slogan 'do or die' was the clarion call for Janaki Ballav Patnaik, a budding politician and student leader. He took active part in the movement for freedom struggle electrifying the ideas and ideologies of Mahatma Gandhi to emancipate India from the British control.

Undaunted Janaki Ballav Patnaik was determined to carry out the movement at any cost. To gain the momentum he was constantly in touch with two great senior freedom fighters like Gokulananda Ray Chudamani and Prananth Patnaik of Khurda. Their inspiring speeches, style of organization, stirring deliberation at different places were consciously followed by Janaki Ballav Patnaik. Their silver linings of address were the pivotal instrument in the orchestra of the freedom struggle.

In the mean while the illegal arrest and detention of the congress leaders led to an outburst of mass revolt. They marched through the streets singing National songs demanding the release of their leaders. The students walked out of schools and colleges and started the campaign of sabotage and destruction.

J.B. in Freedom Movement : The several National Movements organized by students throughout India made Janaki Ballav Patnaiak restless. He too expedited the movement and seriously worked out for the root level organization of his area but two stumbling blocks obstructed his organization and checkmated his plans to proceed further. One was his own Headmaster Bankanidhi Patnaik and the other Jagannath Mishra, Sub-divisional officer of Khurdha. Prior to this situation his revered Headmaster and Jagannath Mishra S.D.O., Khurdha were honored with the highest title 'Ray

Sahib'. After having been honored they became pro British and dissuaded their favorite students not to join the freedom struggle. Both of them had a love and fear image in Khurdha and no student could dare to confront them.

Janaki Ballav Patnaik was a man of determination. In spite of his intimate relation with his headmaster he was indifferent and advise of these tow Ray Sahibs were unheeded to particularly in the matter of freedom struggle. Rather clandestinely he kept in touch with Biren Mitra, the student leader of Cuttack and freedom fighter. Admitted by, it is matter of surprise that despite his busy political career and active involvement in various volunteer organizations and grueling schedule of political activities his academic development was never in shamble. During 1943 he passed out Matriculation in first division and was among the best tenth.

Janaki Ballav Patniks college career was equally deserves worth mentioning. At the age of sixteen he joined in the Ravenshaw College, Cuttack, one of the most leading and premier colleges of Orissa. This institution was a turning point for Janaki Ballav Patnaik as he proved to be the best in all walks of life. In Cuttack he came in contact with various leaders and the makers of modern Orissa. Prominently among other were Hare Krushna Mahatab, Nabakrushna Chaudhury, Biren Mitra who had left indelible impression on his mind and heart. Janaki Ballav Patnaik was a magnanimous man. His qualities of leadersip and warm humanity, his patience and presentence his determination and energy, his courage and force all that have stamped his mark indelibly on the public life of our country. His social and political activities actually started in a vigorous form when he was student leader of Ravenshaw College.

Right from the student days his activities were an edge over others. The quality of his ledership and the burning desire for achieving independence of the country were transparently visible in his behaviour and overall performance as a young and the shining star of the mother land. As a sequel to this he took leading role in removing the union 'Jack Flag' at Ravenshaw College in 1947 and declared the west hostel as independent. He had done all that a true soldier of the mother land could do to free his nation from subjection and bondage. His only joy in life was his service to Mother land. As a mark of great respect and adoration to Gandhian Philosophy he had started wearing khadada (country woven cloth) as his staple dress, right from student career.

Janaki Ballav Patnaik was not all intellect and majesty he was as well very much human, full, of life and humour as well. It was well known fact that wherever Janaki Ballav Patnaik was present he filled the place with laughter. He spared no one from being the object of his humour-sometimes not even himself. There are not many people who can enjoy a joke at their own expense, but Janaki Ballav Patnaik was one of those rare men who did so. His pranks were highly sharp, thought provoking and meaningful.

Over and above Janaki Ballav Patnaik's literary task was equally super. As a student leader all his time was being constructively utilized in discussing the current problems and finding out its solutions through discussion, debate and deliberations among his close colleagues. During the discussion literature, patriotic contribution of great leaders, reformation movement, and renaissance, socioeconomic and political dynamism of his time was given prime importance. The literary contribution of Kalidas, Upendra Bhanj, Shakespeare, Rabindra Nath Tagore, Political and social reformation of Gandhiji and Gopobandhu, revolutionary and social dynamism of Karl Marx and Lenin were very much highlighted among his friends only to revamp the dying spirit of Odias. Even he was so much emotionally attached to such contributions that very often he used to burst into tears and makes to get carried over.

Further, his pivotal concern with national cause was so irrevocable that wherever he may be, whether in the college, play ground, river site,

at Gouri Shankar Park or amidst friends his mind was obsessed with national movement in planning out discussing the removal of the Britishers from Indian soil. Young Janaki Ballav Patnaik was actively involved in organizing various volunteer organizations while at Ravenshaw College. To teach and train the volunteers about the rich heritage and culture of Odisha he had formed one Regional Student Federation at Khurdha, consisting of all like-minded people.

Another note-worthy achievement of Janaki Ballav Patnaik can be better spell out when he also accorded flamboyant reception to Sri Sarat Chandra Bose, brother of great National leader Subhas Chandra Bose 1944. Sri Sarat Chandra Bose was awfully engaged in organizing people against might British ruler. On his enroute to Madras Sri Bose had a brief stop at Cuttack Railway station. But there was pinned restriction of meeting of any kind to Sri Bose. Determined Janaki Ballav Patnaik left no stone unturned to meet Sri Sarat Chandra Bose and finally plunged into discussion with Sri Bose about freedom movement.

Janaki Ballav Patnaik was a student when the 'Quit India Movement' was gaining ground. An upsurge of revolutionary Nationalism was what one was witnessing. It was a movement that elevated the anti-imperialist struggle to new heights. When Quit India Movement was in full swing, Janaki Ballav Patnaik was in the Khurdha High School. Among those who made great scarifies in 1942, for the sake of our motherland was young Janaki Ballav Patnaik.

For an innocent school boy of Khurdha High School, it was nothing but a plunge into the dark known. He was about to sit for the matriculation examination, which would qualify him for college studies. Among millions of followers of Gandhiji, a great sacrifice than that of school boy Janaki Ballav Patnaik has not so for been known. It is natural, therefore, that out of this spirit of sacrifice their blossomed out later on the finest flower of Gandhism on Indian soil. Being very young Janaki Ballav Patnaik was not particularly suitable for Quit India Movement work of any kind. Instead of his childhood, he contributed a lot for the mother land.

It seemed, the innocent school boy Janaki Ballav Patnaik had been slowly, though consciously, preparing himself for the particular role he would play in India's national life. During High School, he was already full more of patriotic feelings than of scholarship. Even in this high school days, he had already formed the habit of avidly reading the daily news paper, searching particularly for reports of the activities of the Indian National Congress leaders in India and Particularly in Odisha.

He seldom missed any important political meeting at Cuttack and Khurdha addressed by various nationalist leaders. But the greatest influence on the young boys, as on millions of that generation, was Gandhiji. Although he had not met Gandhiji, he was a staunch supporter and admirer of Gandhiji.

1945 was a remarkable year for the state of Odisha as well as to India. The end of Second World War has had brought socio-political doll-drum for the entire nation. Odisha too was nonetheless surcharged with political upheavals. In the same year Sri Nabakrushna Chaudhury the great freedom fighter got released from jail. Despite many a restriction imposed upon by the college authority, Janaki Ballav Patnaik was the first man undauntedly accorded a grand reception to the prominent freedom fighter 'Sri Nabakrushna Choudhury. Sri Nabakrushna Choudhury was extremely pleased with the organizing ability of Janaki Ballav Patnaik and had reposed confidence for all other future organization.

He acted like a flamboyant Journalist and expressed his opinion in news papers without any fear and favour. Whenever there was mass movement for justice, always he supported the mass. He had been able to create powerful currents of public opinion, which had been an

instrument in destroying the image of parties and their leaders and heralding their political doom. The police, bureaucrats, Ministers, the breeders and promoters of corruption either in the sphere of education, public health, engineering or civil supply were mortally afraid of the struggle of his facile pen articulated through the editorial columns and news projection of 'Prajatantra'. May it be the boundary movement of 1957 or Praja Andolan of Madhupur in Cuttack district for the abolition of Zamidari system or Binoba Bhave's Bhoodan Movement, Janaki Ballav Patnaik was the powerful nucleus of all movements in Orissa.

Evaluation : Janaki Ballav Patnaik was strongly determined by Gandhian philosophy and took active part in freedom movement to emancipate Indian from foreign rule, which shows he had a free minded personality and obligation towards the national leaders. Leading role in removing the Union Jack Flag at Revenshaw College proves him a fearless leader. Leadership is his born quality reveals from his activities when he was a student in Khurdha High School. He seldom missed any important political meeting by various nationalist leaders which resulted him to give attention towards freedom of nation as well as his state. Being the characteristic of freedom fighter, he never hesitates to support the national leaders of freedom movement and promote the people of the state to participate in freedom movement. He carried through Odisha what national leaders accomplished for the entire country. His creativity supported the national leaders for the freedom movement. He was a distinguish leader for the freedom movement of India. He believed in action and not in talk. He was serious and severe in nature. He was saga of fearless, indomitable and uncompromising fight for the fate of Odisha. He was among those illustrious men like Lalbahadur Sastri, Pandit Gopabandhu Das, Godavarish Mishra and many others, who blossomed out of dust and rose into glory to highest panical of celebrity by dint of their merit and ability. His merit and ability enriched the freedom movement. He is tremendous fortitude and unique capability of true organizer, a patriot and a freedom fighter that made him a dignified personality into one.

Conclusion : Janaki Ballav Patnaik is afrontline freedom fighter social reformer, an educationist, a poet a translator and a politician. Janaki Ballav Patnaik has great faith in the power of the people and in the potency of public opinion to maintain check and balance on any misuse of power. When freedom of expression assured the whole process acts as a check on the arbitrary exercise of authority. His political life is a life ceaseless striving and a life of devotion to emancipate the state as well as nation from the foreign rule. His pioneering attempt and activities reveals his great love for the country. Janaki Ballav Patnaik combined in him the great qualities of truthfulness, boldness and simplicity. He is a courageous leader, never fighting shy of facing bitterest of political storm. He is a man of integrity not only in his personal conduct but also in his understanding life and work.

References :

1. (a)Bailey, F G. Politics and Social Change: Orissa in 1959, Berkley, 1970.
   (b)F G Caste and the Economic Frontier: A Village in Highland Orissa, Bombay, 1958.
2. Bendix, R Max Weber: An Intellectual Portrait, New York, 1960.
3. Brass, Paul R. Caste, Faction and Party in Indian Politics, Vol. 1 Delhi, 1983.
4. Chibber, P Democracy without Associations: Transformation of the Party System and Social Cleavage in India, Delhi, 1999.
5. Currie, B, Political Authority, "Public Deliberation and the Politics of Poverty Reduction" in JayalNirja G. and SudhaPai, op. cit. 2001.
6. Dumont, L., Power and Territory, in Kaviraj, op. cit.
7. Frankel, F, and MSS Rao, Dominance and State Power in modern India: Decline of a Social Order, vol. 1 and vol. 11, Ox. 1990.

8. GuhiaR, India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy, Picador, 2007.
9. Jayal, NirjaGopal, 'the Governance Agenda: Making Democratic Development Dispensable', EPW, 22 February, 1997.
10. Jaffrey, R. Indian Language News Papers and Why they grow in Economic and Political weekly, 28(38),2004
11. Kaviraj, S. Apparent Paradoxes of J Nehru, Mainstream, Nov-Dec, 1980.
12. Khilnani S. The Idea of India, London, 1997.
13. Kohli, A, Democracy and Discontent: India's Growing Crisis of Governability, Cambridge, 1990.
14. Kothari, R Politics in India, Boston 1970.
15. Krishna, A Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy, New York, 2002.
16. Kulke, H. (ed) The State in India, 1000-1700, Delhi, 1995.
17. Kaviraj, S., (ed) Politics in India, Oxford 1999.
18. Lassell, H. 'Faction ' in Encyclopedia of the Social Sciences, New York, 1931.
19. March, James G and Johan P. Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life American Political Science Review, 78, 1984.
20. Mitra, S., 'Effects of Institutional Arrangements on Political Stability in South Asia', Annual Review of Political Science, No.2, 1999.
21. Mohanty, N Oriya Nationalism: Quest for a United Orissa (1866-1936) New Delhi, 1982.
22. Morris Jones, The Government and Politics of India, London, 1964.
23. Myron Weiner, State Politics in India (ed.) Princeton, 1965.
24. Reddy, G Ram and G. Hargopal, The Pyraveerkar: The Fixer in Rural India' , Asian Survey, 25 (11), 1985.
25. SoumyaRanjanPatanaik, The March to Modern odisha, 2013.
26. Weiner, M Party Politics in India: the Development of a Multi Party System, Princeton, 1967.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

चीन की चुनौती और समाधान

सुदेश बाला जैन
सहायक प्राध्यापक, महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय, करोंदी (कटनी)

प्रस्तावना : भारत सहित दुनिया के बड़े बाजारों में अपना एक छत्र कारोबारी राज करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग उठती रहती है। हम अपने राष्ट्रवाद के प्रेम में ओतप्रोत होकर बहिष्कार के नारे गुंजायेमान करने लगते हे, लेकिन बहिष्कार के पहले इस बात पर विचार ही नही, गंभीर मंथन करना होगा कि सिर्फ सामानों के बहिष्कार से कोई देश अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा का त्याग कर देगा। इसका उत्तर नही में होगा। वैसे भी देश में दक्षिणपंथी समय–समय पर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात दोहराते रहते है। पाकिस्तान से चीन की नजदीकियॉ और डोकलाम पठार पर चीनी और भारतीय सेना के आमने–सामने होने के बाद बहिष्कार का मामला तूल पकड़ता जाता है। अपनी भारतीयता को दिखाने के लिए कुछ संगठन सड़कों पर आकर चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील करने लगते है। डोकलाम पठार पर पस्तावित 3500 कि.मी. सड़क निर्माण पर भारत का सीधा हस्तक्षेप भी नही है, विवाद तो भूटान और चीन का है। लेकिन भारत अपनी उत्तर की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सड़क निर्माण का विरोध करता है। विरोध अपनी ज़गह सही है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन चीनी माल के बहिष्कार के पहले कुछ पहुलुओं पर विचार करना भी जरूरी है कि आखिरी पूरा देश चीनी माल पर क्यों निर्भर हो गया। जरूरत है चीनी माल के साथ ही भारत की सरकारे (केन्द्र और राज्य) सब मिलकर चीन का विरोध करे तभी सच्ची देशभक्ति होगी।

सारांश : पाकिस्तान से चीन की नजदियॉ और सिक्किम बार्डर पर भारत और चीन की सेना आमने–सामने होने के बाद बहिष्कार का मामला ज्यादा तूल पकड़ गया। लेकिन क्या अकेले बहिष्कार से बात बनने वाली है, इन बातों पर यदि गौर करते तो भारत का चीन के साथ व्यापारघाटा पिछले साल बढ़कर 46.58 विलियम डॉलर यानि लगभग 3.00 लाख करोड़ रूपये हो गया है, जबकि चीन ने पिछले वर्ष निर्यात 8.33 विलियन डॉलर को 0.2 फीसदी बढा दिया है। भारत का चीन में निर्यात 11 फीसदी गिरकर 11. 76 मिलियम डॉलर पहुॅच गया है। चीन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र दो फीसदी है इससे साफ है कि अगर चीनी माल का भारत में बहिष्कार हो भी जाये तो चीन को तुरंत अपनी अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव नही पड़ेगा। हालांकि इससे इंकार नही किया जा सकता है कि चीन भारत जैसा बड़ा बाजार आसानी से खोना नही चाहेगा।

अब दूसरे पहलू पर भी विचार करे तो चीन के लिए भारत न सिर्फ सबसे बड़ा बाजार है बल्कि सबसे आसान भी है। चीन की पॉलिसी ''वन बेल्ट, वन रोड़'' में भारत का बाजार सबसे फिट है। इसके अलावा हमारी सरकारे (चाहे केन्द्र की हो या राज्य की) निवेश के लिए पलक पावड़े बिछाई हुई है।

1. वर्ष 2011 में चीन का भारत का कुल निवेश 102 मीलियम डॉलर था जो वर्ष 2016 में 01 बिलियन डॉलर हो गया जो रिकार्ड है।
2. वर्ष 10 अप्रैल 2017 को हिदुस्तान टाईम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और चीनी कंपनियों ने भारत में चार बिलियन डॉलर का निवेश किया है वर्ष 2014 के पहले चीन का भारत में सिर्फ अहमदाबाद में रीजनल ऑफिस था अब महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और हरियाणा में ऑफिस खुल चुके है।
3. वर्ष फरवरी 2017 में चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की सात बड़ी फोन निर्माता कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा–

1. चीन की कंपनी ''चाइना रेल्वे रोलिंग स्टांक'' को नागपुर मेट्रो के लिये 851 करोड़ रूपये का ठेका मिला है।
2. इसी कंपनी को गांधीनगर–अहमदाबाद लिंक मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10,773 करोड़ रूपये का ठेला हथिया लिया गया है।
3. हाल ही में गुजरात सरकार ने चीनी कंपनियों से निवेश के लिए 5 बिलियन डॉलर के एम.ओ.यू. साइन किये है।
4. कर्नाटक सरकार चीनी कंपनी को 100 एकड़ जमीन देने पर सहमति दे चुकी है।
5. महाराष्ट्र ई. इंडस्ट्रीयल डेवल्पमेंट कार्पोरेशन ने चीन की दो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को 450 करोड़ निवेश के बदले 75 एकड जमीन दे दी है।
6. हरिणाया सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ 8 सहमति पत्र साइन किये है ये कंपनियॉ 10 बिलियन का इंडस्ट्रीयल पार्क बनायेंगी।

वर्ष जनवरी 2016 की डी.एन.ए. रिपोर्ट के मुताबिक चीन का सबसे अमीर आदमी हरियाणा में 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा। प्रदेश के इंदौर, भोपाल में मेट्रो का ठेका राज्य सरकार चीनी कंपनी को दे चुकी है। पिछले साल चीन ने 61 अरब डॉलर का सामान भारत के बाजारों में बेचा, जबकि भारत मात्र 9 अरब डॉलर का सामान चीन में बेच पाया। वर्ष 1990 से 2010 तक के बीच की वार्षिक औसत उत्पादक विकास दर चीन की 2.8 जबकि अमेरिका की 0.5 फीसदी और जापान की 0.2 फीसदी थी।

क्रिसल के हाल ही के सर्वे में भारत में 8 फीसदी बेरोजगारी है। वर्ष 2017 में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा नौकरी की जरूरत है। फिर भी देश की सरकारे स्थानीय अवसर पर रोजगार के अवसर जुटाने के बजाय विदेशी कंपनियों के लिए पलक पावडे बिछाये हुये है। इतना ही नही जिस चीन की आई.टी. कंपनी ने भारत की 8 आई.टी. कंपनियों की जासूसी कर 8 मिलियन डॉलर की चपत लगायी उसी कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने आई.टी. पार्क बनाने के लिए अपने प्रदेश में जमीन दे दी।

निष्कर्ष : देश की ही सरकारे चीन के साथ कारोबारी रिश्तो को सरकार और अर्थव्यवस्था की कामयाबी के रूप में पेश करती है, लेकिन जब विवाद की स्थिति बनती है तब हम लड़ियॉ, फुलजड़िया का विरोध करते है। बहिष्कार से राष्ट्रवाद दिखाई तो जरूर देता है लेकिन असल में राष्ट्र कमजोर होता है।

वर्ष 2011 में भारत में विदेशी निवेश करने वाले मुल्कों में चीन का 35वां स्थान था जो वर्ष 2014 में 28वां हो गया और वर्ष 2017 में 17वॉ बड़ा देश निवेशवाला हो गया और जल्द ही चीन भारत में निवेश करने वाले 10 बड़े देशों में शामिल हो जाएगा। इंडिया स्पेंड (रेशमा पाटिल) की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, विदेशी निवेश का मात्र 0.5 फीसदी भारत में निवेश करता है इसलिए भारत में बहिष्कार से चीन को त्वरित फर्क नही पड़ेगा, लेकिन यह भी सही है कि सरकारे और जनता एक साथ बहिष्कार करे तो चीन की कंपनियों सहित चीन सरकार को हिलाये जा सकता है। कुछ वर्षों से चीन 21वीं सदी की महाशक्ति (अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में) उभर रहा है। चीन अपने आप को जिम्मेदार अर्थव्यवस्था के रूप में पेश कर रहा है जबकि चीन दुनिया में सबसे कम पारिश्रमिक देनेवाला देश है। इसके अलावा भारत यदि कषि को केन्द्रित करे और कृषि से जी.डी.पी. का योगदान जो अभी 14 फीसदी है उसे बढ़ाकर 25–30 फीसदी करने में कामयाब रहे और लघु कुटीर उद्योगों पर फोकस करे तो चीनी माल भारतीय बाजारों में टिक नही सकता।

इसके अलावा यदि भारत में –

1. एफ.डी.आई. को ज्यादा से ज्यादा मैरिट के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाए।
2. सरकारें अपने नियमों को आसान करे।
3. देशी व्यावसायियों को भारत में व्यापार करने के लिए उत्साहित करें।
4. देश में स्किल्ड वातावरण तैयार करे, फिर चीनी माल का बहिष्कार करे तो चीनी निवेश को रोका जा सकता है।

5. चीन की तरक्की को सोशल मीडिया में कोसने और देशभक्ति–राष्ट्रवाद की लहरों में बहने की बजाय तकनीकी और आर्थिक नीतियों में अमूल चूक फेरबदल कर उत्पादन पर जोर देना होगा। कौशल विकास पर केन्द्रित होना होगा। उत्पादन भी सस्ता–सुंदर और ठिकाऊ हो तो उपभोक्ता देशी उत्पादन की तरफ आकर्षित होगा और यही आकर्षण देश के प्रति सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रवाद होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. पाण्डेय–अनिल आजाद–हैलो चीन देश पुराना नई पहचान, राजकमल प्रकाशन दिल्ली–2016
2- पीटर– Hessler, counting Driving report China.
3- Report China the 13th Five year plans (2016-2020) Economic & Social Development of the people.
4- Maxwell Neville Keywords to understand china source for publication about china 1960.
5- https://Khubar.ndtv.com
6. वार्षिक प्रतिवेदन–मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवल्पमेंट कार्पोरेशन।
7. वार्षिक प्रतिवेदन–भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

ई. पंचायत का महत्व व उसका विकास की गति में योगदान का अध्ययन

डॉ. महेन्द्र कुमार बिसेन
वरिष्ठ अध्यापक, शास. उ.मा. विद्या. मुर्गहाई, जिला–सिवनी म.प्र.

सारांश :– भारत की आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। देश के सम्पूर्ण विकास के लिए इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का विकास अति आवश्यक है। गामीण स्तर पर विकास व परियोजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार ने ग्राम पंचायतों को और अधिक सक्रिय व उनकी भूमिका में पारदर्शिता लाने के लिए ई. पंचायत योजना प्रारम्भ किया है, जो ग्राम पंचायतों को केन्द्र व राज्य सरकार से इन्टरनट से जोड़कर विकास परियोजनाओं व उनसे संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है। इस लेख में हम ई.–पंचायत के महत्व व उसके विकास कार्यो में योगदान पर प्रकाश डालेंगे।

प्रस्तावना :– भारत वर्ष की एक तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, आर पंचायत राज व्यवस्था ग्रामों की शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में 0.235 करोड़ ग्राम पंचायते, 6094 विकासखण्ड व 633 जिला पंचायत है। इन ग्राम पंचायत की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई.–गर्वनेन्स योजना प्रारम्भ किया है, जिसे ई. –पंचायत भी कहते है।

2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के पंचायत राज्य मंत्री से मुलाकाते आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान का भाग IX (पंचायत) तथा PESA (Panchayat Extention to Scheduled area) Act 1986 को लागू करना। इन मुलाकातों के सातवे चरण में सूचना प्रौद्योगिकी का पंचायत में उपयोग पर विचार विमर्श किया गया एवं 2005 National Advisory Council (NAC) ने भारत सरकार को इन पंचायतो के लिए राष्ट्रीय IT Program प्रारम्भ करने की सलाह दी। जिसमें एक राष्ट्रीय नेटवर्क या कम्प्यूटरीकृत सिस्टम होगा, जिसकी एक समिति समूह होगा जो फण्ड व सुविधाओं पर निगरानी रखेगा। NAC ने यह सिफारिश किया की केन्द्र सरकार एक वर्ष तक इस प्रोग्राम को लागू करने में सहायता करेगा। एक वर्ष बाद राष्ट्रीय ई.–गर्वनेन्स योजना को मंत्रीमण्डल ने पारित कर दिया जिसका एक परिणाम ई. पंचायत भी है।

ई.–पंचायत को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 11 करोड़ सॉप्टवेयर व कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर को पंचायती राज्य व्यवस्था के साथ स्थापित किया गया है। यह नई तकनिकी पंचायती शासन में पारदर्शिता लायेगी, जो इनके कार्य सम्बन्धित सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध करायेगी जैसे पेंशन, मकान कर, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है। ई–पंचायत बिजनेन प्रोसेस पुर्नश्चना सुविधा भी उपलब्ध करेगी जो मांग आधारित सुविधा को तेजी से सरल बना सकेगी और इन सबका परिणाम होगा ग्राम पंचायतों का स्वरूप आधुनिकता से सम्पन्न होगा।

ई–पंचायत परियोजना की प्रमुख विशेषताएं :–

1. यह देश की पहली परियोजना है, जिसमें जनपद पंचायत स्तर तक सभी ग्रामीण विकास एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की ऑनलाईन निगरानी की जा सकती है।
2. अत्याधुनिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि का उपयोग करते हुए पंचायतों की मूलभूत जानकारियों का संकलन किया जा सकता है।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऑनलाईन संसाधन डायरेक्ट्री का विकास हो सकता है।
4. ग्राम पंचायत स्तर तक के विभिन्न विकास कार्यो के भौतिक एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रणाली का विकास हो सकता है।

5. विभिन्न योजनाओं के तहत् लाभान्वितों की ऑनलाईन निगरानी प्रणाली का विकास हो सकता है।

6. रोजगार मूलक योजनाओं की ऑनलाईन निगरानी प्रणाली का विकास हो सकता है।

7. ग्राम पंचायतों की आय एवं वित्तीय संसाधनों का संकलन किया जा सकता है।

8. ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शासकीय अनुदान जनभागीदारी से प्राप्त आय दानदाताओं से प्राप्त दान आदि संसाधनों का संकलन किया जा सकता है।

9. ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना एवं आधारभूत जानकारियों का संकलन किया जा सकता है।

ई.–पंचायत की उपयोगिता :–

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न गरीबी उन्मूलन रोजगार मूलक हितग्राही मूलक एवं ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु संचालित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक निगरानी करते हुए राज्य, जिला एवं जनपद स्तर तक सीधे सूचनाओं का आदान–प्रदान ''रूरल सॉफ्ट'' के माध्यम से किया जाता है।

2. पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं तथा उपलब्ध आबंटन एवं व्यय की त्वरित जानकारी का आदान–प्रदान राज्य, जिला एवं जनपदों के मध्य ''प्रिया सॉफ्ट'' के माध्यम से किया जाता है।

3. अन्य शासकीय विभाग जैसे स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण इत्यादि विभागों की योजनाओं का पर्यवेक्षण संबंधित विभाग द्वारा सुगमता से किया जा सकता है।

ई.–पंचायत का क्रियान्वयन :– ई.–पंचायत परियोजना का क्रियान्वयन राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से किया जा रहा है। भारत के लगभग सभी राज्य अपनी ग्राम पंचायतों में ई.–पंचायत का क्रियान्वयन कर रहे है।

निष्कर्ष :– सूचना प्रौद्योगिकी ग्राम पंचायतों की शासन व्यवस्था को गति प्रदान कर विकास कार्यो व योजनाओं को सार्थक करने में अत्यन्त महत्व है। ई.–पंचायतों द्वारा जहॉ एक ओर विकास कार्यो में आने वाली दिक्कतों का निराकरण हुआ है। वही दूसरी ओर उनकी शासन प्रणाली में पारदर्शिता आयी है। ई.–गर्वनेन्स ने नई तकनिकी को ग्रामीण परिवेश से जोड़कर उन क्षेत्रों में सूचना व महत्वपूर्ण जानकारियों को ग्रामवासियों तक सरल सुगम पहुॅच बना दिया है। केन्द्र व राज्य सरकार ई.–गर्वनेन्स के माध्यम से ग्रामीणों से जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ग्राम पंचायतों को सहायता कर सकते है। अतः ई.–पंचायत, ई.–गर्वनेन्स का एक बहुत ही अच्छा व सार्थक प्रयास है।

सन्दर्भ :–

1. वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय.

2. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन पंचायत राज इस्टीट्यूशन्स.

3. जैन, आर.बी.–पंचायत राज वॉल्यूम फ्रॉम आई; आई.पी.ए. नई दिल्ली.

4. जोशी आर.पी तता मंगलानी, रूपा (सं.)– पंचायतीराज के नवीन आयाम, जयपुर यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि. 2000 पृ. 26, 29.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Theoritical Vs. Practical Knowledge of Indian Classical Music

Dr. Tripti Watwe
Assistant Professor, HOD (Dept. of Vocal and Instrumental Music), Women's College, Agartala

Abstract : It's a very ridiculous fact that Indian Society has still got a funny outlook towards music as an institutional subject. What is there to study in music, is a normal inquisitive question by the common masses. And it's also a fact that the scorers in theoretical knowledge of music may not necessarily be distinguished performers on stage.

The following paper will endeavor to throw light on some of the commonly enquired questions about music, its job prospects and its future as a whole.

Key-words : Indian Society, Music, Theory, Practical Knowledge.

As the story Goes : We in the 21st century are heading towards a highly advanced techno-savy world. The earth is spinning around in a digitalized space! Homosapiens are inhaling and exhaling technology but yet some facts remain in inertia. And amongst many such facts, one such fact in India is the quizzical attitude of a common man towards Indian Classical Music. It may sound comical but it is a common thinking that Indian classical Music doesn't have a theoretical aspect and therefore, no future!! Anything that has to be studied or read brings in better prospects for future is a general understanding.

Thus, this paper will try to establish that Indian Classical Music has long been a subject of study and therefore research. It's one of the highest form of performing arts which requires lot of intellectual skill.

Before embarking on our journey through this topic it would be necessary to discuss about the presence of art in mainstream education.

We all have heard about chausath kala and chauda vidya prevalent from the ancient education systems. In both of these systems of education music has been given a very prominent place. This proves that education from time immemorial has been considered incomplete without disciplines of performing arts like music, dance and drama.

It is a well-known fact that Indian Classical Music is one of the chausath kala and Tansen is considered as a ultimate ideal of a performer. A layman in music too knows these facts about music. But music is also a shastra meaning knowledge abiding by the scriptures or texts. People associated with institutional music are well aware that there are various musical texts in music which were written by scholars in different eras and there is a completely different stream pertaining to the theoretical knowledge of music known as musicology.

Career Count : Music brings along with it paraphernalia of job prospects. The need is to increase our vision and throw off the curtain we carry in our minds related to music.

Music once upon a time suffered from degradation in terms of dignity as it became associated with brothels but now in some cases a sort of mental dilemma is seen disturbing a disciple of music and his guardians regarding the future possibilities of musical career. This is mainly because the Indian society is still not sure about music as a discipline or music as a reliable future resource. They believe it to be a sort of hobby or extra-curricular activity but not a mainstream subject.

Reality Register : Sometimes the attitude of such people is also justified because one cannot see

enough job opportunities in a teaching institute as there are comparatively less vacancies in colleges and universities. Nowadays there is a population explosion of qualified Phd and NET candidates who are forced to take up group D employment also due to scarcity of jobs. Consequently students of music are getting demoralized as they see no scope in their profession.

Scope for Survival : There may be various causes of chaos in the professional field of music but as they say wise have solution for every problem and fools create problem for every solution!

Responsible private or government organizations can actively work on two levels for detangling the situation.

First at the level of creating awareness for job opportunities and second at the level of creating more job possibilities for the promising candidates of music. Counselors in every university and college can help the students out of their doubts and confusion.

At the government level more colleges and Universities should be established dedicated to pure Indian Classical Music and Fine arts. Government may have records of a few institutes which are devoted to music and arts but the demand and supply ratio is fast changing. The number of students coming out of institutes and colleges is fast increasing who are in search of employment. Today there are 200 applicants against two or three or in many cases one vacancy in a College or Institute under the performing Arts or Fine arts category.

Apart from creating vacancies in institutes of performing arts and fine arts, there are various other probabilities in musical career. Apart from teaching music, acoustical engineering, musical reporting, music composing in theatres, television serials, films, advertisements, etc. are various other possibilities of a candidate of music.

If possible students can opt for ethnomusicological research from Universities of abroad and earn higher degrees for a brighter career. Ethnomusicology is developing into a new branch of research which works on interdisciplinary research and study of music with other subjects of sociology, science, management or arts etc. Obviously association with other subjects brings in better prospects as our range of expression becomes wider.

Final Snippets : In short, as the saying goes when the going gets tough, the tough gets going, may be situation is a little tough regarding job prospects in Indian music but if a balanced outlook is maintained regarding demand and supply only then this subject will be able to continue as a professional subject otherwise its shrinking job prospects will discourage aspirants to opt for it as a subject and it will remain a hobby!

Bibliography :

1. Neuman, M. Daniel, Studying India's Musicians, Manohar Publishers, New Delhi, 2015.
2. Thielemann, Selina, The Spirituality of Music, A.P.H.Publishing Corporation, New Delhi, 2001.
3. Choudhuri, Pt. Debu, On Indian Music, Sanjay Prakashan, New Delhi, 2005.
4. Gautam, Anita, Bharatiya Sangit me Vaigyanaik Upakarano ka Prayog, Kanishka Publishers, New Delhi, 2002.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

भूमंडलीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाजारीकरण है

डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा
MA (Eco.Rural development), MBA MSW, Social Science and Management Association

सारांश :– भाषा का प्रश्न आर्थिक एवं सामाजिक विकास से भी जुड़ा है। आज का युग भूमण्डलीकरण का युग है। कोई देश अलग–अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। भारत भी ग्लोबलाइजेशन की इस दौड़ मे शामिल है। ऐसे समय में हिन्दी को भी अपनी वृहत्तर भूमिका का निर्वाह करना होगा। हिन्दी विश्व में तीसरी भाषा है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। हिन्दी को भी अपनी वृहत्तर भूमिका निर्वहन करना होगा। और आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है, साहित्य में "आधुनिक" का अर्थ मध्यकाल से भिन्न है मध्यकाल अपनी जड़ता रूढ़िवादिता एवं अवरोध के कारण स्थिर हो गया है। इसे विशिष्ट एवं गव्यात्मक बनाने वाले मूल्य ही आधुनिक मूल्य है। आधुनिकता और भूमण्डलीकरण दोनों ही एक दुसरे के पयार्य हैं। इन दोनों का हिन्दी साहित्य में बड़ा ही वृहत्तर स्थान हैं। हिन्दी के विकास का आधार आज भूमण्डलीकरण पर ही निर्भर है।

वर्तमान संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाजारीकरण है। भारत दुनियाभर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक बड़ा खरीदार और उपभोक्ता बाजार है। बेशक, हमारे पास भी अपने काफी उत्पाद हैं और हम भी उन्हें बदले में दुनियाभर के बाजार में उतार रहे हैं। इस क्रय–विक्रय की अंतर्राष्ट्रीय वेला में संचार माध्यमों का केंद्रीय महत्व है क्योंकि वे ही किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए उपभोक्ता के मन में ललक पैदा करते हैं। यह उत्पाद वस्तु से लेकर विचार तक कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि आज भूमंडलीकरण की भाषा का प्रसार हो रहा है। वर्तमान जीवन का कोई पहलू, कोई कोना भूमंडलीकरण से अछूता नहीं है. भारत में उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रकिया अपने साथ संचार क्रांति लेकर आया, वर्तमान में इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से एक नई हिंदी गढ़ी जा रही है. यह हिंदी फिल्मों, सिरीयलों, विज्ञापनों, समाचार पत्रों और खबरिया चौनलों के माध्यम से तेजी से फैल रही है. सच है कि देश–विदेश में हिंदी की पहुँच इससे काफी बढ़ी है. सच है कि 'विज्ञापन की हिंदी' सहज ही लोगों के दिल में जगह बना लेती है, लेकिन यह भाषा भूमंडलीकरण के साथ फैल रही उपभोक्ता संस्कृति की है, विमर्श की नहीं. किसी भी भाषा के विकास और प्रचार–प्रसार में संचार माध्यमों का विशिष्ट योगदान रहा है. हिंदी इसका अपवाद नहीं है. उन्नीसवी सदी के आखिरी तथा बीसवीं सदी के शुरूआती दशकों में हिंदी भाषा, विशेष रूप से हिंदी गद्य के विकास और परिमार्जन में हिंदी के पत्र–पत्रिकाओं के योगदान का ऐतिहासिक महत्व है. पर पिछले दशकों में हिंदी के स्वरूप में काफी तेजी से बदलाव हुआ है. खास तौर पर हिंदी अखबारों में, जिसकी पहुँच भारत के कोने–कोने में बढ़ती जा रही है. 90 के दशक में तकनीक उपलब्धता, फैलते बाजार तथा सरकार की उदारीकरण की नीतियों के कारण देश में हिंदी के दर्जनों खबरिया चौनलों का प्रवेश हुआ. हिंदी अखबारों की भाषा पर इन चौनलों का खासा प्रभाव दिखता है. आज के भाषा संकट को इस रूप में देखा जा रहा है कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक माध्यम टी. वी. अपने विज्ञापनों से लेकर करोड़पति बनाने वाले लोकप्रिय कार्यक्रमों तक में हिंदी में बोलता भर है, लिखता अंग्रेजी में ही है। इसके बावजूद यह सच है कि इसी माध्यम के सहारे हिंदी अखिल भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक विस्तार के नए आयाम छू रही है। विज्ञापनों की भाषा और प्रोमोशन वीडियो की भाषा के रूप में सामने आने वाली हिंदी शुद्धतावादियों को भले ही न पच रही हो, युवा वर्ग ने उसे देश भर में अपने सक्रिय भाषा कोष में शामिल कर लिया है। इसे हिंदी के संदर्भ में संचार माध्यम की बड़ी देन कहा जा सकता है। सूचना संचार प्रणाली किसी भी व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी तरफ समाज के दर्पण के रूप में साहित्य भी तो संचार माध्यम ही है जो सूचनाओं का व्यापक

संप्रेषण करता है। साहित्य की तुलना में संचार माध्यमों का ताना–बाना अधिक जटिल और व्यापक है क्योंकि वे तुरंत और दूरगामी असर करते हैं। भूमंडलीकरण ने उन्हें अनेक चौनल ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, इंटरनेट और वेबसाइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के नए अस्त्र–शस्त्र भी मुहैया कराए हैं। परिणामस्वरूप इस सबसे हिंदी भाषा के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। संचार माध्यम यदि आज के आदमी को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं तो वे ऐसा भाषा के द्वारा ही करते हैं। संचार माध्यम की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर हिंदी समस्त ज्ञान–विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गई है आज व्यवहार क्षेत्र की व्यापकता के कारण संचार माध्यमों के सहारे हिंदी भाषा की भी संप्रेषण क्षमता का बहुमुखी विकास हो रहा है। हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ही नहीं, विविध अंतर्राष्ट्रीय चौनलों में हिंदी आज सब प्रकार के आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने के अपने सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रमाणित कर रही है। कहा जा सकता है कि वैश्विक संदर्भ में हिंदी की वास्तविक शक्ति को उभारने में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ साहित्य लेखन की भाषा आज भी संस्कृतनिष्ठ बनी हुई है तो दूसरी तरफ संचार माध्यम की भाषा ने जनभाषा का रूप धारण करके व्यापक जन स्वीकृति प्राप्त की है। समाचार विश्लेषण तक में कोडमिश्रित हिंदी का प्रयोग इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, पारिवारिक, जासूसी, वैज्ञानिक और हास्यप्रधान अनेक प्रकार के धारावाहिकों का प्रदर्शन विभिन्न चौनलों पर जिस हिंदी में किया जा रहा है वह एकरूपी और एकरस नहीं है बल्कि विषय के अनुरूप उसमें अनेक प्रकार के व्यावहारिक भाषा रूपों या कोडों का मिश्रण उसे सहज जनस्वीकृत स्वरूप प्रदान कर रहा है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि संचार माध्यमों के कारण हिंदी भाषा बड़ी तेजी से तत्समता से सरलीकरण की ओर जा रही है। इससे उसे अखिल भारतीय ही नहीं, वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हो रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक हिंदी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा थी परंतु आज स्थिति यह है कि वह दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है तथा यदि हिंदी जानने–समझने वाले हिंदीतर भाषी देशी–विदेशी हिंदी भाषा प्रयोक्ताओं को भी इसके साथ जोड़ लिया जाए तो हो सकता है कि हिंदी दुनिया की प्रथम सर्वाधिक व्यवहृत भाषा सिद्ध हो। हिंदी के इस वैश्विक विस्तार का बड़ा श्रेय भूमंडलीकरण और संचार माध्यमों के विस्तार को जाता है। यह कहना गलत न होगा कि संचार माध्यमों ने हिंदी के जिस विविधतापूर्ण सर्वसमर्थ नए रूप का विकास किया है, उसने भाषासमृद्ध समाज के साथ–साथ भाषावंचित समाज के सदस्यों को भी वैश्विक संदर्भों से जोड़ने का काम किया है। यह नई हिंदी कुछ प्रतिशत अभिजात वर्ग की भाषा नहीं बल्कि अनेकानेक बोलियों में व्यक्त होने वाले ग्रामीण भारत की नई संपर्क भाषा है। इस भारत तक पहुँचने के लिए बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी हिंदी और भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। हिंदी के इस रूप विस्तार के मूल में यह तथ्य निहित है कि गतिशीलता हिंदी का बुनियादी चरित्र है और हिंदी अपनी लचीली प्रकृति के कारण स्वयं को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आसानी से बदल लेती है। इसी कारण हिंदी के अनेक ऐसे क्षेत्रीय रूप विकसित हो गए हैं जिन पर उन क्षेत्रों की भाषा का प्रभाव साफ–साफ दिखाई देता है। बाजारीकरण की अन्य कितने भी कारणों से निंदा की जा सकती हो लेकिन यह मानना होगा कि उसने हिंदी के लिए अनुकूल चुनौती प्रस्तुत की। बाजारीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, सूचनाक्रांति तथा जीवनशैली के वैश्वीकरण की जो स्थितियाँ भारत की जनता के सामने रखी, इसमें संदेह नहीं कि उनमें पड़कर हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति कौशल का विकास ही हुआ। अभिव्यक्ति कौशल के विकास का अर्थ भाषा का विकास ही है। यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि बाजारीकरण के साथ विकसित होती हुई हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है लेकिन आज प्रचार माध्यमों की भाषा हिंदी होने के कारण वे भारतीय परिवार और सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते। विज्ञापनों से लेकर धारावाहिकों तक के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि संचार माध्यमों की हिंदी अंग्रेजी की छाया से मुक्त है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है इसका कारण भी साफ है भारत रूपी इस बड़े बाजार में सबसे

बड़ा उपभोक्ता वर्ग मध्य और निम्नवित्त समाज का है जिसकी समझ और आस्था अंग्रेजी की अपेक्षा अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से अधिक प्रभावित होती है। हम देख सकते हैं कि इधर हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप बहुत बदल गया है आज हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी और हिंदीतर राज्यों का अंतर मिटता जा रहा है। हिंदी पत्र–पत्रिकाओं का पाठक वर्ग तो संपूर्ण देश में है ही, उनका प्रकाशन भी देशभर से हो रहा है। विभिन्न आयु और रुचियों के पाठकों के लिए हिंदी में विविध प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है तथा मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा और परस्पर व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में उसका विस्तार हो रहा है। रेडियो तो हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाला व्यापक माध्यम रहा ही है, प्रसन्नता की बात यह है कि टेलिविजन बहुत थोड़े समय के भीतर ही हिंदी–माध्यम बन गया है।

इसी प्रकार फिल्म के माध्यम से भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज अनेक फिल्मकार भारत ही नहीं यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं । सिनेमा ने हिंदी की लोकप्रियता भी बढ़ाई है और व्यावहारिकता भी। मोबाइल और कंप्यूटर की संचार क्रांति ऐसे माध्यम हैं जिन्होंने दुनिया को सचमुच मनुष्य की मुट्ठी में कर दिया है। सूचना, समाचार और संवाद प्रेषण के लिए इन्होंने हिंदी को विकल्प के रूप में विकसित करके संचार–तकनीक को तो समृद्ध किया ही है, हिंदी को भी समृद्धतर बनाया है। इसी प्रकार इंटरनेट और वेबसाइट की सुविधा ने पत्र–पत्रिकाओं के ई–संस्करण तथा पूर्णतरू ऑनलाइन पत्र–पत्रिकाएँ उपलब्ध कराकर सर्वथा नई दुनिया के दरवाजे खोज दिए हैं। आज हिंदी की अनेक पत्रिकाएँ इस रूप में विश्वभर में कहीं भी कभी भी सुलभ हैं तथा अब हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट पर हिंदी में प्राप्त होने लगी है। इस तरह हिंदी भाषा ने बाजार और कंप्यूटर दोनों की भाषा के रूप में अपना सामर्थ्य सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण के साथ मुद्रित और इलेक्ट्रानिक दोनों ही प्रकार के जनसंचार माध्यम नए विकास के आयामों को छू रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हिंदी भाषा भी नई–नई चुनौतियों का सामना करने के लिए और शक्ति का अर्जन कर रही है।

आधुनिकता एवं भूमण्डलीकरणः आधुनिकता शब्द एक सापेक्ष अर्थ व्यक्त करता है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्य निश्चय ही आधुनिक है, जबकि भावी पीढ़ी इन वर्तमान मूल्यों को पुराने मूल्य कहकर तिरस्कृत करेगी। वस्तुतः आधुनिकता की व्याख्या अतीत की सापेक्षता में ही की जा सकती है। अतीत से नितान्त निरपेक्ष रखकर आधुनिकता की कोई व्याख्या नहीं हो सकती अंग्रेज समीक्षक जी.एस. फ्रेजर के अनुसार– आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से सम्बन्ध रखना चाहिए। आधुनिकता का मूल्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण बोध का मानसिक प्रत्यक्षीकरण करके ही हम आधुनिकता की अवधारणा से परिचित हो सकते हैं। प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. जगदीश गुप्त के अनुसार आधुकिता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टिकोण है और मानव मुक्ति से किसी–न–किसी रूप में अवश्य जुड़ी होती हैं।

आधुकिता के जो लक्षण बताए गए है उन्हे निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है –

1. आधुनिकता सापेक्षिक होती है।
2. आधुनिता की व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षित में ही सम्भव है।
3. जो इस समय आधुनिक समझा जाता है, भविष्य में वही पुरातन हो जाएगा।
4. अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता है।
5. आधुनिकता अतीत से जुड़े रहकर ही सुरक्षित रह पाती है।
6. आधुनिकता सम्पूर्ण विकास एवं प्रगति का केन्द्र मानव को मानती है।
7. आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है।
8. साहित्य में आधुनिक का अर्थ मध्यकाल से भिन्नता है। मध्यकाल अपनी जड़ता, रूढ़िवादिता एवं अवरोध के कारण स्थिर हो गया था, उसमें एकरसता आ गई थी। इसे विशिष्ट एवं गत्यात्मक बनाने वाले मूल्य ही आधुनिक मूल्य है।

9. धर्म,दर्शन,साहित्य – सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव ही आधुनिकता है।
10. साहित्य की सभी विधाओं– कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में आधुनिकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। विषयवस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से उसमें आधुनिकता की छाप दिखाई पड़ती है।

आधुनिकता के उदय की पृष्ठभूमिः हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल का उदय मोटे तौर पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने संवत् 1900 वि. (सन् 1843 ई.) से माना है। प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। सन् 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। भले ही इस स्वतन्त्रता संग्राम को अंग्रेजों में "विद्रोह" कहकर कुचल दिया, किन्तु इससे देश में नवचेतना जाग्रत हुई। अंग्रेज सरकार के दमनात्मक रवैये ने देश की मनीशा को झकझोर दिया और कवियों को यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि वे देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई–बुराई के बारे में बतावें। भारतेन्दु जी ने इस सम्बध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा :

अंग्रेज राज साज सजे सब भारी।
पै धन विदेस चलि जात य है अति ख्वारी।

कांग्रेस पार्टी की स्थापना, गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए विविध संघर्षों के परिपेक्ष्य में आधुनिक काल के साहित्य को देखा–परखा जाना चाहिए। अंग्रेजो ने 1849 ई. में सिक्खों को पराजित किया तथा 1856 ई. में अवध को अपने अधिकार में ले लिया। उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर देशी राजाओं ने 1857 ई. में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। परिणामस्वरूप ईस्ट इण्डिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने आर्थिक, शैक्षिणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया जिससे लोगों को लगा कि हमारे हित के बारे में सोच रहें है। भारतेन्दु युग के कवियों ने इसी कारण राजभक्ति एवं देशहित का मिला–जुला रूप प्रस्तुत किया। भारतेन्दु भी यह कहने को बाध्य हुए कि अंग्रेजों के राज में सुख के साज है, किन्तु भारत का धन विदेशो में जा रहा है। इतना तो अवश्य हुआ कि साहित्य मानव के सुख–दुख से पहली बार जुड़ा जिसका पूरा अभाव रीतिकाल में था। मूगलों एवं अंग्रेजों में एक मौलिक अन्तर था। मुस्लिम शासक सामंती व्यवस्था के पक्षधर थे जबकि अंग्रेज विशुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था के, पोषक थे। वे व्यापारी पहले थे, शासक बाद में उनकी नीतियां भी इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बनाई गई।

सर चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार :– भारतीय गांव छोटे–छोटे गणतंत्र थे। उनकी आवश्यकताए गांव मे ही पूरी हो जाती थी, बाहरी दुनियां से उनका कोई सम्बन्ध ही न था। हर गांव मै लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली, आदि सेवक जातियॉ थीं। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं कर सकता था। भारत के नगर तीन प्रकार के थे– राजनीतिक महत्व के नगर, धार्मिक महत्व के नगर और व्यापारिक नगर। नगरों में बनने वाली वस्तुओं – रत्नजड़ित आभूषणों, सूती – रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की मीनाकारी, आदि से ग्रामीण जनता को कुछ लेना–देना न था। राजा, सामंत, श्रेष्ठियों में इन वस्तुओं की खपत होती थी। गांव का कुटीर उद्योग अलग ढ़ग का था जो ग्रमीण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत को अपना बाजार बनाने के लिए यहां के उद्योग – धंधों एवं कुटीर उद्योगों की चौपट कर दिया। गांधीजी का चरखा आन्दोलन करने का एक प्रयास था यह हमें स्मरण रखना चाहिए। लार्ड कार्नवालिस ने भारत के पूर्वी प्रान्तों – बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा प्रारम्भ की जिसे बाद में बम्बई, उत्तरप्रदेश एवं मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। सन् 1820 में टामस रो ने जमीन को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे बदल दिया, जिससे जमीदार और जोतदार दोनो ही जमीन का क्रय–विकय कर सकते थे। खेत व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गए थे अतः खेती का व्यवसायीकरण होना स्वभाविक था। किसानों की हालत खराब थी। वे सरकारी मालगुजारी अदा करने तथा ऋण अदायगी की चिन्ताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते थें परिणामतः

महाजनी चंगुल में फंसते जा रहे थे। आधुनिक काल का साहित्य उनकी इस दुर्दशा का चित्रण करने की ओर प्रवृत्त हुआ। प्रमेचन्द्र का 'गोदान' इसी पृष्ठभूमि में रचा गया है। नई अर्थव्यवस्था ने पारस्परिक सम्बन्धो को जटिल बन दिया। पंचायतों को स्थान अब कचहरियों ने ले लिया। गांवों की जड़ता टूटी, जाति प्रथा के बन्धन एक सीमा तक शिथिल हुए, राष्ट्रीयता के भाव जाग्रत हुए। नए आर्थिक वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति एवं श्रामिक के बीच में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अर्थनीति, षासन व्यवस्था में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए।

भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस की स्वतन्त्रता वरदान सिद्ध हुई। पुनर्जागरण के लिए कार्यरत सामाजिक नेताओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया। भारतेन्दु के समय के प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकार किसी न किसी साहित्यक पत्र–पत्रिका से जुड़े थे। वे इनमें अपनी साहित्यिक रचनाओं के साथ– साथ सामयिक समस्याओं, पर भी प्रकाश डालने वाले लेख लिखते थे। जनतान्त्रिक मूल्यों का पोषक, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुद्रण ने साहित्यकार और समाज को एक – दुसरे से वैचारिक स्तर पर जुड़ने का माध्यम प्रदान किया। राजा राममोहन राय ने 1828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना की और कर्मकाण्ड एवं अन्धविश्वास का विरोध उपनिशदों के आधार पर किया। आज से 175 वर्ष पहले वे अकेले व्यक्ति थे जो अन्धश्रद्धा एवं रूढ़ियों के विरोधी थे। उनके कथन तर्कपूर्ण थे। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा, सही प्रथा का डटकर विरोध किया। वे विधवा विवाह एवं स्त्री – पुरूष की समानता के भी पक्षधर थे। देवेन्द्रनाथ टैगोर एवं केशवचन्द्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। केशवचन्द्र सेन के प्रभाव से 1867 ई. प्रार्थना समाज की स्थपना हुई जिसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविन्द रानाडे थे। सामाजिक रूढ़ियो एवं अन्धविश्वासों के प्रति से निरन्तर संघर्ष करते रहे। वे मानते थे कि समाज जीवित अवयवों का संघटन है जिसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता हैं। उन्होने मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया। वे जाति–पांति के विरूद्ध थे और अन्तर्जातीय विवाह के समर्थक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने की जबकि आर्यसमाज की स्थापना 1867 ई. में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में की। वे वैदिक धर्म को सत्य एवं सार्वभौम मानते थे। जाति, लिंग एवं नस्ल के आधार पर मानव की समानता के वे प्रबल पक्षधर थे। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर आर्य समाज ने एक आचार संहिता बनाई। आर्य समाज का प्रचार मध्य वर्ग के बीच हुआ। सन् 1893 में थियोसोफिकल सोसाईटी से सम्बद्ध एनीबेसेंट भारत आई और अपने ओजस्वी भाषणों से सबको प्रभावित किया। आधुनिकल काल में सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफीकल सोसाइटी प्रार्थना समाज ने जहां परम्परागत भारतीय समाज में नई सामाजिक चेतना का विकास किया और परम्परागत रूढ़ियों, परम्पराओं एवं अन्धविश्वासों से मुक्ति पाने में योगदान किया वहीं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महार्षि अरविन्द के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों ने भी जनता को आधुनिक बोध दिया। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता, सदाचार सविनय अवज्ञा आदि ने जनता को बहुत कुछ 'नया दर्शन' प्रदान किया। आधुनिक काल के साहित्य पर इन सबके प्रभाव को बखुबी देखा जा सकता है। यही नहीं अपितु आधुनिक काल में विविध आन्दोलनों के माध्यम से हुए समाजिक सुधारों यथा–विधवा विवाह, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, अछूतोद्धार एवं जाति प्रथा में शिथिलता ने भी भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों ने भी आधुनिकता की ओर बढ़ने में सहायता पहुँचाई। विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजी ढंग के स्कूल–कॉलेजों की स्थापना ने भी भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पुस्तकों का प्रचार–प्रसार होने, समाचार पत्रों के छपने से भी लोगों को विचार विनिमय का अवसर मिला तथा देश की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी कविताओं को पढ़कर उन्हे यह ज्ञात हुआ। कि कविता में नख–शिख चित्रण के अलावा भी कुछ और होता है। वे उनके अनुकरण पर वैसी कविताए लिखने लगे। कुछ अंग्रेजीं पुस्तकों का

हिन्दी में अनुवाद भी विभिन्न लेखकों ने इस काल में किया। ज्ञान–विज्ञान के प्रचार–प्रसार ने भी हमारी पारम्परिक दृष्टि बदल दी। साहित्य प्रभावित हुआ इसमें दो राय नहीं है। औद्योगिकरण, संचार साधनों में वृद्धि, नई अर्थव्यवस्था ने भी भारत को नूतन गत्यात्मकता की ओर अग्रसर किया। इसे बहुत से लोगों ने पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिककरण की संज्ञा दी है। वस्तुतः आधुनिकरण एक दृष्टिकोण हैं जो होता है। आधुनिक काल में विकसित मानवतावाद मनुष्य–मनुष्य की समता, स्वतंत्रता आदि का सिद्धांत सामाजिक न्याय के आधार पर उचित माना गया। मध्यकाल तक भावाभिव्यक्ति का एकमात्र साधन 'कविता' थी, किन्तु आधुनिक काल में भाव एवं विचार दोनों की अभिव्यक्ति के लिए 'गद्य' विकसित हो गया। यह इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। काव्य भाषा के पद पर लम्बे समय तक टिकी रहने वाली ब्रजभाशा को भी धीरे–धीरे निर्वाशित कर दिया गया और 'खड़ी बोली हिन्दी' का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में 'द्विवेदी युग' से प्राम्भ हो गया।

आधुनिक युग की मूल संवेदना के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा को रखा जा सकता है राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमान की भावनाएं जो इस काल में विकसित हुईं, इसी का परिणाम मानी जा सकती हैं। एक ओर तो हम रूढ़ियो एवं परम्पराओं से मुक्ति हेतु छटपटाने लगे तो दूसरी ओर अपनी परम्पराओं से जीवन मूल्य लेकर नवीन विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। यही नवजागरण का स्वर हमें आधुनिककाल के साहित्य के केन्द्र में दिखाई देता है। कविता निबंध, उपन्यास, नाटक सब इसी से ओतप्रोत है। यही हमारी आधुनिकता का केन्द्रीय भाव भी है तथा यही आधुनिक काल के उदय की पृष्ठभूमि भी है। भाषा का प्रश्न आर्थिक एवं सामाजिक विकास से भी जुड़ा है। आज भूमण्डलीकरण का युग है। कोई देश अलग – अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। भारत भी ग्लोबलाइजेशन की इस दौड़ में शामिल है। ऐसे समय में हिन्दी को भी अपनी वृहत्तर भूमिका का निर्वाह करना होगा। हिन्दी अपनी महत्ता एवं विशाल कलेवर के कारण अस्तित्व में है और रहेगी अपने विपुल एवं व्यापक साहित्य के कारण भी यह समृद्ध देशों को अपनी ओर आकष्ट कर रही है। हिन्दी की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह भारत के बाहर 176 विश्वविद्यालयों में पढी–पढ़ायी जाती हैं, इनमें से 45 विश्वविद्यालयो मे तो केवल अमेरिका के है। ब्रिटेन के साथ–साथ पूर्वी यूरोप के अन्य अनेक देशों रोमानिया, इटली, यूनान में कबीरदास को बड़े चाव से पढ़ा जाता है। आज युरोप के अनेक होटलों में भोजन की सूची हिन्दी में भी तैयार कराई जाती है वहां उपस्थित स्वागतकर्मी हिन्दी मं भारतीयों का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। कनाडा जैसे विकसित देश में क्रिस्टोफर किंग हिन्दी की सेवा में जुटे हैं तो जर्मनी के कॉलोन नगर में स्लेण्डर हिन्दी की सेवा इसे पढ़ाकर कर रहें हैं। विदेशों में भारतीय सिने कलाकारों राजकपूर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, ऐश्वर्याराय, गोविन्दा के प्रशंसक लाखों में मिल जाते हैं। बिल गेटस जैसे 'कम्प्यूटर किंग' ने तो संस्कृत के बाद हिन्दी को ही कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना है। देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता के कारण कम्प्यूटर के लिए उपयुक्त है। हिन्दी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से भी अनुकूल भाषा है। इस भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिपि में अंकित किया जाता है। हिन्दी को भूमण्डलीकरण के अनुरूप ढालना होगा। इसमें हमें उस शब्दावली का समावेश करना होगा जो विदेशी भाषाओं से आयी है अब हिन्दी में प्रयुक्त हो रही है। शुद्ध हिन्दी के जुनैन में इस शब्दावली को बहिष्कृत करने की वकालत करने वाले हिन्दी के दुश्मन समझे जाने चाहिए। विदेशी शब्दो को बलात् एवं अनावश्यक प्रयोग तो निदंनीय है, किन्तु जो शब्द हिन्दी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ग्रहण कर रचा–वसा किए हैं, उनका प्रयोग जारी रहना चाहिए। उर्दू, अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषाओं के प्रचलित शब्दों से हिन्दी शब्द भण्डार को विस्तृत करते रहना उपयुक्ति होगा। हिन्दी फिल्म तथा टेलीविजन ने भी हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस भाषा को वैश्वीकरण स्वरूप प्रदान करने का श्रेय इन्हीं माध्यमों को है। टेलीविजन के हिन्दी चैनल को भी विदेशों में जबर्दस्त लोकप्रियता प्राप्त है। अंग्रेजी की 'ग्लोबल' भाषा बताने वाले लोग मानसिक गुलामी के वातावरण में जी रहे है। वे हीन भावना से ग्रस्त हैं। हमें अपनी राष्ट्रभाषा के पति वही सम्मान रखना चाहिए जो राजचिह्न,

राष्ट्रीध्वज के प्रति होता हैं। साहित्यकारों एवं पत्रकारों को हिन्दी के प्रचार–प्रसार में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना होगा। इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने हिन्दी को ग्लोबल भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी कामकाज में हमें अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करना होगा, तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को राजभाषा के दायरे में लाना होगा। हिन्दी की शुद्धता पर अधिक जोर न देकर हमें लचीला रूख अपनाना चाहिए तभी भूमण्डलीकरण के इस दौर में हिन्दी अपना वर्चस्व बना पायेगी।

निष्कर्ष :– स्वतंत्रता के उपरांत व्यवस्था के प्रति जो मोह भंग हुआ उसने भी आधुनिकता के विकास में महती भूमिका का निर्वहन किया। स्वतंत्रता के पश्चात विकसित स्वार्थ अवसरवादिता, अनिश्चिता, असमन्सस्य रिक्तता बोध ने संवेदनशील रचनाकार को यथार्थ के निकट लाकर खड़ा कर दिया और वह स्वप्नजीवी न रहकर यथार्थ जीवी वन गया। आधुनिकता वर्तमान के संदर्भ में विकसित वह बोध है। जो भविष्योन्मुख्य होती है। अंग्रेजी को 'ग्लोबल' भाषा बनाने वाले लोग मानसिक गुलाबी के वातावरण में जी रहे है। वे हीन भावना से ग्रस्त है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के प्रति वही सम्मान रखना चाहिए जो राजचिह्न, राष्ट्रीय ध्वज जो रहता है। साहित्यकारो एवं पत्रकारों को हिन्दी के प्रचार–प्रसार में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिन्दी को ग्लोबल भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी कामकाज में हमें अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करना होगा तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को राजभाषा के दायरे में लाना होगा। हिन्दी की शुद्धता पर हमें अधिक जोर न देकर हमें लचीला रूख इस दौर में हिन्दी अपना वर्चस्व बना पायेगी।

संदर्भ सूची :–

1. स्मारिका– सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, जून 2003
2. गगनांचल, जुलाई–सितंबर 1999.
3. फीजी में हिन्दी :स्वरूप और विकास – विमलेशकांति वर्मा और धीरा वर्मा
4. विज्ञापन की दुनिया – कुमुद शर्मा प्रतिभा प्रतिष्ठान नई दिल्ली
5. डॉ0 कैलाश नारद – म0 प्र0 में हिन्दी पत्रकारिता एक शताब्दी
6. जोसेफ, बाबू, भूमण्डलीकरण और हिन्दी कविता, हिन्दी बुक सेण्टर, नई दिल्ली, 2013.
7. सिंह, पुष्पपाल, भूमण्डलीकरण और हिन्दी उपन्यास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012.
8. कुमार, रोशन, भूमण्डलीकरण और हिन्दी उपन्यास साहित्य, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइन्टिफिक रिसर्च, वोल्यूम 4, भाग 8 ए अगस्त 2015.
9. सिंह, संध्या, भूमण्डलीकरण संस्कृति का बाजार और साहित्य, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2013.
10. मिश्रा, आर.एन., इक्कीसवीं सदी का समय और हिन्दी कविता, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2015.
11. शर्मा, बी.के., भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक विशिश्टता, शिल्पायान प्रकाशन, दिल्ली, 2010.
12. मिश्रा, आर.एल., भूमण्डलीकरण और 21वीं सदी की हिन्दी कविता, शैलजा प्रकाशन, कानपुर, 2015.
13. आचार्य राममूर्ति, शिक्षा संस्कृति और समाज, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1990.
14. शुक्ला, भानुप्रताप, स्वदेशी चेतना, अभिरूचि प्रकाशन, दिल्ली, 1998.
15. तिवारी रामचन्द्र, हिन्दी का गद्य साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2014.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

झारिया समुदाय विकास के निर्धारकों का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) प्रीती पाण्डे
अतिथि विद्वान, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

अधिकांश जातियों पहाड़ों जंगलों और दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है, जहां उनका अन्य लोगों से संपर्क नहीं हो पाता। क्यों कि आवागमन के साधनों का अभाव है। अतः उन्हें जीवन–यापन के उचित अपसर उपलब्ध नहीं होते है, जिसके कारण उन्हें न तो रोजगार के अवसर मिलते है और न ही शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त हो पाते है। जनजातीय क्षेत्रों में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियें के कारण वहां पर शैक्षिक योजनाओं को लागू करना दुष्कर कार्य है। आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों की स्थिति अत्यधिक सोचनीय थी, तो सामाजिक स्थिति भूमिकायें तथा भौगोलिक स्थिति उच्च कैसें हो सकती है ?

अनुसूचित जातियों का एक बड़ा वर्ग शहरों से दूर दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों मं निवास करता है। गांवों में आज भी स्कूलों का अभाव सा है। पिछड़े इलाकों में तो कई गांव के बीच एक स्कूल ह। अभिभावक अधिक दूर स्कूल होने के कारण प्रायः अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकते है। किन्हीं स्थानों में विद्यालय भी होते हैं और अनुसूचित जाति के लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर देते है। तो भी उचित सुविधायें व माहौल नहीं जुटा पाते है, जिससे बच्चे कक्षा में असफल होने लगते है, जिससे अपव्यय होने लगता है औंर बार बार अवरोधन भी, जिससे क्षुब्ध होकर ये अपने बच्चों को रोक लेते हैं और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है।

भौतिक संरचना :– भौतिक संरचना की दृष्टि से डिण्डौरी जिला पठार तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके एक हिस्सें में नर्मदा, सोन तथा दूसरे हिस्से में सतपुड़ा–मैकल श्रेणी है। डिण्डौरी जिला पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है यहां की भूमि भुरभुरी तथा पथरीली है। पठार समतल होते हुए भी ऊँचे पठार तथा निचले पठार में बंटा हुआ है। इसकी तहों की मोटाई अधिक संख्त एवं कठोरता के अनुरूप है। यहां की मिट्टी काली तथा भूरी चिकनी है जिसमें कंकड़ भी अधिक है। यह क्षेत्र समुद्री सतह से काफी ऊँचा होने के कारण जल की उपलब्धता की समस्या सर्वत्र नजर आती है। भूमि से 150–200 फीट नीचे पानी की उपलब्धता दृष्टिगोचर होती है जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता हैं।

डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां अधिकतर झारिया परिवार अपनी आवश्यताओं के अनुरूप फसलों का उत्पादन करते हैं। अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, रमतिला, चावल, कुटकी, कोदो चना, आदि की खेती की जाती है। भूमि तथा मिट्टी अच्छी कृषि के अनुरूप नहीं है।

जलवायु :– डिण्डौरी जिलें में मानसून जलवायु की सभी विशेषतायें मिलती है। जाड़े तथा गर्मी दोनों ही ऋतुओं में वायुभार की रेखायें पूर्व से पश्चिम की आर जाती है। गर्मी के दिनों में क्षेत्र का तापमान औसत तापमान से अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है।

मध्य भारत जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहां लम्बें ग्रीष्म काल में अधिकतम तापक्रम रहता है। सामान्यतः 42.8^0 से तक रहता है किन्तु रात्रि कालीन तापमान कम होता है तथा रात्रि में इस प्रदेश में ठंडी होती है। इस समय तापमान अधिकतर 12^0 से और न्यूनतम 10^0 से तक रहता है। कभी–कभी इस ऋतु में कोहरे (धुंध) की स्थिति भी ठंडे महीनों में बन जाती है। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, डिण्डौरी, मंडला जिले कुछ आर्दता लिए हुए है। शेष जिलों में अधिक गर्मी है। वर्षा मध्यम होती है, जो फसलों और वनस्पतियों के लिए पर्याप्त है। ऊपरी भागों में वर्षा की मात्रा 1307 मि.मी. ही प्रांप्त होती है तथा निचले भागों में 1569 मि.मी. वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। अधिकतर वर्षा मानसून के माह में प्राप्त होती है। इस प्रदेश के ऊपरी भाग में उत्तर भारतीय शुष्क उष्ण कटिबंधीय

प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जबकि दक्षिणी भागों में जहां मैकाल पहाड़ों की श्रृंखला और संबंधित पठार है, वहां पर उत्तर भारतीय आर्द उष्ण कटिबंधीय जलवायु पायी जाती है। इस प्रदेश के निचले भागों में तापमान ग्रीष्म ऋतु में भी ऊपरी भागों से कम ही रहते है, परंतु शीत ऋतु में तापमान 3.5^0 से तक पहुंचने के कारण थोड़ी ठंड अधिक होती है तथा कोहरे की स्थिति रहती है। इस भाग में वषा भी अधिक होती है, लगभग 1650 मि.मी. तक वर्षा मापी गई है।

अपवाह तंत्र :– मैकल पठार का अपवाह ''मैकल सूता'' (नर्मदा) नदी निर्मित करती है। इसके दाये तरफ बंजर, बूरहनेर, खामेर, एवं सहायक धाराएं तथा बाये तरफ सिलगी और गौर सहायक नदी प्रवाहित है। इस क्षेत्र में सोन और उसकी सहायक नदी और जोहिला नदी प्रवाहित हेाती है। जोहिला नदी ज्वालामुखी बेसिन में प्रवाहित होते हुए अपने उत्तर–पूर्व और उत्तरी भागों में अपवाह बनाती है। बेनगंगा और उसकी सहायक धाराएं अपने पश्चिमी भागों का अपवाह निर्मित करती है। नर्मदा की सहायक नदी टोडा वर्षा ऋतु में नर्मदा में जाकर मिलती है। महानदी की सहायक धाराएं सिओनाथ इस क्षेत्र के दक्षिणी–पूर्वी और दक्षिणी भागों को अपवाहित करती है। इन नदियें ने अपनी घाटी को अपरदित करके उपजाऊ बेसिन का निर्माण किया है। जिससे कृषि के लिए उपजाऊ भूमि इन बेसिनों में उपलब्ध हो गई है।

वर्षा की प्रकृति मानसूनी है। अधिकतम वर्षा जून से सितम्बर के मध्य होती है तथा दिसंबर और जनवरी कुछ वर्षा चक्रवातों से होती है। अन्य माहों में बहुत कम वर्षा होती है। यहां औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता है। मानसूनी वषा की विषमता यहां की सबसे गंभीर समस्या है। यह विषमता औसत वार्षिक वर्षा से कम होने के साथ बढ़ती जाती है। यहीं कारण है कि इस क्षेत्र में यदि किसी वर्ष वर्षा कम हई तो कृषि को अधिक हानि होती है और सूखा क्षेत्र घोषित करने की स्थिति निर्मित हो जाती ह जिससे यहां का जनजीवन प्रभावित होता है। आर्थिक निर्भरता के लिए लोगों को क्षेत्र से पलायन करने की आवश्यकता पडती है। अत्यधिक वर्षा से कई गांव संपर्क से टूट जाते है। जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कच्चे मकान बह जाते है जानवर गंभीर बीमारी के शिकार होकर मर जाते है तथा अन्य संपत्तियों का भी नुकसान होता है।

मिट्टी :– वनस्पति और कृषि की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारकों में मिट्टी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादन की मात्रा तथा उत्तमता भी मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करते है। अतः भौगोलिक वर्णन में मिट्टी का विश्लेषण एक आवश्यक अंग है। डिण्डौरी जिला ऊँची–नीची सतहों तथा पहाड़ी भाग से जुड़ा होने के कारण वर्षा के दिनों मिट्टी के कटाव की समस्या खड़ी हो जाती है। इस क्षेत्र की मिट्टी काली, भुरभुरी, पीली, पथरीली, तथा जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी में लोहे और चने की प्रचुर मात्रा होती है। जो कृषि कार्य को प्रभावित करता है। यह मिट्टी तिलहन, ज्वार, चने की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकतम क्षेत्र में जलोढ़ तथा काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। समतल क्षेत्र के अभाव से अधिकतर मिट्टी की परते जल के साथ बह जाती हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता अपेक्षाकृत कम हो जाती है।

मृदा अपरदन :– जिले में मृदा अपरदन कृषि की गंभीर समस्या है जिसके कारण विस्तृत क्षेत्र में भूमि नष्ट हो रही है। सतह की मिट्टी के महीन कण कटकर बह जाते है, केवल कंकरीली, पंथरीली, मिट्टी बची रहती है या मिट्टी की ऊपरी तह बह जाती है और नीचे की सतह ऊपर दिखने लगती है। इस प्रकार नष्ट हुई मिट्टी में कृषि के लिए पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है फलस्वरूप उर्वरता औंर उत्पाद घटता जाता है। जिले की अधिकतर भमि पठारी और पहाड़ी है तथा ऊँची–ऊँची सतहों पर निर्भर है। जिस कारण मानसूनी वर्षा तथा त्रुटिपूर्ण उपयोग के संयोजन से मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के अधिकतर आदिवासी परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण भूमि संबंधी कमियों का निदानात्मक उपाय करने में असमर्थ हैं जिससे उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं आया है।

जिले की मृदा काली से लाल रंग की चिकनी और लोयस के मिश्रण से युक्त है। प्रदेश के ऊपरी भाग मे हल्की काली रंग और निचले मं हल्की काली से मध्यम काली रंग की मृदा मिलती है। मैकाल श्रृंखला और उससे जुड़े भागों में लाल, काली, और मिश्रित मृदा पाई जाती है। नर्मदा ओर बंजर बेसिन में मध्यम काली मृदा मिलती है। लैटराइट प्रकार की मृदा पहाड़ी भागों में विस्तृत रूप से पाई जाती है।

वर्तमान अध्ययन का वक्तव्य :– देश में विकास से संबंधित अनेक अध्ययन हो चुके है। किंतु दूरस्थ वीरान घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्र जैसे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन पर किये गए अध्ययन पर्याप्त नहीं है क्योकि आज भी अनुसूचित जाति अपने परंपरावादी जीवन शैली तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ जीवन व्यतीत कर रहे है। प्रस्तुत अध्ययन झारिया जाति के संदर्भ में है, जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जातियों में से एक है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में डिण्डौरी जिले को लिया गया है। जहां सभी विकासखण्डों के गांवों में सबसे अधिक झारिया जाति के लोग रहते है। इसमें संदेह नहीं है कि दूसरे मानवीय समूहों की भाति झारिया जाति भी पिछड़े है। जिनके निवास स्थान ऐसे क्षेत्रों में है जहां पहुंचने में अनेक तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनके बीच आवागमन की असुविधा भी है। उनके बीच पेयजल की गंभीर समस्या व्याप्त है। आज भी कई गांव ऐसे है जहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां के तालाब में संचित पानी का प्रयोग खाने–पीने के लिए करते है। उन्हें अनेक प्रकार के जनित रोगों का सामना करना पड़ रहा है। वे उत्पादन उपभोग के लिए करते ह। उनके बीच बचत की धारणा प्रचलित नहीं है। जंगल के अधिग्रहण के कारण उनके सामने भुखमरी और कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति में अशिक्षा व्याप्त है। अशिक्षा के कारण उनके बीच कई प्रकार की कुरीतियां प्रचलित है, उदाहरण के लिए डायन, ओझा, भूत–प्रेत, इत्यादि में विश्वास। कई महिलाओं को डायन बतलाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाताह है तथा जान से भी मार डाला जाता है। बीमारी का इलाज डॉक्टर से न कराकर वे ओझा –गुणी के पास जाते है। ओझा–गुणी के द्वारा ही किसी महिला के बारे में डायन संबधी सूचना देकर समाज में तनाव पैदा कर दिया जाता है। अशिक्षित होने के कारण विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी नहीं हो पाती है अथवा वे शोषित हो जाते है।

उत्तरदाताओं का व्यवसायिक स्थिति के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकतर उत्तरदाताओं को अपनी जीविका के लिए प्रमुख से कृषि तथा मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये लोग इन सघन वन में बहुत कठिनाईयों से जीवन व्यतीत करते है। 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अतिरिक्त परिवार के 3 से 4 सदस्य धनोपार्जन क लिए व्यवसाय से जुड़े हुए है। अर्थात् अधिकतर परिजन संयुक्त रूप से व्यवसाय से जुड़कर धनोपार्जन में अपना सहयोग देते है जिनमें उनके बच्चे भी शामिल है क्येांकि आय को अर्जित करना उनकी विशेषता है। यह स्थिति उनके दयनीय आर्थिक दशा की ओर इशारा करता है।

अधिकांश उत्तरदाताओं की मासिक आय सामान्य है, जिन पर शेष जनसंख्या आश्रित है। इसमें बच्चे विद्यार्थी तथा वे लोग शामिल है जो कोई कार्य नहीं करते है, अर्थात वृद्ध है। अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले है। उच्च आय वाले उत्तरदाताआं का प्रतिशत मात्र 8.7 है, जो झारिया परिवारों की दयनीय आर्थिक दशा को इंगित करता है। दूरस्थ घने वनों मे निवासरत झारिया समुदाय के अधिकतर परिवार की आर्थिक दशा दयनीय है। अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा परिवार के भरण–पोषण के लिए समग्र रूप से प्रयासरत रहने पर विवश रहना पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में भोजन के लिए भी इन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आधे से अधिक उत्तरदाता भूमिहीन है। 3 से 9 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि वाले 30.2 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। अधिक कृषि योग्य भमि वाले उत्तरदाता अत्यंत कम है। यहां की भूमि पथरीली एवं असिंचित होने के कारण उत्पादन भी कम होता है। जीवन गुजर बसर करने हेतु उत्पादन हो जाता है। बड़े कृषक ही अपने खेत में सिचाई

करते है। इनकी संख्या अत्यंत कम है। अधिकतर उत्तरदाताओं के पास सिंचाई के साधन नहीं है वे सभी कृषि के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर करते है। इसके साथ ही साथ बिजली की समस्या तथा डीजल की उपलब्धता से भी सिंचाई का कार्य प्रभावित होता है। जो उनकी सिंचाई संबंधी रूचि को कम कर देता है। मजबूरन उन्हें प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चयनित तीन चौथाई उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है। उन्हे खेती तथा खेतीहर मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अध्ययन के क्षेत्र के सर्वाधिक (63.7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कृषि में बहुतायत परंपरा तकनीकि प्रयोग करने की बात स्वीकार की है जो झारिया समुदाय के परिवार के दयनीय आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कुछ झारिया कृषकगणों द्वारा कृषि कार्य में जैविक खाद तथा रासायनिक खाद का प्रयोग भी करते पाये गये है। जो उनके परम्परागत कृषि कार्य में परिवर्तन की और इंगित करता है। किन्तु इस परिवर्तन की गति धीमी है जिस ओर प्रयास किया जाये तो निश्चित तौर पर उत्पादन में वृद्धि कर आय के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

अधिकतर उत्तरदाता दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत करते है। उनके आवास की प्रकृति मिश्रित है। अर्थात अधिकांश आवास आधे कच्चे तथा आधे पक्के मिश्रित प्रकार से निर्मित है। पक्के आवास में निवास करने वाले बहुत कम परिवार है। आवासों में अधिकतर दो कमरे होते है। 90 प्रतिशत आवासों में विद्युत व्यवस्था है किन्तु बड़ी बिडम्बना है कि आज भी 10 प्रतिशत आवास विद्युत विहीन है। इस क्षेत्र में विद्युत प्रवाह भी बहुत कम रहता है। जिससे यहां की जन–जीवन बहुत प्रभावित रहती हे। पेयजल व्यवस्था के स्त्रोत के रूप में हैण्ड पम्प, नल तथा कुआं उपलब्ध है। पानी के निकटतम स्त्रोत की दूरी उत्तरदाताओं के निवास स्थल से दूर है जिससे उन्हें पानी भरने में काफी समय लगता है। अधिकतर आवासों में दूषित जल के निकासी का स्थान है। एक चौथाई उत्तरदाताओं के आवास कूड़ा–कचरा फेंकने का स्थान नहीं है अर्थात अधिकतर उत्तरदाता के आवास का कूड़ा कचरा फेंकने के प्रति जागरूक नहीं है जो उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से हानिप्रद है।

उत्तरदाताआं से युवाओं का रोजगार पसंदगी के संदर्भ में पूछने पर अधिकतर युवा वर्ग को रोजगार के रूप में नौकरी अधिक पसंद है। तथा शहर जाकर कार्य करना चाहते है। यह सोच युवा परिवर्तन के पथचिन्ह हैं इसे ध्यान में रखकर विकास कार्य को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है तथा भविष्य में युवाओं का पलायन गांव से शहर की और न हो, क्यों कि युवा ही भावी परिवर्तन एवं विकास पथ से सशक्त स्त्रोत है। अतः इस और भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

पूर्व शोध कार्यो का सिंहावलोकन :– व्यक्ति लगातार नये विचारों एवं निष्कर्षो की खोज हेतु जिज्ञासु रहता है। जिसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। इस परिवर्तनशील जगत में शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। जिसमें हर क्षण नवीन अनुभव एवं परिवर्तन होते रहते है जो अनुसंधान शिक्षा की प्रक्रिया को गतिशील बनाये रखता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर अनेक शोध कार्य होते आ रहे है। अतः किसी भी श्शोध कार्य को करने से पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि शोध कार्य के लिए चुने विषयों पर किस स्तर तक अनुसंधान कार्य हो चुके है। प्रस्तुत शोध से पूर्व अनुसूचित जाति पर बहुत से कार्य किये जा चुके हैं। किन्तु झारिया समुदाय पर पूर्व में हुए अत्यन्त कम शोध कार्य मेरी जानकारी में है। पूर्ववत् तत्सम विषयों पर किये गये शोध कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित रूप से स्पष्ट है।

उमाशंकर दुबे ने डिण्डौरी जिले के बच्चों के सामाजिक एवं बौद्धिक विकास पर भौगोलिक प्रभाव, नामक शीर्षक पर झारिया अनुसूचित जाति के बौद्धिक ममता का शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना की है। इसी प्रकार डॉ. रितुरानी ने डिण्डौरी जिले के बैगा जनजाति का पोषण नामक शीर्षक के आधार पर बैगा जनजाति का पोषण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों की विवेचना की है। डॉ. श्रीकमल एवं वाय.बी. जोशी ने डिण्डौरी जिले की जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं उनके विकास पर अपना शोध आलेख लिखा है, यही नहीं समाजशास्त्रियों एवं इतिहाससविदों ने डिण्डौरी जिले के न केवल

झारिया अनुसूचित जाति बल्कि अनेकों अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है किन्तु किसी भी भूगोल वेत्ता ने झारिया समुदाय के ऊपर कोई शोध कार्य नहीं किया। डिण्डौरी जिले की झारिया समुदाय जोकि उनका मूल स्थान है, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले परिवर्तन एवं चुनौतियों का भौगोलिक प्रभावों का विवेचन करता है तथा यह भी बतलाना है कि डिण्डौरी जिले में निवास करने वाली

झारिया समुदाय शासन द्वारा अनेक सुविधाएं दिये जाने के बाद भो अपने मूलस्वरूप सामाजिक, व्यवस्था धार्मिक, एवं सांस्कृतिक मान्यताओं, बोली, भाषा इत्यादि पक्षों पर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर पायी है। जिसके कारणों की खोज करना है, क्यों कि शासन द्वारा सुविधाएं प्राप्त होने के बाद भी ये अपने मूलस्वरूप में ही क्यों प्राप्त हो रही है। वर्तमान सभ्य जातियां बिना शासन की सुविधा के बाद भी न केवल अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन कर रही है। बल्कि बौद्धिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

भौगोलिक अध्ययन में पाया कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को समझने के लिए ऐतिहासिक परिदृश्य में समझने का प्रयास किया है। इन्होंने अत्याचार को परिभाषित करने के लिये हिन्दु वर्ण व्यवस्था से लेकर आधुनिक जाति व्यवस्था की बात को रेखांकित किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है दलित कौन है, उसकी पहचान क्या है। उन्हें किस तरह से अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। अत्याचारों के परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति को किस तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। साथ ही धर्मातरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस धर्मातरण करने के पश्चात् उन पर होने वाले अत्याचारों में किस प्रकार का बदलाव हुआ। तथा उसमें कितनी कमी आयी, इन सब बातों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने ईसाई धर्मातरण तथा उसका दलिजों से संबंध को भी रेखांकित किया है। साथ ही इस बात की सच्चाई भी पता लगाने की कोशिश की है। कि दलितों के धर्मातरण के पीछे मुख्य बात क्या है। इस संदर्भ में उन्होंने पाया कि धर्मातरण के पीछे मुख्य बात उन पर होने वाले अत्याचार है। जिसे वे सदियों से झेजते आ रहे थे। शोधकर्ता द्वारा दलितों के विरूद्ध कई मुहावरों जैसे खाये गधा और मार खाये जुलाहा, डोम के घर खा लो, पर धोबी घर न खाओं आदि के बोर में भी बात कहीं है, जो उन पर पीढ़ी होने वाले अत्याचार को इंगित करती है।

उपर्युक्त भौगोलिक अध्ययन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार का इतिहास काफी पुराना है। यदि इसे आंकड़ों के रूप में देखे तो हम पाते है कि अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार का इतिहास काफी पुराना है। यदि इसे आंकड़ों के रूप में देखे तो हम पाते हैं कि अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों में पिछले वर्षो की तुलना में कमी आई है परंतु अत्याचारों यह कमी सभी जगह समान नहीं है। बल्कि यह कमी शहरी क्षेत्रों में अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई है। यदि यह कहा जाये कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक स्थलों पर यह कमी अधिक दिखाई पड़ती है परंतु निजी स्तर पर यह नही दिखाई देती है। यह भी यर्थाथ है कि अस्पृश्यता को कई मामले आगे चलकर अत्याचार तथा अनुसूचित जातियें व गैर–अनुसूचित जातियों के मध्य लड़ाई–झगड़े के रूप में परिणित हुये। इन सभी अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे अनुसूचिज जातियें के लोगों का आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास होगा, वैसे वैसे गैर अनुसूचित जातियों द्वारा इन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आती जायेगी। इन अध्ययनों से इस बात की भी पृष्टि होती है कि वर्तमान संदर्भ में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में आर्थिक कारक अधिक प्रभावी रहे, न कि सामाजिक कारक। इन्हीं सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारकों को अधिक गहराई तथा विस्तार से जानने के लिये प्रस्तुत अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा गैर–अनुसूचित जातियें के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को भी समझने का प्रयास किया गया है। इस अंतः क्रिया में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायता के मापदण्डों को प्राथमिकता को भी जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह भी

जानने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार को तीव्रता में कितना अंतर आया है और अत्याचार का रूख किस और अधिक है। अत्याचार के प्रकार में आने वाले बदलाव को भी प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से देखने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Farquhar, JN (1929) : Modern Religious Movements in India London: Macmillian.
2. Bose N.K. (1959) "Some Aspects of Cast in Bengal" in Milton singer (ed.) Traditional India: Structure and change, Philadelphia : The American Folklore Society, pp 191-215
3. Silverberg James (1969) "Social Mobility in the caste System in india An Interdisciplinary Symposium". The American Journal of Sociology, 75 (3) November, pp 443-444
4. Galander, M (1972) "The Abolition of Disablity- Untochability and the Law" in J.M. Mohar (ed.) Untochables in Contemporary India, Tuc-son : The University of Arizona Press.
5. Lynch, O.M. (1974) The Polities of Untouchability Delhi, National Publishing House.
6. Keay John (2000) : India : A History London : Harpercollins Publishers Ltd. P 145.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

व्यावसायिक आकांक्षाओं में बैंको की सृजनात्मकता

डॉ. मालती रजक
अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय कुण्डम जबलपुर (म.प्र.)

किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बिना पूंजी के किसी भी व्यावसायिक योजनाओं को या आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सचारु रुप से व्यवसाय चलाने हेतु बैंको की आवश्यकता पड़ती है।

बैंक हमारे जीवन की दैनिक जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बैंक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ किये जा सकते है। बैंक का हमें विभिन्न प्रकार से लाभन्वित करते हैं।

1991 में किए गए आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों के पश्चात अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण का प्रभाव देखने के लिए मिला। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। भारतीय बहुराष्टोय कंपनियां एवं हजारों की संख्या में प्रवेश कर गई। उदारीकरण की नीति अपनाने से लाईसेंस लेने तथा व्यापार एवं व्यवसाय की स्थापना संचालन तथा नियंत्रण करने में अनेक रियायतें प्राप्त हुई। वही निजीकरण को प्रोत्साहित करने के परिणाम स्वरुप देश में निजी क्षेत्र में भी देशी एवं विदेशी कंपनियों ने व्यवसाय प्रारंभ किया।

निजी क्षेत्र में बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों की स्थापना होने से राष्टोयकृत बैंक इनसे प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ा। निजी क्षेत्र में बैंको ने बाजार पर नियंत्रण करने तथा राष्टोयकृत बैंका के ग्राहकों को अपनी और आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिये जिनमें 0 प्रतिशत प्रकिया शुल्क तथा ब्याज की दरें कम करे ऋण प्रदान करना शामिल है।

राष्टोयकृत बैंको को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त दिशा निर्देश तथा नियंत्रण में कार्य करना होता है। इनकी ब्याज दरें भी रिजर्व बैंक इण्डिया द्वारा तय की जाती है, ये ना तो अपनी मर्जी से ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं और न ही कम कर सकते हैं। किंतु निजी क्षेत्र के बैंको को ऐसे कम कर सकते हैं। किंतु निजी क्षेत्र के बैंको को ऐसे नियंत्रण से कुछ हद तक छूट पदान की गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह ज्ञात करना है कि ''राष्टोयकृत'' एवं निजी क्षेत्र के बैंको के ग्राहकों को संतुष्टि स्तर'' किसमें अधिक है और क्यों ?

किसी भी देश क आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास एवं निरंतर चलने वाली प्रकिया होती है। जिसमें देश की विभिन्न वर्गों का योगदान होता है। देश के आर्थिक विकास के लिए बैंको का विकास अत्यंत आवश्यक है।

मनुष्य को वित्त की आवश्यकता हमेशा रहती है चाहे महान बनाना हो, नया स्थान आवास खरीदना हो, वाहन खरोदना है, या उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो, आदि कार्य बिना वित्त के संभव नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में वित्त उपलब्ध करवाने में बैंको की भूमिका बढ़ जाती है और बैंक इन सभी अवसरों के लिए वित्त प्रदान करते हैं। वित्त की व्यवस्था हेतु राष्टोयकृत बैंको के साथ बहुत सारे निजी क्षेत्र में भी बैंक स्थापित किए गए। इस सभी राष्टोयकृत उपलब्ध करवाई। अनेक कम ब्याज दरों पर आकर्षक योजनाएं उपलब्ध करवाते हैं अल्प समय अवधि, दीर्घ समय अवधि वाली ऋण योजनाएं प्रारंभ की।

लेकिन इन राष्टोयकृत निजी क्षेत्र के बैंको से लेन–देन वाले ग्राहक संतुष्ट हैं अथवा नहीं यह जानने के लिए इस शोधपत्र में कुछ आंकड़ों का सम्मेलन भी किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्टोयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंको को शामिल किया गया है। राष्टोयकृत बैंको में आशय इन बैंको से हे जिन पर राष्ट का स्वामित्व एवं प्रबंध में ले लिया प्रस्तुत शोध पत्र में राष्टोयकृत बैंको के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक एवं इलाहाबाद बैंक तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत

आई.सी.आई.सी.आई एवं आई.डी.बी.आई. बैंको से मिलने वाली सुविधाओं को सृजनात्मक अध्ययन किया है।

भारतीय स्टेट बैंक :– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1955 के पूर्व में कार्यरत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्टोयकरण क द्वारा की गई। 1955 में केवल 484 शाखाएं थी। 1992 तक उसकी शाखाओं की संख्या 8582 तक हो गई थी। वर्ष 2015–2016 तक यह संख्या जबलपुर जिले में 35–40 के लगभग हो गयी है।

इसकी प्रशासनिक व्यवस्था एस.बी. आई. एक सरकारी उपकम के रुप में स्थापित किया गया एवं इसका संगठनात्मक प्रारुप एवं लोक निगम के रुप में निर्धारित किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक 1955 की धारा के अनुसार रिजर्व बैंक की सलाह से केंद्रीय सरकार द्वारा 01 अध्यक्ष 01 उपाध्यक्ष की नियुक्ति तथा 2 प्रबंधक संचालकों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिये की जाती है। 8 संचालक मनोनीत किये जायेंगे। इनमें से 2 सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होंगे, 2 वाणिज्य उद्योग बैंकिंग तथा राजस्व के विशेषज्ञ होंगें। 4 वर्षों के लिये नियुक्त की जाती है। स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुबंई में हैं। जहां से केंद्रीय निर्देशक बोर्ड उसकी नीति को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त इसके 13 स्थानीय बोर्ड कलकत्ता, लखनउ, अहमदाबाद, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद, पटना, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में हैं।

स्टेट बैंक वर्तमान समय में अपने ग्राहकों को अनेक सुविधाओं व लाभों में लाभान्वित किया है। छोटी से छोटी ऋण योजनओं से ग्राहकों से विकास करने में सहायक हुये हैं। इंटरनेट से घर बैठे बैंक में खाता खोलना, चैक बुक की सुविधा, अपना एकाउण्ट चैक करना, मुद्रा हस्तांतरण, नेट बैंकिंग से हस्तांतरण आदि।

1. वर्तमान में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा।
2. पेंशन की सुरक्षा।
3. डोर टू डोर बिकी।
4. एस.बी.आई. टांसफर मनी।
5. एस.बी.आई. कैश कियेट गिफ्ट वाउचर।
6. एस.बी.आई. टांसफर फण्ड विथ–आउट।
7. एस.बी.आई. मोबाईल बैंकिंग।
8. एस.बी.आई. एनीयर पर्सनल क्विक फण्ड।
9. एस.बी.आई. कैश डिपोजिट एण्ड एफ.डी.।
10. एस.बी.आई ए.टी.एम.।

75 वर्ष तक की उम्र की कर्मचारियों को ऋण देने की योजना बनायी जा रही है। एस. बी.आई. की मुख्य प्रबंधक अरुणाधति भट्टाचार्य ने बताया है कि वह राशि अधिकारियों के लिए 5 करोड़ तक स्वीकृत होगी।

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण सुविधाएं देता हैं, ये निम्न प्रकार हैं : यह ऋण योजनाएं निम्न प्रकार हैं :–

1. गृह ऋण योजना।
2. शिक्षा ऋण योजना।
3. पेंशन ऋण योजना।
4. स्वर्ण आभूषण ऋण योजना।
5. एस.एम.ई. केडिट कार्ड।
6. राईस मिल प्लस।
7. दाल मिल प्लस।
8. रेण्ट प्लस।
9. स्कूल प्लस योजना।
10. स्वरोजगार केडिट कार्ड।
11. टांसपोर्ट प्लस।
12. एस.एम.ईऋ केडिट कार्ड।
13. एस.एम.ई. स्मार्ट स्कोर।
14. पर्यटन प्लस।
15. आटो लोन।
16. कॉर्पोरेट लोन।
17. आर्टोसेन केडिट कार्ड।,
18. टायअप कमिर्शियल व्हीकल प्रबंधक।
19. मार्टगेज लोन फार टेण्ड एण्ड सर्विस।
20. शार्ट टर्म लोन नॉट लिक्ड विथ वर्किंग केपिटल लिमिट।

उपयुक्त सभी योजनओं के अंतर्गत एस.बी.आई. अपने ऋण सुविधाओं में प्रकिया शुल्क 0 प्रतिशत से .25 प्रतिशत तथा अधिकतम 1 प्रतिशत तक है। मार्जिन राशि 0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक ब्याज की दरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। पुनः भुगतान अवधि की सीमा

अलग–अलग ऋण योजनओं के लिये अलग–अलग है।

दस्तावेज शासकीय नियमों के अनुसार मांगे जाते हैं। इस प्रकार व्यवसाय में बैंको का सृजनात्मक महत्व है। दूसरा राष्टोयकृत बैंक अपने शोधपत्र में शामिल किया है। व्यवासायिक आकांक्षाओं में सृजनात्मकता की भूमिका क अंतर्गत बैंकों में होने वाले लाभ के अंतर्गत तथा बैंको के रचनात्मक कार्य किस प्रकार समाज के विकास मे सहायक हैं। इसमें इलाहाबाद बैंक को भी शामिल किया है।

इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद (उ.प्र.) में हुई। बैंक की स्थापना के प्रेरक यूरोपियन समूह के लोग थे जिनके मुखिया डॉ.जे.एफ. बीटसन थे। जबलपुर में इलाहाबाद बैंक की स्थापना अक्टूबर 1904 ई को की गई जो सिविल लाइन में स्थापित है।

सन् 1913 तक हमारी बैंक संचार के सभी बैंको में समूह बैंकिंग योजना रखने में चतुर के रुप में पहचान पायी। 1923 में बैंक का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में स्थानांतरित हुआ तथा 1927 में बैंक जुड़ाव चार्टेड बैंक से हुआ।

1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में मुद्रा की जिम्मेदारी हमारी बैंक को मिली। 1940 के अंत तक बैंक ने 115 नयी शाखाओं की स्थापना की 1949 से 1964 तक नयी शाखाएं खोलते हुए रांची में 100 वीं शाखा खुली। 2016 तक देश के कोने–कोने में इसकी शाखाएं खोली गई है। जबलपुर में प्रमुख रुप से लगभग 15 शाखाएं कार्य कर रही है।

बैंक में समस्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है हमारी विशिष्ट योजनाएं किसान शक्ति, किसान केडिट कार्ड, जनरल केडिट कार्ड, आटीजन केडिट कार्ड, टेली रुरल, हेल्थ केयर, महिला शक्ति योजना, आम नागरिकों में बहुत लोकप्रिय है। शिक्षा ऋण के बीमा की अनोखी योजना प्रारंभ की गयी। हांगकांग में शाखा शेनझेन चीन में प्रतिनिधि कार्यालय के साथ बैंक का अंतर्राष्टोय क्षेत्र में पर्दापण हो रहा है। बैंको में रंगराजन कमेटी द्वारा कंप्यूटरीकरण किया गया तथा आज बैंको में 95 प्रतिशत व्यवसाय कंप्युटर से किया जाता है।

समाज के विकास में बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक बचतों व व्यवसायों के प्रोत्साहित करन हेतु जगह–जगह शाखाएं खोली गई ताकि हर क्षेत्र के व्यक्तियों को आसानी से बैंको की शाखाएं प्राप्त हो सके। जबलपुर से मुख्य रुप से इलाहाबाद बैंक, सिविल लाईन (प्रमुख शाखा) लालमाटी शाखा कांचघर, गलगला शाखा, फुहारा चौक इलाहाबाद बैंक, कटंगा शाखा, माढोताल शाखा, शास्त्रीब्रिज मार्ग शाखा सिटी आफिस आदि शाखाएं कार्यरत हैं।

समाज में व्यावसायिक विकास के लिए बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हेतु बैंकों ने निम्न योजनाओं का शुभारंभ किया –

1. व्यक्तिगत ऋण योजना।
2. कार वित्तोय योजना।
3. गृह निर्माण योजना।
4. शिक्षा ऋण।
5. व्यक्तिगत ऋण योजना।
6. किसान शक्ति योजना।
7. इलाहाबाद बैंक किराया योजना।
8. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एवं किसान विकास पत्र योजना।
9. इलाहाबाद बैंक संपत्ति योजना।
10. सरल ऋण योजना।
11. ग्राहक ऋण योजना।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का अत्यधिक महत्व है, यदि एक दिन बैंक बंद हो जाता है तो करोड़ों रूपये का व्यवसाय प्रभावित होता है, चूकिं आम व्यक्ति एवं व्यवसायी के सारे लेन देन बैंकों के माध्यम से ही होते है, इसलिए एक दिन की बैंक की हड़ताल में अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है।

बैंक समाज के उन व्यक्तियों तथा वर्गो का धन जमा करते है जिनके लिए वह अनावश्यक अथवा कम उपयोगी होता है फिर इसी पूंजी को बैंक उद्योग, धंधे, व्यापार आदि में लगाते है, जिससे उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने के लिये सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध करवाते है जिससे न केवल पूंजी में गतिशीलता आ जाती है वरन् व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। वित्त व्यवसाय एवं उद्योग का जीवन उद्योगों में भी स्थायी एवं कार्यशील पूंजी करी आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति बैंको के द्वारा ही संभव होती है।

बैंक लोगों की निष्किय कोषों एवं बचतों को एकत्रित करते है और उनके उत्पादक कार्यो के लिये उपलब्ध करवाते है। बैंक केवल लोगों की बचतों को ही एकत्र नहीं करते है। फलतः देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही अनावश्यक उपभोग और फिजूल खर्चो में कमी आती है। देश के आर्थि विकास में बैंकिंग व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में कोषों के उचित वितरण को संभव बनाते है। जिससे क्षेत्रीय असतुलन करने में सहायता मिलती है। बैंक उन स्थानों के विकास के लिये धन उपलब्ध करवाता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े है। इस प्रकार देश के संतुलन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करता है।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

HIGH FIELD MOBILITY FLUCTUATIONS IN SPHERICAL CURRENT FLOW IN INSULATOR WITH CONCENTRATION OF THE LOWER TRAP DISTRIBUTION LARGER OR EQUAL TO ONE OF THE UPPER DISTRIBUTION

Dr. Bhushan Singh Patel and Dr. Yougal Kishore Sharma
Department of Physics and Electronics, Rani Durgavati University Jabalpur M.P

Several workers [1,3,4,7,8,9,10,11] of this area of research have investigated that the trapping states are distributed in energy within the band gap of the insulating material. The understanding of the influence of trapping states is observable after considering the current-voltage characteristic of the sample under bias conditions. A new type of trap distribution function is proposed by the research workers. It is sufficiently general in nature and typically suitable to represent properly the symmetrical distributions of the trapping states as well. The present investigation is simple and it gives the complete picture of the current-voltage characteristic of the insulating material containing two sets of electron trapping states distributed around energy levels $E_1$and E_2. These energy levels have total concentration of trapping states N_1 and N_2 for the energy levels E_1 and E_2, respectively. The maximum structure in the complete current-voltage characteristics is exhibited by the limited case of the present analysis. Different dominated regions are characterized by some parameters obtained in the different portions of the complete current-voltage characteristics which are full of complexities due to the presence of two sets of trap distributions.

The present problem deals with the steady state space-charge-limited single injection spherical current flow in insulator with the situation in which the thermal- equilibrium Fermi level lies below the trap energy levels E_1 and E_2. In the typical case for the situation $N_1 >> N_2$, the concentration of the lower trap distribution N_1 is larger than or equal to one of the upper trap distribution . Such situation of the current flow problems gives a maximum structure in the complete current-voltage characteristics. In general, the proposed trap distribution of the distributed traps around the energy E_n is given by [17,18].

$$H(E) = \frac{N_n}{kT_n} \frac{\exp[(E-E_n)/kT_n]}{\left\{\exp\left[\frac{E-E_n}{kT_n}\right]+1\right\}^2}, \qquad \ldots (1)$$

where N_n is the total concentration of the trapping states, k is Boltzmann's constant, T_n is the characteristic temperature whose magnitude depends on width of the trap distribution, E_n is the energy around which the trap distribution occurs and E is the value of the energy. Both types of trap distributions of the present thesis are described by the equation (1).

Regional Approximation Method :- The regional approximation method [1,3,4,10,11] is used in the obvious physical considerations of the current injection problems in insulating material. The problems are analytically solved. At appropriate injection level of currents, the two imaginary spherical transition planes are considered to divide the spherical diode into three separate regions inside the insulator. The division of the sample is possible, because the concentration of the injected free carriers is a monotonically decreasing function of the radial distance. All the injected free carriers from the cathode are not reachable to anode under the applied voltage across the insulator. The current carriers are drifted from cathode to anode along the spherical radial outwardly alongwith the interaction of the current carriers with the lattice. It provides the decrease in

the concentration of free carriers with the increase of radial distance from cathode to anode.

At low injection level of current in the insulator, the simplifying assumption of the sharpening of the Fermi-Dirac occupation function into a step function of value unity for the energy E below the position dependent quasi-Fermi level F(r) and of value zero for E above F(r) as if T = 0.

In the present problem, the regional approximation method is applied to divide the spherical diode into three regions lying between the cathode and anode as follows –

(i) It is the perfect insulator region which is adjacent to cathode. This region is dominated by the injected current carriers $n_i(r) = n(r) - n_o = n(r)$. It is designated by the region I which is lying between cathode and the transition spherical plane situated at $r = r_1(I)$. The total excess trapped charge is equal to the free electron concentration on the imaginary spherical transition plane r_1.

(ii) The trapped charge region is adjacent to the region I. This is the region II where the excess trapped charge $n_t(r)$ is dominated. This region is found between two transition spherical planes $r_1(I)$ and $r_2(I)$.

(iii) The ohmic region is dominated by the thermal free carriers n_o. It is designated by the region III which is situated adjacent to the anode between the imaginary transition spherical plane $r_2(I)$ and anode at $r = r_a$. The location of the imaginary transition plane depends on the injection level of currents.

The region II is dominated by the trapping effects which depend on the trap distribution function given by the equation. The starting position of the thermal-equilibrium Fermi level ($F_0<E_1<E_2$), the total concentration of trapping states in the insulator lying between thermodynamical Fermi level F_o and the position dependent quasi-Fermi level F(r) is evaluated with the help of the equation (1) as-

$$n_t(r) = n_{t,1}(r) + n_{t,2}(r)$$

$$= \frac{N_1}{kT_1}\int_{F_0}^{F(r)} \frac{\exp[(E-E_1)/kT_1]}{\left\{\exp\left[\frac{E-E_1}{kT_1}\right]+1\right\}^2} dE$$

+

$$\frac{N_2}{kT_2}\int_{F_0}^{F(r)} \frac{\exp[(E-E_2)/kT_2]}{\left\{\exp\left[\frac{E-E_2}{kT_2}\right]+1\right\}^2} dE$$

Or

$$n_t(r) = N_1\left\{\frac{1}{\left(\frac{n_0}{M}\right)^{1/m}+1} - \frac{1}{\left(\frac{n(r)}{M}\right)^{1/m}+1}\right\}$$

$$+ \; N_2\left\{\frac{1}{\left(\frac{n_0}{N}\right)^{1/l}+1} - \frac{1}{\left(\frac{n(r)}{N}\right)^{1/m}+1}\right\}$$

$$= N_1\left\{\frac{\left[\frac{n(r)}{M}\right]^{1/m}}{\left[\frac{n(r)}{M}\right]^{1/m}+1}\right\} + N_2\left\{\frac{\left[\frac{n(r)}{N}\right]^{1/l}}{\left[\frac{n(r)}{N}\right]^{1/l}+1}\right\}, \qquad \ldots(2)$$

where $n_{t,1}(r)$ and $n_{t,2}(r)$ are the concentration of trapped charges at any radial point r in the lower and upper trap distributions, respectively. In the equation (2), the terms $\left(\frac{n_0}{M}\right)^{\frac{1}{m}}$ and $\left(\frac{n_0}{N}\right)^{1/l}$ in the last equality are neglected with compare to unity due to the fact that the trap energy levels E_1 and E_2 lie well above the thermal-equilibrium Fermi level F_o. It is valid for the region II.

The other physical parameters written in the equation (2) are given by-

$$n_0 = N_c\exp[(F_0 - E_{CON})/kT] \;, \qquad \ldots(3)$$

$$n(r) = N_e\exp[(F(r) - E_{CON})/kT] \;, \qquad \ldots(4)$$

$$M = N_c\exp[(E_1 - E_{CON})/kT] \;, \qquad \ldots(5)$$

$$N = N_c\exp[(E_2 - E_{CON})/kT], \qquad \ldots(6)$$

$$m = \frac{T_1}{T} \quad \text{and} \quad l = \frac{T_2}{T} \;, \qquad \ldots(7)$$

where N_c is the density of the states in the conduction band which corresponds to the lowest energy level E_{CON}.

The equation (2) is given for the total concentration of the trapped carriers $n_t(r)$ and it is a proper parameter to give the base of the application of the regional approximation method to the trapped charge region II. This region is divided in tree subregions with the help of the two imaginary transition planes. These subregions are characterized by the following situations:-

Region II_a – this is the subregion inside the insulator where the position dependent quasi-Fermi level F(r) lying between the Fermi levels $F(r_1)$ and $F(r_{ab}) = E_2$. The condition of the concentration of the trapped charged carriers is given for the region IIa as

$$n_t(r) = N_1 + N_2 = N_t \ , \qquad \ldots (8)$$

which shows that the concentration of the free charge carriers in region II_a is sufficiently large and all the trapping states capture the free carriers. Therefore, all the trapping states are filled by the trapped carriers.

Region II_b – it is the region present in the insulator when the values for function F(r) lying between the value function $F(r_{ab})$ and $F(r_{bc}) = E_1$. The density of the trapped charge carriers in the region II_b is written as

$$n_t(r) = N_1 + N_2 \left[\frac{n(r)}{N}\right]^{1/l} \approx N_1 \ , \qquad \ldots (9)$$

which shows that the free carrier concentration reduces to such an extent that only the trapping states belong to the energy level E_1 are filled with the free carriers and the trpping states distributed around the energy level E_2 are mostly vacant.

Region II_c – it is observed in an insulator for the thermodynamic Fermi level F(r) lying between $F(r_{bc})$ and $F(r_2) = F_o + 0.7\ kT$. The concentration of trapped charge carriers in the region IIc is given by

$$n_t(r) = N_1 \left[\frac{n(r)}{M}\right]^{1/m} \ , \qquad \ldots (10)$$

which reveals the fact that the concentration of the free carriers is further reduced to the level so that all the traps distributed around the energy level E_1 do not have the trapping effects and the free current carriers are gradually captured by the other distributed traps.

$$\left[\frac{n(r)}{N}\right]^{1/l}$$

Thus, the three subregions II_a, II_b, II_c are located in the region II and they are characterized by accounting that as long as the thermodynamical Fermi level F(r) lies well above the energy level E_1 and /or E_2 . In such conditions the unity present in the denominator of the terms within brackets of the equation (2) are negligibly small and they are ignored. Although, if F(r) lies well below E_2 and /or E_1 , and/or

$$\left[\frac{n(r)}{M}\right]^{1/m}$$

are neglected with compare to unity. The figure shows the complete variation of the thermodynamical Fermi level in the regional approximation method of the given problem.

The general equations characterizing the current flow and Poisson's law are given for the different regions after the application of regional approximation method to the present problem. The single injection spherical current flow at high field is considered in the insulator with concentration of lower tarp distribution larger than or equal to one of the upper trap distribution. It gives the following sets of general equations of the spherical current flow in insulator in different regions as

Region - I $(r_c \le r \le r_1)$ Perfect Insulator Region

$\left[\mathrm{E_c} \geq \mathrm{F(r)} \geq \mathrm{kTln}\left(\frac{\mathrm{N_c}}{\mathrm{N_t}}\right)\right]$; $n_i(r) = n(r) - n_0 \approx n(r) \gg n_t(r) \gg n_0$,

$I = 4\pi e\mu_0 n(r) r^2 \sqrt{E_c E}$, ...(11)

$\frac{\epsilon}{e}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E) = n(r)$ „ ...(12)

$n(r_1) = N_t = (N_1 + N_2)$, ...(13)

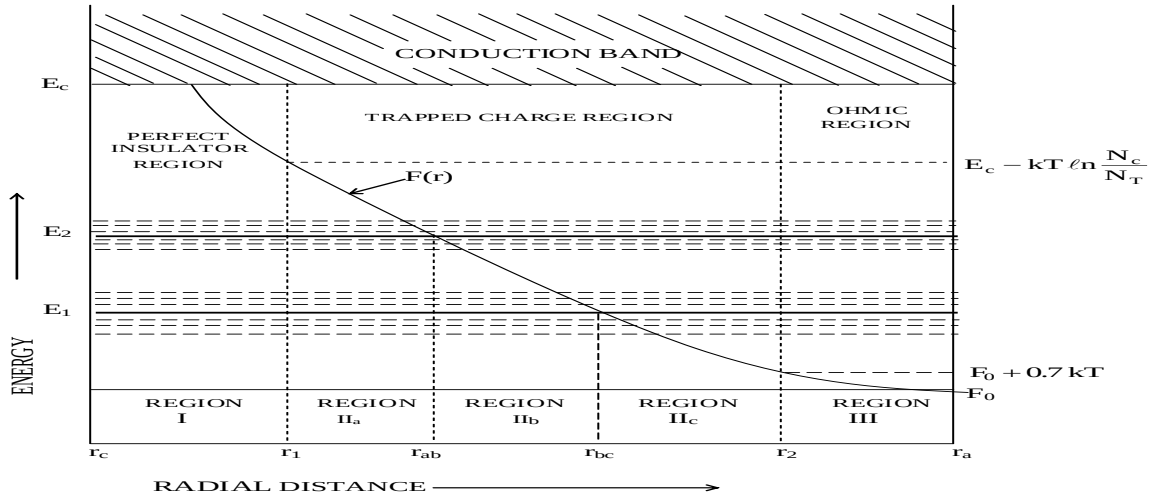

FIG. 2.2 : REGIONAL APPROXIMATION SCHEME FOR INSULATOR WITH CONCENTRATION OF THE LOWER TRAP DISTRIBUTION LARGER THAN OR EQUAL TO ONE OF THE UPPER TRAP DISTRIBUTION UNDER SPHECRICAL STRUCTURE AT HIGH FIELDS.

Region II_a $(r_1 \leq r \leq r_{ab})$ Trapped Charge Region a

$\left[E_c - kTln\left(\frac{N_c}{N_t}\right) \geq F(r) \geq E_2\right]$,

$n_t(r) = (N_1 + N_2) = N_t$,

$I = 4\pi e\mu_0 n(r)\, r^2 \sqrt{E_c E}$, ...(14)

$\frac{\epsilon}{e}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E) = N_t$, ...(15)

$n(r_{ab}) = N$, ...(16)

Region II_b $(r_{ab} \leq r \leq r_{bc})$ Trapped Charge Region b

$[E_c \geq F(r) \geq E_1]$, $n_t(r) = N_1 + N_2\left[\frac{n(r)}{N}\right]^{1/l} \approx N_1$,

$I = 4\pi e\mu_0 n(r)\, r^2 \sqrt{E_c E}$, ...(17)

$\frac{\epsilon}{e}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E) = N_1$, ...(18)

$\mathrm{n(r_{bc})} = \mathrm{M}$, ...(19)

Region II_c $(r_{bc} \leq r \leq r_2)$ Trapped Charge Region c

$[E_1 \geq F(r) \geq F_0 + 0.7kT]$ $n_t(r) = N_1\left[\frac{n(r)}{M}\right]^{1/m}$,

$I = 4\pi e\mu_0 n(r)\, r^2 \sqrt{E_c E}$, ...(20)

$\frac{\epsilon}{e}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E) = N_1\left[\frac{n(r)}{M}\right]^{1/m}$, ...(21)

$n(r_2) = n_0$, ...(22)

Region – III $(r_2 \leq r \leq r_a)$ Ohmic Region

$[F_0 + 0.7kT \geq F(r) \geq F_0]$, $n(r) = n_0$

$$I = 4\pi e \mu_0 n(r)\, r^2 \sqrt{E_c E}\,, \qquad \text{...(23)}$$

$$\frac{\in}{e}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E) = 0 \qquad \text{...(24)}$$

The above regional approximation scheme for the different boundary conditions for current flow and Poisson's law are shown in figure

Electric Field Distribution in Different Regions :- The boundary condition for the continuity of electric field strength inside the insulator is valid as the entire four imaginary transition spherical planes are given by:-

$$\left.\begin{aligned} E\left(r_1^-\right) &= E\left(r_1^+\right) \quad , \quad E\left(r_{ab}^-\right) = E\left(r_{ab}^+\right), \\ E\left(r_{bc}^-\right) &= E\left(r_{bc}^+\right) \quad , \quad E\left(r_2^-\right) = E\left(r_2^+\right), \end{aligned}\right\}, \qquad \text{...(25)}$$

where $E(r_1^-)$, $E(r_{ab}^-)$, $E(r_{bc}^-)$ and $E(r_2^-)$ are the values of the electrical field strength when the imaginary spherical transition planes r_1, r_{ab}, r_{bc}, r_2 reach from the inner side of these spherical planes, respectively and E (r_1^+), E (r_{ab}^+), E (r_{bc}^+) and E (r_2^+) are the value of the electric field strength approaches to the imaginary transition planes r_1, r_{ab}, r_{bc}, and r_2 from the outer side, respectively. The boundary conditions for the continuity of the carrier concentration at four imaginary transition planes are given by the equations (13), (16), (19) and (22). Correspondingly, these boundary conditions are valid for the electric field strength and carrier concentration continuity which are applied to obtain the general solutions for the field strength in the different regions.

Calculations of Spectral Intensity in Different Regions :- In all the five regions I, II_a, II_b, II_c, and III the noise sources present in the insulator is caused by the carrier mobility fluctuations which give the conductance noise as the main source of noise in the insulator. The mechanism of conductance noise in these regions is the same but the concentration of the current carriers in these five separate regions is different. The conductance noise generated in the regions I – IIc is due to the mobility fluctuations in the injected current carriers and conductance noise in region III is developed due to the carrier mobility fluctuations in thermal free carriers. The distribution of the free current carriers in insulator may influence the fluctuation mechanism.

The general expressions for the carrier mobility fluctuations are evaluated with the help of the small signal a.c equations for the electric field strength, carrier concentration and current as

$$E = E_0 + \Delta E \ , \qquad \text{...(26)}$$

$$n = n_0 + \Delta n \ , \qquad \text{...(27)}$$

$$I = I_0 + \Delta I \ , \qquad \text{...(28)}$$

where higher order terms are neglected. These equations are applied to obtain the conductance noise characteristics for all the five regions follows as-

Total Conductance Noise across the Insulator :- The present section estimates the conductance noise of the spherical diode at injection level of current when all the five regions are present in the insulator. The conductance noise is generated in all the parts of the spherical diode caused by the carrier mobility fluctuations. The mechanism of the conductance noise is same in all the five regions but different types of free carriers in different regions contribute the carrier mobility fluctuations. It depends on the dominating physical parameters in the particular region. The total conductance noise generated across the insulator is derived from the addition of the spectral intensities of the voltage fluctuations evaluated for the five regions as-

$$S_V(f) = S_{V_I}(f) + S_{V_{II_a}}(f) + S_{V_{II_b}}(f) + S_{V_{II_c}}(f) + S_{V_{III}}(f)$$

$$= 4kTR_n \ , \qquad \text{...(29)}$$

where,

$$R_n = R_I + R_{II_a} + R_{II_b} + R_{II_c} + R_{III} \quad . \qquad \ldots(30)$$

In the above equations the spectral intensities and the noise resistances of the five regions are given by the equations. (29) and (30). The total noise resistance generated across the entire spherical diode of the present problem is evaluated from the equations as -

$$R_n = aI^{13/5}, \qquad \ldots(31)$$

where,

$$a = \frac{9e}{32\epsilon^2 kT}\left[\frac{\epsilon}{12\pi^2 e^3 \mu_0{}^2 E_c N_t{}^3}\right]^{4/5} + \frac{8eN_1{}^2}{729\epsilon^2 M^2 kT}\left[\frac{3\epsilon}{16\pi^2 e^3 \mu_0{}^2 M^2 E_c N_1}\right]^{4/5}$$

$$+ \frac{8eN_1{}^2}{729\epsilon^2 M^2 kT}\left[\frac{3\epsilon}{16\pi^2 e^3 \mu_0{}^2 M^2 E_c N_1}\right]^{4/5} +$$

$$\frac{32\pi^2 e\mu_0{}^2 E_c}{9kT}\cdot\left(\frac{2m+1}{(3m-1)}\right)^{16/5}\left\{\frac{eN_1}{2\epsilon}\left(\frac{I}{4\pi e\mu_0 M\sqrt{E_c}}\right)^{1/m}\right\}^{\frac{6m}{2m+1}}\cdot\left[\left(\frac{M}{n_0}\right)^{1/m}\left(\frac{\epsilon}{8\pi^2 e^3 \mu_0{}^2 n_0{}^2 N_1 E_c}\right)\right]^{\frac{6(3m-1)}{5(2m+1)}}\cdot$$

$$+\left[\frac{(2m+1)}{(3m-1)}\right]^{6/5}\frac{N_1}{144\pi e\epsilon\mu_0 n_0{}^3 kT}\left(\frac{n_0}{M}\right)^{6/5m}\left[\frac{8N_1}{\pi^3\epsilon e^2\mu_0{}^3 n_0{}^3 E_c{}^4}\right]^{1/5}.$$

The above equations show that the total conductance noise is very much dependent on the injection level of currents and there is a complexity in the conductance noise variation at appropriate injection level of current. The noise resistance increases greatly with the current, since

$$R_n \alpha\, I^{13/5} \quad . \qquad \ldots(32)$$

The schematic diagram for the noise resistance for the problem is shown in fig.

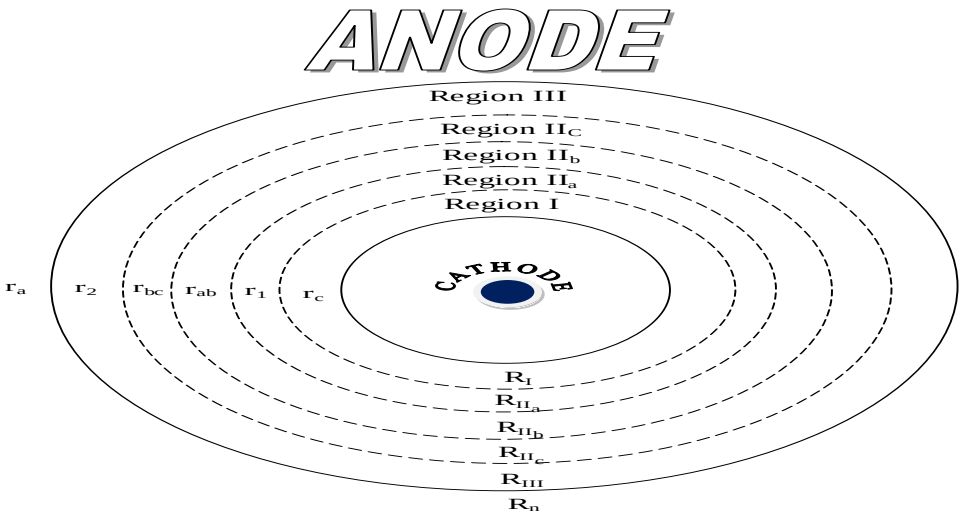

FIG.2.5 : SCHEMATIC REGIONAL DIAGRAM FOR THE NOISE RESISTANCE GENERATED IN SPHERICAL DIODE WITH CONCENTRATION OF THE LOWER TRAP DISTRIBUTION LARGER THAN OR EQUAL TO ONE OF THE UPPER TRAP DISTRIBUTION AT HIGH FIELD

Discussion and Conclusions :- The important assumptions for the current injection portion are given below-

(a) The contribution of the diffusion current to the total current is negligibly small with compare to the drift contribution, and
(b) The cathode is considered as an infinite reservoir of the free current carriers for the carrier injection and one of the electrical contacts is considered to be ohmic in nature. These assumptions are generally made in this field for simplified solutions of the complicated problems.

The high field mobility regime is considered to be present in the conductance noise characteristics. The noise is estimated in terms of the spectral intensity of the voltage fluctuations and noise resistance of the spherical diode. In the high field regime, the mobility of the current carriers is field dependent which affects the conductance noise resistance of the injection device. The contribution of the diffusion current to the conductance noise is small inside the insulator, because the drift current is dominated over the diffusion current due to the applied high field and the conductance noise mechanism of such devices is dominated by the bulk properties of the sample.

The high field conditions are considered in the current injection portion of the present investigation. The high field regime inside the spherical diode is started at the critical field strength E_c which depends on the various physical parameters of the insulating materials. The onset electric field strength E_c is present in the field dependent carrier mobility strongly depends on the material, its chemical and structural purity, and the temperature of the sample. For very pure Germanium at temperature 4^oK, E_c ? 1Volt cm^{-1} for germanium and silicon at 300^oK, E_c?10^3 Volt cm^{-1} for cadmium sulphide and zink sulphide at 300^o K , $E_c \geq 10^5$ Volt cm^{-1} [10,12].

The total current in spherical diode is the sum of the drift and diffusion contributions. The hot electron effects are maintained inside the spherical diode when operating under high field regime. The contact interface is considered under thermal- equilibrium condition when the insulator operates under the high field. The Maxwellian distribution is valid through out the five regions of the spherical diode under thermal-equilibrium conditions. The statistical average of the total current flow is zero due to the exact condition of the opposite values of the drift and diffusion contributions. However, the total current has a finite value of only spatial considerations.

The drift current dominates over the diffusion current in the single injection solid state spherical diode with distributed traps at high field. Such conditions are usually considered in the current injection theories for the planar and nonplanar solid state diodes operating under low and high fields, separately. Now, it is confirmed by the experimental observation that such assumptions are approximately valid under experimental limitations [5,10,11,12]. However, the drift current contribution is sufficiently larger over the diffusion current contribution in the spherical diode operating under hot conditions.

The conductance noise is generated in all parts of the spherical diode and it depends on the carrier mobility. The noise source is caused by the carrier mobility fluctuations which are present at each and every point of the injection device. It occurs due to the high field carrier mobility fluctuations at high field. The conductance noise sources become important and it is considerably large. The theoretical procedure adopted in the present thesis is sufficiently simplified when the diffusion current is neglected. A small error is present in the result due to the assumptions considered in the high field regime. The high field effects inside the spherical diode depend mainly on the device length and the critical electric field strength at which the high field effect is started. The critical electrical field strength depends on the lattice temperature, chemical impurities, current

flow geometry and material contents [5,6,10,11,12].

The presence of thermal free carriers provides the complexities in the results of current injection and subsequently it influences the conductance noise expressions. The current-voltage characteristic of the spherical structure is greatly affected by the length and location and form of the characteristics. They depend sufficiently on the concentration of thermal free carriers which are uniformly distributed thoughout the insulator. The results of current injection portion will finally influence the conductance noise expressions. The concentration of thermal free carriers is a very important parameter of this problem, because it is present in all the noise expressions. Therefore, it must be accurately measured. The slight change in this parameter may give significant change in the conductance noise.

REFERENCES :-

1- Blasi, C. De, Micocci, G., Rizzo, A. and Tepore, A., Solid State Electronics 26, 1095 (1983).
2- Bougalis, D. N. Noise in SCL Solid State Devices Univ. of Minnesota.
3- Dahiya, R. P. and Mathur, V. K., J. Phy. D 7 1512 (1974).
4- Dahiya, R. P. and Mathur, V. K., J. Appl. Phys. 47, 3240 (1976).
5- Gisolf, A. and Zijlstra, R. J. J., Solid State Electronics, 16, 571 (1973).
6- Gisolf, A. and Zijlstra, R. J. J., Solid State Electronics, 17, 839 (1974).
7- Hefrich, W.,Space-Charge-Limited and Volume Controlled Currents in Organic Solids, In “Physics and Chemistry of the Organic Solid State”. Vol. 3, Wiley, New York (1967).
8- Kao, K. C. and Hwang, W., Electrical Transport in Solids, Pergamon Press, New York (1981).
9- Kumar, M., Vashistha, G .K. and Sharma, Y. K., Eur. Phys. J. Appl. Phys. 40, 125 (2007).
10- Lampert, M. A., and Mark, P., Current Injection in Solids, Academic Press, New York (1970).
11- Lampert, M. A., and Schilling, R. B., Current Injection in Solids: The Regional Approximation Method. In” Semiconductors and Semimetals” (R. K. Willasdron and A. C. Beer, Eds.), Vol. 6, Academic Press, New York (1970).
12- Nicolet, M. A. Bilger, H. R., and Zijlstra, R. J., J. Phys. Stat. Sol. (b) 70, 9 (1975) i. b. c. d, 70, 415 (1975).

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

बौद्ध व जैन युग में नारी की स्थिति व सम्पत्ति अधिकार

डॉ. सोनू शर्मा
जी.डी.सी. दशहरा मैदान, उज्जैन

प्रस्तुत लेख में महावीर (599 ई.पू.) तथा बुद्ध के काल मे नारी की स्थित व साम्पत्तिक अधिकार पर चर्चा की जा रही है। बौद्ध सहित्य में कपिलवस्तु के शाक्य गण का बहुत महत्व था बुद्ध इसी गण राज्य में हुए थे। शाक्यों में स्त्रियों और कन्याओं के प्रति सम्मान की भावना अधिक थी। उनकी दशा उन्नत अवस्था में थी। उनकी दशा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए सबसे पूर्व शाक्य स्त्रियाँ ही तैयार हुयी थी। जिसमें सर्वप्रथम शाक्य नारी महाप्रजापति गौतमी थी। 1 इसके आलवा भी बुद्धकाल में ऐसी उनके स्त्रियाँ थी। जिन्होने शिक्षा प्राप्त की थी। शील भट्टारिका विजयांका, प्रभुदेवी आदि। 2

जैन धर्म के संस्थापक तीर्थप्रर महावीर का जन्म वैशाली जातकगण में हुआ, वह भी शाक्यों की तरह लिच्छवी क्षत्रिय थे। लिच्छवी लोग भी स्त्रियों का आदर सम्मान करते थे। 3

जैन ग्रन्थों से जानकारी मिलती है। कि स्त्रियाँ विवाह के समय दहेज लाती थी। अतः इसके सिवाय वह प्रीतिदान के द्वारा भी धन प्राप्त किया करती थी। प्रीतिदान के अन्तर्गत वर के माता–पिता द्वारा अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर धन प्राप्त होता था। जिसे वह अपनी पत्नी को दे दिया करता था जिस प्रकार मेघकुमार को उसके माता–पिता से अनेक, कनक, रत्न, मणि, शंख आदि प्रीतिदान में प्राप्त हुआ जिसे उसने अपनी आठो पत्नियों में बाँट दिया इस प्रकार के बँटवारे से स्पष्ट होता है कि नारी के धन में निरन्तर अभिवृदि होती रहती थी। यद्यपि जैन साहित्य पुत्री की स्थिति व उसके अधिकारो के सम्बन्ध में बहुत अधिक सीमा तक मौन दिखाई देते है 4 एक स्थान पर पुत्र व पुत्री दोनों अपना स्थान प्राप्त करने के लिए पिता के समीप जाते है। तो पिता अपने पुत्र को अपना आधा स्थान दे देते है। और पुत्री को अपनी गोद में बैठा लेते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुत्र उत्तराधिकारी माना जाता था और पुत्रियाँ मात्र भरण पोषण येाग्य मानी जाती थी 5 हालाकि कुम्भजातक से विदित होता है कि पुत्री को भी पुत्र की तरह ही स्थान प्रदान किया जाता था। सयुक्त निकाय में भी पुत्री के जन्म को दुखी नही माना जाता था, अतः पुत्री को भी पुत्र के सम्मान अनेक गुणों का विकास करने वाला माना जाता था 7 महानारद कश्यप जातक से भी उल्लेख प्राप्त होता है कि राजा अग्रयाहिषी अपनी एकमात्र पुत्री से बहुत प्रेम करता और प्रतिपक्ष दान हेतु एक हजार कार्षापण भिजवाया करता था। 8

उपरोक्त विचारों से स्पष्ठ होता है कि बौद्ध काल में पुत्रियाँ माता–पिता की प्रिय माने जाने लगी थी। इसकी पुष्टि मृदुपाणि जातक 9 महानारद कश्यपजातक 10 रोहन्तमिक जातक 11, तथा तसगुण जातक 12 आदि से होती है।

इन सब के अलावा माता–पिता की सम्पत्ति में पुत्री को अधिकार दिया गया या नही, यह हमेशा से ही विचारणीय विषय रहा है। जैन साहित्य से विदित होता है। कि किसी पुरूष के पुत्र न होने की स्थिति में पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति की उत्तराधिकारी पुत्री होगी 13 किन्तु जैन साहित्य में यह भी कहाँ गया है कि पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् एक अविवाहित पुत्री को भाईयों की सम्पत्ति का चौथा भाग दिया जाना चाहिए किन्तु विवाहित को भाई रहते कोई अधिकार नही दिया गया है उसे विवाह के समय प्राप्त उपहार व धन को ही उसकी सम्पत्ति माना जाता है 14 बौद्ध साहित्य भी पुत्री के अधिकार के विषय मे मौन दिखाई देता है। किन्तु एक प्रसंग के द्वारा इसे समझ सकते है कि एक बाह्राण की दो पत्नियाँ थी। प्रथम पत्नि के 10 वर्षीय पुत्र ने अपनीविमाता से कहाँ कि मै अपने पिता सम्पूर्ण सम्पत्ति का अकेला मालिक हूँ, इस पर विमाता ने कहाँ कि है पुत्र जब तक मे इस बच्चे को जन्म नही देती तब तक प्रतिक्षा करो, यदि पुत्र जन्म होता है तो वह तुम्हारे साथ सम्पूर्ण सम्पत्ति का आधा हिस्सेदार होगा, ओर पुत्री जन्म के पर उसका पालन पोषण तुम्हे उसके भाई के नाते करना होगा 15 अतः सिद्ध होता है कि जैन–बौद्ध युग में उसे केवल भरण–पोषण का ही अधिकार प्राप्त था।

यद्यपि जहाँ तक बौद्ध जैन युग में पत्नि की स्थिति व अधिकारों का प्रश्न है। तो कहां जा सकता है

कि बौद्ध काल में देहज की प्रथा का व्यापक प्रचलन था। धम्मपदटीका में श्रावस्ती के श्रेष्ठी निगार की कथा हैं जिसने अपनी पुत्री विशाखा के विवाह पर कल्पना से अधिक धन दिया।

जैन साहित्य भद्रबाहु संहिता में भी ऐसे पाँच प्रकार के धन को सम्पत्ति के अंतर्गत माना है। जैसे अध्यअग्निकृत, अध्यवनिका, प्रीतिदान, सौदायिका, अनविघ्य16

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि विवाहित स्त्री को भी उसके संपूर्ण प्रकार के धनों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उसकी आज्ञा के बिना कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता था। स्त्रीधन का उपयोग कठिन परिस्थति में पति द्वारा किया जा सकता था। उसका अपनी पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। पति के धन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करने वाली, पत्नी देवता के समान मानी जाती है 17 विशाखा ने अपनी सम्पत्ति से अनाथों की सहायता की 18

यद्यपि बौद्ध व जैन युग में सामान्य नारी के अलवा हमें भिक्षुणियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के पूर्व हमारे देश में नारी का भिक्षुणी होना प्रचलित नहीं था 19 जैन धर्म का भी यही विश्वास था क्योंकि श्वेताम्बर पन्थ में तो नारियाँ भिक्षुणी बन सकती थी किन्तु दिगम्बर पन्थ में नहीं क्योंकि उसमें सन्यासी को नग्न रहना पड़ता था। अतः उनका मानना था कि मुक्ति नारी के लिए नहीं है 20 जैन साध्वियों के पास कोई धन सम्पदा नहीं होती थी, 21 उनकी आवश्यकता की पूर्ती संघ करता था संघ की सम्पत्ति पर किसी भिक्षु व भिक्षुणी का अधिकार नहीं होता था 22 पति के भिक्षु बन जाने पर पत्नि के लिए भिक्षु बन जाना ही विकल्प रह जाता था। क्योंकि वह भी संसार से विरक्त हो जाती थी। दाम्पत्य जीवन की विफलता तथा पारिवारिक कलह के फलस्वरूप भी वह भिक्षुणी बनना अंगीकार किया करती थी जिस तरह इतिदास, सोणा भद्धा भिक्षुणी बनी 23

किन्तु कई परिस्थितियों में माताएँ अपनी पुत्रियों को रोकती हुयी प्रतित होती है। थेरीगाथा में उल्लेख मिलता है कि सुन्दरी नामक कन्या को उसकी माता कहती है। कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता सन्यासी बन चुके है। वैसे तुम भिक्षुणी मत बनो क्योंकि तुम ही इस सम्पूर्ण सम्पत्ति की उत्तराधिकारी है 24

यद्यपि कुछ उल्लेख ऐसे भी प्राप्त होते है जिसमें नारी अपनी इच्छानुसार धन व सम्पत्ति से दान दिया करती थी। जिसमें आमृपाली का उल्लेख महत्वपूर्ण है। उसने आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से संघ को सर्वक्षेष्ठ योगदान दिया उसने संघ को आम्रवन दान के रूप में भेट किया जिसका बौद्ध साहित्य में अम्वपालिवन नाम मिलता है 25

उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि नारी अपनी संपूर्ण सम्पत्ति का त्याग नहीं किया करती थी, वह अपनी सम्पत्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार किया करती थी। कतिपय नारीयाँ अपनी समस्त सम्पत्ति को संघ को दान देकर स्वयं भिक्षुणी जीवन अवश्य व्यतीत करती थी। किन्तु कुछ स्त्रियाँ अपने ग्रहस्थ धर्म का पालन करते हुये अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग धम्म कार्यो से करती थी।

जैन–बौद्ध युग से विदित होता है कि इस युग में भी विधवा नारी की स्थिति दयनीय रूप में मानी जाती थी। ऐसी नारी ही विधवा नहीं मानी जाती थी। जिनके पति परिलोकवासी हो गये बल्कि ऐसी ही विधवा मानी जाती थी जिनके पति उन्हें छोड़कर चले गये हो 26 अनेक भाईयों के रहते हुये भी विधवा नारी की स्थिति वैसे ही मानी जाती थी। जैसे बिना राजा के कोई राज्य एवं बिना पानी के जलविहिन नदी 27 किन्तु ऐसी, स्थिति होने पर भी ऐसे प्रमाण प्राप्त नही होते जहां विधवा को अपने केश कटवाने पड़े थे या रंगीन वस्त्र एवं आभूषण धारण न किये हो। क्योंकि रटट्पाल एवं सुदिन्न का उल्लेख प्राप्त होता है इनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी इनकी विधवाओं के द्वारा अनेक प्रकार के अलंकारों को धारण किया गया। 28

किन्तु पति की मृत्यु के पश्चात उन विधवाओं का जीवन अवश्य दुखी होता था जो पुत्रविहिन हो क्योंकि उनका पति दूसरा विवाह कर लेता था और दूसरी पत्नी से प्राप्त पुत्र उस सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता था। ओर उसे मृत पति की सम्पति से वंचित कर दिया जाता था।

यद्यपि इस युग में ऐसे उल्लेख भी प्राप्त हुए है, जहाँ अमीर परिवारों की विधवाएँ अपने पति की सम्पत्ति के द्वारा ही अपना संपूर्ण जीवन बिताया करती थी जैसे सोना पति के सन्यासी बनने पर उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारी बनी, 29 और स्थापत्या सार्थवाही ने भी अपने पति की सम्पत्ति को अपने जीवन एवं व्यापार का आधार बनाया 30

अतः निष्कर्ष रूप में कहां जा सकता है। कि विधवा को धन प्राप्ति का शासकिय अधिकार तो दिया गया था पर प्राप्त धन को संभालना कठिन था। अतः साधारणतया नारीयाँ संघ से प्रवेश लेना श्रेयस्कर समझनी थी। जहाँ उन्हे धनविहिन होने पर भी भोजन व सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था मिलती थी।

1. डॉ. सत्यकेतु विद्यालकार पृ. 171

2. सुरेश भटनागर एवं अनामिका सक्सेना, आधुनिक भारतीय शिक्षा पृ. 22,

3. डॉ. सत्यकेतु पूर्वोवत पृ. 165

4. कुम्भजातक 412 पृ. 97 इसी प्रकार बौद्धगम संयुक्त निकाय 1/85

5. डॉ. सविता विश्नोई पृ. 27

6. कुम्भजातक 412 पृ. 97

7. संयुक्त निकाय 1/85

8. डॉ. के.सी. जैन प्रा.भा. का सामाजिक सा. और भौगोलिक अध्ययन पृ. 105

9. जातक 262 खण्ड 3 पृ. 49

10. जातक 544/ 256, 544 खण्ड 6 पृ. 256

11. जातक 501 खण्ड 5 पृ. 640

12. जातक 521 खण्ड 5

13. डॉ. जगदीश चन्द्र जैन पृ. 245 – 285

14. भद्रबाहु संहिता 17/18

15. दीर्घ निकाय 2 पृ. 246

16. भद्रबाहु संहिता 83– 87

17. अंगुत्तर निकाय पंचम निपात 413

18. जातक कथाओ मे नारी, जैन फूल कुंवर पृ. 55

19. दिनकर रामधारी सिंह पृ. 146 संस्कृति के चार अध्याय

20. दिनकर रामधारी सिंह पृ. 147 संस्कृति के चार अध्याय

21 निरीथ भाष्य 2/1390–97 बृहल्कल्पना 3/3962 आदि

22. सविता विश्नोई पृ. 32

23. डॉ. मदन मोहनसिंह पृ. 59

24. थेरीगाथा 13–14 पृ. 327

25. संयुक्त निकाय 47/1

26. बौद्ध जातको में नारी पृ. 62

27. महावग्ग – 5/57

28. चुल्लवग्ग 273

29. थेरीगाथा 3/6/231

30 बौद्ध जातक मे नारी नृ. 167

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

वैदिक, जैन एवं बौद्ध काल में नारी की प्रशासन एवं राजनीतिक भूमिका

Dr.Renu Rathore
G. D . C College Dashera Maidan Ujjain

भारतीय संस्कृति में नारी के विभिन्न स्वरूप एवं आयाम देखने को मिलते हैं। भारतीय स्त्रीत्व की द्रष्टि से नारी का जीवन युगों–युगों में समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में उसके योगदान एवं गतिशीलता की और ध्यान आकर्षित करती है। जहाँ तक नारियों की प्रशासनिक एवं राजनीतिक भूमिका का प्रश्न है, उसकी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका का क्षेत्र विस्तारित है।

यह सर्वविदित है कि सबसे प्राचीन सैंधव सभ्यता मातृसत्तामक थी। यद्यपि कालांतर में उसकी समाज में सशख्त भूमिका थोड़ी गौण प्रतीत होती है।

वैदिककाल में नारियों की राजनीतिक स्थिति अधिक विस्तारित नहीं थी किन्तु वह राजनीतिक ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं थी। इसका अनुमान हरीत के इस संदर्भ से लगाया जा सकता है, कि नारी के लिए सभी विषय की शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि उसके गर्भ से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगुण संपन्न सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं का जन्म होता है, क्योंकि शुद्र योनी में इन गुणों से संपन्न व्यक्ति जन्म नहीं ले सकते। अतः नारी के तो सभी संस्कार संपन्न कराना चाहिए। 1 अतः पुत्रों के समान पुत्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। यही कारण है कि कालांतर में कई विदुषी नारियों ने ऋषिपद को शोभित किया। वे मंत्रो द्वारा देवताओं की स्तुति करती थीं। जैसे :– घोषा,काक्षीवती 2 लोपामुद्रा 3 ममता 4 अपाला 5 विश्वारा आदि महत्त्वपूर्ण है।

उपनिषदकाल तक नारियों को सहशिक्षा के अधिकार थे। वे दार्शनिकों की सभा में विद्ववतापूर्ण विषयों पर भाषण दे सकती थीं। जिसे हम गार्गी एवं मैत्रेयी 6 का उदाहरण देकर सरलता से समझ सकते हैं। यद्यपि उत्तरवैदिक काल में नारी शिक्षा व समाज में उसके स्थान की स्थिति में हास हुआ। उपनयन संस्कार विवाह के समय औपचारिक मात्र रह गया।

जहाँ तक वैदिक एवं उत्तरवैदिककाल में नारियों की राजनीतिक भूमिका का प्रश्न है प्रशासन में उसकी सहभागिता गौण थी। संभवतः इसके पीछे राजसिंहासन पर उत्तराधिकार का अधिकार पुरूषों तक ही सीमित था। यही कारण है कि वैदिककाल एवं उत्तर वैदिकयुग में हमें किसी भी महिला शासिका का उल्लेख नहीं मिलता।

यद्यपि जब हम इसका गहनता से अध्ययन करते हैं तो वैदिककाल में हमें अवश्य ही कुछ ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से भले ही नारियों ने शासन न किया हो किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान अवश्य दिया। जिसका प्रारंभ राजपरिवार से संबंधित नारियों से होता है, क्योंकि यह स्त्रियाँ शिक्षा क्षेत्रा में अग्रणी, ज्ञान, विज्ञान तथा ललिन कलाओं में निपुण होने के साथ राजनीति एवं युद्धकला की शिक्षाओं का भी ज्ञान अर्जित करती थी। मनु के अनुसार स्त्री राज्य संचालन के योग्य है, राजा की स्वजातीया, गुह लक्षणो वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हद्यप्रिय तथा रूप गुण युक्त राजमहिषी परिस्थिति आने पर राज्य कार्य का संचालन भी कर सकती थी।

अतः इससे स्पष्ट है कि यदि कोई राजमहिषी में प्रशसनिक योग्यता एवं क्षमता है तो उसे शासन संचालन का अधिकार था। यदि किसी राजा द्वारा अत्यधिक कुशलता से शासन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें उसकी राजमहिषी की उचित सलाह सम्मिलित होगी। राजनीति के दांव–पेंच में भी यदा–कदा स्त्रियाँ प्रयुक्त की जाती थीं। स्त्रियाँ दरबार का प्रमुख अंग थी और राजदरबार में राजा के चारों और स्त्रियाँ रहती थीं। 7 इसके अतिरिक्त जो स्त्रियाँ राज्य संबंधी कार्य करती थी, उनके विषय में मनु का कथन है कि, राजकार्यो में स्त्रियाँ, दास एवं दासियों को उनके कार्यो के अनुसार प्रतिदिन का वेतन निर्धारित किया जाए वे क्या कार्य करेंगे, यह भी उन्हें बताया जाए। 8

वैदिककाल में नारियाँ रक्षक के रूप में भी कार्य करतीं थी क्योंकि कई स्थानों पर उसके लिए ''पुरंधि'' शब्द का प्रयोग किया गया है। नगरों के प्रबंध, उनकी आंतरिक रक्षा एवं सफाई आदि का कार्य नारियों

के संरक्षण में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस नाम से यह भी प्रतीत होता है कि नगरों के आंतरिक प्रबंध के लिये एक भिन्न सभा होनी चाहिए, जिसमें स्त्रियों का सहयोग अपेक्षित है। 9

मध्यस्था या दौत्यकर्म के रूप में नारियों के कार्यो का उल्लेख करें तो ऋग्वेद में हमें सरमा नासक एक स्त्री का उल्लेख मिलता है जो इन्द्र के आदेश पर पणियों (चोर, डाकू, लुटैरे) के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाती है और अपनी कूटनीतिज्ञता एवं योग्यता के आधार पर पणियों को संधि प्रस्ताव के लिये मना लेती है। 10 अतः नारियों को ऐसे राजनैतिक संकट के समय चयनित करना उसके राजनैतिक कौशल को इंगित करता है।

जहाँ तक नारियों की स्वतंत्रता का प्रश्न है उसे अर्थवेद के मंत्रों से सरलता से समझा जा सकता है :–

(1) अहं वदामि नेत्वं सभायामह त्वं वद्। 11

(2) सत्याय च तपसे देवताभ्यों निधि शेवधिं परि दहम एतम् अव जान्मा समित्यां। 12

(3) यतसमित्यां यदा वदा अनृतं वित्तकाम्या। 13

अतः नारियां सभा व समिति में भाग लेकर अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट कर सकती थीं।

इन उपरोक्त नारी रूपों के अतिरिक्त एक अन्य रूप योद्धा का है।यजुर्वेद में नारियों का राज्य संचालन की प्रमुख सभाओं में चुनकर जाने के उल्लेख हैं। 14

उपरोक्त विभिन्न नारी के रूपों के अतिरिक्त एक अन्य रूप .योद्धा का है जिसके अंतर्गत विश्वला और मुद्गलानी प्रमुख है क्योंकि इन दोनों के द्वारा युद्ध में भाग लिया गया था। 15

मुद्गलानी अथवा इद्रसेन मुद्गल की पत्नि ने अपने पति द्वारा चोरों का पीछा करने में सहायता की थी क्योंकि चोरों ने उनकी गाय चुरा ली थी। विकट परिस्थिति मे रथ चालन करके अपने पति को सहयोग दिया। उसने न केवल रथ चलाया अपितु धनुषबाण लेकर युद्ध कर उन्हें पराजित किया और राज्य की सम्पत्ति की रक्षा की। 16

इसके साथ हीं ऋग्वेद में हमें सुक्ता का भी वर्णन मिलता ह। जो कि विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कहा जाता है कि उसने रूद्र के धनुष को खींचा एवं मानवता के लिये युद्ध किया। 17 नारी योद्धा में ही हमें वृदमती का उल्लेख मिलता है जिसने युद्ध में भाग लिया तथा उसके हाथ कट गये थे। तब अश्विनी कुमारों ने उसे सोने के हाथ लगवा दिया थे। 18 वेद में इंद्राणी को सेनापति के रूप में निरूपित किया है इंद्राणी एक कुशल सेनानायिका है जो युद्धो मे अश्व सेना के साथ प्रस्थान करती है। युद्ध के अतिरिक्त वह अर्थ नीति में भी कुशल युद्धार्थी थी। वह इतनी तेजस्वी है कि उसके समक्ष शत्रु. ठहर नहीं पाते। 19 उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिककाल में नारियों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक भूमिका सक्रिय थी यद्यपि उनके राजनीतिक अधिकार सीमित थे।

जैन एवं बौद्ध काल में नारियों की राजनीतिक एवं प्रशासन के क्षेत्र में कोई सक्रिय भुमिका का उल्लेख प्राप्त नहीं होता । बुद्ध कभी–भी इस विचार से पूर्ण सहमत नहीं हुए की नारी जाति को राजनीतिक के दाव–पेंचो में उलझना चाहिए। यह उसके लिए अविचारणीय था,की एक नारी किसी राज्य पर शासन करती थी।. बुद्ध के अनुसार एक प्रबंधक के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये नारी संपूर्ण रूप में अनुउपर्युक्त थी।20

उपर्युकत विवरण के आधार पर यादि हम जैन एवं बौद्ध काल के दुसरे पक्ष की और ध्यान केंद्रित करते हैं तो पाते हैं कि वेश्याएँ राज्य में सम्मान की द्रष्टि से देखी जाती थीं। वे गुप्तचर व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग थीं गणिकाओं के वेतनानुसार हम उनकी राज्य में उच्च व्यवस्था का सरलता से आकलन कर सकते है यह वेतन सेनापति के मुख्यामात्य के समान होता था। 21

मुख्य नगरों में प्रधान गाणिका का अभिषेक अत्यंत भव्य रूप से होता था। यह राजा के साथ युद्ध स्थल के पृष्ठ भाग में भी उनके साथ रहती थी। 22 एक राजा को शासन कार्य हेतु जिन महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियो की आवश्यकता होती थी। उनमें वैश्या भी सम्मिलित थी। राजा के किसी मंत्री की गतिविधियों पर राजकीय नजर रखने हेतु नाचने गाने–बजाने वाली तथा तमाशा दिखाने वाली स्त्री गुप्तचर का कार्य सम्पन्न करती थी। 23 अशोक के एक स्तम्भलेख में गुप्तचर का वर्णन है। अभिलेख में गुप्तचर के लिए प्रतिवेदक शब्द का प्रयोग किया है। मैगस्थनीज के अनुसार प्रतिवेदक लोग

सामृाज्य में क्या हो रहा है इसकी सूचना रखते थे। अशोक के समय में कुछ प्रतिवेदक नगरों में नियुक्त किये जाते थे और कुछ सेनाओ में सूचना एकत्रित करने के लिये वैश्याओं से भी गुप्तचर का काम लेते थे। योग्यता एवं विश्वासपात्र व्यक्ति प्रतिवेदक के पद पर नियुक्त किये जाते थे। 24

अतः जैन एवं बौद्ध काल मै नारियों के प्रत्यक्ष शासन करने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने किंतु गाणिका के रूप में गुप्तचर के कार्यों को सफलता से निवर्हन करने हेतु उन्होने अधिक विस्तारित तो नहीं किंतु महत्त्वपूर्ण राजनैतिक योग्यता का परिचय दिया।

अंततः हम यह सकते हैं कि समाज में नारी अपने विभिन्न रूपों का निवर्हन करती थीं। राजनैतिक एवं प्रशासक रूप में उसके प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण यद्यपि अल्प ही है किंतु इतना अवश्य है कि तत्कालीन राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिति में उसकी भुमिका नगण्य न होकर सक्रिय थी।

संदर्भ गंथ सूची

1. हारित ध. सू .21/20–24, उद्धत–प्रशांत कुमार,वैदिक साहित्य में नारी,पृ .21
2. ज्ञानी शिवदत्त, वैदिक कालीन समाज, पृ 161
3. ऋ 1/179, उद्धत, ज्ञानी शिवदत्त, वैदिक कालीन समाज, पृ 161
4. ऋ 6/10/2, उद्धत, ज्ञानी शिवदत्त, वैदिक कालीन समाज, पृ 161
5. ऋ 8/96, उद्धत, ज्ञानी शिवदत्त, वैदिक कालीन समाज, पृ 161
6. राधाकुमुद, हिन्दू सिविलिजेशन, पृ.97
7. अर्थववेद,अध्याय.–20
8. कुमार प्रशांत, वैदिक साहित्य में नारी,
9. शुक्ला,सुषमा,वैदिक वाड़मय में नारी,पृ .62
10. ऋवेद 10/108 (सम्पूर्ण सूक्त) प्रशांत कुमार,वैदिक साहित्य में नारी,पृ .154
11. अथ. 7/38/4, शुक्ला,सुषमा,वैदिक वाड़मय में नारी,पृ .62
12. अथ. 12/04/46, शुक्ला,सुषमा,वैदिक वाड़मय में नारी,पृ .62
13. अथ. 12/3/52, शुक्ला,सुषमा,वैदिक वाड़मय में नारी,पृ .62
14. यजुर्वेद 20/1–10, उद्धत–प्रशांत कुमार,वैदिक साहित्य में नारी,पृ .154
15. ऋवेद 1/12/10;116/15;10/102/2,3 उद्धत–प्रशांत कुमार,वैदिक साहित्य में नारी,पृ .152
16. ऋवेद 1/32/9 उद्धत–प्रशांत कुमार,वैदिक साहित्य में नारी,पृ .152
17. Reg.x,125-6,Noted.Martin Marry.E.R,Women in Ancient India.
18. Madhavanda s, Majumdar R.C, Great women of india
19. ऋवेद 10/86/10 उद्धत–प्रशांत कुमार,वैदिक साहित्य में नारी,पृ .152
20. Indra,Status of Women in Ancient India,P. 238-239
21. आचार्य, दीपंकर, कौटिल्यकालीन भारत पृ . 238
22. बाशम,ए.एल, अद्भुत भारत पृ . 154
23. कौटिल्य,अर्थशास्त्र, 1,12,8,11
24. चौधरी विमला ,प्राचीन भारत में गुप्तचर,व्यवस्था, पृ . 65–70

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

A STUDY ON IMPACT OF GST ON TELECOM SECTOR

Mrs. Meenakshi Swamy
Assistant Professor, St. Aloysius College, Jabalpur (M.P)

ABSTRACT :- Every nation will impose various taxes on people and thing in order to undertake developmental Work. In India the government of India recently enacted a law namely GST. GST also known as the Goods and Services Tax is defined as the giant indirect tax structure designed to support and enhances the economic growth of a country. More than 150 countries have implemented GST so far. However, the idea of GST in India was mooted by Vajpayee government in 2000 and the constitutional amendment for the same was passed by the Loksabha on 6th May 2015 but is yet to be ratified by the Rajyasabha. However, there is a huge hue and cry against its implementation. It would be interesting to understand why this proposed GST regime may hamper the growth and development of the country. The telecommunications industry has impact on every aspect of our lives, from the simple reality of enabling telephonic communication between people in different locations to enabling supply-chains to work seamlessly across continents to create products and fulfill demands. Telecommunication services are now recognized as a key to the rapid growth and modernization of the economy and an important tool for socio-economic development for a nation .This research study includes that what was the impact of GST on telecom sector.

Keywords :- Goods and Service Tax, Telecom sector.

INTRODUCTION :- Goods and Services Tax (GST) has been in the minds of the government for quite some time now and it was implemented on the 1st of July 2017. The implementation of GST is meant to regulate the telecom sector in terms of taxation. The telecom sector has seen several ups and downs in the past decade. For the same reason, TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) has played an important role in synchronizing the Indian telecom sector. The Department of Telecommunication (DOT) has also released a circular clearing the doubts about its effect on the telecom sector.

GST is a system of taxation that merges up individually applied taxes into single tax. This step has been taken to reform the indirect taxation in India. There are various aspects of the impact that GST has created on everything. But as India is embracing a single tax code, the effect on the telecom sector is going to be presumably immense as with the coming times there will be more clarity in the scenario of telecom sector.

Current Scenario of Telecom Sector :- The telecom sector in India has seen a revolution with the post liberalization economic growth after 1991. And the 1999 telecom policy has consolidated it even more. According to TRAI, in October 2015, we crossed a billion mark for the mobile subscribers and the total number of broadband subscribers in the end of October 2016 were 218.42 million. The arrival of smartphone has just increased the number of users exponentially.

The bigger players in the telecom service providers have shown a much promising picture to the consumers in terms of prices and benefits. The increasing competition has only brought the prices to a much beneficial realm for the consumers.

If we look at the trends in the Indian telecom sector for the year 2017, data realization per MB is going to fall by 20-25% in 2017. The fiberisation of network in India has not yet covered a large area, so it is going to be more prominent in 2017. The LTE and Volte enabled phones are going to be a lot cheaper in the coming

year. The growth in the mobile users is going to be 30+% from the existing 370 million users. And this is the reason behind the unexpected upsurge in the mobile advertising. The new GST regime will lead to a highly compliance cost from the telecom companies. All in all, the number of wireless subscribers has increased and the statistics show that the number of users accessing the internet on high speed has also increased.

Indian Telecom Industry Analysis

Composition Of Telecom Subscribers (FY 16)	
Urban wireless	55.6
Rural wireless	42.0
Urban wire line	2.0
Rural wire line	4.0

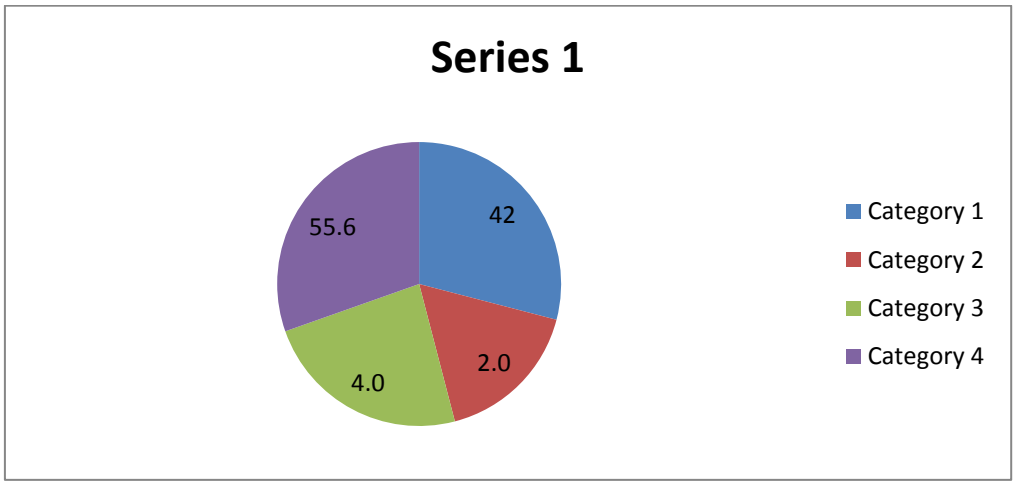

SOURCE: Telecom regulatory authority of India TechSci Research

Wireless Segment Dominates the Market

- In march 2016, India's telephone subscriber base reached 1, 058, 86 million
- In March 2016, the wireless segment (97,62percent of total telephone subscriptions) dominated the market, with the wire line segment accounting for an overall share of 2.4 percent.
- urban regions accounted for 57.6 percent share in the overall telecom subscriptions in the country, while rural areas accounted for the remaining share

Impact of GST on Telecom Sector :- From the arrival and implementation of GST, the government proposal is to levy 18 % tax on the telecom services. The current figure is 15% of tax and so the difference is of 3%. The hike in taxes may have a varied impact on the pricing policies of the telecom companies.

According to the government's press release, currently, the telecom service providers are neither eligible for credit of VAT paid on goods nor of special additional duty (SAD) that is paid on imported goods nor equipment. But under the GST regime, the telecom service providers would avail

credit of IGST paid on domestically procured goods as also imported goods.

Is GST Going To Benefit The Telecom Sector?

Telecom sector has millions of subscribers and it is one of the most basic infrastructural services for subscribers. The current ways of indirect taxes have several challenges which is the reason GST has many promising prospects for the future. GST will turn out to be an absolute solution that will become more concrete with the coming times.

In the current situation, the telecom sector is regulated by TRAI and licenses are distributed by the Department of Telecommunication (DoT). Telcos get circle-wise licenses to provide telephony services. Circle wise license distribution doesn't align with the geographical boundaries of the states. For example, Delhi NCR circle covers Delhi, Ghaziabad, Noida, Faridabad, Noida and Gurgaon telephone exchanges. GST will allow the distribution of license on state wise basis. The disparity of incurring roaming charges will be different further because of the state wise circle allocation. So, the state wise accounting is going to be applied under the GST regime.

Currently India is divided into 22 telecom service areas or circles for the purpose of licensing. Under the effects of GST, it will be levied in 29 states and 7 union Territories (UTs). The IT and billing systems will require a redesign to ensure GST compliance.

The finance ministry has already asked the phone companies to cut down prices of the telecom services, as the higher tax credits is unlikely to exceed the 1% of revenue, which is way below the 3% hike in the tax rate on telecom services .

REVIEW OF LITERATURE :- Das and Gupta (2004): They stated that the tax compliance can be improved by implementing simple reforms in personnel policy in Indian income tax .He concluded that the GST will lead to higher tax compliance and lower tax evasion by Indians.

Gang and Ira N (2000): They concluded that the tax structure India, some tax structure changes were implemented to reduce tax evasion.

Thirupathi and Sweta (2011): They examined VAT is a type of indirect tax that is imposed on goods and services, and they advocated the tax impact on budget and revenue

Sijbren (2013): Sijbren and others suggested, A modern goods and services to alleviate the problems of India's current indirect tax system.

GST As A Game Changer :- If we look at the concept of GST then the prices are going to reduce with it. The current way of taxation has cascading effect meaning a tax is applied on every stage that propels the product or services further. Due to such cascading effects, the end consumer has to pay a higher price for the same product. So it is speculation that due to this common tax scheme, the consumer will have to pay much lesser prices. If we look at another effect of GST, several telecom service providers have come up with mobile wallet services e.g. Airtel Money and Vodafone M-pesa. After the demonetization drive, the mobile wallets have become rife in usage and due to indirect tax implication. . But the mobile wallet services have a very clouded opinion regarding the point of taxation. It varies with the service provider.

It is a concrete speculation that under the GST regime, the wallet services would be clearly defined whether it falls in the service ambit or just a plain transaction. This is just one of the several challenges. The telecom sector is ready for such challenges and GST is here for an unprecedented assistance to the establishment.

SELECTIVE ISSUES PERTAINING TO THE TELECOM SECTOR UNDER THE CURRENT INDIRECT TAX LEGISLATION AND EVALUATION UNDER GST

1. **The Concept of Necessity Service**: One of the major drawbacks of the GST regime could be the direct spike in the service tax rate from 14% to 20-22 %.Being a regressive taxation system, the burn of increased tax rate will directly be faced by the end consumer unless the credit is passed on to the next in business chain. Given the importance of communication services in our lives, they could easily qualify as "Necessity Services". Thus, one could hope that the government considers allotting telecom services under the lower rate category and, in turn, charge a reduced GST rate reserved only for Necessity goods. Nevertheless, this ambitious demand could be presented but is less likely to be accepted.

2. **Mandatory annual audit Compliance**: Telecom service providers did not have to comply with a mandatory "audit obligation "as per the finance Act 1994 (as amended).But they were certainly liable to "audit scrutiny "by the service tax department if the service provider was identified as the select assesse for audit purpose. It is widely perceived that under the GST regime, VAT audit procedures may get adopted. With the merger of both goods and services under one authority, mandatory audit provisions may apply to both goods and services providers alike .As a result, telecom operators may need to engage with at least two entities, one for compliance and another for audit, failing which a possibility of conflict of interest may arise. Such dual engagement with tax firms and management services providers will further lead to an adverse hike in compliance cost.

3. **Status of exemption notification for distributors**: Telecom companies appoint agents and distributors for sale of SIM cards and recharge coupon vouchers. These agents/distributors are exempted from service tax as per Notification Sr.No.29 (f) of notification No .25/2012-ST.But, similar exemptions for distributors may or may not be available under GST.And, if the exemption is rescinded, millions of mobile distributors will have to comply with the provisions of the previously unknown world of indirect tax.

4. **Distribution of input service credits:** Telecom companies usually incur high cumulative service costs such as advertising expenses, legal expenses etc. that are borne by the head office (HO) at the first point of contact. The input credit availed for the above is then split across revenue centres through the input service Distributor scheme (ISD) under service tax. But under the GST regime, an ISD scheme (or any equivalent) is still unheard of, mainly because of the remote practical possibility of splitting a state tax pool (SGST) across other states.

FOR EXAMPLE, a telecom company Ho may incur advertising expenses of INR 1 billion, with input tax credit (ITC) of INR 100 million of Maharashtra GST(MGST @10%) and INR 100 million of central GST (CGST@ 10%),being local procurement OF SERVICES. The telecom company then passes on the expenses (not the ITC) to revenue Centre's across its 22 circles .On the credit front, we can still, theoretically, mull over the possibility of passing on CGST to other revenue centres, but passing on MGST to other revenue Centre's will not serve any purpose as MGST will not be allowed as ITC in other regions.

5. **Mobile wallets**: in these changing times, telecom companies have also evolved tenfold in order to optimize their customer service. From mere communication service, they have grown to include complex services such as value added services, internet services, advertising services etc and next up is the mobile wallet service. Top telecom service providers includingAirtel and Vodafone have already launched their mobile wallet; airtel money and Vodafone M-pesa.Most mobile wallet in India follow either the closed model or the semi-closed Model, which restricts the utilization of credit money to a specified set of services.

6.Inter-linking charges /charges for access to other circles : inter-linking charges are charges

paid by telecom companies to one another(telecom peers) for usage of each other's network and towers when their usage are outsides there ,subscribed region. Currently, these charges may get covered under the definition the term services and hence, service tax is applicable.

7.Cenvat credit on towers : Infrasture provider also known as tower companies, are one of the three broad segment of the telecom sector.in this regard, it is relevant to refer to bharti airtel Ltd VS commissioner of central excise ,pune,wherein credit on the towers. Its parts thereof and pre-fabricated building material used for providing telecommunication service, was denied on the grounds that the goods under consideration would neither qualify under the definition of capital goods nor inputs as defined under cenvat credit rules,2004.Accordingly ,due to the factor of Immovability in the goods, there is ambiguity with respect to availing such credit.

8.Place of supply for telecommunication : currently in case where both the telecom services provider and service receiver are in India ,services would accrue at the place of service receiver through Rule 3 of the place of provision of service Rules: but given its central nature the complication of chargeability were not pondered upon in depth. However, under GST ,it would be pertinent to determine the state that will receive the revenue of the GST so paid and hence, the telecom companies will require a detailed explanation as to what could be perceived as the place of supply of service .

9. **Power and fuel** : power and fuel comprise around 5-10% of the total expense in the telecom industry. And unfortunately, at present, indirect tax in the form of electricity duty, exercise and state levy on both these expenses cannot be availed as input tax credit. On one hand, petroleum consumption is not considered as an input under the cenvat credit rules thus, remaining ineligible for credit availment :and on the other electricity duty also cannot be claimed as a creditable tax as it is a state levy.

10. Sale of SIM cards: Sale of goods or provision of service? : The crux of the various judicial ruling is that the amount received by the cellular telephone company from its subscribers towards SIM cards will form part of the taxable value for levy of service tax as the SIM cards on their own, without the services, would hardly have any value .However, there is a contradiction, wherein certain state VAT legislation (e.g. Andhra Pradesh, Goa, Gujarat etc.) have specifically included SIM cards in the VAT schedules. So it is not clear whether sale of SIM cards is a sale of goods or provision of service.

CONCLUSION :- The telecom sectors presently the tax rate is 14%.By the causes of GST the tax rate on telecom sector would have to increase as 18%. So the result of GST on telecom sector will be negative. The public sector is to be critical. In future the concept of "one tax and one nation" caption is not suitable for Telecom sector. India will emerge as a leading player in the virtual world by having the highest internet users by 2025 ,there is great untapped potential in the rural market for telecom companies .In order to achieve the congruent goal of broadening the telecom business and attaining socio-economic development, it is essential that the cost of consumption of telecom service goes down ,for which it is necessary that lawmakers draft the GST framework considering the issue under the current indirect tax legislation with the intention of curtailing it or having clarity on the same. Additionally, the lawmakers should also consider the advanced products telecom companies offer to their customers (such as mobile wallets) and should seek to cover such transactions appropriately under the new indirect tax legislation with a vision of having minimal litigation at a future date. Furthermore, given the unsettled parliamentary conditions, the industry should step forward and urge the government to clear the GST bill as soon as possible and help spur overall growth.

References :-

1. The Economic Times (2009) Featured Articles from The Economic Times.
2. Gst India (2015) Economy and Policy.
3. Mehra P (2015) Modi govt.'s model for GST may not result in significant growth push. The Hindu.
4. Sardana M (2005) Evolution of Ecommerce In India Part 3.
5. TRAI (2015) Highlights of Telecom Subscription Data as on 28th February.
6. Patrick M (2015) Goods and Service Tax: Push for Growth. Centre for Public Policy Research (CPPR).
7. SKP (2014) GST: Impact on the Telecommunications Sector in India.
8. Dr. P. Mahender GST Effect on Manufacturing Industry – India Department of Business Management, Department of Business Management. Osmania University, Hyderabad, India International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) Volume 5, Issue 1, January 2017, PP 28-30 ISSN 2349-0330 (Print) & ISSN 2349-0349 (Online) .
9. 9.https://www.omicsonline.org/open-access/a-research-paper-on-an-impact-of-goods-and-service-tax-gst-on-indianeconomy-2151-6219-
10. https://www.servetel.in/blog/how-gst-is-going-to-influence-the-telecom-sector/

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

लोक संस्कृति और लोक साहित्य में बुन्देली

खुमान प्रसाद अहिरवार
दमोह म.प्र.

''लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा, जनता के लिये लिखा गया है।'' अंग्रेजी में 'फोक' का अर्थ है लोक, राष्ट्र जाति सर्व साधारण या वर्ग विशेष। इसी से 'फोकसांग' के अनुरूप हिन्दी में लोकगीत गढ़ा गया है जो उचित है। अंग्रेजी का फोकसांग जर्मनी के 'वोल्कालेड' का अपभ्रंश है। समस्त मानव समाज में चेतन रूप में जो भावनाएं गीतबद्ध होकर व्यक्त हुई है उनको 'लोकगीत' कहना उपयुक्त है। फोक शब्द की उत्पत्ति श्म्वसाश से हुई है। यह ऐंग्लो सेक्सन का शब्द है जो जर्मनी के रूप में प्रचलित है। डॉ. वार्क ने 'फोक' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इससे सभ्यता से दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोध होता है। परन्तु इसका यदि विस्तृत अर्थ लिया जाए तो किसी सुंस्कृत राष्ट्र के सभी लोग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं। बांग्लभाषी 'फोक' को असंस्कृत और मूढ़ समाज का द्योतक मानते हैं, परन्तु सर्वसाधारण और राष्ट्र के सभी लोगों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार 'लोक' तो 'फोक' से अधिक भाव प्रवण ज्ञात होता है।

लोक संस्कृति और लोक साहित्य :– लोक–संस्कृति और लोक साहित्य एक दूसरे से भिन्न है। सोफिया बर्न ने फोक्लोर के क्षेत्र में विस्तार के संबंध में लिखा है कि यह जाति बोधक शब्द की भांति प्रतिष्ठित हो गया है जिसके अंतर्गत पिछड़ी हुई जातियों में प्रचलित अथवा अपेक्षाकृत समुन्नत जातियों के असंस्कृत समुदायों के अवशिष्ट विश्वास, रीति–रिवाज, कहानियां तथा कहावतें आती है। प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगत के संबंध में भूत–प्रेतों की दुनिया तथा उनके साथ मनुष्यों के संबंधों के विषय में जादू–टोना, संमोहन वशीकरण, तावीज, भाग्य शकुन रोग तथा मृत्यु के संबंध में आदिम तथा असभ्य विश्वास इनके क्षेत्र में आते हैं। इनके अतिरिक्त इसमें विवाह, उत्तराधिकारी, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ जीवन में रीति–रिवाज तथा अनुष्ठान और त्यौहार, युद्ध, आखेट, मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन आदि विषयों के भी रीति रिवाज और अनुष्ठान इसमें आते है तथा गाथाएं, अवदान (लीजेंड), लोक कहानियां, बैलेड, गीत किवदन्तियां पहेलियां, और लोरियां भी इसके विषय हैं। संक्षेप में लोक की मानसिक सम्पन्नता के अन्तर्गत जो भी वस्तु आ सकती हैं वे सभी उसके क्षेत्र में है। यह किसान के हल की आकृति नहीं है जो लोक संस्कृति से विद्वान को अपनी ओर आकृर्षित करती है। प्रत्युत के उपचार तथा अनुष्ठान है जिन्हें किसान हल की भूमि जोतने के काम में लाने का समय करता है, जाल तथा वंशों की बनावट नहीं, बल्कि वे टोने –टोटके हैं जिन्हें मछुआ समुद्र के किनारे करता है, पुल अथवा किसी भवन का निर्माण नहीं हैं प्रत्युत वह बलि है जो उनके निर्माण के समय दी जाती है। लोक संस्कृति वस्तुतः आदिम मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा औषधि के रूप में हुई हो अथवा सामाजिक संगठन तथा अनुष्ठानों में अथवा विशेषतः इतिहास, काव्य और साहित्य के अपेक्षाकृत बौद्धिक प्रदेश में सम्पन्न हुई हो।''

सोफिया बर्न के फोक्लोर के विषय को तीन भागों में विभक्त किया है –

1. लोक–विश्वास और अंध परम्पराएं पृथ्वी तथा आकाश, वनस्पति जगत, मानव और उसकी निर्मित वस्तु आत्म तथा परलोकपरामानवी व्यक्ति, शकुन, अपशकुन, भविष्यवाणी, आकाशवाणी, जादू–टोना।
2. रीतिरिवाज तथा प्रथाएं : सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाएं, व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, उद्योग–बंबे, व्रत, त्योहार आदि के संबंध में प्रचलित रीति रिवाज।
3. लोकसाहित्य में लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें सहेलियां, सूक्तियां, बच्चों के गीत, खेल के गीत आदि। लोक साहित्य, लोक संस्कृति का ही एक भाग है। एक दूसरे में व्यापक अंतर है सीमा क्षेत्रों में बहुत अंतर है।

बुन्देली कवि :

1. लोक कवि ईसुरी
2. रामचरण हयाचरण
3. डॉ. पूरनचंद श्रीवास्तव
4. शिव सहाय चतुर्वेदी
5. मोतीलाल चौरसिया

बुन्देली लोकगीत :

संस्कृति गीत

''बेर अचार यहां के मेवे, बढ़िया ब्यारी दूध महेरी।

सस्ता साग चने की भाजी, कामधेनु घर घर की छेरी

सतुवा बिरचुन चना चबेना, व्यंजन पूरी पुवा पपरिया।

सादा जीवन थोड़े कपड़े, बण्डी कुरता पंजा फरियां।

अन्नदान कर यहाँ सुख से, तेंदू महुवा खाया करती है।

यह बुन्देलखण्ड की धरती.....

अँचरी लमेटरा जन मन में भक्ति भावनायें भर जाते है,

आल्हा की ललकार ठमक, ढोलक की सुन मुर्दे जी जाते।

और ईसुरी की फागों का, मजा सुने रजऊ सो जाने।

ब्रजवासी की तान रावला, सुनकर जियरा तृप्ति न मानें।

चौपाई चौपालों में तुलसी की धुन लहराया करती है।

यह बुन्देलखंड की धरती.....''[41]

कुन्दरू, करेला, मैनर, पड़ोरा, परमल छौंक सुधारी के हैं हाँजू ।

आलू,रतालू, कुम्हड़ा, कचरिया, अनरस फलिया, बघारी के हैं हाँजू।

खाजे, अदरसे, पपरियां, सैफ पकौरी ढोरी के हैं, हाँजू ।

पूड़ी, कचौरी, ललित लुचइंया, मालपुआ, जुग जोरी के हैं हाँजू ।

विदाई गीत –

''कच्ची ईंट बाबुल देरी न धरियो,

बिटिया न दियो परदेश मोरे लाल ।

माता कये बेटी रोजई आइयो,

बाबुल दोई जोर मोरे लाल ।

वीरन कहैं वैना अवसर आइयो,

भौजी कहें कौन काम मोरे लाल।

कौन के रोये सें नदियाँ भरत हैं,

कौन के रोये सागर ताल मोरे लाल ?

माता के रोये नदियाँ भरत हैं,

बाबुल के रोये सागर ताल मोरे लाल ।

कौन के रोये से छतियाँ फटत हैं,

कौन के जियरा कठोर मोरे लाल ?

वीरन के रोये छतियाँ फटत हैं,

भौजी के जियरा कठोर मोरे लाल ।''

सैरा गीत –

प्रश्न – सरग तरैयें रे कौवें गिनी, कौनें मूड़ के वार,

बंसा की पतियें रे, कौने गिनी, हिलोरों ताल ?

उत्तर – सरग तरैंया रे चंदा गिनी, करवई मूड़ के वार ।

बंसा की पतियां रे भौंरा गिनी, राजा राग हिलोरें दये ताल।

समाज सुधारक गीत –

''गाँजो पियो न प्रियतम प्यारे

जर जेंहे कमल तुम्हारे ।''

जारत काय विगारत सूरत

सूकत रकत न्यारे

जो तो आय शौक संतन को

हम तो गृहस्थी बारे

ईश्वर कात छोड़ दो ईखाँ

हो उम्मर के बारे ''

[41]. बुन्देलखण्ड, डॉ. रमेशचंद्र श्रीवास्तव, पृष्ठ–111

लोकगीत :– 'लोक' शब्द संस्कृत के 'लोकदर्शने' धातु में 'धज्' प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है – देखने वाला। साधारण जनता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है।

डॉ. वासुदेवशरण द्विवेदी ने 'लोक' शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम से न लेकर नगरों व गाँवों में फैली उस समूची जनता से लिया है जो परिष्कृत, रूचिसंपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन की अभ्यस्त होती है।

डॉ. कुंजबिहारी दास ने लोकगीतों की परिभाषा देते हुए कहा है, ''लोकसंगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है, जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक आदिम अवस्था में निवास करते हैं। यह साहित्य प्रायः मौखिक होता है और परम्परागत रूप से चला आ रहा है।''

लोकगीतों को मात्र ग्रामगीत रहकर उनकी व्यापकता को कम नहीं किया जा सकता। ये गीत अब गाँव की चारदीवारी को छोड़ नगरों और महानगरों की सीमा को छू रहे हैं। हिन्दी साहित्य कोश में 'लोकगीत' शब्द के तीन अर्थ किये गये हैं –

1. लोक में प्रचलित गीत,
2. लोक निर्मित गीत तथा
3. लोकविषयक गीत

किन्तु वास्तव में लोकगीत का तात्पर्य लोक में प्रचलित गीत ही हैं, जिसे दो अर्थ दिये जा सकते हैं– 1 अवसरविशेष के प्रचलित गीत तथा 2. परम्परागत गीत।

लोक द्वारा निर्मित होने पर भी लोकगीत को किसी व्यक्तिविशेष से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि रचनाकार को उस गीत में समस्त लोक के व्यक्तित्व को उभारना होता है। लोकसाहित्य वस्तुतः जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा, जनता के लिये लिखा जाता है।

राल्फ वी. विलियम्स का कथन है कि ''लोकगीत न पुराना होता है न नया। वह तो जंगल के एक वृक्ष जैसा है, जिसकी जड़ें तो दूर जमीन में धँसी हुई हैं, परन्तु जिनमें निरन्तर नई–नई डालियाँ, पल्लव और फल लगते हैं।''

लोकगीत हमारे जीवन विकास की गाथा हैं उनमें जीवन के सुख–दुःख, मिलन–विरह, उतार–चढ़ाव, की भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। सामाजिक रीति एवं कुरीतियों के भाव इन लोकगीतों में हैं। इनमें जीवन की सरल अनुभूतियों एवं भावों की गहराई है। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का कहना है कि लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है।

लोकगीतों का विस्तार कहाँ तक है, इसे कोई नहीं बता सकता। किन्तु इनमें सदियों से चले आ रहे धार्मिक विश्वास एवं परम्पराएँ जीवित हैं। ये हृदय की गहराईयों से जन्मे हैं। श्रुतिपरम्परा से ये अपने विकास का मार्ग बनाते रहे हैं। अतः इनमें तर्क कम, भावना अधिक है। न इनमें छन्दशास्त्र की लौह श्रृंखला है, न अलंकारों की बोझिलता। इनमें तो लोकमानस का स्वच्छ और पावन गंगा–यमुना जैसा प्रवाह है। लोकगीतों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें सहज स्वाभिवकता एवं सरलता हैं। इनमें सुख–दुःख, प्रेम और करूणा के विविध रंग हैं। कहीं पुत्रजन्म के अवसर पर हर्ष–उल्लास के स्वर गूँजते हैं तो कहीं कन्या की विदाई या प्रियवियोग की बेला में करूणा के गीत मुखर होते हैं।

''लोकगीतों में भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक और हृदय से निकली हुई लय के साथ होती है। हरे जंगलों में जैसे पंछी उन्मुक होकर गाते हैं, उसी प्रकार लोकगीत स्वाभाविक रीति से हृदय से फूटकर निकलते हैं। इनमें सरल काव्य होता है, भावों की खींचतान नहीं होती।''

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ''लोकगीत की एक–एक बहू के चित्रण पर रीतिकाल की सौ–सौ मुग्धाएँ और खण्डिताएँ न्योछावर की जा सकती हैं, क्योंकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी हैं और वे अलंकारों से विभूषित होने पर भी निष्प्राण हैं। ये अपने जीवन के लिये किसी शास्त्राविशेष की मुखापेक्षी नहीं हैं। ये अपने आप में परिपूर्ण हैं।''[42]

लोकगीतों में लोक का समस्त जीवन चित्रित है। शिशु के प्रथम क्रन्दन से लेकर जीवन की अन्तिम कड़ी तक के भावचित्र इनमें हैं। भाई से मिलने की

[42]. हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी

व्याकुल बहन की व्यथा–कथा, स्त्रियों का आभूषण–प्रेम, सास, ननद तथा सौत के अत्याचारों से पीड़ित स्त्री की मनोव्यथा, कृषक परिवार की विपन्नता, वीरों की शौर्यगाथा तथा मिलन–विरह के रंगारंग भाव इन गीतों में मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, इन लोकगीतों में जीवन का शाश्वत सत्य झलकता है।

महादेवी वर्मा के शब्दों में, ''सुख–दुःख की भावावेशमयी अवस्था विशेष को गिने–चुने शब्दों में स्वरसाधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है और इस गीत में जब सहज चेतना जुड़ जाती है तो वह लोकगीत बन जाता है। लोकगीत गगनचुम्बी, हिम श्रेणियों के बीच में एक ऐसा सजल आलोकोज्जवल मेघखण्ड है, जो न तो इनके टूट–फूट कर गिरने वाले शिलाखण्डों से दबता है और इन श्रेणियों की सीमाओं में आबद्ध होकर ससीम बनता है, प्रत्युय उन चोटियों का श्रृंगार करता है और संगीतलहरी के प्रत्येक स्पन्दन–कम्पन के साथ उड़कर उस विशालता के कोने–कोने को मादकता का सागर प्रस्तुत करता है।''[43]

लोकगीत कवि के परोक्षानुभूतिपरक दृष्टिकोण से सहज रूप में उद्‌भुत संगीतात्मक शब्दयोजना को कहा जा सकता है। मानव–जाति की अनवरत साधना से संजात यह अपौरूषेय साहित्य अपने आपको प्राचीनतम् श्रुतिसाहित्य की भाषापरम्परा में यह सबसे प्रामाणिक भाष्य है।

लोक से तात्पर्य :– हिन्दी में 'लोक' शब्द अंग्रेजी के 'फोक' का पर्याय है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत की है।[44] 'लोक' शब्द का अर्थ 'जनपद' का ग्राम्य नहीं है अपितु नगरों और गांवों में फैली हुई समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। प्राचीनकाल में लोक शब्द का प्रयोग साधारण जनता के अर्थ में होता रहा है। वृहत हिन्दी कोष में लोक का अर्थ संसार, पृथ्वी, मानव जाति से है।

डॉक्टर वार्कर ने 'फोक' शब्द को इस भांति समझाया है कि फोक में किसी सभ्यता से दूर रहने वाली पूरी जाति का बोध होता है। किन्तु 'फोक' के साथ यदि 'लोर' शब्द भी जोड़ा जाये तो ''फोक–लोर'' के प्रसंग में फोक का अर्थ 'असंस्कृत लोग' हो जाता है। 'जन', ग्राम व लोक शब्द 'फोक' शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं किन्तु 'फोक' के लिये 'लोक' शब्द ही अधिक उपयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया गया शब्द है। यद्यपि इस विषय पर अनेक मतभेद भी है। फोक का पर्याय 'ग्राम' मानने का आग्रह पं. रामनरेश त्रिपाठी का है। वे कहते है– ''मैने गीतों का नामकरण ग्रामगीत शब्द में किया है। क्योंकि गीत तो ग्रामों की सम्पत्ति है। शहरों में तो ये गये हैं, जन्मे नहीं..... इसमें मैं उचित समझता हूँ कि ग्रामों की यह यादगार ग्राम–गीत शब्द द्वारा स्थायी हो जाय।''[45] किन्तु यह कथन की संगतपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ''ग्राम'' में ''फोक'' की विशालता और गहराई नहीं है। 'ग्राम' शब्द सीमित है जबकि ''फोक'' की स्थिति का आभास नगर में भी सम्भव है। 'ग्राम–गीतों का समावेश लोक–गीतों के अन्तर्गत हो जाता है। क्योंकि 'ग्राम–गीत' एकमात्र 'ग्राम' की ही सम्पदा है। 'लोक–गीतों' में 'ग्राम–गीतों' के अन्तर्गत इसलिये समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि 'लोक' शब्द की सीमा 'ग्राम' शब्द की सीमा की भांति संकुचित या बंधी हुई नहीं है। 'लोक' शब्द नगर, ग्राम, जंगल, मैदान अर्थात् समूचे 'लोक' की सम्पत्ति है इसीलिये उन्मुक्त विशाल और निर्बन्ध है।

कतिपय विद्वानों का आग्रह दूसरे भ्रामक शब्द 'जन' के लिये भी है। डॉ. मोतीचन्दजी ने 'लोक' शब्द के स्थान पर 'जन' शब्द को स्वीकृत किया है। 'जन' शब्द का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 'जन' शब्द 'जनि' धातु से निकला है जिसका अर्थ 'उत्पन्न होना' है, किन्तु भाषा–विज्ञान के नियमानुसार आगे चलकर अर्थ संकोच होने से 'भक्त' के अर्थ में प्रतिपादित हो गया। यथार्थ में जन–साहित्य शिक्षित व्यक्ति की रचना होती है जिसे शिष्ट समाज का व्यक्ति लिखता है तथा वह साहित्य मुद्रित व प्रकाशित भी होता है। किन्तु 'लोक' में साहित्य रचनाकार का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, अपितु लोक साहित्य का निर्माता व्यक्ति नहीं समूह होता है जिसकी रचना का तादात्म्य लोक–मानस से रहता है। ये रचनाएं लोक संगति के प्रभाव से स्वयंभू होती है।

डॉ. सत्येन्द्र 'फोक' अथवा 'लोक' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक एवं उपयुक्त है – ''लोक, मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य–संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना

[43]. सांध्य गीत की भूमिका, महादेवी वर्मा
[44]. लोक साहित्य का अध्ययन, हजारी प्रसाद द्विवेदी,, पृष्ठ–65
[45]. जनपद अंक–1, रामनरेश त्रिपाठी,, पृष्ठ–11

अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है।''[46]

डॉ. नामवरसिंह ने जन–साहित्य और लोक–साहित्य की भेदकता स्पष्ट करने में पारखी का कार्य किया है। वे लिखते है– ''जन–साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज–व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। इसीलिये जन–साहित्य लोक–साहित्य में इसी से अर्थ भिन्न है कि लोक–साहित्य जहां जनता के लिये जनता ही द्वारा रचित साहित्य है, वहां जन–साहित्य जनता के लिये व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है।''[47]

निष्कर्ष :– ''बुन्देली लोक गीतों में व्यक्त लोक संस्कृति का अनुशीलन'' में प्रतिबिंबित ग्राम्य समाज तथा संस्कृति के मुख्य रूप से परिलक्षित किया है। बुन्देलखण्ड की सीमा विस्तार तथा यहाँ पर निवास करने वाले कवियों ने अपनी अलग पहचान बनायी है। यहाँ का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन एवं सुसंस्कृत, प्राकृतिक वातावरण, विशाल पर्वत, मोक्षदायिनी एवं जीवन दायिनी नदियाँ, समुद्र के समान ताल तलैयाँ बुन्देलखण्ड की पहचान हैं। यहाँ का इतिहास जिसकी प्रशंसा करते हुए थकता नहीं है। बुन्देली के विस्तृत भूभाग के काव्य रूप में बुन्देली कवियों लोकगीतकारों ने इस प्रकार से चित्रित किया है –

''यमुना उत्तर और नर्मदा दक्षिण अंचल ।
पूर्व ओर है टोंस, पश्चिमांचल में चंबल ।''[48]

''यमुना चम्बल टौंस नर्मदा नदियों से घिरा हुआ ।
केन घसान वेतवा की निर्मल लहरों से मिला हुआ ।
तानसेन संगीत विद बैजू की मोहक तान लिये ।
झाँसी, गढ़कुण्डार गढ़कोट, दृढ़ दुर्गों की शान लिये ।
हीरा पन्ना नर रत्नों की खान, यही अद्‌भुत अखण्ड है।
बिन्ध्यांचल के प्रांगण में बसा हुआ बुन्देलखण्ड है ।
यही देवगढ़ खजुराहों की मूर्तिकला का वैभव है ।
वीरभूमि बुन्देलखण्ड सम्पूर्ण देश का गौरव है ।''[49]

बुन्देली का प्राकृतिक स्वरूप चार विशाल नदियों के मध्य है और इसका नितप्रति विकास हो रहा है। बुन्देली भाषा एवं साहित्य अब हिन्दी की किसी भी बोली के सामने मुकाबला करने में पीछे नहीं है। बुन्देली का नामकरण विभिन्न मत मतांतरों का अवलोकन करने के बाद हम कह सकते हैं कि बुन्देली वंशीय राजाओं के राज्याधिकार का भू–भाग बुन्देलखण्ड कहलाया तथा यहाँ की भाषा बुन्देली कहलाई।

अध्याय तीन में बुन्देली लोकगीतों के वर्गीकरण के आधार पर हमने उनमें निहित सांस्कृतिक तत्वों को खोजने की चेष्टा की है। सभी गीतों में संस्कृ ति उभरकर आती है। जन्मोत्सव धूम–धाम से मानते हैं। ईश्वर के प्रति कितनी श्रृद्धा है – ज्ञात होती है। विभिन्न, संस्कारों को पूर्ण कराने में तन, मन, धन से तल्लीन रहते हैं। इन गीतों में राम, कृष्ण, सीता, राधा आदि के चरित्र अंकित हैं। इन्हीं को आधार मानकर गीत गाये जाते हैं। इन गीतों में रसानुभूति होती है। इन लोकगीतों में 'बरूआ' का अधिक महत्व है। विवाह संस्कार पूर्ण करने में कोई कमी शेष नहीं रह पाती। बुन्देलखण्ड में दहेज प्रथा प्रचलित है। यहाँ तक देखने में आता है कि दहेज में कमी के कारण बारात लौट जाती है। यद्यपि घर का प्रमुख अपने तक कोई कमी नहीं रखता किन्तु वर पक्ष के लिये कमियाँ ही दिखाई देती हैं। विवाह सरलता एवं सानंदपूर्ण निपट जाना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

ऋतु गीतों में उल्लास झलकता है। एक तो ऋतुएँ सुहानी होती हैं, दूसरे सामयिक गीत इन्हें और सुहावने बनाते हैं। ऋतु गीतों से ऋतुओं का भली भाँति ज्ञान होता है। इनमें मनाये जाने वाले प्रसंगों की चर्चा मिलती है। विधि विधान का सम्पूर्ण योग होता है। नीति एवं आदर्श भावनाएँ बुन्देली ऋतु गीतों में प्राप्त है। कार्तिक स्नान–गीत पुरूषोत्तम माह के महत्व को प्रकट करते हैं। लौकिक एवं अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। व्रत, उपवास, तीज–त्यौहार एवं देवी देवताओं से सम्बन्धित गीत उनकी महत्ता प्रतिपादित करते हैं। दार्शनिक और नैतिक दोनों पक्ष उभर कर आते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम भावना, धर्म के प्रति धार्मिक भावना इन गीतों में प्रमुख रूप से प्राप्त है।

जाति गीत किसी विशेष वर्ग के प्रति होते हैं। जाति विशेष के रहन–सहन और आचार–विचार का आभास मिलता है। इन लोकगीतों में श्रृंगार भावना प्रधान है। ये लोग नख–शिख वर्णन करने में चतुर हैं।

---

[46]. लोक साहित्य का विज्ञान, डॉ. सत्येन्द्र, पृष्ठ–3
[47]. जनपद त्रैमासिक, खण्ड एक अंक 2, डॉ. नामवर सिंह का लेख, पृष्ठ–63–64
1. बुन्देली हिन्दी उद्‌भव विकास ओर रूप, डॉ. हरदेव बाहरी पृष्ठ –82
2. बुन्देलखण्ड साहित्यिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभव, डॉ. रमेशचंद श्रीवास्तव पृष्ठ –07

जातीय व्यवसाय का चित्रण भी इन गीतों में मिलता है। तद्युगीन सामंतीय प्रभाव इन गीतों में दिखाई देता है। क्रियागीत कार्य विशेष से सम्बन्धित होते हैं। खेतों में कार्य करते हुए मजदूर इन गीतों को अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं। गीत गाते हुए कार्य करने से श्रम का आभास कम हो जाता है। मन इन गीतों की उमंग में बह जाता है जिससे कार्य साधारण तौर से कहीं अधिक होता है।

अध्याय चार में बुन्देली लोकगीतों के माध्यम से हमने लोक विश्वास, रूढ़ियों धार्मिक मान्यताओं का यथेष्ठ विवरण प्रस्तुत किया है। सच है कि बुन्देलखण्ड का वासी इन सबसे ग्रसित है। उसकी रग–रग में इन मान्यताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बुन्देलखण्ड में गाँवों की भरमार है, जिसके कारण ही ग्रामीण प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इस वैज्ञानिक युग में इनका निराकरण अवश्य प्रतीत होता है। समय के अनुसार ये भी धीरे–धीरे अपने आपको बदलने की चेष्टा में प्रयत्नशील है। इसके सम्बन्ध में श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है– ''जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है। उसकी मानसिक दासता के बंधन भी उतने ही अधिक होते है। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो शक ही नहीं है और इसलिए आगे बढ़ने के इसके रास्ते में रूकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दासता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्यायें इतनी अधिक हैं और जटिल हैं कि हम तब तक उनका हल सोच नही सकते जब तक कि हम स्वतंत्रापूर्वक इन पर सोचने का प्रयत्न न करें।

उपर्युक्त कथन से भारत की स्थिति का अनुमान होता है। पूरे भारत में ऐसी ही धारणाएँ व्याप्त थी। जो पूर्वज करते थे, उसी के बगैर सोचे समझे क्रियान्वित करते है। पूरे बुन्देलखण्ड में बाढ़ सी आई है। इसका मुख्य कारण शिक्षा की कमी कहा जा सकता है। शिक्षित लोग इससे नाता तोड़ते दिखाई देते हैं। पुराने लकीर के फकीर बने रहना इस युग में उचित नहीं है। बुन्देली लोकगीतों का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों पर भी प्रकाश अंकित है। इन सबका विवरण लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार अध्याय पाँच में समकालीन समाज एवं लोकगीतों की तुलना में मैने दो क्षेत्र छत्तीसगढ़ी एवं बुन्देलखण्डी लोकगीतों का अध्ययन किया। जिसमें मैने दोनों क्षेत्रों के समकालीन गीतों को चुनकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया ताकि हम अलग–अलग क्षेत्रों में रहकर भी यह जान सकें कि एक ही भावधारा के गीत अनेक रंगों को भरते हैं। समकालीन गीतों की तुलना में पाया कि कहीं–कहीं करूणा की धाराओं ने आँखों को गीला कर दिया है। उदाहरण के लिए – ससुराल की व्यथा में एक बहिन अपने भाई से बखान कर देती है। कहीं परिवार के सम्बन्धों की कड़ुवाहट तथा स्नेहिल भावनाओं की विस्मृतता दिखाई देती है। खेलों में नदी, पहाड़, लुका लुकौवा उड़ गये तीतर मोर में गाँवों की वास्तविकता संस्कारिता को दर्शाते हैं। नृत्यों में छत्तीसगढ़ का नाचा एवं बुन्देली का राई नृत्य ग्रामीण जन का मनोरंजन ही नहीं वरन् समाज की वास्तविकता को दर्शाते हैं।

अंततः दोनों क्षेत्रों के गीतों में भावनाओं की यह गंगा समस्त लोक मानस में समान रूप से प्रवाहमान है। दोनों क्षेत्रों में ज्यादातर साम्यता ही प्रतीत होती है। अध्याय छह में सांस्कृतिक ढांचे को समझने के उपरांत ही हमने उनका विस्तृत योगदान दिखाया है। सभी तत्वों के महत्वों को प्रस्तुत किया है। संस्कृति के निर्माणक तत्वों में जीवन–चर्या, आचार–विचार, रहन–सहन, संस्कार प्रमुख हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक ही समस्त प्रवृत्तियाँ यहाँ की संस्कृति में समाहित हैं। सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण बुन्देली लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बुन्देली लोकगीतों ने संस्कृति का कोई भी पक्ष अछूता नहीं छोड़ा है। बड़ी सूक्ष्मता से इसका वर्णन मिलता है। गीत पढ़ने या सुनने में संस्कृतिक के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। समस्त भारत की संस्कृति को विभिन्न लोकगीतों ने अपनाया है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है क्योंकि मूल में भारतीय संस्कृति ही विद्यमान है।

अध्याय सात में हमने पारिवारिक जीवन की एक झाँकी लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त की है। परिवार का गठन एवं एक दूसरे के सम्बन्धों का विवेचन भी पर्याप्त मात्रा में किया है। हमारा मुख्य लक्ष्य बुन्देली प्रदेश की ओर रहा है। यहाँ कि संस्कृति को अपने इस अध्याय में दर्शाने की चेष्टा की गई है। तदोपरांत हिन्दू संस्कृति के अनुसार मान्य षोडस (सोलह) संस्कारों की चर्चा की है। इनमें से प्रमुख संस्कारों को लेखनी का विषय बनाया है। इनमें कितनी सरलता एवं मधुरता है यह पढ़ने पर ही ज्ञात हो सकेगा। जैसे –

''जे के पांव न फटी विमाई, वो का जाने पीर पराई''

अतः स्वयं अनुभव किया है। बुन्देली जन धार्मिक प्रवत्ति के अधिक दिखाई पड़ते है। इसलिए वे देवी–देवताओं को अधिक मानते हैं। अतः उनके कृ पाकांक्षी बनने के लिए सदैव आगे रहते हैं। प्रत्येक कार्य के पूर्व उनका स्मरण और स्तुति विधि विधान से करते हैं। यही कारण है कि बुन्देलखण्ड में देवी–देवता बहुतायत में मिलते हैं। बुन्देलखण्ड में मेले, उत्सव एवं त्यौहार असंख्य हैं। प्रमुख उत्सवों, त्यौहारों का वर्णन मैंने किया है। अन्य तो अनगिनत हैं। प्रत्येक माह में 3–4 उत्सव मनाये जाते हैं। सभी विषयों से सम्बन्धित हुआ करते हैं। वर्ष भर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। ये हमारी दिनचर्या को बदलने में सहायकत होते हैं।

अंततः देखा गया है कि लोकगीतों का मुख्य स्थान ग्राम तक ही सीमित हैं। शहरों से उसका सम्बन्ध है जरूर, किन्तु उतना सरस व सटीक नहीं है। ग्रामों के लोकगीतों में जो रोचकता, सरसता रहती है वह शहरी लोकगीतों में नहीं मिलती। यही कारण है कि उत्सव, त्यौहार और पर्व गांवों में अधिक होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि शहरी जीवन बहुत व्यस्त रहता है। लोगों को रोजमर्रा के कार्यों से फुरसत मिलने के बाद इन उत्सवों को मनाने में समय देते हैं। गांवों में लोग उत्सवों में आनंद विभोर होते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF SLOW GROWING MUTANTS OF *NEUROSPORA CRASSA*

Paridhi Singh Kanojia[1], Vyas Harish[2] and Vyas Alka[1]
1. S. S. in Microbiology,Vikram University, Ujjain (M.P.) 456 010, INDIA
2. Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) 456010, INDIA

ABSTRACT : In this study we have mutagenised macroconidia of *Neurospora crassa* using chemical mutagen (EMS) and generated many mutants which have retarded growth rates. These mutants have been examined under microscope and specific defects in their hyphal morphogenesis and branching have been characterized. The genetic characterization of these mutants may reveal new genes which control branching and hyphal growth in fungi, so they may be useful in understanding fungal growth and morphogenesis.

Key Words : Fungi, *Neurospora*, mutants, EMS, growth rates.

INTRODUCTION : *Neurospora,* a heterothallic filamentous fungus has been used extensively in biochemical and genetic work. It has been used as a model system for studying various aspects of cell growth and development, gene silencing, understanding circadian clock and stress responses in eukaryotic cells (Ghosh *et al.,* 2014). *Neurospora* grows in a polarized manner and its growth rate is about 4 mm/h and genome size is 43 MB revealing about 10,000 genes (Honda and Selker, 2009, Riquelme *et al.,* 2011 and Shanker *et al.,* 2007).

Neurospora is being widely used for understanding various aspects of growth and morphogenesis of filamentous fungi. Studies have shown that septins are involved in maintaining cell polarity, tip growth, septation and conidiation (Berepiki and Read, 2013). Kinesin-3 actively plays an important role in anterograde motility of early endosomes and dynein is involved in retrograde motility (Schuster *et al.,* 2011). Calcineurin has a significant role in normal growth, asexual development and sexual fertility (Tamuli *et al.,* 2016). Berepiki *et al.,* (2010) have described the role of F-actin in cell polarity, exocytosis, endocytosis and organelle movement. Microtubules (MT's) in *N. crassa*, are arranged longitudinally along the hypha and moves as the hypha extends. They have been shown to play an important role in cell shape maintenance, division, migration and intracellular transport (Mourino-Perez, 2013). Still, there are many aspects of fungal growth which are not clearly understood, important being tip extension, polarity and branching (Riquelme *et al.,* 2011). We have morphologically characterized new mutants of *N. crassa* which show retarded growth. Further genetic and biochemical studies of these mutants may help in identifying key molecules involved in growth and morphogenesis of fungi and help in understanding unexplained aspects of fungal growth.

AIMS AND OBJECTIVES :

The objective of the study was to isolate and characterize the mutants of *Neurospora crassa* having retarded growth.

MATERIALS AND METHODS

Fungal strains

Neurospora cultures (FGSC #2489; mat A and FGSC #4200; mat a) used in study was obtained from Fungal Genetics Stock Center, Kansas City, USA. The cultures were grown in Vogel's minimal medium at 34±2 ºC (Mukati *et al.,* 2015).

Isolation and characterization of mutants

A week old macroconidia of *N. crassa* (FGSC #2489; mat A) were mutagenised using EMS following the method described by Mukati *et al.,* 2015. The mutagenised macroconidia were plated on 1% sorbose containing minimal agar media and well spaced individual colonies were isolated. These cultures were purified by subculturing. The growth rate of cultures were determined using race tubes and detailed hyphal morphologies were studied under microscope and mutants showing specific defects were identified.

Inheritance of defects

The mutant cultures were crossed with wild-type strain (FGSC #4200). After one month of crossing 30 random ascospores were picked and heat shocked to obtain progeny cultures. The cultures were analyzed for morphological defects as already described.

RESULTS AND DISCUSSION :

Ninety different cultures were isolated by mutagenesis of macroconidia. The cultures were grown in race tubes (Fig. 1) and five mutant cultures having reduced growth rates were isolated. Table 1 and Fig. 2 show the growth rates of mutants and wild-type cultures.

Fig. 1 : *Neurospora* culture growing in race tube.

Table 1. Growth rates of wild-type (FGSC #2489) and mutant cultures of *Neurospora crassa*

S. No.	Culture No.	Extension growth (cm/h)	Reduction in growth
1	FGSC #2489 (Wild-type)	4.3 ± 0.13	-
2	VU13-12 (Mutant)	1.3 ± 0.05	3.3 fold
3	VU13-20 (Mutant)	2.1± 0.11	2.0 fold
4	VU13-36 (Mutant)	3.0 ± 0.07	1.4 fold
5	VU13-38 (Mutant)	2.3 ± 0.10	1.8 fold
6	VU13-46 (Mutant)	2.3 ± 0.05	1.8 fold

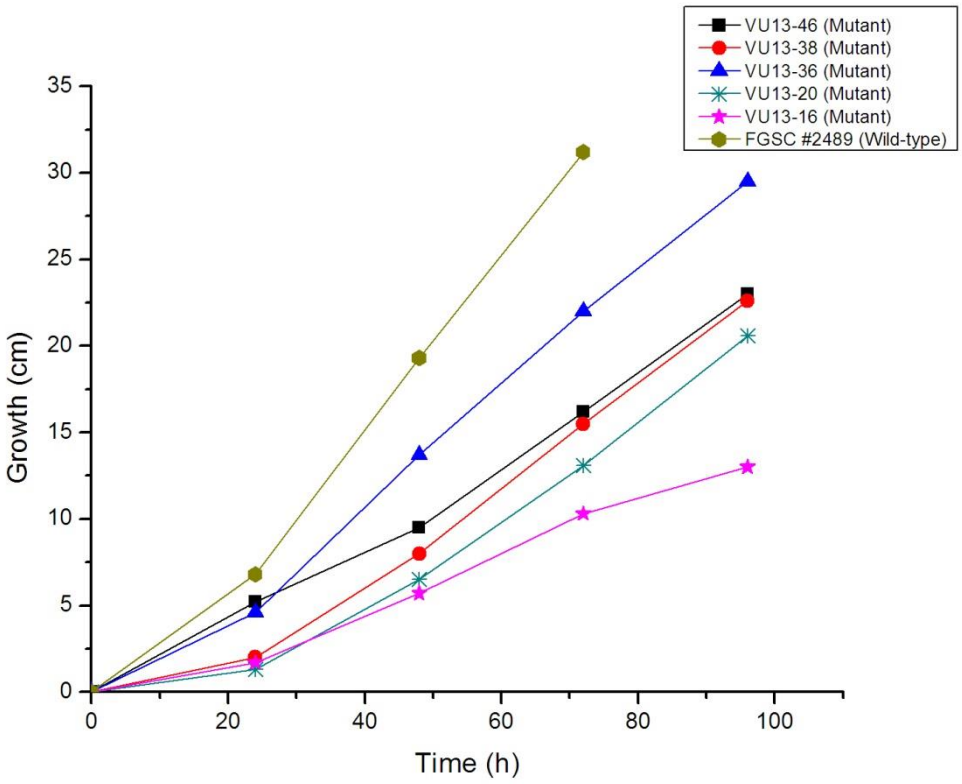

Fig. 2 : Extension growth of wild-type *N. crassa* (FGSC #2489) and mutant cultures (VU13-12, VU13-20,VU13-36, VU13-38 and VU13-46) at 34±2 ºC.

It can be seen (Table 1 and Fig. 2) that all the five cultures have retarded growth rates in comparison to wild-type culture. The growth rates of mutant cultures are 3.3 to 1.4 fold less than the wild-type culture. This indicates that there must be some defect in the cultures which does not allow these results are shown in Fig. 3.

cultures to grow with optimum growth rate. In order to find out these defects, the cultures were grown on Vogel's minimal agar medium and the hyphal characteristics were observed under microscope. The

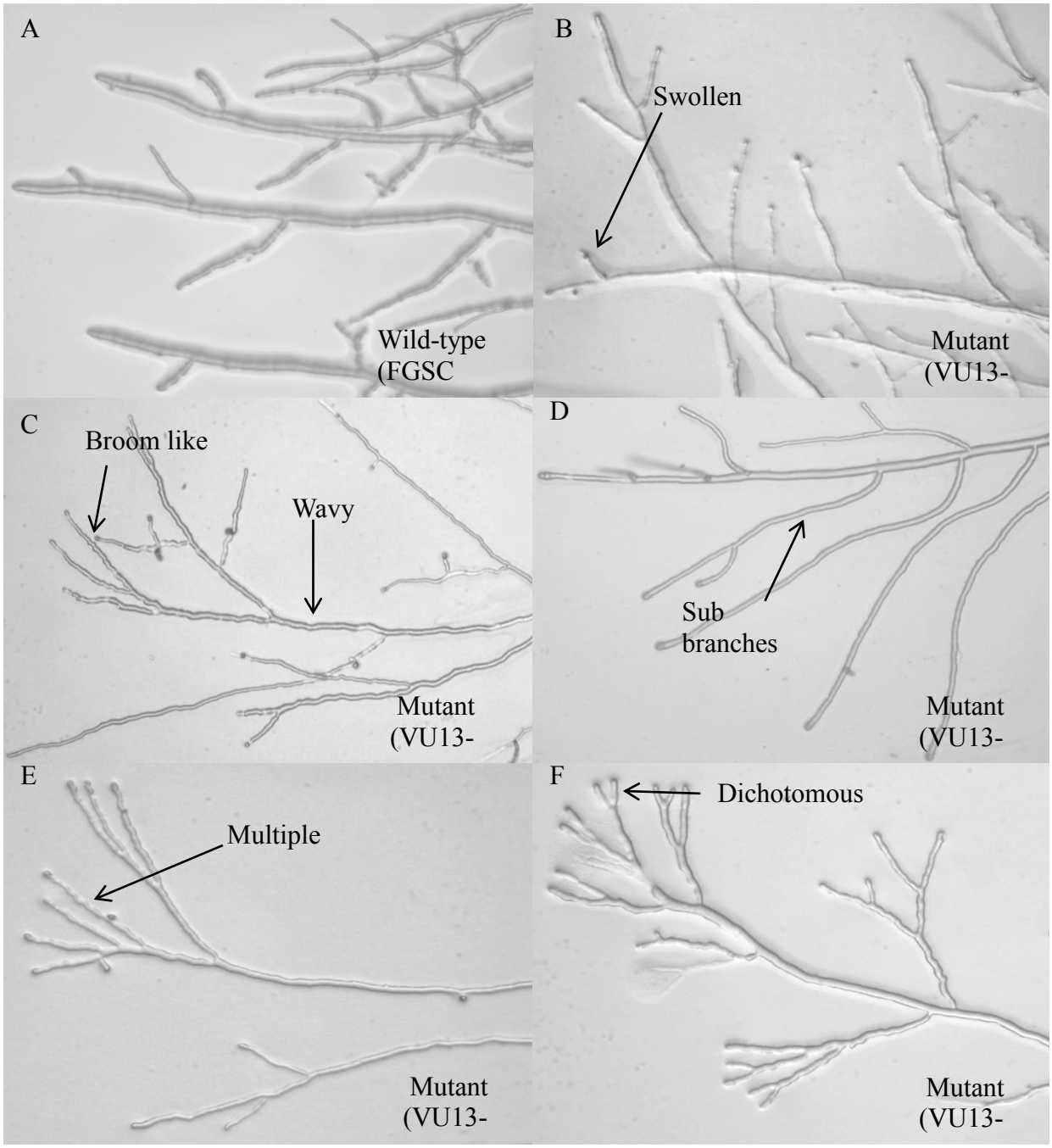

Fig. 3 : Microscopic photographs of (A) wild-type (FGSC #2489), (B) Mutant (VU13-12), (C) Mutant (VU13-20), (D) Mutant (VU13-36), (E) Mutant (VU13-38) and (F) Mutant (VU13-46).

It can be seen (Fig. 3) that in mutant culture VU13-12 distance between the branches is long and branch tips are swollen. The mutant culture VU13-20 has wavy growth of hyphae and has broom like appearance at the hyphal front due to dichotomous branching. There is a visible gap between the two branches. This mutant has defect in branching as well as in hyphal movement. Further genetic characterization of this culture may help in understanding hyphal growth and branching. The mutant culture VU13-36 shows straight hyphal growth but branches in hypha

occurs distantly and the sub branches are very long which do not branch further for long time. Thus it has some defect in branching. Wavy growth and multiple branching is the characteristic feature of mutant culture VU13-38. Mutant culture VU13-46 show slight wavy growth pattern and dichotomous branching occurs at many places at hyphal tip because of which it gives broom like appearance. It differs from VU13-20 in having the close distance between the branches. The cultures were crossed with the wild-type tester strain and 20 random progeny from each cross was analyzed (Table 2).

Table 2. Progeny analysis of mutant cultures.

S. No.	Cross No.	Parents	Results
1	PS-14	VU13-12 (♀) X FGSC #4200 (♂)	The mutant defects were inherited in many progeny
2	PS-6	VU13-20 (♀) X FGSC #4200 (♂)	The mutant defects were inherited in some progeny
3	PS-25	VU13-36 (♀) X FGSC #4200 (♂)	The mutant defects were inherited in some progeny
4	PS-21	VU13-38 (♀) X FGSC #4200 (♂)	The mutant defects were inherited in some progeny
5	PS-37	VU13-46 (♀) X FGSC #4200 (♂)	The mutant defects were inherited in many progeny

The results (Table 2) show that the morphological defect were inherited in the next progeny. It is not clear whether the defects are due to nuclear or cytoplasmic gene and further studies are required to clarify this. Thus these mutants can be used for further biochemical studies to identify the molecular component responsible for the defect. This molecular component could be used for targeting drugs for reducing fungal growth.

CONCLUSION : In this study we have isolated five mutants of *Neurospora crassa* (VU13-12, VU13-20, VU13-36, VU13-38 and VU13-46) which have defects in hyphal growth and branching. The defects in these mutants are heritable. These mutants may be very useful for understanding mechanisms of fungal growth.

ACKNOWLEDGEMENT : We are thankful to UGC-CRO Bhopal (Project- F. No.: MS-31/107024/XII/14-15/CRO) and MPCST, Bhopal (Project- No. 3586/CST/R&D/Bio. Proj. S/2012) for financial assistance.
We also thank Fungal Genetics Stock Center FGSC; Department of Microbiology, University of Kansas Medical Center) for providing *Neurospora* cultures.

REFERENCES :

1. Schuster M., Kilaru S., Fink G., Collemare J., Roger Y. and Steinberg G., Kinesin-3 dynein cooperate in long range retrograde endosome motility along a nonuniform microtubule array, *MBoC*, **22**, 3645-3657, **(2011)**.
2. Ghosh A., Servin J.A., Park G. and Borkovich K.A., Global Analysis of Serine/ Threonine and Tyrosine Protein

Phosphatase Catalytic Subunit Genes in Neurospora crassa Reveals interplay Between Phosphatases and the p38 Mitogen Activated Protein Kinase, *G3 : Gene, Genomes, Genetics,* **4**, 349-365, **(2014)**. doi: 10.1534/g3.113.00813.

3. Riquelme M., Yarden O., Bartnicki-Garcia S., Bowman B., Castro-Longoria E., Free S.J., Fleiβner A., Freitag M., Lew R.R., Mourino-Perez R., Plamann M., Rasmussen C., Richthammer C., Roberson R.W., Sanchez-Leon E., Seiler S. and Watters M.K., Architecture and development of the Neurospora crassa hypha- a model cell for polarized growth, *Fungal Biology*, **115**, 446-474, **(2011)**.
4. Shanker A., Singh A. and Sharma V., In silico mining in expressed sequences of *Neurospora crassa* for identification and abundance of microsatellites, *Microbiological Research*, **162**, 250-256, **(2007)**.
5. Berepiki A. and Read N.D., Septins are important for Cell Polarity, Septation and Asexual Spore Formation in *Neurospora crassa* and Show Different Patterns of Localization at Germ Tube Tips, *PLoS ONE*, **8**(5), 1-21, **(2013)**. doi: 10. 1371/journal.pone.0063843.
6. Tamuli R., Deka R. and Borkovich K.A., Calcineurin Subunits A and B Interact to Regulate Growth and Asexual and Sexual Development in Neurospora crassa, *PLoS ONE*, **11**(3), 1-17, **(2016)**. doi: 10.1371/journal.pone.0151867.
7. Berepiki A., Lichius A., Shoji J., Tilsner J. and Read N.D., F-Actin Dynamics in *Neurospora crassa*, *Eukaryotic cell*, **9**(4), 547-557, **(2010)**.
8. Mukati A., Vyas A. and Vyas H., A new mutant of *Neurospora crassa* (VU-82) having defects in branching and tip growth, *J. Environ Res. Develop.,* **10**(1), 28-34, **(2015)**.
9. Mourino-Perez R.R., Linacre-Rojas L.P., Roman-Gavilanes A.L., Lew T.K., Callejas-Negrete O.A., Roberson R.W. and Freitag M., MTB-3, a Microtubule Plus-End Tracking Protein (+TIP) of *Neurospora crassa*, *PLoS ONE*, **8**(8), 1-9, **(2013)**. doi: 10.1371/journal.pone.0070655.
10. Honda S. and Selker E.U., Tools for Fungal Proteomics: Multifunctional Neurospora vectors for gene Replacement Protein Expression and Protein Purification, *Genetics*, **182**,11-23, **(2009)**.
11. Mukati A., Vyas A. and Vyas H., A study of natural population of *Neurospora* and isolation of novel morphological mutants, *J. Environ. Res. Develop*., **7**(2A), 923-935, **(2012).**

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

''ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी का विशलेषण''

डॉ. नीता ठाकुर
सहायक प्राध्यापक
नचिकेता इंस्ट्रीट्यूट एंड मैनेंजमेट, जबलपुर

पुरूष और स्त्री : समाज निर्माण के दो परस्पर पूरक तत्व है। पर समाज–संचालन में एक सक्रियता और दूसरे की वाध्यता है । यह बाध्यता जीवन के सतत प्रवाह में गतिरोध पैदा न क रें तो भी उसे कुंठित अवश्य करती है । इसलिए विभिन्न युगो में भारतीय स्त्री की स्थति क्या रही है, भानवीय विकास में इसका योगदान कितना और कैसा रहा है । यहां आकर यह संतुलन बिगडा इस असंतुलन ने समाज को, पुरूष को व स्वयं नारी को कितनी क्षति पहुंचाई इस अध्ययन सदियो से से विद्वानो की रूचि का विषय रहा है । ***एवलिन सुलेराट*** ने लिखा है कि ''किसी समाज में स्त्रियो की दशा एक ठोस समाजिक संरचना की ओर संकेत करता है । जिससे अनेक इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती है । जैसे एक आदर्श परिवार समाज की भूमिका आर्थिक भूमिकाएँ कार्यक्षेत्र समाज में उनके लिए निषेधो का क्षेत्र यह सब कारक समाज में स्त्रियो को गतिशीलता देते है ।'' मध्यकाल से 19 वी शताब्दी तक स्वयं स्त्री इस स्थिति से बेखवर थी ।

लेकिन नवजागरण काल और स्वातंत्र–संघर्ष के बाद स्वत्रंत भारत के संविधान द्वारा प्राप्त नई स्थिति इस यात्रा को जैसे वर्षों से दिनों में बदल दिया। तीव्र गति से बदलाव के इस अंतरिम काल में आज जबकि वर्तमान ही स्पष्ट नहीं है। भविष्य की कोई निश्चित कल्पना करना आसान नहीं है । पर विभिन्न युगो में स्त्री की स्थिति का संक्षिप्त अध्ययन से एक निष्कर्ष तो निकाल ही सकते है कि महिलाओं की भागीदारी समाज के विकास में कितना योगदान रहा है। महिलाओं की विभिन्न कालो की स्थिति निम्नानुसार है

प्रागैतिहासिक युग –

इस युग में नारी की स्थिति पुरूष के बराबर ही नहीं उससे श्रेष्ठ थी क्योंकि परिवार मातृसतात्मक थे । आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में नारी के विशेष अधिकार प्राप्त थे । उस काल की मूर्तियों में देवत्व पर स्त्री को सुशोमित होने के प्रमाण मिलते है तत्कालीन संस्कृति के निर्माण उनका प्रमुख हाथ रहा है । ऐसा कला–शिल्प के प्राप्त नमूनो और घरो के उन्नत सुसंस्कृत स्तर के अवशेषो से पता चलता है ।

वैदिग युग –

आर्यो की सभ्यता संस्कृति के प्रसार में भी महिलाओं का योगदान कम नहीं रहा । आर्यो के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद जो कि भारतीयो की बुनियादी प्रेरणा माना जाता है, ये ऐसे उल्लेख मिलते है जिनसे तत्कालीन समाज में स्त्रियो की उन्नत स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है उस समय की सर्वोच्च शिक्षा (बह्म ज्ञान) प्राप्त करने पर स्त्रियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । वेद और शास्त्रो में पारंगत होने के अतिरिक्त वेदऋचाओं की भी रचना करती थी।

स्त्रियां वैदिक शिक्षा के साथ–साथ यज्ञ आदि का संपादन भी करती थीं । उनका भी पुरूष के समान 'उपनयन संस्कार' होता था। वेदो में अनेक जगह लोपामुद्रा, रीमसा, घोषा, सूर्या अपाला, विलोमी, सावित्री यमी, विश्वभरा, श्रदा कामायनी देवयानी आदि नाम मिलते है, जिन्हे विद्धता के आधार पर ऋषिका और ब्राह्मणी कहा गया है। सामाजिक और धार्मिक समाजो में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त थे ।

उत्तर वैदिक काल –

उपनिषदों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। **श्री अत्तेकर** के अनुसार इस काल में भी ऊँची जाति में पुरूषो के समान ही स्त्रियो का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा उन्हे आध्यामिक ज्ञान और दर्शन शास्त्र की शिक्षा देना अनिवार्य था । धार्मिक कार्य करने योग्य केवल शिक्षित स्त्रियाँ ही मानी जाती थी । स्त्री–धन का प्राय अभाव था। तत्कालीन दार्शनिक समाओ में महिलाओं की भी सफल भागीदारी रहती थी। ऊँचे स्तर की इन चर्चाओं में उद्दालिका आर्तभागा, विदग्धा, अश्वला, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषियो के भाग दे लेने का अर्थ है कि उपनिषद काल में भी महिलाएँ उच्च शिक्षा से विभूषित थीं ।

इस काल में पुरूष राज्यो को जीतने और उन्हे एक सूत्र में बॉधने में लगे हुए थे तो स्त्रीयों खेती का काम देखने, कपड़े बुनने, तीर कमान बनाने आदि कामों के साथ गृहस्थी की देखमाल में समय बिताती थी ।

यद्यषि वर्ण व्यवस्था के नियमों में कडाई आने के साथ ही स्त्रियों के पद में ह्रास होने लगा था। बाद में बहुपत्नी प्रथा और 'अनुलोम' विवाह प्रथा के कारण स्त्री का दर्जा हीन हो गया । आर्यो के दक्षिण विजय के साथ ही में प्रथाएँ प्रचलित हो गयी थी। यहीं से यानि उत्तर वैदिक काल से ही भारतीय नारी की स्थिति में गिरावट का प्रारंभ माना जाने लगा।

महाकाव्य काल –

रामायण और महाभारत काल में भी स्त्री का वर्णन विदुषी के रू‍ में कम और तप त्याग नम्रता पति सेवा आदि गुणों में विभूषित गृहस्वामिनी के रूप अधिक मिलता है । रामायण में भी कैकैयी अनसुइया आदि नारियों को विदूषी के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार महाभारत में भी कहीं कही नारी के स्वत्रंत विकास के उदाहरण मिलते है। किंतु उत्तर वैदिक काल व उसके बाद रामायण महाभारत काल में नारी के अधिकार पहरे जैसे नहीं रहे। धीरे–धीरे नैतिकता के मापदंड बदलने लगे। पतिव्रत धर्म ही स्त्री मात्र के लिए सर्वोच्च धर्म और स्वर्ग प्रारित का साघन जाने लगा। इसी का परिणाम कालांतर में सती प्रथा के रूप में सामने आया।

लगभग 300 ई.पू. तक स्त्रियो का पति की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं रह गया । इसी काल में प्रसिद्ध समाजसुधारक मनु ने स्त्रियों के लिए नियम बनाया कि वे बचपन में मां–बाप, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहकर सुरक्षित जीवन विताऐं । इन्ही नियमो के अधीन विवश स्त्रियों में अपना भला–बुरा समझने की शक्ति समाप्त हो गई।

मध्य युग –

मध्य युग में विशेष रूप से भारत पर मुसलमानो के आत्रमणो और मुगलो के राज्य–स्थापन के बाद भारत में स्त्रियो की स्थति में और गिरावट आई। मुस्लिम आत्रमणो के के कारण लडकियों के अपहरण की घटनाएँ बढ़ी तो हिंदुओ में छोटी–छोटी बच्चियो का विवाह किया जाने लगा और बाल विवाह एवं पर्दा–प्रथा प्रारंभ हो गई ।

भारत में बिट्रिश राज्य के प्रभाव से तथा शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा कर दिये जाने से भारतीय जीवन पद्धति और राष्ट्रीय चरित्र में नए परिवर्तन प्रारंभ हो गये। कुटीर उघोग नष्ट हो गये। सयुक्त परिवार बिखरने लगे। ग्रामीणो के बीच गरीबी और अज्ञानता का राज्य आ गया । भारतीय समाज एक नए प्रकार के शेषण का शिकार हो गया। पहले से ही शोषित नारी पर इसका दुष्प्रभाव पडा। वह और अधिक पददलित और पीड़ित हुई।

इन्ही सब कारणो से देश की आधी जनसंख्या पिछडे वर्ग में शुमार हो गयी। समाज सुधारकों का ध्यान पिछडे वर्गो के साथ ही नारी को ओर भी केंद्रित हुआ।

नारी जागरण और नारी प्रगति –

बीसवी सदीं के प्रथम 45–50 वर्षो को जागरण कहा जा सकता है और स्वत्रंता के पश्चात का युग जो प्रारंभ हुआ वह नारी प्रगति का था। पहली अवधि में नारी ने अपनी सामाजिक अधीनता और राजनीतिक पराधीनता की वेडिया काटे फेकने के लिए संघर्ष किया और अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरी अवधी में उस लक्ष्य को पाने के लिए उस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया । और उसके परिणाम जल्दी ही सामने आने लगे और स्त्री फिर सभंलने लगी । अपनी क्षमताओ के साथ वह अपनी सीमाओं को भी पहचानने लगी ।

कुल मिलाकर बहुत संक्षेप में भारतीय नारी भी अनेक उतार चढ़ावो से भरी प्रगति की यात्रा है। इसी यात्रा में मिली सफलताओं और उपलब्धियों की झलक हमारे शोध का विषय है । जो ग्रामीण महिलाओं को लेकर किया गया जिसमे ग्रामीण महिलाओ की सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है ।

महिलाओ की भागीदारी

महिलाओ की भागीदारी आत्मविश्वास और स्वाभिमान पर आधारित है । समाज में सम्मान जनक स्थान एवं पुरूष और महिलाओं की स्थिति में अंतर यू तो समुचे समाज में मौजूद है । किन्तु ग्रामीण समाज में उनकी हालत विशेष रूप से काफी सोचनीय है । जहाँ शहरो में शिक्षा, समाज सुधारो की वजह से महिलाओ को स्वत्रंता समानता के अधिकार मिले है वही गाँवो में महिलाएँ परिवार और समाज के शोषण का शिकार होती है ।

सामाजिक भागीदारी का विशेलेषण –

भारत वर्ष में ग्रामीण स्त्रियो की सामाजिक स्थिति एवं भूमिकाओ पर अनेक अध्ययन किये गये। भारत का ग्रामीण समाज बाहा कारको से प्रभावित हो रहा है और नारी जगत भी प्रभावित हो रहा हैं। भारत में पुरूषो की अपेक्षा स्त्रियो की स्थिति एवं भूमिकाओं का क्षेत्र उतना उत्साहवर्घक नहीं है जितना होना चाहिए।

यह बात सच है स्त्री स्त्रियों की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है । बच्चों का भविष्य माताओं के हाथो से बनता है । स्त्रियों की भूमिका परिवार और घर के कार्यो में महत्वपूर्ण है । वस्तु उन्हे सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में अधिकार नहीं मिले है जो उनको मिलना चाहिए । अभी तक भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज रहा और महिलाओं का शोषण होता रहा है। भोजन बनाना प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करना बच्चों की देखभाल करना यह सवस्त्रियों के कार्य क्षेत्र है । वस्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यों को कोई महत्व नही दिया जाता है क्योंकि पुरूष यह सोचता है कि यह सब कार्य महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। महिलाओं के कार्यो का कम मूल्यांकन करने के निम्न सामाजिक कारक है–

1. विवाह व्यवस्था सम्बन्धी नियमो में समानता नहीं है । विवाह और विवाह–विच्छेद सम्बन्धी नियम प्राय महिलाओ के हितों में नहीं है ।
2. विवाह के बाद दहेज जैसी प्रथा महिलाओ की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है ।
3. वेश्यावृति पुरूषों द्वारा महिलाओं के शोषण का संस्थागत माध्यम है ।
4. पुरूषों की तरह महिलाओं को सार्वजनिक स्थानो पर गतिशीलता भी स्वत्रता न होकर उसमें नियंत्रण पाया जाता है । जिससे महिलाओं में आत्म विश्वास नहीं आता है । जो व्यक्तिव के विकास में बाधक है ।

उपर्युक्त तथ्यो के अतिरिक्त सामाजिक भागीदारी के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं की परम्परागत और आधुनिक दृष्टिकोणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है । परम्परागत रूप से महिलाओं को पुरूषों के अधीन माना जाता है और महिलाओं का स्थान घर के भीतर सीमित है उनका सामाजिक भागीदारी का कोई मूल्य नही है । एक आधुनिक भारतीय महिला का तात्पर्य शिक्षित होना रोजगार मुक्त होना स्वत्रंता होना स्वयं में सोचते समझने की क्षमता होना देखने को मिलता है ।

समाजशास्त्रियों ने महिलाओ की सामाजिक शक्ति सम्पन्नता के निम्न मानको को माना है – शिक्षा, स्वास्थ, उत्तम पोषाहार, स्वच्छ पेयजल उत्तम आवास, एवं स्वच्छ सामाजिक पर्यावरण आवश्यक है ।

ग्रामीण नारी की आर्थिक भागीदारी का विश्लेषण–

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । आर्थिक स्थिति का जब विश्लेषण किया जाता है तो निम्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है –

1. रोजगार 2. व्यवसाय 3. आय 4. ऋण 5. भूमि और कृषि सम्बन्धी यंत्र 6. आवास 7. भौतिक वस्तुएँ

ग्रामीण स्त्रियों की आर्थिक क्रियाओं को हम तीन भागों में बॉट सकते है –

1. गृह सम्बन्धी कार्य 2. कृषि सबन्धी कार्यो में संलग्न होना 3. मजदूरी और रोजगार के द्वारा जीविका चलाना ।

सामाजिक और आर्थिक घटनाओं का अध्ययन एक दूसरे के सन्दर्भ में किया जाता है क्योंकि समाजिक और आर्थिक पहलू एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखते है ।

उषा तलवार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि – ''भारत में स्त्रियों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है रही है । सम्पति में उनको अधिकार तो है परन्तु व्यावहारिक नहीं है । परिवार के प्रति व्यक्ति आय देखी जाय तो बहुत कम है ऐसा देखा गया है 98.5 प्रतिशत स्त्रियॉ दबाव के कारण कोई न कोई कार्य करती है।'' आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण समुदायो में देखा जाता है कि कृषि कार्यो के लिए बडे भूस्वामियों द्वारा महिला श्रमिकों का शोषण किया जाता है।

यद्यपि गॉवो में परिवार की आय में आधे से अधिक योगदान महिलाओं का रहता है परन्तु उनके

द्वारा किये गये काम को आर्थिक गतिविधियॉ मानने की बजाय सामान्य पारिवारिक दायित्व समझा जाता है।

महिलाएँ गृहस्थी के कार्य एवं बच्चों के पालन–पोषण के साथ–साथ ग्रामीण महिलाएँ, पशुपालन ईधन बटोरने, पानी लाने, और खेत खलिहान में भी काम करती है परन्तु इन सभी कार्यो को व्यवसाय के बजाय पारिवारिक कार्यो के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके विपरीत पुरूषों द्वारा दिये जाने वाले कार्य को व्यवसाय माना जाता है । बुवाई से लेकर कटाई तक खेती बाडी के सारे कार्यो में बराबर की भागीदारी होने पर भी महिलाओं को किसानो का दर्जा प्राप्त नहीं है। यह बिडम्बना ही है कि काम धन्धे में सतत् सक्रिय रहने पर भी महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः पराश्रित है।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को उच्च और विकसित करने में जो अधिनियम और एक्ट बनाये है उनका भी ठीक से पालन नहीं हो पाता है । इन सबके मूल में ग्रामीण श्रमिको और महिलाओं का असंगठित होना है ।

इस गतिरोध को तोडने के लिए महिलाओं को नए और परम्परागत व्यवसाओं की ओर मोडने की आवश्यकता है जिनसे अर्जित आय को भी महिलाओं की आय माना जा सके ।

ग्रामीण नारी की राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में महिलाओं ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें रानी कर्णवती, चॉद वीवी, रानी पदमिनी, जहाँ आरा, रजिया सुल्तान एक कुशल राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ थी ।

भारतीय स्वंत्रता आदोलन में रानी लक्ष्मीबाई, अंबतीबाई, देवी अहिल्लया बाई ने अपने युद्ध कौशल में अंग्रेजो को नाको चने चवाने को मजबूर किया था । वही मैडम भीकाजी कामा, अरूणा आसाफ अली, सरोजनी नायडू इत्यादि ने अपने बुद्धि कौशल से अंग्रेज और अंग्रेजियत दोनों को दंभित किया । स्वाधीनता के बाद भी भारतीय महिलाओं ने भारत में ही नही बल्कि विश्वस्तर पर भी अपनी छवि निर्मित की है।

विजय लक्ष्मी पंडित जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली अध्यक्षा बनी तो वहीं सुचेता कृपलानी सरोजनी नायडू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजनैतिक क्षेत्र में अमिट छाप छोडी है ।

संविधान (73 वॉं संशोधन) अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं के तीनो स्तरो पर (ग्राम पंचायत पंचायत समिति तथा जिला परिषद) महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है ऐसी व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं के एक तिहाई सदस्य तथा अध्यक्ष महिलाएँ ही होनी चाहिए ।

उपरोक्त संस्थाओं में सक्रिय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी निम्नानुसार है –

क्र.	संस्थान / पंचायत	अ.ज.	अ.ज.जा.	महिलाएँ
1.	ग्राम पंचायत	3,08,290	11,99,401	5,77,270
2.	पंचायत समितियॉ	18,797	8,479	37,611
3.	जिला पंचायत	1,714	1,165	2,516

तालिका से ज्ञात होता है कि भारत सरकार किस प्रकार ग्रामीण विकास में जन सहभागिता विशेष कर महिलाओं की समुचित सक्रिय सहयोग के द्वारा ग्रामीण समाज के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीति भागीदारी को तीव्र करने में कृत संकल्पित है।

निम्न तालिकाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी स्पष्ट होती है ।

तालिका क्र. 1

स्त्रियो के घर के कार्यो का विवरण

कार्य विवरण	आवृति	प्रतिशत
घर साफ करना	50	17.85%
सास ससुर की सेवा करना	42	15.00%
कढाई बुनाई सिलाई करना	20	7.14%
खाना बनाना	150	53.57%
अन्य	18	6.42%
योग	**280**	**100.00%**

ग्रामीण क्षेत्र में महिला कुल 280 उत्तरदाताओं के द्वारा उनके घर में किये जाने वाले कार्यो का विवरण पूछा गया जिस सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य सामने आये। घर में किये जाने वाले कार्यो को

कुछ मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया जैसा कि उपर वर्णित है। सारिणी से स्पष्ट होता है ग्रामीण अचंल में ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक भागीदारी कितनी अधिक है। वें अधिकांश समय गृहकार्य में संलग्न रहती है और सामाजिक भागीदारी निभाती है ।

तालिका क्र. 2

ग्रामीण महिलाओं का परिवार की आय में सहयोग

क्र.	आय में सहयोग	आवृति	प्रतिशत
1.	सभी कार्य	36	12.85%
2.	बोनी	1742	6.00%
3.	कटाई	3620	12.85%
4.	मजदूरी	58	20.71%
5.	बोनी एवं कटाई	36	12.85%
6.	निदाई कटाई पशुपालन	30	10.71%
7.	निदाई, गुडाई, कटाई	26	9.28%
8.	पशुपालन	32	11.42%
9.	भडारण	6	2.14%
10	अन्य कार्य	18	6.42%
	योग	**280**	**100.00%**

सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाऐं उपरोक्त प्रकार के कार्य करके परिवार के आय में सहयोग करती है और आर्थिक भागीदारी निभाती है।

तालिका क्र. 3

ग्रामीण महिलायों की राजनीतिक भागीदारी

क्र.	भागीदारी	कुल सीट	महिला
1.	सासद	1	00
2.	विधायक	4	01
3.	जिला पंचायत अध्यक्ष	01	00
4.	जिला पंचायत सदस्य	00	00
5.	जनपद पंचायत	144	72
6.	पंच	6635	3318
7.	सरपंच	461	231
	योग	**7260**	**3630**

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में 73 वे सविधान संशोधन द्वारा प्राप्त महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के आधार पर महिलाएं राजनीति में चुनी गई । ग्रामीण क्षेत्र में पंच जिला पंचारयत के कुल 15 पदो में से 8 पर महिला है जनपद पंचायत के कुल 144 पदो में से 72 पद पर महिलाए है पंच कुल 6635 पदो में से 3318 पद महिलाएं है सरपंच के कुल 461 पदो में से 231 पद पर महिलाऐं है क्योंकि यहां पर 50 प्रतिशत पद राज्य द्वारा महिलाओं को आरक्षित किये गये है क्षेत्र में सांसद का एक पद है परन्तु उसमे महिला निर्वाच्च नही है। इसी प्रकार विधायक के चार पदो में केवल 1 पद पर महिला निर्वाचित है । क्योंकि यहां आरक्षण नही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य द्वारा आरक्षित पदो पर ही महिलां भागीदारी है ।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि महिलाओं की भागीदारी आत्म विश्वास और स्वाभिमान पर आधारित है। समाज में सम्मान जनक स्थान पुरूष और महिलाओं की स्थिति में अंतर यू तो समूचे समाज में मौजूद है किन्तु ग्रामीण समाज में उनकी हालत विशेष रूप से काफी सोचनीय है। जहॉ शहरों में शिक्षा स माज सुधार आंदोलनों और प्रचार प्रसार के माध्यमो के प्रभाव से महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ीं है जिससे उन्हें कुछ हर तक समानता, स्वंत्रता, और सामाजिक व कानूनी अधिकार प्राप्त हुए है परंन्तु गॉवो में इसका बहुत ही हल्का असर हुआ है। ग्रामीण समाज में महिलाऍ परिवार और समाज के घोर शोषण का शिकार होती रहती है और उनकी, सामाजिक, पारिवारिक आर्थिक राजनैतिक भागीदारी को नकारा जाता है ।

स्पष्ट है कि पुरूष प्रधान समाज व शासन प्रशासन में मात्र कानून नये अधिकारो की स्थापना से ही सशक्तता नही की जा सकती बल्कि इसके लिए परिवारों में ही महिलाओं के प्रति संकुचित दृष्टिकोण को व्यापक उदार बनाने पर बल दिया जाना चाहिजए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी के लिए अधिकारों के साथ–साथ स्वंत्रता व समानताओं को भी अपनाना होगा। इसके लिए महिलाओं को निर्णय लेने, नीति निर्धारण करने जैसी समस्त प्रत्रियाओं में स्वयं को शामिल करने की नितांत आवश्यकता है ।

संन्दर्भ सूची –

1. एवलिन सुलेराट – ''ओमेने सोसायटी एण्ड जेंच'' वर्ड यूनिर्सिटी लाइब्रेरी लन्दन 1971
2. अर्थववेद – 11/15, 118
3. रिचार्ड एच.हाल. ''ओफोपेसन्न एण्ड सोशल स्ट्चर'' पी. हाल 1969
4. रगीला नंदनी – द पैराडाइक्स इन क्वेलिटी 1984
4. उषा तलवार– सोशल प्रोफाइल ऑफ वर्किंग बूमेन वारसनी प्रिटिंग प्रेस दिल्ली 1984

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

पर्यावरण प्रदूषण एवं शहरीकरण

डॉ. (श्रीमति) सुधा भोला
सहायक प्राध्यापक, पी.डी. अंजुमन इस्लामिया महिला महाविद्यालय गोहलपुर, जबलपुर म.प्र.

पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली सतस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग हैं इसे हम जीव मंडल भी कह सकते है जो जल मंडल स्थल मंडल वायु मंडल आदि भागों का योग होता हैं।

जीव मंडल में जीवन की शुरूवात विकास एवं विलुप्त होना इस तथ्य पर निर्भर करता हैं कि प्रक्रति का वातावरण के साथ कितना सामंजस्य हैं।

पर्यावरण में ऐसे समस्त सामाजिक जैविक तथा भौतिक या रासायनिक कारकों का योग होता हैं जो मानव के परिवेश से संबंधित होते है। मानवीय वातावरण का प्रत्येक तत्व एक संसाधन के रूप में होता है जिसको मानव द्वारा उन्नत्व जीवन स्तर जीने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता हैं।

इस प्रकार पर्यावरण को दो बडे भागों में बाँटा गया है प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण भौतिक वातावरण से तात्पर्य प्रकृति को बनाये कारकों से हैं जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण हैं। जिसका निर्माण मनुष्य से दूर है जो प्रकृति द्वारा उपहार रूप में मिला है वह सब भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है जैसे–: सूर्य, ताप, ऋतु परिवर्तन भूकम्प ज्वालामुखी जीव जंतु आदि।

सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित प्रभाव को रखा जाना है जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है जैसे–: भवन, मार्ग शहर, परिवहन संचार, उद्योग व्यापार आदि। सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण के कारकों से पूरी तरह और कहीं आंशिक रूप से प्रभावति है जैसे–: अति नगरीय अधिक औद्यागिक जनसंख्या घने क्षेत्रों में पर्यावरण भौतिक पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते है। ऐसे क्षेत्रों में वायु, जल, मृदा आदि भौतिक पर्यावरण के तत्व अपना स्वाभाविक रूप खोकर प्रदूषित होने लगते है फिर भी भौतिक वातावरण की ही सबसे अधिक सत्ता है तथा भौतिक वातावरण का वर्चस्व ही मानव जीवन के लिये व विकास के लिये अनुकूल है। इस प्रकार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु या मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।[2]

पर्यावरण के किसी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है प्रदूषण कहलाता हैं। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया तथा आधुनिकता का महत्वपूर्ण योगदान है।[3] सभी जीवधारी अपनी बुद्धि विकास व सुव्यवस्थित रूप से जीने के लिये संतुलित वातावरण पर निर्भर रहते ह। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक कम या अधिक हो जाता है तो जीवधारियों के लिये हानिकारक होता है। प्रदूषण वायु, जल, भुमि की भौतिक, रासायनिक जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और इसके लिये लाभदायक दूसरे जंतुओं पौधो औद्योगिक संरचाओं को किसी रूप मे हानि पहुँचाता है जहाँ भी मानव ने अपने आस पास फैले प्राकृतिक पर्यावरण को तोडा है वहाँ प्रदूषण की समस्याओं ने जन्म लिया है।

पर्यावरण प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा नाभिकीय प्रदूषण।

विश्व की जनसंख्या ने प्राकृतिक साधनों का अधिक उपयोग किया है औद्योगिकीकरण से बड़े–बड़े शहर बंजर बनते जा रहे है इन शहरों व नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इससे शहरों में आवास समस्या उत्पन्न हो गई है। इस आवास समस्या को सुलझाने के लिये नागरिको ने बस्तियों का निर्माण किया वही पर जल निकासी आदि की मुत्वित व्यवस्था न होने से गंदी बस्तियों ने वायु प्रदूषण को बढावा दिया उद्योगों से निकलने वाला धुआँ, कृषि रासायनिक उपयोग से भी वायु प्रदूषण बढ़ा हैं। यातायात के साधनों में बहुत वृद्धि हुई है पौधे हानिकारक प्रदूषण कार्बन डाईऑक्साइड को अपने भोजन के लिये ग्रहण करने है और जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।

जल ही जीवन है इसकी सच्चाई में अगर हम विश्वास करते है तो जलीय पवित्रता का दायित्व भी

हमारा ही है। पिछले दशकों में विश्व की जनसंख्या में अधिक हुई वृद्धि शहरी जीवन जीने के प्रति ललक तथा विकास के नाम पर जल में बहाई जाने वाली गंदगी की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोडकर निश्चिन्त हो जाते है परिणामस्वरूप समुद्री जल का बहुत बडा भाग सभी नदियॉ आज जीव व संसार के लिये जीवन की सरलता नहीं बल्कि मौत की कठोरता को लेकर बह रही हैं। जल प्रदूषण का कारण कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अपशिष्ट पदार्थों की नदियाँ नहरों तालाबों आदि का किसी अन्य स्त्रोतों में बहा दिया जाता है जिससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही जल पीने योग्य नहीं रह जाता और जल प्रदूषित हो जाता है। जल में मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थ गर्म, जल, स्त्रोत को दूषित करने के साथ–साथ वहाँ के वातावरण को भी गर्म करते है जिससे वहॉ की वनस्पति व जंतुओं की संख्या कम होने से समुत्वित पर्यावरण असंतुलित हो जाता हैं।

भूमि जिस पर हमारा और अन्य जीवों का आवास और भोजन निर्भर करता है। प्रदूषण और भू उत्खनन से लगातार प्रदूषित होती जा रही है। घरेलु अपशिष्ट नगरपालिक अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट कृषि अपशिष्ट औद्याकगिकीकरण शहरीकरण जनसंख्या घनत्व में वृद्धि आधुनिकीकरण जैसे कारण है। जो भूमि को नष्ट कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट के रूप में उद्योगों से निकलने वाला जिंक, तांबा, सीमेन्ट, चूना, फैक्ट्री से निकला मलबा आस पास की भूमि को नष्ट कर रहा हैं।

मानसिक या शरीरिक रूप से आघात पहुँचानें वाली किसी भी प्रकार की अनचाही आवाज से संपर्क ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण का सीधा संबंध मानव के आधुनिक क्रियाकलापों की प्रधानता विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्रों में लाउड स्पीकरों व बैंड बाजों की अधिक आवाज से रेडियो टेलीविजन चल चित्रों तथा आण्विक विस्फोटो से उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है।

जब किसी परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है तो असंख्य रेडियोएक्टिव कण वायुमंडल से दूर–दूर तक फैल जाते है कणों का बहुत धीमी गति से विघटन होता हैं। रेडियों एक्टिव परमाणु नाभिक से अल्फा, बीटा गामा किरणें निकलती है इनमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा होती है रेडियों धर्मी की किरणों से डी. एन. ए. की बिगड जाती है। डी. एन. ए. में परिवर्तन के कारण अगली पीढी में कई जन्म दोष हो जाते हैं।

भारत में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने सामाजिक रीतिरिवाजों और निवेश को बहुत हद तक कम किया है सामाजिक मूल्यों में गिरावट आयी है। नगरों में सांस्कृतिक परिवर्तन शिक्षा उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीक आदि ने ग्रामीणों के सामाजिक जीवन में काफी परिवर्तन किया है साथ ही शहरी नागरिक के संपर्क और प्रभाव का ग्रामीण नागरिक पर दुष्प्रभाव भी पडा हैं।[9]

''शहरीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण का घनिष्ट संबंध है जिसमें तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे अधिक दुष्प्रभाव डालती हैं। निवास व स्थान की समस्या खडी हो गई जंगल काटे जा रहे है मानव की आवश्यकताओं मल मूत्र आदि पर्यावरण को प्रभावित करने ही है साथ ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगाये जा रहे नये–नये उद्योग चिमनियों से निकलने वाला धुआँ पर्यावरण को अधिक प्रभवित कर रहा हैं। जनता का अशिक्षित व गरीब होना भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण हैं। भारत के कुल 750 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 23 प्रतिशत है। जबकि पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कम से कम 33 प्रतिशत वनों का होना अनिवार्य है इसके बावजूद पेड़ों की अधिक कटाई पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है।''[10]

''मनुष्य विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण दे रहा है। प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य साधारण जनता को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक निम्नतम वस्तुओं को उपलब्ध कराना था किन्तु अब प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्राकृतिक साधनों का तीव्रगति से विदोहन करना तथा मानव समाज के भौतिक स्तर को बढ़ाने के लिये इन संसाधनों से अनेक प्रकार के उत्पादन करना है।

मानव ने वैज्ञानिक तकनीक प्रौद्योगिकी अधिक उत्पादन करने वाले बीज उत्पादन उपभोग में वृद्धि ने कृषि का विस्तार व विकास किया है। जनसंख्या बढ़ने के कारण मांग पूर्ति तो बढ़ती गई परंतु साथ–साथ पर्यावरण समस्या को जन्म मिला। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है

वहीं दूसरी ओर इससे उत्पन्न समस्याओं से निपटने के उपाय करना भी आवश्यक है।

इस समय प्रति मिनट लगभग 100 एकड़ जंगल काटे जा रहे है जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां जिससे विलुप्त होती जा रही है। जंगलों के काटे जाने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा गंधक की मात्रा बढ़ रही है। आक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बड़े बांधों के निर्माण से उसके आसपास की जमीन दल–दल में बदल जाने की चेतावनी भू–गर्भशास्त्रियों ने सरकार को दी है। मोटर गाड़ियां बिजली घरो कारखानों आदि से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो वायु को प्रदूषित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। शहरों में कारखानों की मशीनें लाउंडस्पीकर विमान रेलगाड़ी से उत्पन्न ध्वनि, शोर प्रदूषण के लिये जिम्मेदार है जिससे श्रवण शक्ति के ह्रास व नींद की कमी की समस्या सामने आती है। इस प्रकार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता है। शहरीकरण का प्रभाव प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक पर्यावरण पर अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों ही प्रकार से पड़ता है। यह अधिक मात्रा में प्रतिकूल होने के साथ–साथ अल्पकालीन व दीर्घकालीन भी हो सकता है।[11]

''चाहे वह भू–प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण अथवा जैविकी वनस्पति या मानव प्राणी से संबंधित हो अनेक बार इन प्रदूषण के निवारण हेतु पर्यावरण को पुनः स्थापित करने के प्रयास किये गये उससे शहरों में कुल मिलाकर जो प्रभाव पड़ता है उससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है।

नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में असीमित वृद्धि मलमूत्र तथा अनुपयुक्त पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है जिससे नगर प्रशासकों को कूड़ा करकट एकत्रित करने उनको उपयुक्त स्थान पर एकत्रित करवाने तथा उन्हें प्रबंध करने की समस्या सामने आने लगी है। भारत के महानगरों एवं शहरों में आवास की समस्या अधिक है। विगत चालीस वर्षो से जिस गति से महानगरों की जनसंख्या की वृद्धि होती आयी है उसकी तुलना में आवासीय सुविधा मंदगति से बढ़ रही है। परिणामस्वरूप शहरी जनसंख्या अमुप्रदत्त आवासों और मलिन बस्तियों में रहने के लिये बाध्य है।

इस प्रकार शहरीकरण का परिणाम गंदी बस्तियों के रूप में देखा जा सकता है। स्लम बस्तियों का पर्यावरणीय प्रभाव व आंकलन किया गया है।[12]

संदर्भ–सूची :

1. पर्यावरणीय अध्ययन का अनुशासनिक स्वरूप : 2004 प्रथम संस्करण पृष्ठ 1,2
2. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय अध्ययन–प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल 2008–10 पृष्ठ 2,3
3. हरिशचंद्र व्यास, जनसंख्या प्रदूषण और पर्यावरण मार्च 2004
4. पर्यावरण प्रदूषण : म.प्र. हिन्दी अकादमी पर्यावरण चेतना पृष्ठ 153
5. ''जनसंख्या प्रदूषण और पर्यावरण : मार्च 2004 पुस्तक क्र. 2571
6. पर्यावरण प्रदूषण पृ. 180–182
7. जनसंख्या प्रदूषण एवं पर्यावरण हरिशचंद्र व्यास मार्च 3, 2004
8. समाज शास्त्र नगरीय विकास ''प्रो. एम.एल. गुप्ता एंड डी.डी.शर्मा 2010, साहित्य भवन पब्लिकेशन बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर
9. मोर्या साहबवीन, शहरीकरण की विशेषताएं, कूछ पब्लिकेशन, इलाहाबाद
10. पर्यावरण प्रदूषण समाजशास्त्र डा. बघेल, पुष्पराज प्रकाशन, रीवा 1996– पृष्ठ 251–252

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

GENDER EQUALITY : ROUTE TO EMPOWERMENT

Smt. Devi Krishna yadav Prof.
Deptt. Of sociology, P.D. Anjuman Islamia Girl's college Gohalpur Jabalpur
Dr. Priti Bala Mishra
Deptt. of sociology Govt. M.K.B. college Jabalpur

Women and Gender issues are center relevance of social work. Education al practices, seminars , conferences and workshop. Recently emerged and developed concern for women has stirred a major discourse in fast developing contemporary Indian society. So far women were marginalized in all development programs, of late she is being recognized in her owe worth. There have been glorious achievements and improvements in terms of status of women but on the other hand society still paints a very distressing picture of girl child. Sex discrimination is crystal clear in spite of cracking up of patriarchal system. Examples of women succeeding in a man's world is auspicious signal but the bulk of women hood is still backward Discrimination holds women back .At present empowerment of women through gender equality has received high priority by Indian planners . Sex ratio in our society is strictly in favors of males. This confirms son preference and female foeticide has reached an alarming level.

The root of gender inequality :

The practice of gender bias among children is widely prevalent in our society with some change in its form. The reasons behind what has been called 'son mania' are both multifaceted and deep imbedded in Indian culture. Son is a preferred for maximizing several economic and non economic activities such as contributing to family's resources by working in the family in the village factional politics and so on. Some superstitious beliefs related to salvation also added strength to gender disparity.

Women empowerment an overview :

The social and economic prosperity of every society depends on the development of both gender women today are not given the same opportunities as men, thus constitutes a neglected section of society. Girls and women face inequality lead a healthy and productive lives across the Indian sub continent, it is long been a matter of shame in modern society that gender bias begins when the foctus is in mother's womb itself. Empowerment will certainly reduce gender disparity.

Empowerment approach towards women's issue is considered best. Empowerment of women, is here interpretated to mean total empowerment including political economic, social, legal, and cultural aspects of human life. Griffen for instance, defines women's empowerment as adding to women's power. Empowerment of women is not about power over others but power to make decisions and power to achieve economic goals and ends, Economic independence along is not likely to bring her on pre with man. Decision making power is key fartoe of women empowerment which begins with improvement in economic position of women. Low status of women stems from their low economic position which is largely due to high levels of illiteracy and patriarchy eradication of gender bias and ignorance as well as participation women reduce the age old atrocities against her. Among the many pillars on which empowerment rest is the gender parity. Concrete instead of action are required to tackle the problem of discrimination which leads to female foeticide.

STRATEGIES :

Gender inequalities are institutionalized and systematized in a regular form .Its eradication is herculean task If not impossible Efforts to strengthen gender equality requires following remedial measures at different levels with sincere and honest approach –

1. Special care for education – Urgent steps should be taken for compulsory education of girls. Education women can manage her Multitasking responsibility at home and work place with great efficiency. Literacy and education is a powerful medium of empowering women. Technical, professional, job training programs should be incorporated into curriculum.

2. Role of media – press and electronic media should emphasize gender awareness generation programs to discourage gender discrimination. It should expose the unethical practice of gender bais, female foeticide to make people conscious about atrocities and exploitation against women.

3. Attitudinal change – there is a need of bringing about in harmful mind set of discriminatory practices. Efforts should be made to influence public opinion regarding the importance of a girl child. Small family norms should be promoted effectively on voluntary basis. Women have to change their attitude about themselves. Improvement in professional skills morals and performance level will lead to confidence and esteem amongst women. Dowry system deters the birth of a girl child should be eliminated from should be eliminated from society.

4. Welfare measures gender equal society can be developed by protecting and providing old age parents with various welfare schemes such as pension, insurance, health plan old care homes women focus polices should be drawn.

Gender gaps are man and therefore can be altered by gender specific policies, adequate support system and positive mental setup. Last but not least is the awareness which is the first step towards concrete change of empowerment.

Conclusion : Today women are making mark in almost every aspect of life, but ours is a very stratified society. Ages old phenomenon of women's subordinates still persists in society. Denial of educational facilities process of exclusion, lack of access to gainful economic activities is the challenges to be faced by Indian women with courage and discrimination. The patriarchal ideology has recognized gender as a tool of discrimination and inequality. Women have been relegated to secondary roles. In the journey of empowerment, to ensure equal rights and opportunities for women, attention has been shifted from welfare, development to equality.

Now it is time for action not debate. Society has to formulate a vision for setting gender relation on an even level. True empowerment can only occur with an integrated approach to promote women issue. To achieve the goal of gender parity effort will e more effective if organized and property coordinated jointly at government and non government levels.

To conclude, women have not come up in a big way not because of la ck of skills but mere due to cultural and gender biases. High status and importance given to male child across the country has increased female foeticide.

Empowerment of women is a shared responsibility of individual and shared responsibility of individual and society. Man woman and government both central as well as state should consciously make adjustments too the policies they promote and pledge to end gender discrimination. Instead of wasting time on symbolic events which h will have no real impact and will be reduced to mere ritual we must take the campaign against female foeticied by adopting sustainable programs and concrete plan of action.

References :

1. Jeffery R, Jeffery P. 1984 "Female infanticide and amniocentesis." Social science and medicine .19(II) : 1207-12.
2. Ramanamma A , Bambawale U.1980 . "The mania for sons: analysis of social values in south Asia. "social science and Medicine, 14B(2):107-10
3. Sociological bulletin 49-52 Nos.
4. Social Welfare VoL. 51, 52, 53.
5. Times of India various editions.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

सामाजिक क्रांति चेतना के संवाहक 'श्रीकृष्ण' ('महासागर' के संदर्भ में)

डॉ. (श्रीमती) श्रीकान्ता अवस्थी
प्राचार्य, पी.डी. अंजुमन इस्लामिया महाविद्यालय, जबलपुर

परम्परा और इतिहास की रचना काल चक्र अनवरत गतिमान है। उसकी गतिशीलता के अनेक प्रस्थान हैं, जो शाश्वत हैं और जिनकी कोख से निरन्तर नूतन विचारधाराएँ जन्म लेती हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है। इतिहास और पुरणा उसके स्त्रोत हैं, और साहित्य उनसे प्रेरणा लेता हुआ, कुछ ऐसा सृजित करता है, जो परम्परा में विच्छिन्न होते हुए भी उससे विच्छिन्न नहीं होता। साहित्य की नूतन भावविधि, कलाविधि में कहीं न कहीं स्रोत की अंतर्धारा प्रवहमान रहती है। नरेन्द्र कोहली ऐसे ही कथाकार हैं जिन्होंने पौराणिक पुनलेखन के द्वारा नयी विचार क्रांति और युगीन यथार्थ की अलख जगाई है। इसी रूप में उन्होंने महाभारत को उपन्यस्त किया है। महाभारत के व्यापक गूढ़, जटिल कथानक को कोहली ने नई उपन्यास शिल्प संरचना से सॅवारा। उसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र की पुष्टि है, वैचारिक संधान और अंतर्द्वन्द्व है, सार्थक कल्पना की रंगीनी है। कथानक के मूल तत्व कौतूहल के माध्यम से उपन्यास के कहानीपन को संजोते हुए व्यक्ति समाज और काल के विश्लेषण महासमर उपन्यास को मील का पत्थर बनाते हैं।

नरेन्द्र कोहली ने मानवीय मूल्यों का रचाव एवं भावबोध को संवेदनीयता के साथ–साथ नैतिक अनुशासनों के प्रतिबद्ध करने का प्रयास किया है। 'महासमर' के पात्रों के चरित्र–चित्रण को मनोविश्लेषणात्मक धरातलपर प्रस्तुत करने में कोहली से सफल रचनाकार के रूप में सामने आते हैं। इसी श्रृंखला में 'कृष्ण' का चरित्र अत्यन्त बुद्धिमान, प्रतिभावान, प्रज्ञावान एवं अद्भुत प्रकाश पुंज के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कृष्ण मानवता के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में प्रतिबिम्बित हाते हैं।

''धर्म मानवता के हित में होता है। प्रकृति के अनुकूल चलने में होता है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में होता है।..... मनुष्य का जीवन धर्म स्थापना के हित में आए। अधर्म की रक्षा के लिए इस शरीर को बचाये रखने का क्या लाभ ?''1

(महासमर भाग 07 नरेन्द्र कोहली प्रत्यक्ष– पृ. 15–16)

नरेन्द्र कोहली ने कृष्ण को ही धर्म माना है। ''कृष्ण' को त्यागने का अर्थ है प्राणों को त्यागना, धर्म को त्यागना।''2

(महासमर भाग–7, प्रत्यक्ष पृ.134)

सामाजिक क्रांति चेतना के संवाहक ''श्रीकृष्ण'' निरन्तर कर्मशील, आसक्तिरहित, धर्म मर्मज्ञ उन सभी मनुष्यों के हितैषी जो वंचित शोषित एवं पीड़ित हैं। सारा 'महासमर' कृष्ण के कर्मबंधनों और धर्म की ओर से बंधा हुआ है। धर्म कर्म का अटूट बंधन है 'महासमर' जिसको जोड़ने वाले हैं, श्रीकृष्ण। सारा संचालन श्रीकृष्ण के माध्यम से ही हुआ है।

कृष्ण भीष्म से हते हैं– ''जिस व्यक्ति, संगठन मत और विचार से मानवता में दरारें डाली हैं, उनका विभाजन किया है। मनुष्य को तुच्छ बनाया, उसके हृदय को संकीण किया। महान् वे ही लोग हैं पितामह! जिन्होंने मानवता के बीच बनाई गई कृत्रिम दीवारें तोड़ी हैं, उसके मध्य की खाइयॉ पाटी हैं। वे वास्तविक मानव हैं, सृष्टि के तुल्यरूप प्रकृति के समान विराट।''1

(महासमर भाग 2 अधिकार नरेन्द्र कोहली पृ. 372)

नरेन्द्र कोहली के पाण्डवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर का चरित्र 'महासमर' में मूर्तिगत, प्रजापालक, सत्व गुण प्रधान धैर्य, स्थरता, सहिष्णुता, विनम्रता, अविचल प्रेम आदि महान गुणों से परिपूर्ण बताते हुए अनेक विषम परिस्थितियों में भी धर्म के पक्ष में खड़ा पाया। सम्राट के जो पॉच गुण होने चाहिए, शत्रु विजय, प्रजा पालन, तप, शक्ति, धन समृद्धि तथा उत्तम नीति ।''2

(महासमर भाग 4 धर्म पृ. 304)

एक ओर जहॉ युधिष्ठिर एकता का मूल्य चुकाने के लिए वह राज्याधिकार भी छोड़ देने में संकोच नहीं करते । वे अपने स्वार्स्थ के लिए मावता का अहित नहीं कर सकते वहीं दूरी ओर सामाजिक क्रांति चेतना संवाहक के रूप में श्रीकृष्ण नवीन दिशा व गति प्रदान करते हैं। कृष्ण मानवतावाद की स्थापना के लिए संघर्षरत प्रतीत होते हैं। उन्होंने अधर्म, शोषण, अत्याचार तथा अन्याय के विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक युद्ध को नैतिक धरातल पर स्थापित करने का प्रयास

किया। कोहली ने व्यक्तिगत तत्व की बजाय समष्टितत्व को प्रधानता दी है।

श्रीकृष्ण सामाजिक क्रांति चेतना पाण्डवों में जगाते हुए कहते हैं अन्याय–अधर्म के विरूद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं–

''धृतराष्ट्र के मनमाने नियमों में बॉधकर आपका सर्वस्व हरण कर लिया और कृष्ण का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। आप यह सब देखते रहे और समझते रहे कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अतः धर्म आपकी रक्षा करेगा। नहीं धर्मराज ! यह धर्म नहीं है। मैं वहॉ उपस्थित होता तो दूत को रोक देता, चाहे मुझे बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़ता । वे न मानते तो मैं सारे धृतराष्ट्रों का वध कर देता इस प्रकार अपमानित और वंचित होना धर्म नहीं है।''1

(महासमर भाग 5 – अंतराल पृ. 95)

उसी क्रांति चेतना को और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं– ''मैंने अपने प्रति उनका अपमान क्षमा किया है, समाज के प्रति उनके अपराध क्षमा नहीं कर सकता। धर्म के प्रति निष्ठा किसी भी व्यक्ति के प्रति निष्ठा से महान है।''2

(महासमर भाग 4 धर्म पृ. 213)

नरेन्द्र कोहली ने मानव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए मानवाधिकारों से वंचित, पीड़ित, त्रस्त जनसामान्य के हित में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 'महासमर' उपन्यास का सृजन कर पात्रों के माध्यम से श्रीकृष्ण को सामाजिक क्रांति चेतना का अग्रदूत बनाया तथा युधिष्ठिर द्वारा राजसूर्य यज्ञ में उन्हें अग्रपूजा के लिए आमंत्रित किया जिन्होंने शिशुपाल जैसे– अन्यायी, अधर्मी राजा का मस्तक काटकर धर्म स्थापना के प्रथम चरण दुष्ट दलन को पूर्ण किया तथा धर्म स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार जब कौरव पाण्डव का युद्ध हो रहा था तब युधिष्ठिर और अर्जुन हताशा–निराशा से भरे हुए मोहजाल में फॅसकर युद्ध विरत हो रहे थे तब श्रीकृष्ण अकेले युद्धरत रहे और अंत में अर्जुन को ही उन्होंने दिव्यदृष्टि प्रदान कर युद्ध के लिए पुनः प्रेरित किया। महाभारत के सूत्रधार और 'महासमर' उपन्यास के सामाजिक क्रांति चेतना के संवाहक श्रीकृष्ण ही थे। जिनके माध्यम से नरेन्द्र कोहली ने अपने चिन्तन एवं सामाजिक दृष्टिकोण को नया आयाम प्रदान किया। आधुनिक वैचारिक पष्ठभूमि प्रदान कर तर्क, बुद्धि की विश्वसनीयता एवं मनोकल्पना द्वारा जीवन्त रूप प्रदान किया है।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Tagore and the Tradition of the Gitanjali

Dr. Anju Pathak
Asst. Prof., S.G.T.B. Khalsa College, Jabalpur

Background of the Study

1.1 **Tagore and the tradition of the Gitanjali** :- Tagore is the first great Indian poet of the modern age and perhaps the greatest Indian poet of the twentieth century. Tagore himself was always aware of, and proud of, the literary and spiritual tradition to which he belonged and which he rein forced and renewed by the force of his own genius. The influence of the Brahmo movement on Tagore's Gitanjali is evident from the title of his collection of songs. Tagore was the first to collect the songs of the Bauls into an anthology. Tagore's literary work shows how Indian and Western literary traditions could bend seamlessly to create something of universal relevance. Tagore uses the images common to classical Indian love-poetry to symbolise his yearing to merge with God.

1.2 **Tagore's Gitanjali** :- The poems in the Gitanjali are usually divided by readers into nine groups. Each poem in a group has its individual beauty, melody and significance. The first group (1 to 7) deats with immensity of God's gifts. The second group of poems 8 to 13 describes where God can be found. The third group (14 to 27) the poet's intense yearing to unite himself to God. The obstacles in the way of meeting God the loved are many, describe in group of poems (28 to 36) fifth group (37 to 56) expresses poets faith in God's infinite love. sixth group (57 to 69) unending joy of perfect union milk God through images of Nature. In the next group (70 to 80) poet suggests that it is not man alone who feels fulfilled this ecstasy but God also shares gladness. The fear caused by Maya is the theme of the group comprising poem (79 to 84) the theme of last nineteen poems (85 to 103) is death, which releases the Soul.

1.3 **Sri Aurobindo and this Tradition** :- Sri Aurobindo wrote devotional, religious and philosophical verse that was at once basd on Vedic and Vedantic thought and deeply influenced by Western literary and spiritual tradition.

If on the one hand his work belongs to the long tradition of Vedic and Vedantic inspired poetry, because of his upbringing and education it was largely Western in inspiration. The sonnet itself is a European literary form. It was introduced into India by Michacl Madhusudan Dutta and Derozio was the first Indian poet in English, was also the first Indian to write Sonnets in English Sri Aurobindo was the second Indian atter Derozio to write Sonnets in English.

1.4 **Sri Aurobiondo's Sonnets** :– Sri Aurobindo's sonnets, however, were written individually, at various times in his life, and were later put together by editor in collected edition of his works. The editor of the centenary edition of the collected poems of Sri Aurobindo (1972) has grouped them together in volume V and has classified them according to chronology : Early period (1890-92), Sonnets (1930-1950) and Sonnets (Undated). There are seventy three Sonnets in Sri Aurobindo's Collected Poem.

Review of Related literature :

Gupta, Nolini. Seer poets Rabindranath and Sri Aurobindo. The Modern Review July 1928 (www.search forlight. org/.... Rabindranath 20 and 20 Sri Aurobindo.htm).

Both had the vision of a greater Tomorrow for their mother land and that was why both regarded her freedom as the basic necessity for the recovery of her greatness Sri Aurobindo retired from the outer political, world to devote himself more intensively to the discovery and conquest of a new consciousness and force, glimpses of which he was having at the time and

which alone could save mankind. In five major sequences published month after month through several years, he envisaged, in the main progressive march of man towards a divine life or earth towards the unity of mankind and a perfect social order. Sri Aurobindo hailed those who feel and forsee this distant dawn behind the horizon as the fore runners of the new spirit, among whom he included Rabindranath, because he saw in Tagore's the first beginning "a glint of the greater era of man's living".

Mc Dermott, Robert A. The legacy of Sri Aurobindo, Cross current Vol. XXII, No 1, winter, 1972, SBN 0-940262-22-3

In the following excerpt, Mc Dermott compares Aurobindo's career with those of Rabindranath Tagore, Mohandas Gandhi and others in an effort to determine his place in the modern Indian philosophical tradition. Of the four great exponents of modern Indian idcals, Rabindranath Tagore Mahatma Gandhi, S. Radhakrishnan, and Sri Aurobindo at least understood in both India and the west is surely the political revolutionary, poet and philosopher of pondicherry, Sri Aurobindo Ghose 1872-1950. If the first half of the century belonged to the first three figures, the last half (dating from his death in 1950) or, more certainly the last quarter (dating from the centenary of his birth, August 15, 1972) will belong to Sri Aurobindo.

Roy, Choudhary Roy. The Dancer Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo's All Shall be Might and bliss and happy force Savitri Book VII, Canto IV 15 Aug. 2010.

On 15th Aug. 2010 or one eve of Sri Aurobindo's birthday and India's independence Day, wanted to share this consciousness Analogue on Rabindranath Tagore's painting. The Dancer which has the symbolic force of the role of the Divine Mother in Savitri Tagore is closer to the new scientific truth involving Consciousness and its connection with Quantum Physics that describe. Art critics are talking about the history and the value of these paintings and their artistic value of these paintings.

Both had the vision of a greater Tomorrow for their Mother and that was why both regarded her freedom as the basic necessity for the recovery of her greatness Sri Aruobindo retired from the outer political world to devote himself more intensively to the discovery and conquest of a new consciousness and force, glimpses of which he was having at the time and which alone could save mankind. In five major sequences published month after month through several years, he envisaged, in the main, progressive march of man towards a divine life on earth towards the unity of mankind and a perfect social order. Sri Aurobindo hailed those who feel and forsee this distant dawn behind the horizon as the forerunners of the new Spirit, among whom he included Rabindranath, because he saw in Tagore's the first beginnings "a glint of the greater era of man's living".

CONCLUSION :- The purpose of this research work has been to compare Rabindranath Tagore's Gitanjali and Sri Aurobindo's Sonnets, as short religious or philosophical lyres.

Tagore's Gitanjali, like all his poetry, has received considerable literary and critical attention all over the world. As is well known, he received the Nobel Prize for literature in 1913 for this collection devotional poems. He almost equally famous at least in India, contemporary Sri Aurobindo, was like him a Bengali Brahmo and a product of the great Indian Renaissance of the mid-nineteenth century. But when Tagore's entire literary corpus is read, analysed and discussed. Sri Aurobindo the poet is known primarily in India, and for Savitri rather than for his other poetry. His Sonnets, certainly, have seldom been examined as short religious and philosophical lyrics in their own light. It is hoped, therefore that this comparison will encourage greater critical attention upon these spiritiral and philosophical lyrics.

References :-

1. Ram, Atma, Sri Aurobindo Sonnets. A Thematic study Morality in Tess and other Essays : In Honour of Mulk Raj Anand 1995-1996.
2. Tagore, Rabindranath, Gitanjali Macmilln Indian Ltd. 2003. Print.
3. Sonnet, A Gvide to the Sonnet (http://wwwutm.edu/department.html) Web.
4. Sonnet. The free Encyclopedia wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia)

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

Pandita Ramabai : Pioneer of Women's Empowerment in India

Dr. Satarupa Pal
Assistant Professor in Political Science, Rampurhat College, Birbhum

Pandita Ramabai is one of the pioneers of women's empowerment in India. She raised her voice against gender inequality in India and desired to form a free and gender inclusive society in future India. She is strong leader with a clear vision. Her talent is multifaceted. She considered to be a social reformer, an erudite Sanskrit scholar. She devoted her life working for upliftment of women. She has been challenged lifelong patriarchal norms and made commitment to establish gender just society in India. Pandita Ramabai's name stands out as important figure in nationalist and colonial debates in 19th century India. She is remembered for breaking several caste, religions and gender boundaries for her work as a social reformer, for giving hope to many , 'fallen' widows in 'Mukti Mission', the home that she established in 1889, for her great reputation as a Sanskrit scholar and poet, for her pioneering work in education, and translation of her work are still relevant(Dyer 2004; Ramabai 1992; Sengupta 1970). Her voice and contribution to the debates on nationalism, colonialism and the politics of gender in the late 19th century are the essential elements to redefine women and democracy in India. Celebrated scholars like Uma Chakraborty and Meera Kosambi have viewed that the colonial and patriarchal contexts for the emergence of Ramabai's feminist consciousness, her conversion to Christianity, her personal aspirations, her international travels and her social contributions at the expense of alienating mainstream Hindu society and some noted social reformers. Apart from that , she also establishes the relevance of Ramabai's fight for gender just to contemporary societies, globally.

Devotion for the cause of women :- Ramabai Dongre was born into high caste Hindu family. Her father was a professional recite of Hindu epic and mythological texts. After her parent's death in the 1874 famine, she and her brother continued the family tradition. Going to Calcutta in 1878, the titles 'Pandita' and 'saraswati' were bestowed on her as an acknowledgement of learning. Later on she joined the Brahmo Samaj and in June 1880 married a man of much lower caste than hers. Her only child, Manorama, was born in April 1881. In 1882 her husband died of Cholera, leaving her in the unenviable situation of a high caste Hindu widow.

Through influence of Nehemiah Goreh's apologetical writings she became intellectually convinced that whatever was true in Brahmo theology was actually Christians in origin, and in 1883, during a visit to England, some of whose members she had met in Poona (Pune). She was in Europe to purse a medical degree, which in the end her deafness made impossible. From 1883 to 1886 Ramabai was lecturing and studying social reform and education. In 1887 she published her first English book, **the High-Caste Hindu woman** presented terrible condition of Hindu women from their community. In other words, this book Ramabai reviewed the treatment given to Hindu women throughout in her life.

It is noteworthy that Ramabai believed that education can uplift women's status in India. She was the first introduce the kindergarten system of education in India and also pioneer to a vocational bias to give school education in India. The curriculum of Ramabai based on unique-literature, attributing morality and sensitivity among the pupils. "Physiology and biology was incorporated in the system to incalculate adequate knowledge about the bodily anatomy and the natural world around us".(" Insight into Child Theology through the Life and Work of

Pandita Ramabai paper for Oxford Centre for Mission Studies" Tuesday, 31 st October, 2006).

However, Ramabai writings presents the low status of women in both the philosophy and the practice of Hinduism, and raised her voice women's education as a means of women's empowerment.

It is noteworthy that Ramabai viewed that the child marriage puts an early stop to childhood ," it is not easy to determine when the childhood of a Hindu girls ends and married life begins. "She treated low status in father-in-laws house. Breaking the young wife's spirit is an essential part of the discipline of the new abode". (Kosambi cited Ramabai **the High-Caste Hindu woman)**

Regarding widowhood, she said that widowhood virtually ends a woman's livable life, being" the worst and the most dreaded period of high-caste woman's life". Further Ramabai said that " throughout India, widowhood is regarded as the punishment for a horrible crime as crimes committed by the women in her former existence upon earth".

In March 1889, Ramabai opened a school in Bombay for women, and especially for widows. She received financial support from the Ramabai Association in America and from some friends in England. In 1897, her daughter, Manorama, returned to Wantage, to study medicine. Later on Ramabai established Mukti Mission. Mukti was largely provided 2000 people living there with American and European helpers. Ramabai publicized the plight of the Hindu widow in India. All in all, her throughout life was devoted for ameliorating the condition of Indian women.

Ramabai as a meritorious student :- Ramabai 's first class education was incredibly rare. She notes in her book, The High Caste Hindu Woman, that less than one- quarter of one percent of Indian women at the time were able to read or write. Of these privileged few, many were required to quit their studies at a young age of nine or ten years old when they were married. Early marriage was the norm for young Brahmin girls, and it was often considered dishonorable for a woman to continue her education once wed. As orthodox person, Hindu traditionalists, Ramabai father further went against the grain by refusing or arrange her marriage.

However, Ramabai was encouraged by the New Testament, she was deeply touched by the gospel stories of Jesus ministering to the oppressed. The way he treated people like the Samaritan woman made a strong impression on her. Her feminism was freely reconciled with this new faith; she realized that Christ could truly "transform and uplift the downtrodden women of India." She wrote later (cited in Sonia Hazard: 2009).

Setting up institutions for uplifting women :- Pandita Ramabai was a distinguished figure of feminism in India is equally substantiated by her institutional pursuits for the emancipation women. Even before she could fully articulate her views on the status of women in India, she founded the Arya Mahila Samaj in 1882 in Pune to mobilize and unite women to seek social reforms. But with veiled opposition Tilak as well as her own voyage to foreign countries did not allow this organization to become the centre of feminist movement. However, the zeal of Ramabai for women's empowerment intact during her foreign stays, she looked for arranging support to make such an enterprise more effective and autonomous. Resultantly, the initiatives such as the Ramabai Association of Boston produced financial support for the schemes of Ramabai to be launched in India.

Later on, after returning India, she set up the Sarada Sadan (Home of Learning) to promote shelter to the widows of high caste Hindus in Mumbai. However, in order to gain more direct access to the orthodox Brahmin families when shifted the Sarada Sadan to Pune, she faced immense pressure from the conservative Hindu society in India. Consequently, high caste Hindu

widows stated distancing themselves from the Sadan, pressurizing Ramabai alienate her from the Hindu society and exposing her bonds with Christianity . Thus led her to open a new Christian body, the Mukti Sadan to house the victims of the Gujarat famine of 1896. Later on , she depended on Sarada Sadan which were amalgamated into an overtly missionary body called the Christian Mukti Mission. It is to be said that this created an unbridgeable gap between Ramabai and the high caste Hindu community of Bombay Presidency.

Significantly, the institutional intervention of Pandita Ramabai in uplifting the conditions of women demonstrated the perceived duality of her mission. The Christian Mukti Mission later named as 'Ramabai Mukti Mission' and subsequently 'Pandita Ramabai Mission' .It is no doubt, this Mission became the women bastion where numerous activities were performed for women's empowerment. Moreover, the structures and ambience of the Mission were so encouraging to women that it was sometimes called as a 'female kingdom'. However, the conversion of the Sarada Sadan into a Christian Missionary organization presumably defeated the basic purpose of Ramabai to provide for an emancipator home for the high caste Hindu widows as they were the most marginalized women in the country.

The Founder of Mukti Mission :- The High-Caste Hindu woman also reflects Ramabai emerging commitment to minister to India's high caste child widows. Ramabai expressed that Brahmin women married off as children, they usually live with their husband's family. If the husband dies young, as prescribed by a particular interpretation of Hindu scriptures. These issues are documented in detail in her book on Widow's plight.

The Kedgaon establishment , known as the Ramabai establishment, known as the Ramabai Mukti (salvation) Mission, soon grew into a large community of 2000 women, and was neatly divided into various sections: the original Hindu Widow's Home, a Home for Christian Women, a ' Rescue Home' for sexually victimized women, a separate section for old women and one for blind women. The usual domestic chores such as cooking, cleaning, caring for the young and the sick were done by the inmates themselves (Kosambi 1998:199).

Further she conceded her view that the widow must wear a single coarse of garment, white or brown. She must eat only one meal during the twenty-four hours of a days. She must never take part in family feasts with others. She must not show herself to people on auspicious occasions. It is also believed that widows are stigmatized in society in many aspects of their life (Sonia Hazard: 2009).

It is noteworthy that the more famous orphanage, Mukti (salvation) opened at Kedgaon in 1998. In the meantime, Ramabai herself has passed through second conversion, this time an evangelical one, and for the remainder of her life Christianity was close to 'holiness' pattern. At that time her health was poor, running of Mukti was left mainly to others. Her daughter died 1921, and Ramabai herself died the following year.

However, Mukti opened its doors and provided services for those who suffered from sexual abuse, famine and disability of every caste while presiding over the flourishing mission until her death in 1922. She continued to write and lecture. Among other achievements, she translated the entire Bible from its original Hebrew and Greek into her native language i.e. Marathi, was awarded a gold medal Kaiser-e- Hind from the British government for her community service in the year 1919.

Ramabai as a feminist :- Previously , we have said that Pandita Ramabai tried to elevate the status of women in India. She tried eradicated the oppressive patriarchal norms from the society. She gave a concrete form to her feminist idea by establishing the Arya Mahila Sabha which provide a space to the woman to meet and discuss the problems confronting women at large. Undoubtedly, her liberal parents ensured that she

'managed to escape a rigid gender-specific role, unlike her peers who were locked into wifehood and motherhood at an early age, confined to the domestic sphere, subjected to the pressures of the extended family, and denied education or even literacy(Kosambi 2000:5).Yet, she was aware of the numerous inequalities and discriminations faced by women in the face of patriarchal privileges of men. She also noticed that less asymmetric gender relations in the Western society which was absent in the Indian society. She also revolt against gender-specific social evils of Hinduism. Uma Chakravarty (1998) observes that Ramabai an indomitable activist-theorist bent upon highlighting and ameliorating the pathetic conditions of the women in the Indian society.

However, feminist ideas of Ramabhai eradicate structural inequalities and oppressive discrimination against women. She has tried to elevate the condition of High Caste Hindu widows. She marked that plight of Hindu widows in domestic sphere as well as public domain in Indian society. She made some techniques for empowering them through education, skill development. Meera Kosambi in her article 'Tracing the voice: Pandita Ramabai's life through her landmark texts' analyses her feminism by tracing her ideological trajectories mainly through a discussion of some of her landmark writings, and then indicate the problematic of her representation of the highly oppressed 'Indian woman'.

Ramabai is a dauntless example of India's evolving feminist movement. The world she faced was grim and relentlessly difficult ---- but she never bower her head. Madrascourier.com/ biography/pandita-ramabai-indias-first-feminist (accessed on 5th February, 2018).

All in all, the theoretical base of her feminism led to oppressive aspects of Hindu social and religious order which exhibited exclusionary treatment towards the women. In this regard, Kosambi (1988) observes that the logical conclusion of such a perceptible analysis of gendered nature of Hindu society and religion could be to evolve concrete policies and programmes for emancipating the women and ensuring the equality of status for them.

Conclusion :- The foregoing discussion expresses that Pandita Ramabai made foundations for feminist movement in India. She had been imbibed with revolutionary aspect from her childhood, her entire life represented an unending devotion for women's empowerment. For instance, he started her social reform with the objective of ameliorating the condition of High caste Hindu widows and later on she devoted to Christian missionary activities. Nonetheless, her sincere effort in making women aware of their socio-political aspect in contemporary society paid off in due course. She founded Christian Mukti Mission at a time when there was hardly an effective voice against the oppressive patriarchal norms was carried forward in independent India with the creation of 'Self Employed Women's Association(SEWA)'. Given the patriarchic influence of social values opposed to gender equality, Ramabai's liberal feminist aspects made a important perspective in the nationalist movement in India.

References :-

Chakravarty, Uma (1998). Rewriting History: The Life and Time of Pandita Ramabai, New Delhi: Kali for Women.

Dyer, Helen(2004) Pandita Ramabai: The Story of Her Life, Reprint, Montana: Kessinger Publishing.

Hazard, Sonia. (2009) 'Pandita Ramabai Student, seeker, visionary leader, Focus India Pacific, Vol. 56.

Kosambi, Meera(1988).'Women Emancipation and Equality: Pandita Ramabai's Contribution to Women's Cause', Economic and Political Weekly, Vol. 23, No. 44 ,Oct. 29, pp. WS38-WS49..

Kosambi, Meera (1998). 'Multiple contestations: Pandita Ramabai's educational and missionary

activities in late nineteenth-century India and abroad', Women's History Review, Vol. 7, No. 2, pp. 193-208.

Kosamb,i Meera(2004).'Tracing the voice: Pandita Ramabai's life through her landmark texts,' Australian Feminist Studies , Volume 19, Issue 43.

Ramabai, Pandita(1992). A Testimony of Our Inexhaustible Treasure, Pune: Pandita Ramabai Mukti Mission.

Ramabai, Pandita(2007) The High –Caste Hindu Women, Reprint, Montana: Kessinger Publishing.

Sengupta, Padmini. (1970). Pandita Ramabai: Her Life and Work, Bombay: Asia Publishing House.

White, Keith J. (2007) 'Insights into Child Theology through the Life and Work of Pandita Ramabai' Transformation, Vol 24, No.2, pp.95-102.

Website :

Pandita Ramabai: India's First Feminist? ,Madras Courier madrascourier.com/biography/pandita-ramabai-indias-first-feminist (accessed on 5th February, 2018).

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation October 2017
A Monthly Journal of Multidisciplinary Research (UGC APPROVED, Peer Reviewed & Refereed Research Journal)

रतौंधी रोग का प्राकृतिक चिकित्सा में प्रबंधन

डॉ. मनोज कुमार शर्मा
पी. एच. डी. योग

रोग परिचय :– रतौंधी आंखो की एक बीमारी है इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वत्त वह नजदीक की चीजें भी ठीक से नही देख पाता। रोगी की आँखो की जांच के दौरान पता चलता है कि आँखो का कॉनिया (कनीमिका) सूख सा गया है और आई बाल (नेत्र गोलक) धुधला व मलमैला सा दिखाई देता है उपतारा (आधरिस) महीन छिद्रो से युत्त दिखता है तथा कार्निया के पीछे तिकोनी सी आकृति नजर आती है। आँखो मे सफेद रंग का स्त्राव होता है।

रतौंधी का सबसे आम कारण रेटिनाइटिस पिगमेटोसा एक विकार है जिसमे रेटिना में राड कोशिका धीरे–धीरे उनके प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते है। इस अनुवांशिक हालत से पीडित मरीजों को प्रगतिशील रतौधी है और अंत में उनके दिन दृष्टि भी प्रभावित हो सकती है एक्स जुड़े जन्मजात स्थिर रतौंधी जन्म से छड़ या तो सब पर काम नही है। या तो बहुत कम करते है, लेकिन हालत बदतर नही मिलता है। रात का अन्धापन का एक अन्य कारण (तमजपदंस) या विटामिन 'ए' की कमी है मछली का तेल, लीवर और डेयरी उत्पादो मे पाया जाता है।

'' अपवर्तक दृष्टि सुधार सर्जरी'' रतौंधी का एक व्यापक कारण है, जो विपरीत संवेदनशीलता समारोह की हानि (सी एसएफ) जो कॉर्निया के प्राकृतिक संरचात्मक अखंडता में 'शल्य चिकित्सा के हस्तक्षेप से उत्पन्न प्रकाश स्कैटर (पदजतंवबनसंत) से प्रेरित है आधुनिक परिवेश में युवा वर्ग में 'शारीरिक सौन्दर्य आकषर्ण को विकसित करने पर अधिक ध्यान देते है। ऐसे में वे 'शरीर के विभिन्न अंगो के स्वास्थ्य पर ध्यान नही दे पाते । ऐसे में नेत्रों को बहुत हानि पहुंचती है और अधिकतर युवक–युवतियां रतौंधी रोग से पीड़ित होते है। रतौंधी रोग में रात्रि होने पर रोगी को स्पष्ट दिखाई नहीं देता ।यदि इस रोग में 'शीघ्र चिकित्सा न कराई जाए तो रोगी नेत्रहीन हो सकता है।

उत्पत्ति :– अधिक समय तक दूषित, बासी भोजन कर,पौष्टिक व वसायुक्त खाद्य पदार्थों का अभाव होने से नेत्र ज्योति क्षीण होती है। और रात्रि के समय रोगी को धुंधला दिखाई देने लगता है।

लक्षण :–रतौंधी होने पर सूरज ढलते ही रोगी को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। रात होने पर रोगी को पास की चीजें भी दिखाई देती है। इस रोग की चिकित्सा से अधिक विलम्ब किया जाये तो रोगी को पास की चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देती । रोगी तेज रोशनी में ही थोड़ा बहुत देख पाता है।

रोगी बिना चश्में के कुछ नही देख पाता। चश्में से भी रोगी को बहुत धुंधला दिखाई देता है। बल्ब के चारों ओर रोगी को किरणें फूटती दिखाई देती है। धूल मिट्टी व धुएं के वातावरण से गुजरने पर धुंधलापन अधिक बढ़ जाता है।

रतौंधी का कारण :– नेत्रो के भीतरी भाग मे स्थित रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ कोशिकाएँ बना होता है। कुद कोशिकाएँ छड़ की आकार की होती है। इन कोशिकाओ मे जो रंग कण होते है, वे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते है।

इन छड़ कोशिकाओ में रोडोप्सीन नामक एक पदार्थ पाए जाते है जो कि एक सयुम्मी प्रोटीन होता है, यह पदार्थ आप्सीन नामक प्रोटीन और रेटीनल नामक अप्रोटीन तत्वो से मिलकर बना होता है।

1. अधिक समय तक प्रकाश रहने पर रोडोप्सीन का विघटन, रंगहीन पदार्थ रेटीनल और आप्सीन के रूप मे हो जाता है, लेकिन प्रकाश से अंधेरे में आने पर रोडोप्सीन का तुरंत निर्माण हो जाता है। और एक क्षण में भी कम समय मे सृष्टि सामान्य हो जाती है।
2. उक्त प्रक्रिया मे शामिल रेटीनल विटामिन ए का ही एक प्रकार है। अतः विटामिन एक की कमी हो तो उजाले से अंधेरे से आने पर या कम प्रकाश में रोडोप्सीन का निर्माण नही हो पाता और दिखाई नही देता। इस स्थिति को रतौंधी कहते है।
3. आधुनिक विशेषज्ञों के मुताबिक रतौंधी की वजह विटामिन 'ए' की कमी होना होता है। अक्सर

कुपोषण के शिकार लोग इसके चपेट में आ जाते है। आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार कफ दोष के कारण रतौधी रोग का जन्म होता है।

4. इनका कहना है कि दिन के समय सूर्य के असर से ऑखों पर जमा हुआ कफ साफ हो जाता है, जिससे रोगी को दिन के वक्त दिखाई देने लगता है। मगर रात को कफ फिर से आंख की पुतली में आ जाता है। और रोगी को दिखाई पड़ना बन्द हो जाता है।
5. हालॉकि आयुर्वेद के पुराने ग्रंथो के मुताबिक रतौंधी रोग के दो प्रकार होते है। एक तो वह जिसमें कफ का क्षय होने लगता है और दूसरा वह जिसमें कफ की वृद्धि होने लगती है पहले प्रकार के रतौंधी रोग की वजह कुपोषण माना जाता है । कुपोषण से हुआ रतौंधी रोग ही देखने में आता है।

रतौंधी के लक्षण :– इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है,लेकिन रात के वक्त वह नजदीक की चीजें भी ठीक से नहीं देख पाता। रोगी की आंखों की जॉच के दौरान पता चलता है कि ऑखों का कॉर्नियां (कनीनिका) सूख सा गया है और आई बाल (नेत्र गोलक) धुंधला व मटमैला सा दिखाई देता है। उपतारा (आधरिस) महीन छिद्र से युक्त दिखता है। तथा कॉर्नियां के पीछे तिकोनी सी आकृति नजर आती है आंखों से सफेद रंग का स्त्राव होता है। रतौंधी होने पर सूरज ढलते ही रोगी को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। रात होने पर रोगी को पास की चीजें भी दिखाई देती है। इस रोग की चिकित्सा से अधिक विलम्ब किया जाये तो रोगी को पास की चीजें बिल्कुल दिखाई नही देती। रोगी तेज रोशनी मे ही थोड़ा बहुत देख पाता है। रोगी बिना चश्में के कुछ नही देख पाता । चश्में से भी रोगी को बहुत धुंधला दिखाई देता है। बल्ब के चारों ओर रोगी को किरणें फूटती दिखाई देती है। धूल मिट्टी व धुएं के वातावरण से गुजरने पर धुंधलापन अधिक बढ़ जाता है। जब यह रोग पुराना होने लगता है। तो ऑखों की पलकों पर छोटी–छोटी फुन्सियां व सूजन दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही दर्द भी महसूस होने लगता है। ज्यादा लापरवाही करने पर ऑख की पुतली अपारदर्शी हो जाती है और कभी–कभी क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। रतौंधी की इस स्थिति के शिकार ज्यादातर बच्चें होते है। अक्सर ऐसी स्थिति में औषधियों से इलाज भी बेअसर साबित होता है।

क्या खांए?

1.प्रतिदिन काली मिर्चका चूर्ण घी या मक्खन के साथ मिश्री मिलाकर सेवन करने से रतौंधी नष्ट होती है।

2.प्रतिदिन टमाटर खाने व रस पीने से रतौंधी का निवारण होता है।

3.आंवले और मिश्री को बराबर मात्रा में कूट–पीसकर 5 ग्राम चूर्ण जल के साथ सेवन करें।

4.अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम,आंवले का रस 10 ग्राम और मुलहठी का चूर्ण 3 ग्राम मिलाकर जल के साथ सेवन करें।

5.मीठे पके हुए आम खाने से विटामिन 'ए' की कमी पूरी होती है। इससे रतौंधी नष्ट होती है।

6.सूर्योदय से पहले किसी पार्क में जाकर नगे पांव घास पर घूमने से रतौंधी नष्ट होती है।

7.'शुद्ध मधु नेत्रों में लगाने से रतौंधी नष्ट होती है।

8.किशोर व नवयुवकों को रतौंधी से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भोजन में गाजर, मूली, खीरा, पालक, मैथी, बथूआ, पपीता, आम, सेब, हरा धनिया, पोदीना व पत्ता गोभी का सेवन करना चाहिए।

क्या न खांए? :–

1. चाइनीज व फास्ट फुड का सेवन न करें।
2. उष्ण मिर्च–मसाले व अम्लीय रसों से बने खाध पदार्थो का सेवन से अधिक हानि पहुंचती है।
3. अधिक उष्ण जल से स्नान न करें।
4. आइसक्रीम, पेस्ट्री, चाकलेट नेत्रो को हानि पहुंचाते है।
5. अधिक समय तक टेलीविजन न देखा करें। रतौंधी के रोगी को धूल–मिट्टी और वाहनों के धुएं से सुरक्षित रहना चाहिए।
6. रसोईघर में गैस के धुएं को निष्कासन करने का पूरा प्रबंध रखना चाहिए।
7. खट्टे आम,इमली,अचार का सेवन न करें।

चिकित्सा :– आजकल एलौपैथिक पद्वति में डॉक्टर अकसर इस रोग मे रोगी को विटामिन 'ए' की भरपूर मात्रा लेने की सलाह देते है, मगर एलोपैथिक चिकित्सा में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। लिहाजा आयुर्वेदिक औषधियों से रतौंधी को कंट्रोल करने के

काफी अच्छे व उत्साहवर्धक नतीजे देखने को मिलते है। आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा इसका सफल इलाज संभव है।

आँखो मे लगाने वाली औषधियाँ :– शंखनाभि विभीतकी, हरड,पीपल,काली मिर्च,कूट,मैनसिल,खुरासानी बच ये सभी औषधियाँ समान मात्रा में लेकर बारीक कूट–पीसकर कपड़छान चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को बकरी के दूध में मिलाकर बत्तियाँ बना ले। दवा इतनी बारीक हो कि बत्तियाँ खुरदूरी न होने पाएँ। इन बत्तियो को चकले या चिकने पत्थर पर रोजाना रात को पानी में घिसकर आँखो मे लगाने से रतौंधी रोग ठीक हो जाता है।

2. चमेली के फूल, नीम की कोपल (मुलायम पत्ते) दोनो हल्दी और रसौत को गाय के गोबर के रस में बारीक पीस कपड़े से छानकर आँखो मे लगाने से रतौंधी रोग दूर हो जाता है।

3. रीठे की गुठली को यदि स्त्री के दूध में घिसकर आँखो में लगाएँ तो यह भी रतौंधी मे काफी फायदेमंद होता है।

4. सौठ हरड़ की छाल, कुलत्थ, खोपरा (सूखा नारियल) लाल फिटकरी का फूला, माजूफल नामक औषधियाँ पाँच–पाँच ग्राम लेकर बारीक पीस ले। अब इसमे ढाई–ढाई ग्राम की मात्रा मे कपूर कस्तूरी और अनवेधे मोती को मिलाकर नींबू का रस डालकर पाँच सात दिन खरल करें। फिर इसकी गोलियाँ बनाकर छाया मे सुखा ले । इस गोली को गाय के मूत्र में घिसकर लगाने से रतौंधी रोग में फायदा होता है। यदि इसे स्त्री के दूध में घिसकर लगाया जाए तो आँख का फूला (सफेद दाग) व पुतली की बीमारियाँ भी दूर हो जाती है।

6. कंरज बीज, कमल केशर, नील कमल, रसौत, और गैरिक 5–5 ग्राम लेकर पावडर बना ले। इस पावडर को गोमूत्र में मिलाकर बत्तियां बनाकर रख लें। इसे रोजाना सोते समय पानी मे घिसकर आंखो में लगाने से रतौंधी रोग में काफी पानी में घिसकर आंखो में लगाने से रतौंधी रोग में काफी लाभ होता है।

खाने वाली औषधियाँ :– 50 ग्राम आमलकी, 50 ग्राम बहेड़ा, 125 ग्राम हरीतकी, 5 ग्राम पीपल, 5 ग्राम सेंधा नमक और 150 ग्राम शकर लेकर बारीक पावडर बनाकर कपडछान कर लें। इसमें से 3 से 5 ग्राम की मात्रा लेकर गाय के घी या शहद के साथ लगभग 6 से 8 हफ्ते तक सेवन करें। इसका सेवन आँखो की कई बीमारियाँ (रतौंधी, फूला, जलन व पानी बहना आदि) मे काफी फायदेमंद होता है। जरूरत के मुताबिक इस औषधि को 8 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक सेवन किया जा सकता है।

इसके अलावा कुपोषणजन्य या विटामिन 'ए' की कमी से होने वाले रतौंधी रोग में अश्वगंधारिष्ट, च्यवनप्राश, रातावरीघृत, अवलेह अश्वगंधाघृत व अश्वग्रंधा अवलेह काफी फायदेमन्द साबित हुए है।

लाभकारी पत्ते :– रतौंधी के रोगी को चाहिए कि वह अतिमुक्त, अरंड, रोफाली निर्गुण्डी व शतावरी के पत्तों की सब्जी देसी घी मे अच्छी तरह पकाकर खाँए। अगधिया के पत्ते की सब्जी भी रतौंधी में काफी फायदेमन्द होती है।

बबूल के पत्ते व नीम की जड़ का काढ़ा पीना भी रतौंधी मे काफी लाभ पहुंचाता है। यह काढ़ा बना बनाया बाजार मे भी मिलता है।

प्राकृतिक चिकित्सा :– रतौंधी की सबसे सस्ती व अच्छी चिकित्सा चौलाई का साग है। चौलाई की सब्जी भैंस के घी में भूनकर रोजाना सूर्यास्त के बाद आप जितनी खा से खाँए, लेकिन इसके साथ रोटी,खिचड़ी न खाए। इसका सेवन विश्वास के साथ लम्बे समय तक करने से रतौंधी रोग मे फायदा होता है।

2. रतौंधी के रोगी को सहिजन (सुरजना फली) के पत्ते व फली मेथी, मूली के पत्ते, पपीता, गाजर और लौकी व कदू का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिये। गूलर व अंजीर के फलों का भी उचित मात्रा में सेवन फायदेमन्द होता है।

3. डोंडी के पत्तो की घी में सब्जी बनाकर सेवन करें।

4. गोमूत्र मे छोटी पीपल घिसकर आँखो मे प्रतिदिन अंजन करे।

रतौंधी के रोगियो के लिए योगाभ्यास :– अपनी दृष्टि में सुधार लाने के लिए कई लोग चश्मा या लेंस लगाते है चश्मे से दृष्टि दोष दूर नही होता है। नेत्र सम्बंधी व्यायामों को नियमित रूप से धैर्य और लगन के साथ करना चाहिए। तुरन्त नीरोग या सुधार होने की आशा नही करनी चाहिए। नेत्र दोष कई वर्षो मे प्रकट

होते है, इसी प्रकार सुधार के लक्षण परिलक्षित होने मे भी कुछ महीने या उससे अधिक समय लगेगा ही। कई लोगो ने यौगिक जीवन पद्वति अपनाकर अपने दृष्टि दोष को दूर किया है।

तैयारी :– अभ्यासों को प्रारम्भ करने के पूर्व आँखो मे ठण्ढे जल के कुछ छीटे डालना लाभप्रद होता है। हथेलियों में थोडा जल भर लें और बेसिन के पास खडे होकर आँखो में छीटे मार ले। दस बार ऐसा करने के बाद व्यायाम प्रारम्भ करें। इस प्रक्रिया से आँखो की पेशियो में रक्त संचार में वृद्वि होगी और आँखो को पोषण प्राप्त होगा।

सीमायें :– जिन्हे नेत्र सम्बंधी गम्भीर रोग या दृष्टि दोष होता है उन्हे विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही ये अभ्यास करे। सिर के बल किया जाने वाला आसन और कंजल क्रिया इन रोगो की अवस्था मे सर्वथा वर्जित है। यौगिक जीवन प्रणाली और सुपाच्य शाकाहारी भोजन से निश्चित रूप से लाभ पहुँचेगा।

अभ्यास टिप्पणी :– नेत्र व्यास निर्धारित क्रमानुसार ही करने चाहिए। इन्हे क्रमानुसार प्रातः काल एक बार और अथवा सायंकाल एक बार करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है वह यह कि अभ्यासकाल मे पूर्णतः तनाव रहित और शिथिल रहना चाहिए। अधिक जोर न लगाये। क्योकि इससे नेत्रो को थकान और क्लान्ति होगी। प्रत्येग अभ्यास के बाद नेत्रो को बन्द कर लगभग आधा मिनट विश्राम करना चाहिए। इस समय हथेलियों को आपस में रगड़कर आँखो पर रखा जा सकता है। अभ्यास के समय चश्मा उतार देना चाहिए।

अभ्यास :– आँखो पर हथेलिया रखना, दाएँ–बाएँ देखना घुमना, दृष्टि को ऊपर–नीचे करना, प्रारम्भिक नासिकाग्र दृष्टि। ''शरीर के अन्य अंगो के स्नाने की भांति नेत्र स्नान भी आवश्यक नेत्र स्नान दो प्रकार से लिया जाता है।''

प्राकृतिक नेत्र स्नान :–

पहला प्रकार :– शीशे के तसले मे साफ पानी भरकर मेज पर रखिए उसमे दोनो आँखो को डुबाइये पानी मे डुबाते समय आँखो को खोले रखिये यह क्रिया 5 से 7 बार करना चाहिए।

दूसरा प्रकार :– बाजार से नेत्र स्नान वाला शीश या प्लास्टिक का गिलास लाइए। इसे म्लम हर्से कहते है। इसमें साफ जल भरकर बारी–बारी से डालकार 5–7 मिनट तक आंखो को जल के अन्दर खोलिए और बंद कीजिए। गुलाबजल,त्रिफला, जल, अथवा फिटकरी का घोल भी नेत्र स्नान के काम मे लिया जाता है।

भीगी पट्टिया और लपेट :– जल चिकित्सा में ठंडे जल से भीगी कपउे की पट्टियो और लपेट का बहुत बडा महत्व है। कितने ही रोगी मे तो इन पट्टियो के प्रयोग से जादू का असर होता है पट्टियो और लपेट के लिए खादी का कपडा सर्वोत्तम होता है लेकिन उन्हे सदेव साफ रखना चाहिए पानी जो पट्टियो और लपेटों को भिगोने के काम मे लाया जाये वह साफ होना चाहिए जैसे कि हम ऊपर पढ चुके है।

ठंडी जल पट्टी :– पट्टियां दो प्रकार की होती है एक ठंडी जल की पट्टि कहते है। और दूसरे को गरम जल पट्टियाँ ठडी जल की पट्टी लगाने के बाद खुली रहती है उसके ऊपर कोई सूखा कपड़ा नही लपेटा जाता है जिसे 2–5 मिनट के बाद गरम होने पर बदला जाता है यदि रोगी किसी वजह से ठड़ी जल पट्टी सहन न कर सकता हो अथवा तो उसे गुनगुने जल की पट्टी लगानी चाहिए।

गर्म जल पट्टी :– ठड़ी जल पट्टी लगाने के बाद उसके ऊपर जब सूखे फलालेन या किसी अन्य ऊनी कपड़े की एक दूसरी पट्टी लपेट दी जाती है तो उसे गर्म जल पट्टी कहते है कारण ऊनी कपड़े आदि की सूखी पट्टी के प्रयोग से नीचे की ठंडी जल पट्टी थोड़ी ही देर में आप गर्म हो उठती है यह सरासर गलत है।

गर्म जल पट्टी भी ठंडी जल पट्टी की तरह ही लगाई जाती है मगर इसे ठंडे पानी से इतना तर नही किया जाता है कि लगाने के बाद उसमे पानी टपकता रहे, अपितु पट्टी को तर कर लेने के बाद उसे निचोड़कर प्रयोग किया जाता है।

तीन से छः घंटे तक यह गर्म पट्टी रखी जाती है उसके बाद उसे बदल दिया जाता है। गरम जल–पट्टियाँ पुराने रोगो तथा बिना दर्द की हालतो मे विशेष रूप से लाभकारी है।